खण्ड–493, अंक–2
सोमवार, 25 फाल्गुन, शक संवत् 1936
(16 मार्च, 2015 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2015)

(खण्ड 493 में 9 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रदेश में ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद होने के प्रकरण पर चर्चा कराने की मांग	7–10
प्रश्नोत्तर	10–63
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	63–65
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	65–66
जनपद गाजीपुर के कतिपय क्षेत्रों में छलका का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	66–67
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव में दिनांक 27–02–2015 को हुई ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	67
जनपद इलाहाबाद के जमुनापार क्षेत्र के कतिपय इलाकों में बुन्देलखण्ड की भांति विकास कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	67–68
जनपद अमेठी में स्थापित पोस्टमार्टम हाउस को प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	68
जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में चिकित्सीय सुविधायें बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	68–69
जनपद मथुरा के मन्दिरों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	69
मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शहीद रामचन्द्र इण्टर कालेज, देवरिया के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	69–70
जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम बेल्तुआ से नौरंगपुर पुल तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	70
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूप शहर के किसान ज्ञानेन्द्र पुत्र धर्मवीर के लगभग 15 पशुओं की हुई असामयिक मृत्यु का मुआवजा दिलाये जाने एवं गांव में फैली हुई बीमारी की रोकथाम हेतु समुचित उपाय कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के	71

अन्तर्गत सूचना ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् में नियुक्त अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरित शिक्षकों की पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	71–72
जनपद बस्ती में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	72
फिरोजाबाद नगर में ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	72–73
कानपुर महानगर के लोहिया ग्राम पूरनपुर की क्षतिग्रस्त गलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	73
विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के वार्ड सं0–6 की जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	73–74
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	74
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–04–2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	74
उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–09–2014 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	74
उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–03–2011 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	74–75
उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–04–2012 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	75
उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–02–2012 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	75
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 132वां (एक सौ बत्तीसवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	75
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 133वां (एक सौ तैंत्तीसवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	75–76
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा (2013–14) का पंचम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	76

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2013–14) का पंचम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ... 76

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2013–14) का षष्ठम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ... 76

विषय	पृष्ठ–संख्या
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	76–90
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत)	90
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	90–104
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–69 व्यावसायिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	104–122
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या–75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत)	122–153
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	153–154
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	154–179
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	180–193
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	193–194
जनपद मथुरा अन्तर्गत गोवर्धन दानधारी मन्दिर के सामने दिनांक 15 सितम्बर, 2014 को गाड़ी संख्या यू0पी0 32 एफ0ए0 2002 का शीशा तोड़कर की गई चोरी के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	194
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा स्थित मझिगवां मौरंग बालू घाट को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ..	194
फिरोजाबाद नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र हिमायूंपुर में 800	194–195

मीटर कच्ची पटरी की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य .. ..

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में बी0पी0एल0 कार्ड/अन्त्योदय योजना में कार्ड के लाभार्थियों के चयन में की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	195–196
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग सी0डी0–1 तथा प्रान्तीय खण्ड के अन्तर्गत मुख्य सड़कों की मरम्मत/नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	196
जनपद बस्ती के तहसील भानपुर व रुधौली में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय प्रताप जयसवाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	196
जनपद बहराइच के विकास खण्ड नवाबगंज के किसानों के धान व गेहूं के मूल्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	196
जनपद बरेली में जिला विद्यालय निरीक्षक बरेली द्वारा शिक्षकों के जी0पी0एफ0 के भुगतान में की जा रही धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य... ...	196–197
जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र कस्ता के ग्राम बेहजम से नीमगांव तक की सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार लाला द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	198
जनपद शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम–हजरतपुर के निवासी श्री महेश की दिनांक 08 मार्च, 2015 को ट्रैक्टर–ट्राली पलटने से हुई मृत्यु में कृषक दुर्घटना बीमा का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित) ...	198
जनपद झांसी में कुख्यात भू–माफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों का बिना	198

लैण्ड यूज बदले अवैध प्लाटिंग कर विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि शर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)... ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद हाथरस के कस्बा सिकन्दराराऊ में रोडवेज बस स्टैण्ड स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	198
जनपद वाराणसी के रामनगर स्थित सुल्तानपुर गांव में स्थापित मिनी ट्यूबवेल को बिजली कनेक्शन दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	198

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 16 मार्च, 2015 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–305

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
5. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
7. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
8. अताउररहमान, श्री बरेली
9. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
10. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
11. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
12. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
13. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
14. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
15. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
16. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
17. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
18. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
19. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
20. अमित गौरव यादव, श्री एटा
21. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
22. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
23. अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमती प्रतापगढ़
24. अरूण कुमार, डा0 बरेली
25. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
26. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
27. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
28. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
29. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
30. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
31. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
32. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
33. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
34. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
35. आलमबदी, श्री आजमगढ़
36. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
37. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
38. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
39. आशीष यादव, श्री बदायूं
40. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
41. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
42. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
43. इकबाल, श्री बिजनौर
44. इकबाल महमूद, श्री संभल
45. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
46. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
47. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
48. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
49. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
50. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर

51. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्रीलखीमपुर खीरी
52. उदयराज, श्री उन्नाव
53. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
54. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
55. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
56. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
57. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
58. ओम कुमार, श्री बिजनौर
59. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
60. काली चरन सुमन, श्री आगरा
61. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
62. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
63. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
64. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
65. कैलाश, श्री गाजीपुर
66. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
67. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
68. गजराज सिंह, श्री हापुड़
69. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
70. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
71. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
72. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
73. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
74. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
75. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
76. गोमती यादव, श्री लखनऊ
77. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
78. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
79. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
80. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
81. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
82. जगपाल, श्री सहारनपुर
83. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
84. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
85. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
86. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
87. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
88. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
89. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
90. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
91. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
92. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
93. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
94. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
95. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
96. दलजीत सिंह, श्री बांदा
97. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
98. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
99. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
100. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
101. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
102. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
103. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
104. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
105. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
106. धर्मराज, श्री बाराबंकी
107. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
108. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
109. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
110. नदीम जावेद, श्री जौनपुर

111. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
112. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
113. नारद राय, श्री बलिया
114. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
115. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
116. परवेज अहमद (टंकी), हाजीइलाहाबाद
117. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
118. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
119. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
120. पीतमराम, श्री पीलीभीत
121. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
122. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
123. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
124. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
125. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
126. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
127. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
128. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
129. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
130. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
131. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
132. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
133. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
134. बदलू खां, श्री उन्नाव
135. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
136. बाबू खां, श्री हरदोई
137. बाबूलाल, श्री गोण्डा
138. बावन सिंह, श्री गोण्डा
139. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
140. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
141. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
142. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
143. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
144. बैजनाथ, श्री मऊ
145. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
146. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
147. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
148. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
149. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
150. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
151. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
152. मनबोध, श्री देवरिया
153. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
154. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
155. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
156. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
157. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
158. महबूब अली, श्री अमरोहा
159. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
160. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
161. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
162. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
163. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
164. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
165. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
166. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
167. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
168. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
169. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
170. मो0 आसिफ जाफरी, सी0ए0कौशाम्बी
171. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
172. मो0 रेहान, श्री लखनऊ

173. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
174. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
175. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
176. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
177. यासर शाह, श्री बहराइच
178. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
179. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
180. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
181. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
182. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
183. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
184. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
185. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
186. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
187. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
188. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
189. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
190. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
191. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
192. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
193. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
194. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
195. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
196. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
197. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
198. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
199. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
200. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर
201. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
202. राधे श्याम, श्री अमेठी
203. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
204. राम करन आर्य, श्री बस्ती
205. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
206. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
207. राम गोविन्द, श्री बलिया
208. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
209. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
210. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
211. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
212. राम मगन, श्री बाराबंकी
213. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
214. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
215. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
216. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
217. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
218. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
219. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
220. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
221. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
222. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
223. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
224. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
225. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
226. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
227. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
228. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
229. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
230. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
231. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
232. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
233. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
234. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
235. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी

236. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
237. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
238. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
239. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
240. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
241. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
242. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्रीफर्रुखाबाद
243. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
244. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
245. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
246. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
247. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
248. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
249. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
250. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
251. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
252. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
253. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
254. शाकिर अली, श्री देवरिया
255. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
256. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
257. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
258. शिव कुमार बेरिया, श्रीकानपुर देहात
259. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
260. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
261. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
262. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
263. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
264. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
265. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
266. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
267. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
268. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
269. संजय कपूर, श्री रामपुर
270. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
271. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
272. सतवीर सिंह गुर्जर, श्रीगौतमबुद्ध नगर
273. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
274. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
275. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
276. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
277. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
278. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
279. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
280. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्रीबदायूं
281. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
282. सियाराम सागर, डा0 बरेली
283. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
284. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
285. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
286. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
287. सुधाकर, श्री मऊ
288. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
289. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
290. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
291. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
292. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
293. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
294. सुरेश राणा, श्री शामली
295. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
296. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद

297.	सुल्तान बेग, श्री	बरेली	302.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
298.	सुशील सिंह, श्री	चन्दौली	303.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी
299.	सूरज पाल सिंह, श्री	आगरा			
300.	सैय्यदा शादाब फातिमा,	श्रीमतीगाजीपुर	304.	हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद
301.	सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	305.	हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत

नोट :– पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

ख11.00, प्रदेश में ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद होने के प्रकरण पर चर्चा कराने की मांग

(भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सदस्य सदन के वेल में आ गये। वेल में आये हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा एक साथ अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करते रहने पर सदन मे घोर व्यवधान बना रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सतीश महाना–

(सदन के वेल से) मान्यवर, ओलावृष्टि से फसलें बरबाद हुई हैं मैं इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, किसानों पर कहर टूटा हआ है और सरकार सुनने को तैयार नहीं है।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करते रहने पर सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

आपने नियम–56 में दिया है यह ओलावृष्टि वाला मैने उसे स्वीकार कर लिया है नियम–56 में आपका है आप नियम–56 में बोलियेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि लगातार 24 घन्टे पानी बरसा है इस बारिश से प्रदेश का किसान तबाह हो गया है। मान्यवर, मैं सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से गेहूं, आलू, सरसों, लाही सारी की सारी फसलें बरबाद हो गयी है इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाय। यह किसानों से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री अध्यक्ष–

आपने नियम–56 में दिया है मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। आप इस पर अपनी पूरी बात कहियेगा ओर सरकार भी इस पर जवाब देगी और आप लोगों का भी नियम–56 में आयेगा आप अपनी पूरी बात कहियेगा। प्रश्न प्रहर क्यों बाधित कर रहे हैं। आपने दिया है मैंने ले लिया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं अनुरोध करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय। (घोर व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, ओलावृष्टि से सारी फसल बरबाद हो गयी है। यह बहुत गम्भीर मामला है। (घोर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह सरकार चर्चा कराने से कतरा रही है इसलिए किसान विरोधी सरकार के इस रवैये को देखते हुए मैं अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल बहुजन समाज पार्टी के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री प्रदीप माथुर–

ख ग ग ग ,

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। जो आप बोल रहे हैं यह न कुछ लिखा जायेगा और न कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

नियम–56 में आपको पूरा अवसर मिलेगा। (घोर व्यवधान)

अब आप लोग चलिये।

(वेल में आये हुए सदस्य माननीय अध्यक्ष के आग्रह पर अपने अपने आसन पर चले गये)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही खेद का विषय है और यह क्यों कि कुदरत की तरफ से यह जमीनी मार है इसमें तो आवश्यकता इस बात की है कि सब सब एक साथ बैठे और इस पर बात करें कि इसका क्या निदान हो, क्या हल हो, लेकिन सिर्फ खबर बनाने के लिये अगर वाकआउट किया जाता है तो

(श्री सतीश महाना द्वारा सदन के वेल में आकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

श्री महाना जी, कृपया आप अपने स्थान पर चलिये।

(श्री सतीश महाना अपने स्थान पर चले गये)

श्री मोहम्मद आजम खां–

हम आपको नहीं कह रहे हैं, अगर केवल इसलिये वाकआउट किया जाता है कि खबर बन जाये, तो यह कोई बहुत अच्छी सोच नहीं है। प्रश्नकाल में यह उठा, आपने आश्वासन भी दिया, उसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष का अपने दल को ले जाकर बर्हिगमन करना, यह मामलें की संजीदगी नहीं है, मामलें की संजीदगी तो यह है कि इस पर बहस हो, बात हो कि कैसे मदद की जा सकती है, उस मदद की आपस में चर्चा हो, केवल वाकआउट कर देना और क्षण भर में फिर वापस आ जाना यह कोई बहुत अच्छी परम्परा नहीं है और यह हल्कापन है राजनीति का। राजनीति को हल्का करना है और जो गरीब किसान जो बरबाद हुआ है, उसका मजाक उड़ाना है, बजाय इसके कि उसके मामलों पर चर्चा हो, बहस हो। मान्यवर, संजीदगी खत्म हो गई सदन की और प्रश्नकाल को जिस तरह से लिया जाने लगा, मैं बिल्कुल संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत में यह बात कह रहा हूं कि इस तरह के विषयों पर जो संवेदना होनी चाहिये थी, वह संवेदना नहीं हुई।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सिर्फ खबर बनाने के लिये कि पहले मेरी खबर छप जाये, तो यह अच्छा नहीं है और यह किसानों के साथ बड़ा धोखा है और बड़ा दुखद मामला है।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर एकसाथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब क्या है, अब आगे चलिये, जब आयेगा, तो उसमें बोलियेगा। नियम–56 में है। मौर्या जी ने दिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे आग्रह यह है कि आप थोड़ी देर के लिये सदन स्थगित कर दें और सभी माननीय नेताओं को ले चले और उनसे बात करें और इस पर संजीदा बात होनी चाहिये कि किसानों से हमदर्दी है, या केवल खबर छपवाना है। अगर किसानों से हमदर्दी है, तो अभी हम 10–15 मिनट के लिये बैठ लेते हैं और किस तरह चर्चा होगी और क्या तरीका होगा सदन को चलाने का यह तय होना चाहिये, क्योंकि यह किसानों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। क्या रास्ता निकला इतनी देर में, क्या कहा गया किसानों के लिये, कहां से मदद मांगी गई, किसने मदद की मांग की, किसको मदद देना है, इस पर तो कोई बात हुई नहीं। वाकआउट हो गया, वापस भी आ गये, तो इस पर मान्यवर थोड़ा सा संजीदा रूख होना चाहिये और थोड़ी देर के लिये दलीय नेताओं के साथ बैठकर इस पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने प्रवचन में इस बात को कह दिया कि इस पर चर्चा होनी चाहिये। जब सरकार तैयार है, तो अलग से किसी बैठक की आवश्यकता नहीं है एक चीज और दूसरी चीज यह कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आज प्रश्नों का उत्तर देने के लिये अपने मंत्रियों के अभाव में प्रश्न प्रहर टालने की नियत से आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि 15 मिनट के लिये बैठ लिया जाये जिससे कि सारे मंत्री इनके आ जाये। यह सरकार नदारद है, माननीय मंत्रीगण कितने संवेदनशील हैं इस प्रश्न प्रहर के लिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी क्या प्रश्न लिया जाये ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न लिया जाये। यह प्रश्न हमारा है, संसदीय कार्य मंत्री का नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जी का काम उत्तर देना है और जब–जब इस प्रकार की बातें आती हैं, तो संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि मंत्रि–मण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज सरकार अपनी नाकामियाओं पर एवं संवेदनहीनता पर, अपनी गैरहाजिरी पर पर्दा डालने का काम कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है अब हो गया, मौर्या जी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं यहां केवल भाषण सुनने के लिये नहीं आया हूं। मैं किसानों की समस्या लेकर आया हूं या तो मेरा अनुरोध स्वीकार करें और चर्चा अभी कराना शुरू कर दें यह पूरा अधिकार आपका है और जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है कि इस पर चर्चा होनी चाहिये तो चाहे अभी कराये या चाहे प्रश्न प्रहर के बाद कराये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्या जी, इस पर कैसे चर्चा हो, किन नियमों के अंतर्गत चर्चा हो, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस पर कहा कि हम लोग, नेता लोग बैठकर तय कर लें कि इस पर क्या करना है और क्या नहीं करना है, फिर इस पर चर्चा हो। चलिये आप लोग हमारे चैम्बर में आईये, दस मिनट के लिये। मैं दस मिनट के लिए सदन को स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण 11 बजकर 08 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित कर दी।)

(11 बजकर 18 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

ख11.19, प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

ख्उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न,

प्रदेश में मार्च, 2013 से दिसम्बर, 2014 तक दो साम्प्रदायिक दंगों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

'01–श्री नदीम जावेद, श्री सुरेश राणा तथा श्री वीरपाल राठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माह मार्च, 2013 से दिसम्बर, 2014 तक कुल कितने साम्प्रदायिक दंगे हुये तथा उक्त दंगों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार दंगों की रोकथाम हेतु कोई प्रभावी योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माह मार्च, 2013 से दिसम्बर, 2014 तक प्रदेश में 02 साम्प्रदायिक दंगे हुये–

- वर्ष 2013 जनपद मुजफ्फरनगर में हुए दंगे की घटना के सम्बन्ध में कुल 477 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें विवेचना के दौरान 1359 अभियुक्तों की संलिप्तता पायी गयी है। अब तक 1046 अभियुक्त गिरफ्तार, 298 अभियुक्त मा0 न्यायालय में हाजिर हुये व 05 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा–83 द0प्र0सं0

की कार्यवाही की गयी। अब तक कुल 1349 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है।

- वर्ष 2014 में जनपद सहारनपुर में हुए साम्प्रदायिक दंगे की घटना के सम्बन्ध में कुल 237 अभियोग पंजीकृत हुए, अभियुक्तों की संख्या–229, गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या–99, हाजिर अदालत–02, शेष अभियुक्तों की संख्या–128, 19 प्रकरणों में आरोप–पत्र प्रेषित किये गये हैं, शेष अभियोगों की विवेचना में आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया प्रचलित है।

प्रदेश के सभी जनपदों में दंगों की रोकथाम के लिये कार्य योजनायें बनायी गयी हैं, जिन्हें समय–समय पर अद्यावधिक करते हुए उसका पुर्नभ्यास कर उसका कड़ाई से अनुपालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त जनता के प्रभावशाली/सम्भ्रांत व्यक्तियों को साथ लेकर अमन कमेटियों का गठन किया गया है, जिनकी समय–सीमा पर गोष्ठियां आयोजित कर साम्प्रदायिक विवादों का पता लगाकर उनका निराकरण कराया जाता है। संवेदनशील/मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में समुचित पुलिस गश्त एवं पिकेट की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी (क) तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर)

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

पहले प्रश्न हो जाने दीजिये आप फिर व्यवधान डालने लगे, आप कहिये तो पूरा प्रश्नकाल स्थगित ही कर दें, अब मैंने प्रश्नकाल ले लिया, अब प्रश्नकाल में क्या हो गया।

श्री सतीश महाना–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न, प्रश्न से ही संबंधित है। पहले इसे आप सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

अब आप जिद न करिये और प्रश्न का उत्तर आने दीजिये, जब प्रश्न प्रहर खत्म हो जायेगा तो हम आपकी व्यवस्था का उत्तर देंगे।

श्री नदीम जावेद–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न पर राज्य सरकार के द्वारा यह जवाब आया है कि मार्च, 2013 से दिसम्बर, 2014 तक प्रदेश में 02 साम्प्रदायिक दंगे हुये हैं। भारत सरकार का मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स का जो डेटा है, वह यह कहता है कि इस अवधि में साम्प्रदायिक संघर्ष की, साम्प्रदायिक हिंसा की और दंगों की 247 घटनायें हुयी हैं जो देश में सबसे अधिक हैं। इस प्रकार राज्य सरकार का कथन और भारत सरकार का जो डेटा है, उसमें बहुत अंतर दिखाई देता है। दूसरी बात, यह कहना चाहता हूं कि मान्यवर,

मुजफ्फरनगर की जो घटना हुयी थी उस पर कृष्ण रामपुरयानी का पेपर आया है, उसमें यह कहा गया है कि देश के दंगों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्ट्रानिक टूल का और सोशल मीडिया का बहुत बड़े लेविल पर इस्तेमाल हुआ है। दूसरी बात, अध्यक्ष जी, भारत के दंगों के इतिहास में शायद इतना बड़े स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में दंगे नहीं हुये जितना मुजफ्फरनगर में हुये। तो राज्य सरकार ने दंगा रोकने के लिये जो सिस्टम लाने की बात की है और जो सुझाव दिया है उसमें वही ट्रेडीशनल तरीके 20–25–30 साल पुराने उन्हीं तरीकों को दिखाया गया है, जो बदलते हालात की हमारी चुनौतियां हैं, उस पर राज्य सरकार क्या कर रही है और क्या दंगों को रोकने के लिये कोई ऐसा कानून राज्य सरकार लायेगी जिसमें टाइमबाउंड होगा और जो लोग इसमें संलिप्त हैं, चाहे वह राजनेता हों, चाहे वह आम लोग हों, चाहे अधिकारी या पुलिस के लोग हों, टाइमबाउंड तरीके से उनके ऊपर आरोप सिद्व हों और आम लोगों के साथ जस्टिस हो जो दंगों में पीड़ित होते हैं। तीसरी एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जो लोग दंगों से पीड़ित हैं उनके लिये न्याय की क्या व्यवस्था है अगर वह अपने घर से दूसरी जगह पर आते हैं, शेल्टर्स सेंटर में आते हैं तो जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर के दंगों में जो दंगा पीड़ितों का हाल हुआ।

श्री अध्यक्ष–

पहले इतना पूछ लीजिये, क्या सब एक साथ ही पूछेंगे।

श्री नदीम जावेद–

ठीक है अध्यक्ष जी, तो मैं इसके बाद अपना दूसरा सवाल पूछूंगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं समझ नहीं पाया। सुझाव ज्यादा थे और सवाल तो मुझे कोई नहीं लगा कि इसमें था। एक चीज आपने कही कि इलेक्ट्रानिक मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल हुआ है, यह सही बात है। अब क्योंकि दुनिया तरक्की कर रही है और कम्प्यूटराइजेशन का दौर है, तो उसे कानून के जरिये ही रोका जा सकता है और उसे रोकने के जो भी तरीके हो सकते हैं, वह कोशिश हो रही है और उसके लिये सिस्टम को डेवलप किया गया है। एक बात आपने यह कही कि शायद भारत के इतिहास में गांवों में इतने बड़े दंगे नहीं हुये तो मेरे ख्याल से अगर इस इतिहास में न ही जायें तो अच्छा है क्योंकि आप जिस दल से बैठे हैं, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जायेगी, तो इसे यहीं रहने दें।

श्री नदीम जावेद–

अध्यक्ष जी, वही कातिल, वही शाहिब, वही मुसिंफ भी हैं, अकरबा मेरे तरह खून का दावा किस पर करें। अध्यक्ष जी, मैं इंसीडेंट कोड करता हूं। राज्य सरकार ने जवाब दिया है कि केवल दो दंगे हुये। मैं बताना चाहता हूं कि 10 मई, 2014 मेरठ, गौरी बाजार, 23 मई, 2014 दारूलउलूम में दो लोगों को मार दिया गया। 2 जून, 2014 दिल्ली

गेट, मेरठ में एक और घटना। 05 जून, 2014 शामली चौसाना गांव में 20 लोग इंजर्ड, 19 जून, 2014 ...

श्री अध्यक्ष–

आप ऐसे ही जोड़कर बता दीजिये कि कुल इतनी घटनायें हुयीं ।

श्री नदीम जावेद–

अध्यक्ष जी, मैं केवल यह बात कह रहा हूं कि राज्य सरकार इतने संवेदनशील विषय पर जिस प्रकार से लीपा–पोती करने का प्रयास कर रही है, क्या राज्य सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इतने संवेदनशील विषय पर सचमुच राज्य में दंगों को रोकने के लिये क्या उपाय हो सकते हैं और जस्टिस सिस्टम को किस प्रकार इम्प्रूव किया जाय, इस पर जवाब चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हम मुंसिफ तो नहीं हैं लेकिन आंखें हैं देखते हैं, कान हैं सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, जानकारी भी रखते हैं। नौजवान की इतनी उम्र नहीं होगी, इतने साल के वह नहीं होंगे जितने हजार दंगे हुए हैं। पार्लियामेंट के आंकड़ों के ऐतबार से तकरीबन 50 हजार कम्युनल राइट्स कॉग्रेस के राज्य में हुए हैं, जिसमें अहमदाबाद, मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद ऐसे दंगे हैं जो दिल दहला देने वाले हैं। नहीं, आप ऐसे मत कीजिए जब सवाल उठायेंगे तो जवाब सुनेंगे। हम मुंसिफ तो नहीं हैं लेकिन आप जहॉ पहुंच गये हैं इसके बाद भी अगर लुटने वालों और मरने वालों का आप सदन में मजाक उड़ायेंगे, हमें मुंसिफ भी बतायेंगे तो जाहिर है इसका संदेश बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। हमने सच कह दिया था तो आप सब वेल में चले आये थे, क्या गलत कह दिया था, ख ग ग ग ,

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां–

जब मुंसिफ ठहरे हैं तो सुनो, जब मुंसिफ ठहरे हैं तो सुनो, ख ग ग ग ,

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें, आपको भी कहने का मौका मिलेगा, अभी सुन लीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, मुंसिफ बताया है।

श्री प्रदीप माथुर–

उन्होंने शेर पढ़ा है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

शेर पढ़ा है ना तो शेर की तफ्सील भी सुन लें, शेर का मतलब भी तो बता दूं, यह वह शेर थोड़े ही है जो दीवार पर आप टांग देंगे, यह वह शेर नहीं है। रात को रात

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कह दिया मैंने, बस इसी पर बिगड़ गई दुनियां। मैंने तो यह केवल एक वाकया बताया है, कहिये तो मुरादाबाद का भी बताऊं, मलियाना का बताऊं, मेरठ का बताऊं। मैं इंसाफ कर रहा हूं, आपने बताया ना, तो मान्यवर, मैं नौजवान से यह कहना चाहूंगा कि जिन शहरों के हादशात उन्होंने बताये हैं वह क्रिमिनल हादसे हैं, आपराधिक मामले हैं और हमने जो दो बताये हैं यह साम्प्रदायिक दंगे हैं। आपराधिक मामले और साम्प्रदायिक दंगे अलग–अलग होते हैं और दोनों की अलग–अलग धाराएं होती हैं और अलग–अलग कार्रवाईयां होती हैं।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, यह विषय बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही गम्भीर भी है। निश्चित रूप से सरकार की ऐसी मानसिकता होनी चाहिए कि प्रदेश का माहौल साम्प्रदायिक रूप से ठीक रहे। संख्या के आधार पर मैं जाना नहीं चाहता कि कितनी संख्या सरकार ने बताई है मैं उस आंकड़े पर जाना नहीं चाहता। मैं तो कुछ ऐसे बिन्दुओं की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर की घटना हुई, कई बार सही कार्यवाही न होना और गलत लोगों को मुल्जिम बना देना, यह भी आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं होता है, इससे भी साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, बनता नहीं है। मुजफ्फरनगर की घटना हुई, मैं आंकड़ों के आधार पर और स्पष्ट जानकारी के आधार पर मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुकदमें कायम हुए, उन मुकदमों में, मुकदमों की गम्भीरता का अंदाजा आप इस बात से लगाइये कि मुकदमों में जो मुल्जिम बनाये गये, जांच के दौरान उनमें 11 लोग ऐसे पाये गये जो कि मुकदमा दर्ज होने के समय दुनिया में थे ही नहीं। 11 लोग मृत थे और मृत लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया गया, जिनको बाद में जांच में निकाला गया, 11 लोग ऐसे थे जो मृत पाये गये। 49 मामले ऐसे थे।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, आप प्रश्न पूछिये।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, प्रश्न का आधार यही है, 49 मामले ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमने मुकदमा किया ही नहीं है। 49 वादी ऐसे थे जांच में जिन्होंने कहा कि हमने मुकदमा किया ही नहीं है। एक मुकदमें में चार–चार तहरीर 2544 लोग इस आधार पर नामजदगी से बाहर हुए कि उनका चार–चार तहरीर में नाम था, 2544 लोग इस आधार पर बहाल किये गये। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि कुछ लोगों के खिलाफ और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत गम्भीर हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि निर्दोषों का समाधान हो जायेगा। 25 लोगों को बलात्कार में मुल्जिम बनाया गया है जिन लोगों को मुल्जिम बनाया गया है और उस रिपोर्ट के आधार पर आपने देख ही लिया कि एस0आई0टी0 ने क्या किया ? वह लोग अपना हर प्रकार का चाहे नार्को टेस्ट करा लो, चाहे आप पोलियोग्राफी टेस्ट करा लो, सब प्रकार के टेस्ट के लिए तैयार हैं, उम्र 70 साल मुकदमा छेड़खानी का, उम्र 76 साल मुकदमा बलात्कार का, उम्र 84 साल मुकदमा

छेड़खानी का। वहां इतने बड़े चौधरी सीताराम बहालवी केवल इसलिए उनकी मौत हो गयी कि उनके बेटे के खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम कर दिया गया। मैं यह नहीं चाहता कि जो लोग दागी हैं वह बख्शे जायं, मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि निर्दोषों के खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाई हो, तो मैं माननीय मंत्री जी से, सरकार से कहना चाहता हूं कि क्या सरकार जो लोग वहां अपना पोलियोग्राफी टेस्ट कराने के लिए तैयार है, नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, ऐसे लोगों जिनके खिलाफ झूठे मुकदमें पंजीकृत हुए हैं क्या सरकार उनका पोलियोग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट कराकर सच्चाई जानने का प्रयास करेगी, नम्बर–दो, दूसरी घटना सहारनपुर की थी, सहारनपुर में क्या हुआ इस पर मैं जाना नहीं चाहता। मैं वहां गया था करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ, आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूं गोलू ऑटो सर्विस, जो सरकार ने जांच करायी थी और सरकार की जांच में ही आया था कि 50 लाख रुपये का नुकसान हुआ लेकिन मुआवजा मिला 24 लाख रुपये का, जनता ऑटो, नुकसान हुआ 36 लाख रुपये का, मिला 18 लाख रुपया।

श्री अध्यक्ष–

राणा जी, आप घटना बता रहे हैं, प्रश्न पूछिये।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, प्रश्न ही पूछ रहा हूं। अमित एसोसियेट्स का 45 लाख रुपये का नुकसान हुआ, मिला कुछ नहीं, प्रकाश ऑटो सेल्स का 40 लाख का नुकसान, मिले दो लाख रुपये। प्रश्न यह है कि अपना जो आंकलन सरकार ने कराया है, अपनी जो जांच सरकार ने करायी है जिन लोगों का भारी नुकसान हुआ है, उन लोगों को जो सरकार ने जांच में पाया है उसके अनुसार ही नुकसान के मुताबिक मुआवजा देगी, यह मेरा दूसरा प्रश्न है ? पहले प्रश्न में मैंने कहा है कि जो लोग बलात्कार में, छेड़खानी में झूठे फंसाये गये हैं, एस0आई0टी0 की जांच पर वहां के लोगों को भरोसा नहीं है, जांच का बिन्दु मैंने बता दिया कि ऐसे लोगों को वहां नामजद करा दिया जो लोग निर्दोष थे तो उन लोगों को नामजदगी से बाहर करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

पहला प्रश्न आपका यह है कि कुछ नाम फर्जी आ गये जो पुलिस ने निकाल दिये। आप भी जानते हैं कि दंगे के माहौल में जिस तरह से एफ0आई0आर0 लिखे जाते हैं और जो एफ0आई0आर0 लिखवाने वाले होते हैं उनके कथन पर यकीन करते हुए नामों का इंद्राज कर दिया जाता है और जब जॉच होती है तो सही और गलत तय किये जाते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद कि आपने इसको कम से कम माना कि जो लोग बेगुनाह थे वह निकाल दिये गये। लेकिन यह भी मान लीजिए कि जो लोग रह गये हैं, वह गुनाहगार हैं। आपके जवाब में ही यह बात निहित है कि बेगुनाह लोग निकल गये और जो लोग बच गये हैं वह गुनाहगार हैं, जिन लोगों के बारे में यह कहा गया कि उन्होंने कम्पलेन्स वापस ले ली, मरता क्या नहीं करता मान्यवर, ये कौन लोग थे जिनकी कम्पलेन्ेस थी ? ये जानवर से भी ज्यादा बदतर जिन्दगी गुजारने वाले, मारने वालों के

ख़िदमतगुजार, उनकी खेतियां उगाने वाले, उनकी पैरों पर मालिश करने वाले, उनके घर में झाड़ू–पोछा करने वाले, उनके जानवरों की सेवा करने वाले, उनको नहलाने वाले, ये वे लोग थे। अगर जालिमों के नाम वापस ले लिये गये तो यह बहुत शान की बात नहीं है। जाहिर है कि अगर उन्हें रहना है तो फिर इसी तरह रहना है, वरना पलायन करना है, आखिर क्या वजह है कि अपनी ही सरजमीं को छोड़कर अपने ही घर, घर क्या थे मान्यवर, न छप्पर थे, न दीवारें थीं किसी का खेत तो था नहीं, खेतों पर काम करने वाले मजदूर थे बहरहाल जहां रहते थे, जगह से मोहब्बत तो थी ऐसे कमजोर लोगों ने अगर यह कह दिया कि यह नहीं थे तो कोई बहुत शान की बात नहीं थी। इससे कोई सम्मान नहीं बढ़ता। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की गूंज और वहां हुए अन्याय का जो संदेश पूरी दुनियां में गया अगर उसके लिए सदन में अगर हम लीपापोती की कोशिश करें और हम गुनहगारों को बचाने की कोशिश करें तो यह उन लोगों के साथ बहुत अन्याय होगा जो अपने ही वतन में इस तरह से लूटे और बरबाद किए गए। आपने जहां तक टेस्ट की बात की 72 साल आशाराम बापू की क्या उम्र है और हम आपसे यह कहना चाहते हैं मेडिकली इसके लिए कोई उम्र का तकाजा नहीं होता कोई उम्र की पाबन्दी नहीं होती। मैं क्योंकि सदन में महिलाएं भी हैं पत्रकार भी हैं वह मिसालें नहीं देना चाहता जिससे मेडिकली यह साबित होगा कि इसके लिए उम्र की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन आपके जवाब में यह निहित है कि बेगुनाहों के नाम निकाल दिए गए और जो बचे हैं वह गुनहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी मेरा कोई ऐसा विषय नहीं है मैं आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं चाहता। आरोप प्रत्यारोप लगाने से यह लोग माहौल भी दूसरी तरह का बनाते हैं। मेरा केवल यह निवेदन था कि अभी कहा गया कि नाम निकाल दिए गए मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो उस समय मृत थे उनके खिलाफ मुकदमा होना इस बात का सबूत है कि दबाव में सरकार के पुलिस ने एकतरफा वोटर लिस्ट लेकर गांव की वोटर लिस्ट उठा ली और सरकार के दबाव में पुलिस ने आनन–फानन में फर्जी मुकदमें लोगों के खिलाफ कायम किए। यह इस बात का सबूत है। सरकार ने पालीग्राफ टेस्ट भी कराए सरकार ने नार्को टेस्ट भी कराए जब मैं कह रहा हूं कि वह लोग खुद कह रहे हैं कि अगर हम दोषी हैं तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं इसमें सरकार को बचना नहीं चाहिए। सहारनपुर के दंगे की चर्चा हुई कि बहुत कार्यवाही हुई है मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने दंगा कराया खुलेआम मीडिया में छपा वह लोग वहां से चुनाव भी लड़े और वह खुलेआम घूम रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल पूछें।

श्री सुरेश राणा–

अध्यक्ष जी मैं सवाल ही कर रहा हूं मेरे सवाल का माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया मैं जवाब की उम्मीद कर रहा था कि उन लोगों का क्या मुआवजा जो लोग

पीड़ित हैं करोड़ों करोड़ की दुकानें जलीं मुआवजा मिला आठ लाख क्या जांच कराकर क्या ठीक से उनका मुआवजा दिलवाएंगे। जो निर्दोष जेल में हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आज सैकड़ों लोग मुजफ्फरनगर की जेल में हैं जो लोग निर्दोष जेलों में बन्द हैं उनके लिए कोई हाई पावर कमेटी बनाकर उन लोगों को न्याय दिलाएंगे। पहला सवाल यह है दूसरा सवाल मुआवजे का है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह सही है कि लोकतंत्र में ऐसे लोग जिन्हें जेलों में होना चाहिए फांसी के तख्तों पर जाना चाहिए। जब तक उनका जुर्म साबित नहीं हो जाता वह चुन लिए जाते हैं इसी सदन में कत्ल के मुल्जिम पार्लियामेंट में बैठे हैं देश चला रहे हैं। 40–40 पिल्ले पैदा कराने वाली मंत्री बनी हुई हैं। पाकिस्तान भेजने वाले मंत्री बने हुए हैं तो ऐसा होता है जिन लोगों पर हीनियस क्राइम्स के मुकदमें हैं उन्हें भारत सरकार कमाण्डोज दे देती है। यह सही है मैं आपकी इस बात को मानता हूं। मैं आपकी इस बात को मानता हूं कि बड़े बड़े अपराधी जिन्हें फांसी के तख्तों पर झूल जाना चाहिए वह एसेम्बली और पार्लियामेंट में जाते हैं भी इस वक्त। यह तो माननीय सदस्य की बात सही है इसे सरकार मानती है। जहां तक मुआवजे का सवाल रहा मान्यवर बहुत सी रिपोर्टस ऐसी थीं जो बहुत ही भगदड़ में उस वक्त बना दी गई थीं बाद में उसके बाद दूसरी रिपोर्टस आई थीं लेकिन अगर इसमें कहीं किसी के साथ ज्यादती हुई है और उनकी तरफ से कोई रिटेन रिप्रेजेन्टेशन लिखित दिया जाता है तो अवश्य विचार किया जाएगा किसी के साथ कोई पक्षपात का सवाल ही नहीं उठता यह भी आप देखेंगे कि जब भी जब जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है उसने। जाहिर है जिन्दगी का कोई बदल नहीं है, जिन्दगी वापिस नहीं आ सकती। किसी को लाख, दो लाख, पांच लाख, दस लाख, बीस लाख रूपया दे देने से उसका परिवार जिन्दा नहीं हो जाता लेकिन पैसे के मामले में कोशिश यह की है कि आंसू पोछें जा सकें। मुआवजे के मामले में भी आपने खुद यह फरमाया कि 50 लाख रुपये की रिपोर्ट आई तो 25 लाख रुपया दिया गया। मान्यवर, हमें अच्छी तरह याद है हमारे नौजवान सदस्य पता नहीं उस वक्त पैदा भी हुए थे या नहीं हुए थे। जब बाराबंकी में ईदगाह में गोली चली थी और लोग मारे गये थे तब भी हम इस सदन के मेम्बर थे गालिबन नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मंत्री हुआ करते थे हमने केवल पांच हजार रुपया मरने वालों के लिये मुआवजा मांगा था तो आपकी सरकार ने किसी मरने वाले को 5 हजार रुपया मुआवजा नहीं दिया था। लेकिन समाजवादी सरकार का जो तरीका रहा है वह आप जानते हैं। 50 प्रतिशत दिया गया है, इसका तो धन्यवाद कहिये। बाकी के अगर सही है तो उस पर भी विचार होगा। (श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नाम पुकारे जाने पर) मान्यवर, एक मिनट, मैं एक सूचना और दे दूं। हालांकि समाचार–पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जाता है लेकिन एक बड़े अखबार में कम्युनल राइट वॉयलेंस केसेज ड्राप्ज बाई 22 परसेन्ट फ्राम 2013 टू 2014 इसमें मान्यवर, जो राष्ट्रीय आंकड़े दिये गये हैं, जो भारत सरकार के हैं।

उत्तर प्रदेश में 2013 में 247 और 2014 में 140, बहुत बड़ी गिरावट आई है। महाराष्ट्र में 2013 में 88 और 2014 में 93, गुजरात में 2013 में 68 और 2014 में 75, कर्नाटक में 2013 में 73 और 2014 में 74, राजस्थान में 2013 में 52 और 2014 में 70, बिहार में 2013 में 63 और 2014 में 61 और यह बड़ी विडम्बना है और यह हमें इसका दुःख है कि जहां–जहां उस पार्टी की सरकारें है जो देश चला रही हैं वहां क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक बात पूछी थी कि जो लोग मुजफ्फरनगर में जेलों में निर्दोष लोग बन्द हैं क्या उनके लिये कोई हाई पावर कमेटी से जांच कराकर उनको न्याय दिलायेंगे ? सीधी सीधी सी बात है, इस पर कोई जवाब नहीं आया। मान्यवर, इसी पर सबसे ज्यादा फोकस माननीय राणा साहब ने किया था कि जो लोग निर्दोष बन्द हैं। मान्यवर, 549 लोग करीब निर्दोष बन्द हैं। वह लोग हर तरीके का टेस्ट फेस करने के लिये तैयार हैं जो भी सरकार चाहे। क्या इन लोगों को सरकार न्याय दिलायेगी ? यह लोग निर्दोष बन्द हैं मान्यवर।

श्री मोहम्मद आजम खां–

हमारे नौजवान दोस्त के एक सवाल का जवाब रह गया था गालिबन और वही सवाल आपने फिर पूछ लिया कि इस तरह के मामलात पर कैसे रोक लगे ? पार्लियामेन्ट में कानून आ रहा था कि जहां साम्प्रदायिक दंगें होंगे दंगा करने वालों की जिम्मेदारी तय की जायेगी जिसका सबसे ज्यादा विरोध पार्लियामेन्ट में भारतीय जनता पार्टी ने किया था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

यह गलत है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

चलिये। जरूरी थोड़ी है। मैं हर बात सही कहूं। अब अगर एक आध बात गलत है तो उसको चलिये इतिहास में देख लें। अभी चलिये लाइब्रेरी चलते हैं, समाचार–पत्र निकाले लेते हैं अगर मेरी बात सही है तो आकर सॉरी कह दीजियेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

केवल बहुसंख्यक समाज को दोषी कि कहीं भी अगर अल्पसंख्यक समाज और बहुसंख्यक समाज में अगर झगड़ा होगा तो बहुसंख्यक समाज दोषी ठहराया जायेगा उसमें इस बात का हमने विरोध किया था। उसमें केवल बहुसंख्यक समाज चाहे गलती करे न करे और हम दोषी ठहराये जायेंगे, इस बात का विरोध किया था। इस बात का विरोध मान्यवर।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अभी हमारे फाजिल दोस्त यह फरमा रहे थे कि ऐसा किया ही नहीं। लेकिन अब मान लिया। देखिये, अब मेरी भी तो सुन लें। मान्यवर, लोकतंत्र में फैसला तो जो

अकसरियत होगी वह करेगी। पार्लियामेन्ट में बिल पेश होना था और उसके बाद यह बात तय हो जाती कि देश क्या सोच रहा है, राजनैतिक दलों के क्या विचार है, अगर आपकी बात सही होती है तो आपकी बात मानी जाती लेकिन आपने तो बात ही नहीं रखने दी। क्योंकि आपको तो मुजफ्फरनगर का फायदा लेना था, देश में सरकार बनानी थी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

हमको आपकी नाकामियों का फायदा मिला, समाजवादी पार्टी की नाकामियों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और इसी वजह से हम चुनाव जीते। समाजवादी पार्टी ने दो साल में कहीं कोई काम किसानों के हित में नहीं किया।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें। प्रश्न बहुत स्पष्ट है मंत्री जी आप जबाव देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी मान्यवर, कानून सी0आर0पी0सी0 में कोई एमेन्डमेंट करना हो, देशव्यापी कोई कानून बनाना हो, इस समय आप इतनी बड़ी अक्सरियत में हैं, एक बिल ले आइए कि साम्प्रदायिक दंगों में जितने कातिल हैं, बलात्कारी हैं, लूट करने वाले हैं सबको बाइज्जत बरी किया जाता है, ले आइए कानून।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

हमें बहुमत का अत्याचार झेलना पड़ता है। यह सब इसलिए सुनना पड़ता है कि समाजवादी पार्टी अक्सरियत में है। हमारा विनम्र निवेदन यह है कि हम टू दि प्वाइन्ट जवाब पूछ रहे हैं उसका जवाब मिल जाए मैं ज्यादा समय सदन का खराब भी नहीं करना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

बेचारे, सब चुप बैठे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है जो मुजफ्फरनगर की जेलों में निर्दोष लोग बन्द हैं यह सरकार उनको न्याय दिलाएगी ? कोई हाई पावर कमेटी से जांच कराकर उन निर्दोष लोगों को न्याय दिलाकर जेल से बाहर करेगी ? मान्यवर, सीधा–सीधा सवाल है।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, दोषी होने का या निर्दोष होने का कोई मापदंड होगा, हमारे यहां कानून का एक सिस्टम है। रपट कायम होती है, जांच होती है, धारायें कम होती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, जेल जाते हैं जमानत पर रिहा होते हैं नहीं होते हैं फिर मुकदमा अदालत में जाता है, फिर उसका फैसला होता है, उससे इत्तेफाक करें या न करें, बड़ी अदालत में जाते हैं, उससे इत्तेफाक करें या न करें उससे बड़ी अदालत में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं इसका मतलब तो यह हुआ कि जो जुडीशियल प्रॉसेस है हमारा

आपने उसे ही खारिज कर दिया और यह बात इसलिए सही है कि आप उसमें यकीन ही नहीं करते, मारो और रोने भी न दो, कहां रोने दिया ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, कभी–कभी बहुमत का अत्याचार झेलना पड़ता है। यह बहुमत का अत्याचार झेल रहे हैं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को टू द प्वाइन्ट यह बताना चाहिए कि हम हाई पावर कमेटी बनाकर इसमें न्याय दिलायेंगे, आप न्याय करते हैं लेकिन आज पता नहीं क्यों न्याय नहीं कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

कोई ऐसा दृष्टान्त है नहीं, अब देखिए ऐसा कैसे हो जाएगा। गुजरात में कितने बड़े–बड़े दंगे हुए। कहां बनी कोई कमेटी, आप गुजरात के दंगों के लिए एक हाई पावर कमेटी बनवा दीजिए। आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। जो पूरी दुनिया में एक कलंक लगा हुआ है आपके चेहरे पर..

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

अगर यही चाहते हैं तो हम उसके ऊपर भी जवाब देने को तैयार हैं। हम सदन का समय नहीं खराब करना चाहते हैं। (शोर) निर्दोष लोगों को यह सरकार न्याय नहीं दिला रही है इसलिए हम और हमारा दल सदन से बर्हिगमन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के श्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने दल के साथ सदन का बर्हिगमन किया)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें। मा0 नेता विरोधी दल खड़े हैं कुछ तो मर्यादा देखें। बीस–तीस मिनट चले गए। (शोर)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न अत्यन्त संवेदनशील है। चूंकि इसकी त्रासदी उत्तर प्रदेश विगत वर्षों में अनेक बार झेल चुका है और स्वाभाविक रूप से जब–जब भी इस प्रकार की घटनायें होती हैं तो कहीं न कहीं समाज और राष्ट्र दोनों कमजोर होते हैं, क्योंकि भाईचारा हमारा सबसे बड़ा आधार है। मान्यवर, पूर्व में भी वर्ष 2013–14 में यह प्रश्न आया था और उस समय सरकार का उत्तर था 116 दंगे। अभी भारत सरकार की रिपोर्ट मा0 मंत्री जी ने पढ़ी, उसमें इसी अवधि में 247 दंगों का जिक्र आया है। मा0 मंत्री जी ने माह मार्च 2013 से दिसम्बर 2014 तक प्रदेश में दो साम्प्रदायिक दंगों की बात कबूल की है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जो क्रिमिनल ऑफेन्सेस थे उनका है, दंगे नहीं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि अगर मात्र दो दंगे हुये जिसमें मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का जिक्र किया, यानी एक मुजफ्फरनगर और एक

सहारनपुर, तो मुजफ्फरनगर में अगर एक दंगा हुआ तो 477 अभियोग क्यों पंजीकृत किये गये ? यदि दंगा एक हुआ तो अभियोग भी एक ही पंजीकृत होना चाहिये। दूसरी चीज, आपने कहा कि सहारनपुर में 237 अभियोग पंजीकृत हुये, तो अगर दंगा एक हुआ तो अभियोग भी एक ही पंजीकृत होना चाहिये। इस बात को स्पष्ट करें कि क्या 477 अभियोग इस बात का संकेत नहीं है कि सहारनपुर में 477 जगहों पर दंगे हुये ? क्या यह स्थिति यह स्पष्ट नहीं करती कि मुजफ्फरनगर में एक दंगा कहने के लिये है, लेकिन 237 जगहों पर दंगे हुये ? यही कारण है कि सहारनपुर में 477 अभियोग और मुजफ्फरनगर में 237 अभियोग दर्ज किये गये। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि एक तो सरकार का जो उत्तर है वह आपस में ही कहीं न कहीं विरोधाभासी है, इसको स्पष्ट करें और दूसरी चीज, क्या सरकार की ऐसी कार्य योजना है जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के हिन्दू–मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ने वाली ताकतों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये ? जैसाकि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी अपने उत्तर में कह रहे थे कि कुछ ऐसे भी दंगाई हैं जो सुरक्षा में चलते हैं, कुछ ऐसे भी दंगाई हैं जो पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं और असेम्बली में आ जाते हैं, तो सरकार के रहते यदि कोई दंगाई पार्लियामेंट में पहुंच गया, सरकार के रहते यदि कोई दंगाई विधान सभा में आ गया तो हम समझते हैं कि कहीं न कहीं क्या यह सरकार की कमी नहीं है कि समय रहते यदि ऐसे दंगाइयों पर कार्रवाई करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया होता तो आज वह पार्लियामेंट और असेम्बली में नहीं होते? (विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) यह सरकार की नाकामयाबी और असफलता को ही जाहिर करता है। मा0 मंत्री जी इसका उत्तर दें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने बहुत अच्छे सवाल उठाये हैं, बड़ी समझदारी के भी हैं और बहुत कानूनी सवालात हैं। मैं इतना सक्षम तो नहीं हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपके इन कठिन सवालों का जवाब दे सकूं। दरअसल, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं, कानून की प्रक्रिया को मानते हैं। यहां तानाशाही नहीं है कि शहंशाह की जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज इंसाफ होता है। तानाशाही नहीं है। एक प्रक्रिया है जो प्रक्रिया मैंने बताई थी और हम इसमें यकीन नहीं रखते कि कोई मुजरिम पकड़ा जाये, जेल जाये और जेल में मरवा दिया जाये ताकि सबूत मिट जाये। आपकी सरकार में ऐसा होता था। हम इसमें यकीन नहीं रखते। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में और कानून की व्यवस्था में यकीन रखते हैं। आपने देखा कि आपकी सरकार में जो डॉक्टर्स गिरफ्तार हुये, सी0एम0ओ0 गिरफ्तार हुये उनका क्या हुआ, जेल में मार दिये गये। तो हम इसमें यकीन नहीं रखते। जो कानूनी प्रक्रिया है उसी में यकीन रखते हैं और उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अब आगे बढ़ा जाये, बहुत हो गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, आप आगे बढ़ें, आपको आगे बढ़ने से हम नहीं रोक रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार से प्रश्न इसलिये किये जाते हैं कि उनका उचित उत्तर आये।

माननीय मंत्री जी ने तो प्रश्नों का उत्तर दिया नहीं। अपनी असफलताओं को, अपनी नाकामयाबियों को या यूं कह लिया जाए सरकार का गुण्डा, माफिया, अपराधी और दंगाईपरस्त होने का यह प्रमाण–पत्र दे रहे हैं, यानि कानून अन्धा बन करके देखता रहेगा, दंगाई, गुण्डे, माफिया, अपराधी प्रदेश की एकता की भेंट चढ़ाते रहेंगे। सरकार के इस गुण्डा, माफिया, दंगाईपरस्ती और सरकार की नीयत के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सदन का बहिर्गमन कर रही है।

(बहुजन समाज पार्टी के श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल सहित सदन का बहिर्गमन किया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इतने कम–कम समय में नेता प्रतिपक्ष बहिर्गमन कर रहे हैं, यह अच्छा–खासे थक जाते होंगे, बार–बार आने–जाने में। मान्यवर, यहीं बैठे–बैठे कह दिया करें, बहिर्गमन हो गया और फिर कह दें कि हम आ गए तो कम से कम आने–जाने की जहमत बच जायेगी और कालीन भी घिसती।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, बैठिए।

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के जिलों में बड़ी मात्रा में नकली नोट पकड़े जाने पर अभियुक्तों के विरुद्ध कृत कार्रवाई की जानकारी

'01–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिन जिलों में बड़ी मात्रा में नकली नोट (जाली करेंसी) पकड़े जाते हैं, इस संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए सरकार की क्या नीति है ? क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जुलाई, 2014 में बड़ी मात्रा में जाली करेंसी रखने के अभियुक्तों को इसलिए जमानत मिल गयी क्योंकि उनके विरुद्ध तय सीमा पर चार्जशीट फाइनल नहीं हो सकी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे गंभीर अपराधों को रोकने के लिए अभियुक्तों के विरुद्ध तय समय सीमा के अंतर्गत चार्जशीट लगाने हेतु कोई अलग निर्देश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नकली नोटों के प्रसार को रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा इकाइयों के माध्यम से अभिसूचना एकत्र करते हुए ऐसे तत्वों, जो जाली नोटों के व्यापार में संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्राविधानों के तहत तथा उच्च श्रेणी के कूटकृत

भारतीय करेंसी के अपराधों में शामिल तत्वों के विरुद्ध विधि विरुद्ध क्रिया–कलाप निवारण अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाती है।

ऐसे प्रकरणों में पुलिस द्वारा तय समय–सीमा में आरोपियों के विरुद्ध आरोप–पत्र दाखिल किया जाता है। बड़ी मात्रा में जाली करेंसी (एक लाख रुपये से ऊपर) की बरामदी के अभियोगों में सिर्फ एक मामले में थाना महानगर, लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0–101/2014 में अभियुक्त के विरुद्ध निर्धारित समय–सीमा पर आरोप–पत्र प्रेषित न करने के कारण दिनांक 09–07–2014 को जमानत मिल गयी थी।

जाली नोटों के अभियोगों के अन्वेषण में प्रभावी कार्यवाही हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 के परिपत्र दिनांक 30–04–2014 तथा दिनांक 25–08–2014 द्वारा प्रदेश स्तर पर विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिनके अनुसार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस प्रश्न के सन्दर्भ में दो अनुपूरक सवाल पूछना चाहता हूं, पहला सवाल कि क्राइम संख्या–101/2014, थाना–महानगर, लखनऊ में किन परिस्थितियों में समय–सीमा के अन्तर्गत चार्जशीट फाइल नहीं हो सकी और जिन लोगों की वजह से चार्जशीट फाइल नहीं हो पायी, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई और दूसरा प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति एटीएम से रुपये निकालता है और उसमें से कोई नोट जाली निकलता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से, उसे नाजायज न फंसाया जाए, इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? इन दो सवालों का उत्तर मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह जाली नोटों का कारोबार बार्डर के क्षेत्रों से होता है, जैसे बांग्लादेश है, जिसका जिक्र आपने किया है, नासिक में यह गिरफ्तारी हुई थी और नासिक से यहां जांच रिपोर्ट आनी थी, लेकिन वहां से रिपोर्ट नहीं आयी। बार–बार कोशिश करने के बावजूद भी, क्योंकि वहां की रिपोर्ट के बाद ही यहां पर उस रिपोर्ट को दाखिल किया जाना था, क्योंकि रिपोर्ट नहीं आ पायी और समय से चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। हम उन कारणों का भी पता लगवा रहे हैं कि जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आयी। इसकी भी जांच बैठा दी गयी है कि क्या कारण रहा कि जांच रिपोर्ट वहां से नहीं आयी ? जांच रिपोर्ट डिलेड होने के कारण ही उसे जमानत मिल गई, मान्यवर, यह कारण था और दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा है, जो गड्डी में इस प्रकार की जाली नोट निकल आती है, यह निर्देश है कि ऐसे मामलों में कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा और उस व्यक्ति को उत्पीड़ित नहीं किया जाता है।

प्रदेश में सी0सी0टी0एन0एस0 योजना का मुख्य उद्देश्य तथा उसकी पूर्ति हेतु आवश्यक कदम

'02–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सी0सी0टी0एन0एस0 (क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम) योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ? क्या इस योजना के अन्तर्गत थानों पर कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों की आपूर्ति के बावजूद भी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो इस योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सी0सी0टी0एन0एस0 योजना का मुख्य उद्देश्य देश के समस्त पुलिस थानों और वरिष्ठ पुलिस कार्यालयों को एक नेट में जोड़ना है। इसके साथ ही इस योजना में थाना स्तर पर कार्यवाही को कम्प्यूटर के माध्यम से किया जाना है जिसमें वादी को कम्प्यूटर जनित एफ0आई0आर0 की प्रति प्रदान किया जाना है। उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री मनीष असीजा–

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से पुलिस विभाग की सुधारवादी योजना के अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा। सी0सी0टी0एन0एस0 योजना 2009 में भारत सरकार के द्वारा इस उद्देश्य से इसे लागू किया गया था कि देश भर के चौदह हजार से अधिक थाने सभी पुलिस अधिकारियों का आपसी सम्पर्क सभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ सी0बी0सी0आई0डी0, सी0बी0आई0 सभी अपराधियों का सभी थानों का एक नेटवर्क के अंतर्गत रिकार्ड आ जाए। अगर उत्तर प्रदेश के किसी शहर में किसी अपराधी ने अपराध किया है और वह गोवा में जा छिपा है या गोवा का अपराधी है तो यहां थाने में ही इसकी सूचना आ जाए। इस उद्देश्य की यह योजना है और इस महत्वाकांक्षी और जनोपयोगी योजना को लागू करने के लिए जो कठिनाई हैं उनसे सम्बन्धित मैं अनुपूरक पूछता हूं। इस योजना के लागू होने से जनता को बहुत सुविधा होगी। जनता को थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आई0ओ0, एफ0आई0आर0 में फेरबदल नहीं कर पाएगा। जैसे रेलवे के टिकट का पी0एन0आर0 नम्बर मिल जाता है ऐसे ही अगर ऑन लाइन रिपोर्ट होती है तो उसको एक यूनिक कोड मिल जाएगा जिससे अपने पूरे मुकदमें की प्रगति वह देख सकता है। इस योजना में सीपा योजना इससे पहले लगी थी जिसमें प्रदेश के सभी थानों में कम्प्यूटर मॉडम प्रिन्टर आदि दिए गए थे। पिछले 2004 से दिए गए जो उपकरण थे इसमें बहुत सारे खराब हो गए इनको केंद्र सरकार नहीं दे रही है। क्या राज्य सरकार इनको दे कर योजना को शत–प्रतिशत लागू करने की स्थिति बनाएगी ? दूसरा इस पूरी योजना का मेन तत्व है वह बी0एस0एन0एल का नेटवर्क है जो सुदूर थानों में तो दिक्कत देता ही है शहरों में भी उसकी स्पीड बहुत कम है। क्या विभाग चिन्ता करके नेटवर्किंग के लिए बी0एस0एन0एल से जैसे हर ब्लॉक में ई–सुविधा है हर थाने में ई–सुविधा को

स्थापित कराने का काम करेगा ? एक और प्रश्न है कि यह योजना सौ प्रतिशत केन्द्र के द्वारा पोषित है लेकिन इसको चालू करने के लिए बड़े बजट की आवश्यकता होगी। मसलन जनरेटर आपने दिए और उनके लिए डीजल के खर्चे का अभी प्रावधान नहीं किया है इसके लिए बहुत बड़ी स्टेशनरी की जरूरत होगी अगर जेनरेटर का विकल्प होने के लिए इन्वर्टर या सोलर चैनल की जरूरत होगी तो इसके लिए बजट का प्रावधान करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 अध्यक्ष जी जब यह योजना लागू हुई है उस वक्त जिस तरह के थानों में स्टाफ थे वह कम्प्यूटर के फन से वाकिफ नहीं थे और खराब हुए भी और खराब किए भी गए। अगर कम्प्यूटर का इस्तेमाल ज्यादा दिन न हो और सीलन और धूल आने लगे तो स्वतः खराब हो जाते हैं। मान्यवर, इसमें शायद ऐसा भी रहा होगा मैं किसी को लांछित नहीं कर रहा हूं कि अगर चलते रहेंगे तो काम करना पड़ेगा खराब हो जाएंगे तो कहने के लिए होगा कि साहब खराब पड़े हैं। तो खराब अच्छे–खासे हो गए और इसके बहुत से कारण रहे। जानकारी न होना। हमारे थानों का वातानुकूलित न होना। थाने बहुत अच्छी तरह से न बने होने के कारण सीलन होना। बहुत सी जगहों में बारिश में छतों का टपकना। यह सब हमें विरसे में मिली हुयी चीजें हैं। जो सभी को मिलती हैं। तो वह खराब हुये। अब बड़े थानों को एक–एक कम्प्यूटर दिया गया है। लेकिन यह बहुत अच्छी स्कीम है। 1504 थानों में यह लगाये गये हैं और 1180 में काम कर रहे हैं और 324 पर कनेक्टिविटी नहीं हो पायी है और बी0एस0एन0एल के लिए लोगों से कहते सुना है कि भाई साहब नहीं लगेगा। तो इसमें हमें भारत सरकार से सहयोग चाहिए क्योंकि बी0एस0एन0एल0 आपके कंट्रोल की चीज है। अगर आप थोड़ा सा डॉट देंगे तो भाई साहब लगने लगेगा। और जो स्कीम भारत सरकार की है। मान्यवर, अब देखिये, जैसे अगर आप किसी को दावत पर बुलायें। बढ़िया–बढ़िया पकवान हों बहुत अच्छा सा होटल हो बड़े अच्छे बर्तन हों और आप यह कहें कि आप खायेंगे नहीं। तो मान्यवर, ऐसी दावत का क्या फायदा। सब कुछ भेज दिया आपने तेल का खर्चा नहीं भेजा। तो आपसे दरख्वास्त है कि जब आपने इतनी कृपा की तो जनरेटर और डीजल के खर्च की भी थोड़ी सी व्यवस्था हो जाये। तो काम चल सके।

श्री मनीष असीजा–

देखिये, केंद्र की अगर कोई भी योजना भेजी जाती है, माननीय नगर विकास मंत्री जी बहुत योग्य हैं और अनुभवी हैं। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की योजना थी वह सब केंद्र के द्वारा पोषित थी लेकिन उसको संचालित करने का तो सारा जिम्मा स्थानीय राज्य प्रशासन के ऊपर होता है। इसलिए यह वास्तविक बात है कि यह सारे देश के प्रदेशों में यह योजना लागू है। तमिलनाडु ने तो इसमें 100 प्रतिशत से ऊपर काम कर लिया है। कर्नाटक, गुजरात भी आगे है। तो इसमें रेकरिंग खर्चे के लिए आप गृह विभाग के ही अधिकारियों के साथ बैठेंगे वह भी यह बतायेंगे कि इसको चलाने के रोजमर्रा के खर्चे और आपके आपरेटर के लिए भी आपकी 2800 भर्तियां स्वीकृत हैं। 600 की भर्ती हो गयी

है। 2200–2300 की और भर्ती करा देंगे। क्योंकि योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिए उसको चलाने वाले लोग उपलब्ध होंगे तभी यह योजना आपके पुलिस विभाग के आमूलचूल परिवर्तन का कारण बनेगी और पूरे प्रदेश की पुलिस की एफिसिएंशी बढ़ेगी। आम जनता को लाभ होगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छी योजना है। कोशिश भी है। जहां तक जे0एन0एन0यू0आर0एम0 का प्रश्न है। तो उसकी तो शर्तों में है, कहीं 40 प्रतिशत, कहीं 25 प्रतिशत राज्य सरकार का योगदान होता है। इसमें मेरे ख्याल से वह मिसाल बहुत फिट नही है। लेकिन हां ऐसा होना चाहिए और इस पर विचार है।

प्रदेश में नदियों के प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार की ठोस योजना की जानकारी

'03–श्री सतीश महाना तथा श्री सुरेश राणा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नदियों के प्रदूषण को रोकने हेतु कोई ठोस कार्य योजना सरकार द्वारा बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना में जनपद कानपुर एवं इलाहाबाद को भी सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

गंगा एवं उसकी सहायक नदियों यमुना व गोमती आदि के प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने हेतु गंगा कार्य योजना तथा वर्तमान में एन0जी0आर0बी0ए0 द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अन्तर्गत कार्य योजना तैयार की गयी है, जिसके अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे 26 नगर एवं इसकी सहायक नदियों काली नदी के किनारे 03, रामगंगा नदी के किनारे स्थित 02 नगरों को चिन्हित किया गया है। वर्तमान में इलाहाबाद नगर की 06, वाराणसी नगर की 02, बिठूर (कानपुर), कन्नौज, मुरादाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, अनूपशहर व नरौरा नगर की एक–एक कुल 14 परियोजनाओं (स्वीकृत लागत रु0 2256.01 करोड़) का क्रियान्वयन प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद नगर की 01, कानपुर नगर की 04 तथा वाराणसी नगर की 02 परियोजनायें भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी हैं।

जी हां, उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को जो कानपुर से गंगा गई है उसके ऊपर थोड़ा सा चिन्ता है, यह प्रस्ताव लाईये कि रामपुर से होकर निकलें। माननीय अध्यक्ष जी यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और कई बार इस सदन में आता है और मैं इस बात को विश्वासपूर्वक कहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसके लिए चिन्तित हैं। हर बात आरोप–प्रत्यारोप के लिए नहीं होती। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से

दो छोटे–छोटे प्रश्न करना चाहता हूं। एक तो इसमें मान्यवर, गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत सेकेण्ड फेज में काम चल रहा है, फर्स्ट फेस में कितने की लागत के काम हुए जो अभी तक जनता के लिए उपयोग में नहीं आया। यह मैं प्रमाणिकता के साथ कह रहा हूं कि उपयोग के लिए एक पैसा भी नहीं आया। हजारों करोड़ रुपये खर्चा होने के बाद भी कहीं लग भी नहीं रहा है। अभी पिछले दिनों मेरे प्रश्न के जवाब में कृपा पूर्वक माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया और पहले भी बैठकों में स्वीकार किया कि ओवर हैड टैंकों की स्थिति को गिराने की नौबत आयी, इसको स्वीकार किया। बहुत दिल वाला क्या ताकत वाला व्यक्ति स्वीकार करता है। मान्यवर, ऐसे कितने पैसे हैं, जनता को पता चलना चाहिए कि जनता की गाढ़ी कमाई का कितना पैसा शून्य हो चुका है। अगर ओवर हैड टैंक गिराये जायेंगे के ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपया लगा है तो पब्लिक को पता लगना चाहिए कि हजारों करोड़ रुपया जिन पापियों ने विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई है ? क्यों नहीं उन्हे जेल भेजा गया ? सरकार यहां पर बैठी है और सरकार सही तरीके से काम कर रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके के माध्यम से सिफ दो छोटे से प्रश्न हैं, एक तो कितना पैसा इन योजनाओं के ऊपर खर्चा हो गया और उसका क्या लाभ मिला और आगे लाभ मिलने की उम्मीद है ? दूसरी बात मान्यवर, मैं कई बार यहां पर लेकर आना चाहता था परन्तु अवसर नहीं मिला और अनावश्यक मैं विषय को उठाता नहीं हूं, माननीय मंत्री जी ने इस सदन में पिछले महीने की 21 तारीख में यहां कहां था कि उसकी जांच कराकर 03 दिन में बतायेंगे, क्या उसकी जांच की रिपोर्ट आयी है ? यदि आयी है तो क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, गंगा नदी में जो प्रदूषण है, फरवरी, 1985 में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण नाम से एक संगठन गंगा कार्य योजना के नाम से शुरू हुआ और जहां तक मान्यवर, पहले चरण में क्या हुआ, गंगा कार्य योजना के प्रथम चरणों को एक लाख आबादी से अधिक जनसंख्या वालें नगरों में हैं, लागू किया गया है। जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर स्थित छः नगर क्रमशः हरिद्वार, ऋषिकेश जो कि अब उत्तरांचल में है, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी तथा मिर्जापुर को सम्मिलित किया गया है। इन नगरों को सेण्टर की प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व उत्तर प्रदेश जलनिगम को सौंपा गया है। गंगा कार्य योजना प्रथम चरण में सम्मिलित प्रदेश में 05 नगरों में गंगा नदी में प्रवाहित होने वाले कुल 646.30 एम0एल0डी0, सीवेज में से 349.50 एम0एल0डी0 क्षमता के 09 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट भी निर्मित किये गये। इनके अतिरिक्त इन नगरों में 27 पम्पिंग स्टेशन, 13 शवदाह गृह, 12 कम लागत के शौचालय तथा 08 नदी घाटों का विकास कार्य भी किया गया।

श्री सतीश महाना–

ठीक है मंत्री जी अगर नहीं आयी है, तो दोबारा मंगा लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं चाहूंगा कि विभाग उसे आपको भेज दे।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर मुझे पूछने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले भी कई बार सवालों के माध्यम से जो नदियों मे भारी प्रदूषण है और प्रदूषण के कारण से जिस प्रकार से उसका प्रभाव, कुप्रभाव पड़ रहा है, आप भी लगातार चिन्तित है, आपसे जब भी चर्चा होती है किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में कैन्सर एक महामारी के रूप में बना हुआ है और लगता है जैसे पूरा प्रदेश कैन्सर का शिकार हो गया है। हर गांव में 10 से 15, 20 पेशेन्ट कैन्सर के हैं, और जो मूल कारण है वह केवल प्रदूषित जल है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पहले प्रश्नों के आधार पर जो जवाब मिला उसकी मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता, क्या सरकार जो नदियां जैसे हमारे यहां कृष्णा नदी है, काली नदी है, हिण्डन नदी है, पूरी तरह से प्रदूषित नाले हो गयें हैं। नदियों से प्रदूषित नाले हो गये हैं और उनके आस–पास जो गांव है, उनमें फैल रही जलजनित बीमारियों की जांच कराकर जांच के कारण का पता लगाकर उन्हें दूर करने के लिए उसके आस–पास के गांवों में सरकार कोई टंकियों की व्यवस्था करायेगी, नम्बर–एक। नम्बर–2 जैसे मैंने कहा था गत्ता फैक्ट्री नरौता, शुगर फैक्ट्री नरौता, बजाज हिन्दुस्तान फैक्ट्री थानाभवन, शामली की अनेक फैक्ट्रियां, लगातार अपना प्रदूषित जल, जबकि मानक के अनुसार इन्हें वाटर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट लगाना चाहिए और उसे साफ करके पानी बाहर डालना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी मानक का पालन नहीं हो रहा है, ऐसी फैक्ट्रियां जो मानक के अनुरूप नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, क्या सरकार कार्यवाही करेगी ? यह मेरा दूसरा प्रश्न है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इस पर मा0 सदस्य चिन्तित हैं, सरकार भी बहुत चिन्तित है और बड़ा सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं, पानी जिन्दगी है, पानी मौत है। हम अच्छा पानी दे सकें यह हमारी पूरी कोशिश है, लेकिन बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा प्रदेश है और कुछ हमारी अपनी सांस्कृतिक मान्यतायें, हमारी ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यतायें ऐसी हैं, वह भी इसमें बाधित हैं। हमारे अन्दर उतनी शिक्षा नहीं है, उतनी अवेयरनेस नहीं है कि हमें इस गन्दे पानी को नदी में छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, बहुत सी मल्टी प्रॉब्लम्स हैं, मैं किसी को कोई दोष देने के लिए नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार ने खुद केवल गंगा नदी के बारे में जो मा0 सुप्रीम कोर्ट में एफीडेविट लगाया था, उसमें यह कहा जो लेटेस्ट एफीडेविट है कि बहुत बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाने के बाद भी जल्द ऐसा सम्भव नहीं है, उस पर मा0 सुप्रीम कोर्ट का जो कमेण्ट है मान्यवर, केन्द्र की गंगा सफाई योजना पर मा0 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे तो 200 साल में भी साफ नहीं होगी नदी। तो यह बहुत बड़ा काम है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि केन्द्र सरकार इसकी सफाई नहीं चाहती, वाकई बहुत बड़े संसाधन चाहिए और समय भी चाहिए। अर्ध कुम्भ हुआ बहुत

अच्छा हुआ, लेकिन यकीनन कुछ कमियां रही होंगी, इसलिए अर्ध कुम्भ की वह तारीफ नहीं हो सकी दुनियाभर में, जितनी महाकुम्भ की हुई और महाकुम्भ में एक बूंद पानी भी प्रदूषित हमने नहीं आने दिया, एक बूंद पानी भी। इतना अच्छा पानी था मान्यवर कि उस पानी को सिर्फ नहाने के लिए नहीं, उसको जब टेस्ट कराया गया तो वह पीने के लिए बहुत अच्छा पानी था, पीने के लिए भी बहुत अच्छा पानी था। तो वह क्योंकि एक पर्व था, उसके लिए कोशिश की गई, सारी टेनरीज को बन्द कर दिया गया, उनके सारे नाले सील कर दिये गये। उस तरफ हम बहुत काम कर रहे हैं मान्यवर और बहुत प्लाण्ट्स लगा रहे हैं। यहां तक आपकी शिकायत है, वह भी शामिल है, समय–समय पर इन लोगों के चालान भी करते हैं, मगर मान्यवर, कुछ बहुत ज्यादा बेशर्म भी हैं, जो चालानों से भी बाज नहीं आते, सजा से भी बाज नहीं आते, लेकिन इसमें कोई कसर नहीं रख रही है सरकार और हमारा यह कमिटमेण्ट है, वायदा है आपसे और पूरे समाज से, देश से वायदा है मान्यवर, हम अच्छा करेंगे, तो यहां बैठेंगे, अच्छा नहीं करेंगे, तो जो हश्र हुआ है, वह होगा। तो हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और जहां–जहां कमियां हैं, उन्हें दूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त।

प्रदेश में महिला हेल्पलाइन 1090 पर वर्षवार दर्ज शिकायतों एवं कृत कार्यवाही

'04–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2012–13 व 2013–14 में महिला हेल्पलाइन 1090 पर वर्ष वार कितनी–कितनी शिकायत दर्ज की गई एवं इनमें से कितनी शिकायतों में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई ? क्या सरकार इस हेल्पलाइन को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कोई कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

प्रदेश में वर्ष 2012–13 में 46,486 शिकायतें व वर्ष 2013–14 में 1,45,923 शिकायतें पंजीकृत हुई हैं एवं 117 शिकायतों में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गयी।

जी हां।

प्रदेश सरकार इस हेल्पलाइन को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये कदम उठा रही है। जिसके अन्तर्गत प्रशासनिक ढांचा के तहत एक पुलिस महानिरीक्षक, वूमेन पावर लाइन, उ0 प्र0 एवं

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

क पुलिस अधीक्षक, वूमेन पावर लाइन का पद सृजित किया गया है। साथ ही साथ प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक शहर के हर मोहल्ले एवं गांव की स्कूल जाने वाली लड़कियों को अपने सिस्टम से जोड़कर उन्हें प्रशिक्षित करने एवं हाई स्कूल से ऊपर प्रत्येक कक्ष के प्रत्येक सेक्शन से 2–3 लड़कियों को पावर एंजिल (विशेष

पुलिस अधिकारी) बनाकर सीधे वूमेन पावर लाइन 1090 से जोड़ा जा रहा है। इस वर्ष करीब 50,000 लड़कियों को पावर एंजिल बनाये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दरवाजे पर न्याय (जस्टिस ऐट डोर) को सफल बनाने हेतु प्रत्येक तहसील स्तर पर जुडीशियल मैजिस्ट्रेट (मुंसिफ) अदालतों की स्थापना किये जाने की सरकार की योजना

'05–श्री अनुग्रह नारायण सिंह

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दरवाजे पर न्याय (जस्टिस ऐट डोर) को सफल बनाने हेतु प्रत्येक तहसील स्तर पर जुडीशियल मैजिस्ट्रेट (मुंसिफ) अदालतों की स्थापना की है ? यदि हां, तो कितनी तहसीलों में उक्त अदालतों की स्थापना की गई है तथा शेष में कब तक स्थापना किये जाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जस्टिस जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट में आगरा को उपयुक्त स्थल मानते हुए हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के सम्बन्ध में

'06–डा0 धर्मपाल सिंह, श्री रविन्द्र भडाना तथा श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाई कोर्ट बैंच की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1981 में गठित जस्टिस जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट में आगरा को उपयुक्त स्थल मानते हुए हाई कोर्ट बैंच की स्थापना किये जाने की सिफारिश वर्ष 1986 में की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आगरा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

इस सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 द्वारा भारत के प्रधानमंत्री जी से दिनांक 07–11–1994 एवं दिनांक 05–09–1995 को यह अनुरोध किया गया है कि वह जिस स्थान पर उपयुक्त समझे मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के विषय में निर्णय लेकर राज्य सरकार को अवगत करायें।

प्रश्न नहीं उठता है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–1 संघ सूची की प्रविष्टि संख्या–78 की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय, उसकी खण्डपीठ की स्थापना तथा

क्षेत्राधिकार का प्रकरण केन्द्र सरकार के विचार का बिन्दु है, अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है।

प्रदेश के महानगरों में बढ़ती जनसंख्या को दृष्टिगत करते हुए यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु नयी योजना बनाये जाने विषयक जानकारी

'07—श्री नदीम जावेद तथा श्री बंशी सिंह पहाड़िया—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में बढ़ती जनसंख्या का दुष्प्रभाव वहां की यातायात व्यवस्था पर भी पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु कोई नयी कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

प्रदेश के महानगरों व नगरों में बढ़ती जनसख्या के फलस्वरूप वाहनों व सड़कों के जाल में उत्तरोत्तर वृद्धि, अन्तर्राज्यीय मार्गों/बाईपासों की संख्या में हो रही वृद्धि, दिन—प्रतिदिन तेज गति से चलने वाले वाहनों की संख्या में हो रही बढ़ोत्तरी ने यातायात व्यवस्था को और कठिन व जटिल बना दिया है। वाहनों की संख्या में हो रही वृद्धि के कारण पीक आवर्स में सड़कों पर यातायात कुछ समय के लिये धीमी गति से संचालित होता है।

पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिस व स्थानीय पुलिस बल लगाकर यातायात का सुगम संचालन कराया जाता है। यातायात समस्याओं के निराकरण हेतु प्रदेश के जनपदों में यातायात दबाव से निपटने के लिये यातायात पुलिस/स्थानीय पुलिस द्वारा नगर निगम, विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग आदि के सहयोग से कार्य योजना तैयार कर अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जाती है तथा अनधिकृत रूप से मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाता है। यातायात के भारी दबाव वाले क्षेत्रों में स्कूलों के खुलने एवं बन्द होने के समय एकल दिशा मार्ग की व्यवस्था कर यातायात का दबाव कम करने का प्रयास किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार शहर के अन्दर भारी वाहनों का आवागमन प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 भीमराव अम्बेडकर लॉ कालेज, लखनऊ की छात्रा सुश्री गौरी श्रीवास्तव का अपहरण कर निर्मम हत्या हो जाने के कारण अपराधियों को शीघ्र पकड़ने की मांग

'08—डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 03 फरवरी, 2015 को अमीनाबाद, लखनऊ निवासी एवं डा0 भीमराव अम्बेडकर लॉ कालेज, लखनऊ की एल0एल0बी0 आनर्स की छात्रा गौरी श्रीवास्तव की अपराधियों द्वारा अपहरण करके निर्मम

हत्या कर दी गई जिसके शरीर के टुकड़े शहीद पथ पर पाये गये ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा इन अपराधियों को शीघ्र पकड़ने के क्या प्रयास किया जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

मृतका गौरी श्रीवास्तव के शरीर के टुकड़े थाना–पी0जी0आई0 क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 02–02–2015 को बरामद हुये।

मृतका के पिता श्री शिशिर श्रीवास्तव की तहरीर पर दिनांक 01–02–2015 को थाना–अमीनाबाद पर मु0अ0सं0–14/2015 पंजीकृत हुआ था। दिनांक 02–02–2015 को थाना–पी0जी0आई0 अन्तर्गत मृतका गौरी का शव बरामद होने तथा उसकी पहचान होने पर अभियोग में धारा 302/201 भादंवि की बढ़ोत्तरी की गयी। विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त हिमांशू प्रजापति एवं अनुज कुमार गौतम को गिरफ्तार कर, उनके कब्जे से आलाकत्ल (आरी), मृतका का मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, घटना करते समय अभियुक्त द्वारा पहने कपड़े, जिस पर मृतका के खून के धब्बे मौजूद थे, को बरामद कर दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपदों के पुलिस लाइनों के कमरों में बोरों में पाये गये नर कंकाल एवं उसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

'09–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किस–किस जनपद के पुलिस लाइनों के कमरे में गतवर्ष 2014 से अब तक बन्द बोरों में नर कंकाल पाये गये तथा उक्त नर कंकाल कब से रखे गये थे और किसके थे तथा क्यों रखे गये ? क्या सरकार बतायेगी कि जांच कराकर इसके लिए दोषियों के विरुद्ध क्या कोई कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वर्ष 2014 से अब तक पुलिस लाइन के कमरे में बन्द बोरों में नर कंकाल पाये जाने का 01–01 प्रकरण जनपद उन्नाव एवं मुरादाबाद में प्रकाश में आया है। जनपद उन्नाव में 47 अस्थिपंजर की बोरियां पायी गयी। उक्त नर कंकाल दिनांक 28–02–1980 से 12–03–2008 तक के रखे गये थे। जनपद मुरादाबाद में पूरा नर कंकाल न होकर हाथ व सिर की हड्डियां एवं दांतों का नमूना तथा कुछ विसरों के जार मिले हैं। वर्ष 2008 के पूर्व पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर की रिपोर्ट व ऐसे अस्थिपंजर को मृत्यु का कारण, पहचान, उम्र, लिंग, मृत्यु की समय की जांच हेतु यथास्थिति में सुरक्षित रख लिये जाते थे।

जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा गठित कमेटी की जांच व अभिलेखों के सत्यापन से पाया गया कि अस्थिपंजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उपरान्त के हैं। जांच समिति द्वारा 47 पोटलियों/बोरियों की पोस्टमार्टम की संख्या का अभिलेखों से मिलान कर लिया गया है।

उनकी सूची जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को भेजकर निर्देशित किया गया है कि इन मामलों में यदि कोई मुकदमा या अपराध पंजीकृत/विचाराधीन है, तो न्यायालय के आदेश के अनुसार निस्तारण कराया जाय। जनपद मुरादाबाद में अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी है। जांच के उपरान्त दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

01—श्री सन्तराम कुशवाहा—

खदिनांक 10—03—2015 के अता0प्र0सं0—19 द्वारा उत्तरित,

जनपद आगरा में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ताजमहल के निकट सेवला सराय ग्वालियर रोड स्थित सरस्वती विहार कालोनी के विकसित किये जाने की मांग

02—श्री गुटियारी लाल दुवेश—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ताजमहल के निकट सेवला सराय ग्वालियर रोड स्थित सरस्वती विहार कॉलोनी में केशव देव शर्मा के घर से भगवान दास अग्रवाल के घर तक डॉ0 केदार सिंह प्रजापति के घर से श्री चरन सिंह चाहर एवं श्री बच्चू सिंह के घर तक गली व नाली अत्यन्त जर्जर है जिससे जलभराव व कीचड़ होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गलियों व नालियों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां।

प्रश्नगत कालोनी प्राइवेट कालोनाइजरों द्वारा विकसित की गयी है तथा नगर निगम आगरा को हस्तगत नहीं है। अतः उक्त क्षेत्र के विकास कार्य कराने का दायित्व नगर निगम का नहीं है।

जनपद गाजियाबाद में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विजय नगर में एक सड़क जो एन0एच0—24 से प्रताप विहार को जोड़ती है के क्षतिग्रस्त होने से मरम्मत कराया जाना

03—श्री सुरेश बंसल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विजय नगर में एक सड़क जो एन0एच0—24 से प्रताप विहार को जोड़ती है, पूर्णतः क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत सड़क के मरम्मत कार्य हेतु आगणन स्वीकृत हो चुका है। उक्त कार्य की निविदा दिनांक 18–02–15 को समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराकर आमंत्रित की गयी थी किन्तु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुयी। पुनः निविदा आमंत्रण की कार्रवाई प्रक्रिया में है। निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त उक्त कार्य को कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विजय नगर वार्ड नं0–66 में मुख्य नाले के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण ठीक कराये जाने विषयक

04–श्री सुरेश बंसल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विजय नगर वार्ड नं0–66 में एक मुख्य नाला जो चिल्ड्रन एकेडमी से लेकर जल निगम प्लाट तक जाता है, पूर्णतः क्षतिग्रस्त है एवं सदैव ओवर फ्लो रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त नाले की मरम्मत एवं सफाई कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्नगत नाले की सफाई माह अक्टूबर, 2014, पुनः दिनांक 20–01–2015 एवं दिनांक 28–01–2015 को करायी गयी है तथा उसकी सिल्ट भी उठवा दी गयी है। इस नाले की सफाई समय–समय पर तीन माह के अन्तराल पर करायी जाती है तथा सिल्ट उठवायी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विजय नगर क्षेत्र में प्रेमपुरी से कैलाश नगर गौशाला तक की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

05–श्री सुरेश बंसल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विजय नगर क्षेत्र को नहर से जोड़ने के लिए जो अण्डरपास है उसकी सड़क जो प्रेमपुरी से कैलाशनगर गौ–शाला तक जाती है पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत सड़क के निर्माण कार्य का आगणन तैयार किया गया है, जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है। स्वीकृति के उपरान्त नियमानुसार कार्य कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विजय नगर में प्रताप विहार को जोड़ने वाली क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

06–श्री सुरेश बंसल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विजय नगर में एक सड़क जो हिण्डन बैराज से मा0 कांशीराम योजना होते हुए प्रताप विहार को जोड़ती है, पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

उक्त सड़क का रख–रखाव आवास विकास परिषद्, गाजियाबाद द्वारा किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करवाया जाना

07–श्री सुरेश बंसल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत एक सड़क जो एन0एच0–24 से कमला सिनेमा के सामने से होती हुई बिहारीपुरा सामुदायिक केन्द्र तक जाती है, पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत सड़क के निर्माण हेतु नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत आगणन तैयार किया गया है। वांछित धनराशि की स्वीकृति के उपरान्त ही उक्त सड़क का निर्माण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गाजियाबाद के वार्ड नं0 6 गणेश एन्क्लेव बौद्ध विहार में गली नं0–6 व 7 पूर्णतः क्षतिग्रस्त मार्ग को बनवाया जाना

08–श्री सुरेश बंसल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गाजियाबाद के वार्ड नं0–6 गणेश एन्क्लेव बौद्ध विहार में गली नं0–6 व 7 पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, तथा जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण नाले का गन्दा पानी भरा रहता है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त गलियों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र प्राइवेट कास्तकार द्वारा अपनी भूमि को छोटे–छोटे भू–खण्डों को में बाटकर कालोनी बनायी गयी है। इस क्षेत्र की अन्य गलियां भी कच्ची है। क्षेत्र में जल निकासी का कार्य कराये बिना सड़कों को निर्मित किया जाना उचित नहीं है। इस क्षेत्र की कच्ची सड़कों को पक्का करने एवं मेन रोड होते हुये हिण्डन नदी तक जल निकासी हेतु नगरीय सड़क सुधार एवं जल निकासी योजना के अन्तर्गत आगणन तैयार कर लिया गया है। धनराशि की स्वीकृति के उपरान्त ही गलियों को निर्मित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा में उमाकुंज कालोनी व राधाकृष्ण कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत की मांग

09–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में उमाकुंज कालोनी व राधाकृष्ण कालोनी, सिकन्दरा की गली नं0–1 से 5 तक की आन्तरिक सड़कें विगत कई वर्षों से मरम्मत न होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिससे कालोनीवासियों का उक्त गलियों से आवागमन मुश्किल हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों व नालियों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

उमाकुंज कालोनी व राधा कृष्ण कालोनियों का विकास/निर्माण कार्य प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा किया गया है जिन्हें नगर निगम आगरा को अभी तक हस्तान्तरित नहीं किया गया है। उक्त प्रकृति की कालोनियों में विकास कार्य का दायित्व नगर निगम का नहीं है।

सिकन्दरा गली न0–1 से 5 के विषय में नगर निगम आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षेत्रीय पार्षद, स्थानीय नागरिकों एवं प्रश्नकर्ता मा0 विधायक जी से जानकारी की गयी। यह विदित हुआ कि उक्त गलियां अस्तित्व में नहीं हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

आगरा में ग्रीन पार्क तोता के ताल में कतिपय एरिया पार्क की सड़क के दोनों पार्क का सौन्दर्यीकरण का प्रकरण में वाद दायर होने से कार्य प्रभावित होना

10–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में ग्रीन पार्क तोता के ताल व राजामण्डी स्टेशन पार्क व न्यू राजामण्डी कालोनी की साइड में दोनों पार्क ए0डी0ए0 द्वारा लगभग 35 वर्ष पूर्व बनाये गये थे पर भू–माफियाओं द्वारा नगर निगम के सौन्दर्यीकरण कार्य को रुकवा कर कब्जा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क को अवैध कब्जे से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

आगरा में ग्रीन पार्क तोता के ताल व राजामण्डी स्टेशन पार्क, न्यू राजामण्डी कालोनी की साइड में दोनों पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य नगर निगम द्वारा पूर्व में प्रारम्भ कराया गया था, परन्तु दोनों पार्कों के भूमि स्वामित्व के सम्बन्ध में मा0 जनपद न्यायालय में वाद संख्या–549/2011 लम्बित चल रहा है, जिसमें आगरा विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम आगरा आदि को पक्षकार बनाया गया है। उक्त वाद में सुनवाई हेतु 13–4–15 की तिथि नियत की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड–28 की अनेकों ध्वस्त सड़क व नाली निर्माण कराने की मांग

11–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड–28, कृष्णानगर में पुरानी पुलिस चौकी शनिदेव मन्दिर के पीछे तथा वार्ड नं0 31 में कूड़ाघर के सामने बसन्त लाल की गली में ध्वस्त सड़क एवं नाली का निर्माण न होने के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों एवं नालियों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

वार्ड 28, कृष्णा नगर में पुरानी पुलिस चौकी शनिदेव मंदिर के पीछे ध्वस्त सड़क एवं नाली का निर्माण करा दिया गया है। वार्ड नं0–31 में कूड़ा घर के सामने बसन्त

लाल की गली में ध्वस्त सड़क एवं नाली का निर्माण कराया जाना वित्तीय संसाधन पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड–77 में डी ब्लाक में सड़क निर्माण कराये जाने की मांग

12–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड–77, में डी ब्लाक के मकान नं0 317, 318, 333, 332 के सामने एवं 75 मुन्शीपुरवा के अंतर्गत म0नं0–132/687 से म0नं0–132/678 तक सड़क निर्माण न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर सड़कों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

वार्ड–77 में डी–ब्लाक के म0नं0 317, 318 के सामने की सड़क बनायी जा चुकी है तथा म0नं0–332, 333 एवं वार्ड–75 मुंशीपुरवा के अन्तर्गत म0नं0–132/687 से म0नं0–132/678 तक सड़क निर्माण कराया जाना वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड–96, मुंशीपुरवा के अन्तर्गत एक हैण्डपम्प स्थापित करवाने की मांग

13–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड–96, मुंशीपुरवा के अन्तर्गत म0नं0–132/754 एवं 132/715 के पास हैण्डपम्प न होने से जनता को पीने के पानी की परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर हैण्डपम्प लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं। जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड–96, मुंशीपुरवा में जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर द्वारा पेयजलापूर्ति की जाती है। मकान नं0–132/754 एवं 132/715 की गली में पाइप लाइन पूर्व से बिछी हुई है, जिसके माध्यम से समुचित जलापूर्ति हो रही है।

वार्ड सं0–96, मुंशीपुरवा में मकान न0–132/754 के सामने श्री मोहर सिंह के मकान के पास कोई हैण्डपम्प अधिष्ठापित नहीं है। मकान न0–132/757 के पास हैण्डपम्प अधिष्ठापित है जो चालू हालत में है। मकान नं0–132/754 के पीछे पार्क में सबमर्सिबल पम्प अधिष्ठापित है और चालू हालत में है। मकान नं0–132/715 के पास कोई हैण्डपम्प अधिष्ठापित नहीं है।

वर्णित स्थिति में उक्त स्थानों पर हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर शहर के मध्य नालों के गन्दे पानी को गोमती में गिरने से रोकने की कार्यवाही किये जाने की मांग

14—श्री नदीम जावेद—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर शहर के मध्य से बहने वाली गोमती नदी में गिरने वाले नालों के गंदे पानी को रोकने के लिए मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में क्या सरकार कोई ठोस कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जौनपुर शहर के गोमती नदी में गिरने वाले नालों के गंदे पानी को रोकने हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित एन0जी0आर0बी0ए0 योजनान्तर्गत सीवरेज योजना हेतु अनुमानित लागत रुपये 264.00 करोड़ का डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है, जिसे अप्रैल, 2015 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक जिले की सारी तहसीलों में अग्निशमन केन्द्र खोलने की योजना की जानकारी

15—श्री नदीम जावेद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जिले की सारी तहसीलों में अग्निशमन केन्द्र खोलने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत नगर मोहम्मदी में ध्वस्त पुरानी सीवर लाइनों को हटाकर जनसंख्या के आधार पर अधिक क्षमता की नई सीवर लाइन डलवाया जाना

16—श्री अवस्थी बाला प्रसाद—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत नगर मोहम्मदी में ध्वस्त पुरानी सीवर लाइनों के स्थान पर जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए अधिक क्षमता के बड़े पाइप लाइन डलवाकर नयी सीवर लाइनें डालने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अद्यतन नगर पालिका परिषद्, मोहम्मदी में जलापूर्ति डायरेक्ट पम्पिंग से की जा रही है और वर्तमान जनसंख्या को लगभग 30 एल0पी0सी0डी0 की दर से जलापूर्ति प्राप्त हो रही है। वर्तमान में नगर में कोई सीवर व्यवस्था नहीं है तथा नगरवासियों द्वारा अपने घरों के शौचालयों का कनेक्शन सैप्टिक टैंक से किया गया है। सीवरेज व्यवस्था हेतु नगर की पेयजल योजना को 135 एल0पी0सी0डी0 का होना आवश्यक है। मोहम्मदी नगर हेतु पूर्व निर्मित पेयजल योजना 135 एल0पी0सी0डी0 के आधार का न होने के कारण नगर पालिका परिषद्, मोहम्मदी द्वारा सीवरेज व्यवस्था हेतु प्रस्ताव भी पारित नहीं किया गया है।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बहुत से लोग झुग्गी–झोपड़ी व खुले आसमान के नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं, ऐसे गरीबों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराया जाना

17–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बहुत से लोग झुग्गी–झोपड़ी व खुले आसमान के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों के आवास निर्माण के लिए कोई प्रभावी कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

शहरी क्षेत्रों के आश्रयहीन लोगों के लिये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अधीन शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना आरम्भ की गई है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित उक्त योजना प्रदेश के चयनित 82 नगरों में लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत रैन बसेरों का निर्माण किया जा रहा है। कानपुर महानगर सहित कुल 32 शहरों की 42 परियोजनाएं 2962 शहरी बेघरों के लिये स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिसकी परियोजना लागत रु0 76.45 करोड़ है। उक्त नवीन रैन बसेरों के निर्माण व सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त नगर विकास विभाग के अधीन नगरीय निकायों द्वारा रैन बसेरों का संचालन पूर्व से अतिरिक्त रूप से किया जा रहा है।

आवासहीन शहरी गरीबों के लिये प्रदेश सरकार द्वारा राजीव आवास योजना, आसरा योजना व एफोर्डेबल हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। राजीव आवास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 21 शहरों, कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, गाजियाबाद, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, गोरखपुर, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, मथुरा, शाहजहांपुर, रायबरेली, रामपुर, इटावा एवं कन्नौज में से 10 शहरों की कुल 4239 आवास निर्माण की 12 परियोजनाएं लागत रु0 35145.04 लाख की स्वीकृति की गयी है।

प्रदेश सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जाने की आसरा योजना में प्रदेश के 64 शहरों की 14899 आवासों के लिये रु0 52152.07 लाख की परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं, जिसके सापेक्ष रु0 22413.45 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के गिहारा बस्ती बजीरपुरा में श्री अब्दुल सत्तार चश्मे वाले के मकान के बगल में नाली, खड़न्जा का निर्माण करवाया जाना

18—श्री जगन प्रसाद गर्ग—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के गिहारा बस्ती बजीरपुरा में श्री अब्दुल सत्तार चश्मे वाले के मकान नं0 23/327 के बगल में गली का 8 फुट चौड़ा व 200 फुट लम्बा खड़न्जा व नाली जर्जर व टूटी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त खरंजा व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां।

प्रश्नगत गली में इण्टरलाकिंग से फर्श निर्माण एवं नाली मरम्मत के कार्य हेतु आगणन तैयार कराया गया है।

धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के लोहामण्डी क्षेत्र की बागअन्ता गली की सड़क का निर्माण करवाने की मांग

19—श्री जगन प्रसाद गर्ग—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के लोहामण्डी क्षेत्र की बागअन्ता गली की सड़क जर्जर होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गली की सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

उक्त गली में सी0सी0 सड़क बनी हुयी है जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत गली के क्षतिग्रस्त आंशिक भाग की मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के सौंठ की मण्डी के कृष्णा कुंज के ताज गैस गोदाम वाली गली में सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने की मांग

20—श्री जगन प्रसाद गर्ग—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के सौंठ की मण्डी के कृष्णा कुंज के ताज गैस गोदाम वाली गली में सड़क व नाली जर्जर होने के कारण नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी नहीं।

प्रश्नगत सड़क इण्टरलाकिंग की बनी हुयी है एवं नालियां सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं। सड़क आवागमन हेतु सुगम है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नं0—53 में न्यू आजाद नगर में सड़क निर्माण करवाने की मांग

21—श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नं0—53 में न्यू आजाद नगर में मकान नं0—1 से मकान नं0—30 तक सड़क निर्माण न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

प्रश्नगत क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश सं0—05097/9—अ—3—2001/अ0व0, दिनांक 26—05—2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। अतः यहां के विकास कार्य का दायित्व कानपुर विकास प्राधिकरण का है।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नं0—53 देहली सुजानपुर के अंतर्गत दुर्गा चौराहे से सड़क निर्माण कराया जाना

22—श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नं0—53 देहली सुजानपुर के अन्तर्गत दुर्गा चौराहे से म0नं0—201 एवं न्यू आजाद नगर, कोयला नगर में म0नं0—195 से 230 तक सड़क निर्माण न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का निर्माण कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

प्रश्नगत क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश सं0–05097/9–अ–3–2001/अ0व0, दिनांक 26–05–2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। अतः यहां के विकास कार्य का दायित्व कानपुर विकास प्राधिकरण का है।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड नं0–28 के कृष्णानगर में खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराया जाना

23–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड नं0–28 के कृष्णानगर में लगभग 25 हैण्डपम्प खराब होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं। कानपुर महानगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड संख्या–28 कृष्णानगर क्षेत्र में 76 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं जिनमें से 51 हैण्डपम्प चालू हैं तथा 25 हैण्डपम्प री–बोर योग्य हैं। इसके अतिरिक्त 02 नलकूप अधिष्ठापित है जो चालू है जिनसे क्षेत्र में सामान्य जलापूर्ति की जा रही है। जलकल विभाग उक्त 25 रि–बोर योग्य हैण्डपम्पों की रि–बोरिंग की कार्यवाही की जा रही है, जिन्हें माह मार्च, 2015 के अन्त तक रि–बोर कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नं0–77 जोन–2, श्यामनगर वार्ड नं0–28 की कतिपय गली में सड़क एवं नाली का निर्माण कराया जाना

24–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नं0–77 जोन–2 श्यामनगर ई ब्लाक में म0नं0 एल0आई0जी0–343 के सामने एवं वार्ड नं0–28 कृष्णानगर के म0नं0–07/1 से 07/49 ब्लाक नं0–7 की गली में सड़क एवं नाली निर्माण न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों व नालियों का निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

वार्ड नं0–77 जोन–2, ई–ब्लाक में मकान नं0 एल0आई0जी0 343 के सामने के कार्य नगर निगम के सीमित एवं वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

वार्ड नं0–28 कृष्णा नगर के मकान नं0 7/1 से 7/49 ब्लाक नं0 7 की गली/प्रश्नगत क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश सं0 05097/9–अ–3–2001/अ0व0, दिनांक 26–05–2001 के अनुसार सोसाइटियों के

नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। अतः यहां के विकास कार्य का दायित्व कानपुर विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना कराने की मांग

25—श्री अवस्थी बाला प्रसाद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना न होने के कारण नागरिकों को 70 किमी0 दूर जनपद मुख्यालय पर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील धौरहरा में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

अधीनस्थ न्यायालयों पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का पूर्ण नियंत्रण होता है। न्यायालयों की स्थाना के सम्बन्ध में पहले मा0 उच्च न्यायालय का अभिमत/संस्तुति प्राप्त की जाती है। वर्तमान में जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति प्राप्त नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी में अरबी—फारसी बोर्ड से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त मदरसा स्कूलों को अनुदान देने पर सरकार का विचार

26—श्री अवस्थी बाला प्रसाद—

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में अरबी—फारसी बोर्ड से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त कितने मदरसा स्कूल हैं तथा उनमें कितने अनुदान प्राप्त है ? क्या सरकार शेष मदरसों को अनुदान देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जनपद लखीमपुर खीरी में अरबी—फारसी बोर्ड से सम्बद्ध स्थायी/अस्थायी मान्यता प्राप्त कुल 17 मदरसें हैं, जिनमें 02 मदरसे अनुदान प्राप्त हैं।

प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के दृष्टिगत स्थायी मान्यता प्राप्ति के आधार पर मदरसों को अनुदानित करने की कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश में 146 मदरसों को 02 वर्षों में अनुदान सूची में लिये जाने के लिये फेजिंग करते हुये प्रथम वर्ष 2013—14 में वर्ष 2003 तक के आलिया स्तर के स्थाई मान्यता प्राप्त 75 मदरसों को वर्तमान में अनुदान सूची पर लिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जो 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर के राजकीय सचिवालय कालोनी, पुरनिया तिराहा सीतापुर रोड में जल निकासी की व्यवस्था को ठीक करवाने की मांग

27—श्री अवस्थी बाला प्रसाद—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के राजकीय सचिवालय कालोनी, पुरनिया तिराहा सीतापुर रोड में जल निकासी व्यवस्था न होने के कारण वर्षा ऋतु में के0सी0 टाइप के भू—तल आवासों में जल भराव हो जाने के कारण प्रतिवर्ष अध्यासियों का लाखों रुपयों का सामान खराब हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी में जल निकासी की समुचित व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

प्रश्नगत कालोनी राज्य सम्पत्ति विभाग की है। कालोनी की आन्तरिक नालियों आदि का रख—रखाव लोक निर्माण विभाग अनुरक्षण खण्ड—1 (सिविल/विद्युत) द्वारा कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नं0—53 के मंगला विहार प्रथम में सड़क न होने के कारण सड़क निर्माण की मांग

28—श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नं0 53 के मंगला विहार प्रथम में ईशाक अहमद के मकान से जयराम कुशवाहा के मकान होते हुये 60 फीट रोड तक सड़क न होने के कारण जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

प्रश्नगत क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश सं0—05097/9—अ—3—2001/अ0व0, दिनांक 26—05—2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। अतः यहां के विकास कार्य का दायित्व कानपुर विकास प्राधिकरण का है।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड नं0—31 के बगाही भट्ठा मलिन बस्ती की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

29—श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया—

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड नं0—31 के बगाही भट्ठा मलिन बस्ती में म0नं0 130/2 भरत सोनकर के मकान से बाबूराम सोनकर के मकान

तक सड़क क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद–कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड नं0–31 के बगाही भट्ठा मलिन बस्ती में म0 नं0–130/2 भरत सोनकर के मकान से बाबूराम सोनकर के मकान तक सड़क का निर्माण मलिन बस्ती योजनान्तर्गत जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), कानपुर नगर द्वारा पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड–31 के अन्तर्गत 130/19 बगाही भट्ठा के निकट पेयजल हेतु हैण्डपम्प लगाया जाना

30–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 31 के अन्तर्गत 130/19 बगाही भट्ठा के निकट पेयजल हेतु हैण्डपम्प न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर हैण्डपम्प लगवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं। जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड संख्या–31 के अन्तर्गत बगाही भट्ठा में जलकल विभाग नगर निगम कानपुर द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। मकान नम्बर 130/19 की गली में पूर्व से पाइप लाइन बिछी हुई है, जिसके माध्यम से समुचित जलापूर्ति की जा रही है। वार्ड संख्या–31 के अन्तर्गत 130/19 बगाही भट्ठा हाता में श्री इन्द्रजीत के घर के पास एक इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प पूर्व से स्थापित है, जो कि चालू हालत में है। अतः हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जाने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के तहसील कोरांव परिसर में दीवानी न्यायालय की स्थापना हेतु शासनादेश

31–श्री राजबली जैसल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के तहसील कोरांव परिसर में दीवानी न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त दीवानी न्यायालय की स्थापना कब तक करा दी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद इलाहाबाद के तहसील कोरांव में दीवानी न्यायालय की स्थापना न्याय अनुभाग–2 (अधीनस्थ न्यायालय) के शासनादेश

संख्या–2783 / सात–न्याय–2–07–202(25) / 76टी0सी0, दि0 28–01–2008 द्वारा की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय वार्डों के निकट सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने की मांग

32–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड नं0–77 जोन–2 श्याम नगर ई ब्लाक स्थित पानी की टंकी तक एवं वार्ड नं0–53 के न्यू आजाद नगर स्थित भूतेश्वरी मंदिर के निकट म0नं0–26 से 735 तक सड़क एवं नाली ध्वस्त होने से नागरिकों को आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर सड़कों एवं नालियों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां

छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड–77 श्याम नगर ई–ब्लाक में पानी की टंकी तक सड़क का निर्माण कराया जा चुका है एवं वार्ड–53 न्यू आजाद नगर स्थित भुतेश्वरी मंदिर के निकट मकान नं0–26 से 735 तक का क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश सं0–05097 / 9–अ–3–2001 / अ0व0, दिनांक 26–05–2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। अतः उक्त क्षेत्र के विकास का दायित्व विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक क्षेत्र बंथर दही चौकी अकरमपुर व उन्नाव नगर के लोने ड्रेन एवं सिटी ड्रेन की सफाई व निर्माण हेतु धन के निर्गत करने विषयक–पत्र पर की गई कार्यवाई

33–श्री पंकज गुप्ता–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र बंथर दही चौकी अकरमपुर व उन्नाव नगर के लोने ड्रेन एवं सिटी ड्रेन की सफाई एवं पक्का निर्माण हेतु धन निर्गत करने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय के कम्प्यूटर में दर्ज प्रकरण में कम्प्यूटर सं0 पी0जी0 10474432 सी0एम0 / वि0को0 / एम0 / पी0जी0–10474432 / 2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रस्ताव का परीक्षण कराया जा रहा है। प्रस्ताव के औचित्यपूर्ण पाये जाने तथा धन की उपलब्धता की स्थिति में अग्रेतर कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा में कर्मयोगी फुब्बारे से अमित विहार तक, वैभववाटिका के तरफ होते हुए सड़कों को निर्मित किये जाने की मांग

34–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में कर्मयोगी फुब्बारे से एस0एस0 कान्वेन्ट स्कूल–अमित विहार तक, वैभववाटिका के तरफ की एवं ठंकी रोड से होते हुए यमुनोत्री को जाने वाली सड़कें विगत कई वर्षों से जर्जर व गड्ढायुक्त होकर क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का सी0सी0 निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

हरिपर्वत वार्ड कमला नगर कक्ष संख्या–82 कर्मयोगी चौराहे से एस0एस0 कान्वेन्ट स्कूल होते हुये डी–470 यमुना विहार पुलिया तक नाली, साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग टाइल्स एवं हाटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य नगर निगम द्वारा अवस्थापना विकास निधि से प्राप्त धनराशि से कराया जा रहा है।

डी–470 से अमिता विहार वैष्णों धाम तक क्षतिग्रस्त सड़क एवं कर्मयोगी फुब्बारे पानी की टंकी होते हुये गौ–शाला तक की क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कार्य हेतु आगणन तैयार कराया गया है। उक्त कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराये जा सकेंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा में बल्केश्वर क्षेत्र में गंगे गौरी पार्क की बाउण्ड्रीवाल व पैदल पथ विगत कई वर्षों से क्षतिग्रस्त पार्क में समरसेविल लगाकर सौन्दर्यीकरण कराने, पैदल पथ तथा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया जाना

35–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में बल्केश्वर क्षेत्र में गंगे गौरी पार्क की बाउण्ड्रीवाल व पैदल पथ विगत कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क में समरसेविल लगाकर सौन्दर्यीकरण कराने, पैदल पथ तथा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

पार्क की बाउण्ड्रीवाल क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत पार्क की बाउन्ड्रीवाल व पैदल पथ निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु आगणन तैयार कराया गया है।

धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा में कमला नगर क्षेत्र के पुरानी अवधेशपुरी की सड़कें ठीक कराने विषयक

36–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में कमला नगर क्षेत्र के पुरानी अवधेशपुरी की सड़कें विगत कई वर्षों से जर्जर व गड्ढायुक्त होकर क्षतिगस्त हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का सी0सी0 निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत सड़कों के निर्माण कार्य हेतु आगणन तैयार कराया गया है।

धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में पूर्वान्चल निधि (राज्यांश) योजना में स्वीकृत कार्यों में की गयी अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

37–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में पूर्वान्चल निधि (राज्यांश) योजना में स्वीकृत वर्ष 2002–03 के कार्यों में की गयी अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर में दर्ज पत्र संख्या पी0जी0 10555063, पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10555063/2014, दिनांक 06–12–2014 प्रमुख सचिव/सचिव ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)–

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं के स्व0 सत्यवीर सिंह आरक्षी नं0–496 नागरिक पुलिस की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने से उनकी पत्नी मृतक आश्रित को देय सभी लाभों का भुगतान करने विषयक

38–श्री पूरन प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के स्व0 सत्यवीर सिंह आरक्षी (नं0–496 नागरिक पुलिस) की सेवाकाल के दौरान दिनांक 2–2–2013 को आकस्मिक मृत्यु होने पर मृतक आरक्षी की ड्यूटी के दौरान रवानगी जी0डी0 में दर्ज थी ? यदि हां, तो क्या उक्त आरक्षी की कर्तव्य पालन के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को नियमावली, 1961–75 के नियम–3 तथा शासनादेशों के अन्तर्गत असाधारण

पेंशन आदि दे दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

थाना जी0आर0पी0, इलाहाबाद की नकल रपट नं0–18 समय 08.35 रो0आ0 दिनांक 02–02–2013 के अनुसार श्री सत्यवीर सिंह को जनपद बदायूं रवाना किया गया था।

स्व0 सत्यवीर सिंह, आरक्षी की मृत्यु कर्तव्य पालन के दौरान न होने के कारण असाधारण पेंशन स्वीकृत किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। स्व0 सत्यवीर सिंह की आश्रिता श्रीमती अंजली के पक्ष में निम्नांकित धनराशि का भुगतान किया गया है :–

नकदीकरण की धनराशि रु0 2,39,400/– सामूहिक बीमा की धनराशि रु0 1,24,751/–, उपादान धनराशि रु0 4,83,827/–, पी0वी0एफ0 धनराशि रु0 4,000/–, उपादान 10 प्रतिशत धनराशि रु0 78,763/–पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पी0पी0ओ0 संख्या–चार–1494–2013, दिनांक 28–5–2013 के अनुसार आश्रिता, श्रीमती अंजली की पारिवारिक पेंशन की धनराशि रु0 6,650/–प्रतिमाह की दर से स्वीकृत की गयी है।

नगर फैजाबाद में मोहल्ला सन्त नगर अम्बेडकर बगीची से लेकर मुस्तफाबाद तक की क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक कराया जाना

39–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में मोहल्ला सन्त नगर अम्बेडकर बगीची से लेकर मुस्तफाबाद तक की सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में कठिनाइयां होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर निगम, फिरोजाबाद नव सृजित नगर निगम है। इसमें कतिपय ग्राम सभाओं को भी सम्मिलित किया गया है। निकाय के पूर्व निर्धारित सीमा के साथ–साथ बढ़े हुये नयी आबादी क्षेत्र में भी विकास कार्य कराना निगम का दायित्व है। वर्तमान में नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा उक्त नई आबादी क्षेत्र में अतिमहत्वपूर्ण विकास कार्यों को धन की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। प्रश्नगत कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर फिरोजाबाद में मीरा चौराहा, सेन्ट जॉन्स चौराहा से लेकर लालऊ गांव के तिराहे तक दल–दल युक्त सड़क का निर्माण

40–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में मीरा चौराहा, सेन्ट जॉन्स चौराहा से लेकर लालऊ गांव के तिराहे तक माल पूरी तरह से कच्चा एवं दल–दल युक्त होने के कारण आवागमन में बहुत असुविधा होती है ? यदि हां तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर निगम, फिरोजाबाद नव सृजित नगर निगम है। नगर निगम द्वारा सर्वप्रथम आवासीय क्षेत्रों में अति प्राथमिकता वाली सड़क/गलियों का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आवासीय जन मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित हो सकें। मीरा चौराहा/सेंट जॉन्स चौराहा से लालऊ रोड तक प्रश्नगत सड़क इण्डस्ट्रियल एरिया के क्षेत्रान्तर्गत है। धन की उपलब्धता के आधार पर उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में कोटला रोड बम्बा चौराहे से लेकर सत्कार टॉकीज के सामने गुजरता हुआ कोटला एवं छारबाग तिराहे से सोफीपुर तिराहे तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण

41–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में कोटला रोड बम्बा चौराहे से लेकर सत्कार टॉकीज के सामने गुजरता हुआ कोटला एवं छारबाग तिराहे से सोफीपुर तिराहे तक मार्ग क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद फिरोजाबाद में कोटला रोड बम्बा चौराहे से लेकर सत्कार टॉकीज के सामने गुजरता हुआ कोटला तक सड़क लोक निर्माण विभाग के अधीन है एवं उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है। छारबाग तिराहे से सोफीपुर तिराहे तक की सड़क नगर निगम सीमा मे है तथा पूरी तरह से ठीक है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के छोटे शहरों में विकास के लिये अधिकतर स्थानीय निकायों में अधिशासी अधिकारियों की भारी कमी देखते हुये रिक्त पदों पर नियुक्ति करने विषयक

42–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छोटे शहरों में विकास के लिए अधिकतर स्थानीय निकायों में अधिशासी अधिकारियों की भारी कमी है ? क्या यह भी

सही है कि अधिशासी अधिकारियों की कमी के कारण इन निकायों में विकास कार्य ठप्प हैं ? यदि हां तो क्या सरकार विकास कार्यों को गति देने के लिए अधिशासी अधिकारियों की रिक्तियों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी नहीं।

अधिशासी अधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाई प्रक्रियाधीन है।

अधिशासी अधिकारियों के पदों पर चयन के उपरान्त नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों के रिक्त पदों पर तैनाती की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के कमला नगर में नालियां, सड़कें ठीक करवाने की मांग

43–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के कमला नगर में कावेरी फेस–2 के म0नं0 107 से 120 तक, बी–651 से ए–776 श्री विश्वेन्द्र के घर तक एवं आवास विकास कालोनी से 8/934 से 944 तक की नालियां एवं सड़कें विगत कई वर्षों से जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों एवं नालियों का सी0सी0 निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत सड़क एवं नाली के निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु आगणन तैयार कराया गया है।

धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

स्व0 विजय बहादुर पाल, कनिष्ठ लिपिक–ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड कार्यालय, अधिशासी अभियंता, उन्नाव के देयकों का भुगतान, उनके नाबालिग पुत्र को नियमों में शिथिलता कर सेवायोजित करने विषयक

44–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 विजय बहादुर पाल, कनिष्ठ लिपिक–ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड कार्यालय, अधिशासी अभियंता, उन्नाव के देयकों का भुगतान, उनके नाबालिग पुत्र को नियमों में शिथिलता बरतते हुए मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति तथा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27–09–2004 का अनुपालन न करने के दोषियों को दंडित करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31–12–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

जी हां।

प्रश्न में संदर्भित प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र में अभिलिखित प्रकरण की वस्तुस्थिति/कृत कार्यवाई का विवरण निम्नवत् है :–

- श्री विजय बहादुर पाल की नियुक्ति अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड–उन्नाव के कार्यालय आदेश सं0–1492, दिनांक 24–12–87 एवं पुनः आदेश सं0–101, दिनांक 21–04–1988 द्वारा कार्य की आवश्यकता को देखते हुये तदर्थ रूप से तीन–तीन माह के लिये कनिष्ठ लिपिक के पद पर की गयी थी।
- दिनांक 27–05–1988 को सड़क दुर्घटना में श्री पाल की मृत्यु हो गयी।
- स्व0 विजय बहादुर पाल की पत्नी श्रीमती मंजुला देवी द्वारा अपने पति की मृत्यु के लगभग 14 वर्ष 10 माह पश्चात्, प्रखण्ड–उन्नाव को प्रस्तुत अपने दिनांक रहित प्रार्थना–पत्र द्वारा अपने पुत्र को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त करने एवं देयकों का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया।
- श्रीमती मंजुला देवी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका सं0–399322/2004 योजित की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27–9–2014 पारित किया गया।
- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में याची श्रीमती मंजुला देवी के प्रत्यावेदन दिनांकित 04–10–2004 एवं 21–12–2004 को सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निस्तारित करते हुये याची को देय सामूहिक बीमा की धनराशि रु0 25071.00 का भुगतान चेक सं0–ए0एल0–003399, दिनांक 24–08–2005 द्वारा किया जा चुका है तथा तदनुसार मा0 उच्च न्यायालय में विभाग की ओर से शपथ–पत्र भी दिनांक 10–10–2006 को दाखिल किया जा चुका है।
- याची का अन्य कोई भी देयक विभाग के पास लम्बित नहीं है।
- स्व0 विजय बहादुर पाल के तदर्थ रूप से नियुक्त होने के कारण याची के पुत्र को सेवायोजित किये जाने का प्रकरण उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार आच्छादित न होने/काल बाधित होने के कारण स्व0 विजय बहादुर पाल के पुत्र को मृतक आश्रित के रूप में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति/सेवायोजन का लाभ अनुमन्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में मुकदमा अपराध संख्या–2160/12 थाना सदर कोतवाली धारा–147, 336, 341,332,353,436,427 में दर्ज मुकदमें को वापस लेने विषयक पत्र, कृत कार्यवाई की जानकारी

45—श्री पंकज गुप्ता—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अपराध संख्या 2160/12 थाना सदर कोतवाली धारा—147, 336, 341,332,353,436,427, जनपद उन्नाव में दर्ज मुकदमें को वापस कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री सचिवालय कम्प्यूटर सं0 पी0जी0 10548501 में दर्ज प्रश्नकर्ता के पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10548501/2014 पर अब तक क्या कार्यवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

प्रश्नगत प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव से आख्या मांगी गयी है, जो अभी प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

46—श्री मनीष असीजा—

ख्आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त,

जनपद जौनपुर में तहसील स्तर पर फायर ब्रिगेड स्टेशन की स्थापना की तर्ज पर ब्लाक स्तर पर भी फायर ब्रिगेड का सब—स्टेशन बनाये जाने विषयक

47—श्री नदीम जावेद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में तहसील स्तर पर फायर ब्रिगेड स्टेशन की स्थापना की तर्ज पर क्या सरकार ब्लाक स्तर पर भी फायर ब्रिगेड का सब— स्टेशन बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में तहसील स्तरों पर अग्नि शमन केन्द्र स्थापित करना प्राथमिकता है।

प्रदेश में बिगड़ती कानून—व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही सब—इंस्पेक्टरों तथा पुलिस इंस्पेक्टरों की नियुक्ति व तैनाती कराये जाने की मांग

48—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने पुलिस इंस्पेक्टर तथा सब—इंस्पेक्टरों की कमी है ? क्या सरकार बिगड़ती कानून—व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही सब—इंस्पेक्टरों की नियुक्ति तथा पुलिस इंस्पेक्टरों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

निरीक्षक नागरिक पुलिस की रिक्तियां पूर्ण कर ली गयी हैं। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के कुल 8191 पद रिक्त हैं।

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस सीधी भर्ती के कुल 5803 रिक्तियों के सापेक्ष 3698 पदों पर चयन की कार्यवाही अन्तिम चरण में है, किन्तु प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण लम्बित है। शेष उप निरीक्षकों के 2105 रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाई प्रक्रियाधीन है। उप निरीक्षक रैंकर की कुल 2388 रिक्तियों पर पदोन्नति की कार्यवाई प्रक्रियाधीन है।

पुलिस विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती/पदोन्नति की कार्यवाई चरणबद्ध रूप से उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जाती है। सेवा में रिक्तियां एवं उनको भरे जाने की कार्यवाई एक सतत् प्रक्रिया है, जो निरन्तर चलती रहती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के वार्ड मुरलीनगर मोहल्ला बरफखाना 14/72 उदयगंज में रोड पर जबरन कब्जा किये जाने विषयक भगवान सिंह कुशवाहा, स0वि0स0 का पत्र पर की गई कार्यवाई की जानकारी

49—श्री चन्द्रभान सिंह पटेल—

विधान सभा के तृतीय सत्र—2014 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0—70 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के वार्ड मुरलीनगर मोहल्ला बरफखाना 14/72 उदयगंज में 20 फिट चौड़ी सड़क पर जबरन कब्जा कर स्थानीय निवासियों का आवागमन अवरुद्ध किये जाने विषयक भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा का पत्र सं0 092/2014, दिनांक 06—08—2014, नगर आयुक्त, नगर विकास लखनऊ को सम्बोधित, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर लखनऊ विकास प्राधिकारण द्वारा अब तक क्या कार्यवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां।

नगर निगम, लखनऊ द्वारा यह अवगत कराया गया है कि इस योजना के समस्त भू—खण्ड विकास प्राधिकरण, लखनऊ के नजूल विभाग द्वारा विक्रीत किये जा चुके हैं। प्रश्नगत योजना के भवनों के मानचित्र की स्वीकृति लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दी गयी है। अतः आर0बी0ओ0 एक्ट के अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाई लखनऊ, विकास प्राधिकरण द्वारा की जानी है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर के बालागंज क्षेत्र के मोहल्ला सरदार नगर लाल मस्जिद के पास अन्दर जाने वाला मार्ग सीवर लाइन डालने के कारण क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

50—श्री नदीम जावेद—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के बालागंज क्षेत्र के मोहल्ला सरदारनगर लाल मस्जिद के पास अन्दर जाने वाला मार्ग सीवर लाइन

डालने से अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा जनहित में उक्त मार्ग का डामरीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत क्षेत्र में सीवर लाइन डाले जाने का कार्य जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के सीवरेज परियोजना डिस्ट्रिक्ट–1 के अन्तर्गत लगभग 5 वर्ष पूर्व कराया जा चुका है, जिसकी सड़क के पुनर्निर्माण का कार्य भी नगर निगम द्वारा उसी अवधि में पूर्ण करा दिया गया था। इस क्षेत्र में वर्तमान में पेयजल पाइप लाइन का कार्य भी पूर्ण कराया जा चुका है, जिसकी सड़क पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है तथा इसे अप्रैल, 2015 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर फिरोजाबाद में गणेश नगर स्थित अवर जलाशय (पानी की टंकी) में नलकूपों द्वारा सीधे पानी चढ़ाने हेतु वांछित क्षमता के सी0डब्ल्यू0आर0 निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर हुई कार्यवाई की जानकारी

51–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में गणेश नगर स्थित अवर जलाशय (पानी की टंकी) में नलकूपों द्वारा सीधे पानी ऊपर चढ़ाने हेतु वांछित क्षमता के सी0डब्ल्यू0आर0 निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क5 नं0 233800 दिनांक 07–09–2013 उन्हें, प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

गणेश नगर स्थित अवर जलाशय के पास सी0डब्ल्यू0आर0 का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 07–09–2013 द्वारा अनुरोध किया गया है। फिरोजाबाद नगरीय पेयजल योजना का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें गंगा कैनाल के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जानी है। इस योजना की लागत रु0 43281.56 लाख निर्धारित की गयी हैं, जिसके सापेक्ष रु0 25.0 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। प्रश्नगत परियोजना में गणेश नगर में 430 किलोलीटर सी0डब्ल्यू0आर0 बनाये जाने का कार्य भी सम्मिलित है। कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम द्वारा उक्त परियोजना का कार्य कराये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में गोमती नदी की सफाई सम्बन्धी कार्य योजना तथा उस पर हुए व्यय का विवरण की मांग

52–श्री नदीम जावेद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में गोमती नदी की सफाई की कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त कार्य योजना क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जौनपुर में उक्त नदी की सफाई में अभी तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ? क्या सरकार उसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद जौनपुर में गोमती नदी में गिरने वाले नालों के गंदे पानी को रोकने हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित एन0जी0आर0बी0ए0 के अन्तर्गत सीवरेज योजना अनुमानित लागत रुपये 264.00 करोड़ का डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कोई पृथक से कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

53–श्री जय प्रकाश निषाद–

ख्राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त,

जनपद जालौन में आत्म सुरक्षा हेतु लम्बित शस्त्र लाइसेंसो को स्वीकार करने की मांग

54–श्री सन्तराम कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में वर्ष 2013–2014 एवं 2014–2015 में फरवरी, 2015 तक कितने शस्त्र प्रार्थना–पत्र लम्बित हैं व दो वर्षों में कितने शस्त्र स्वीकृत किये गये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वारिसानों के कितने प्रार्थना– पत्र लम्बित हैं ? क्या सरकार वारिसानों के लम्बित प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण कराते हुए आत्म सुरक्षा हेतु लम्बित प्रार्थना–पत्र वाले प्रार्थियों की सुरक्षा हेतु शस्त्र स्वीकृत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद जालौन में वर्ष 2013–14 के 2072 एवं वर्ष 2014–15(फरवरी तक) के 1002 शस्त्र प्रार्थना–पत्र लम्बित हैं। वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में कुल 763 शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये गये हैं।

जनपद जालौन में वारिसानों के 51 शस्त्र प्रार्थना–पत्र लम्बित हैं।

रिट याचिका संख्या–3268(एम/बी)/2012 जितेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक 07–10–2013, 25–11–2013 एवं 06–09–14 के अनुपालन में शस्त्र लाइसेंस की वास्तविक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विरासत के आधार पर, अपराध पीड़ित आवेदकों के प्रकरण पर एवं राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभावान खिलाड़ियों

(शूटर) के लाइसेंस निर्गत किये जाने सम्बन्धी प्रकरणों को छोड़कर नये शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये जाने पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक वर्तमान में भी प्रभावी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

55—श्री सन्तराम कुशवाहा—

ख03रे बुधवार के अता0प्र0सं0—186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद बस्ती में अन्य जनपदों की भांति पुलिस कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिये माडर्न विद्यालय स्थापित करने हेतु सरकार का विचार

56—श्री संजय प्रताप जयसवाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में अन्य जनपदों की भांति पुलिस कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए माडर्न विद्यालय स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जनपद बस्ती में पुलिस माडर्न स्कूल की स्थापना हेतु पुलिस अधीक्षक, बस्ती के आवास के सामने नजूल की लगभग 100000 वर्ग फिट रिक्त भूमि को आवंटित किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, बस्ती द्वारा जिलाधिकारी, बस्ती से अनुरोध किया गया है। भूमि अभी आवंटित नहीं हुई है। भूमि आवंटित होने के उपरान्त पुलिस माडर्न विद्यालय स्थापित किये जाने पर विचार किया जायेगा।

57—डा0 धर्मपाल सिंह—

खविस्तीर्णता के आधार पर निरस्त,

राज्य कर्मचारियों एवं गैर सरकारी शिक्षकों की भांति स्थानीय निकाय कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने की दशा में उनकी पेंशन उपादान आदि को देने हेतु समय—सीमा तय करने तथा/अव्यवस्था को दूर करने हेतु आदेश की मांग

58—डा0 धर्मपाल सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों एवं गैर सरकारी शिक्षकों की भांति स्थानीय निकाय कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने की दशा में उनकी पेंशन, उपादान, पारिवारिक पेंशन एवं सामूहिक बीमा के दावे के सम्प्रेषण हेतु कोई समयसारिणी/रोस्टर शासन द्वारा निर्धारित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त अव्यवस्था को दूर करने के लिए कोई ठोस कार्यवाई करके दिशा—निर्देश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1981 के नियम—13 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका (अकेन्द्रीयित) सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली, 1984 के नियम—13 के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की पेंशन, उपादान एवं पारिवारिक पेंशन के दावे के सम्प्रेषण हेतु समय—सीमा निर्धारित है।

सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सामूहिक बीमा के दावे सम्बन्धित निकायों द्वारा सीधे भारतीय जीवन बीमा निगम को सम्प्रेषित किये जाते है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

आगरा के सिकन्दरा की गुरूतेग बहादुर कालोनी की आन्तरिक सड़कें एवं कमलानगर मऊ में कालिन्दीपुरम् क्षेत्र की राधा विहार कालोनी के बड़ा पार्क में बाउण्ड्रीवाल व पैदल पथ का निर्माण कराया जाना

59–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के सिकन्दरा की गुरू तेग बहादुर कालोनी की आंतरिक सड़कें एवं कमलानगर मऊ में कालिन्दीपुरम क्षेत्र की राधा विहार कालोनी के बड़ा पार्क में बाउण्ड्रीवाल व पैदल पथ विगत कई वर्षों से जर्जर व टूटी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क का सौन्दर्यीकरण कर पैदल पथ तथा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

कालिन्दीपुरम् मऊ रोड की आन्तरिक सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। सिकन्दरा की गुरू तेग बहादुर कालोनी की आन्तरिक सड़कें आवागमन हेतु सुगम बनी हुई हैं। एल0आई0जी0 नं0–1 के सामने 10 मीटर रोड क्षतिग्रस्त है। राधा विहार कालोनी का बड़ा पार्क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

कालिन्दीपुरम् मऊ रोड तक की सड़क का हाटमिक्स से निर्माण कार्य हेतु एवं राधा विहार कालोनी के बड़े पार्क की बाउण्ड्रीवाल, फुटपाथ, रंगाई–पुताई एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य हेतु आगणन तैयार कराये गये हैं। उक्त कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

गुरू तेग बहादुर कालोनी में एल0आई0जी0–1 के सामने 10 मीटर क्षतिग्रस्त सडक पर पैच मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कानून–व्यवस्था की गम्भीर स्थिति को सुधारने के लिये स्थाई रूप से योग्य पुलिस महानिदेशक की तैनाती पर सरकार की व्यवस्था की जानकारी

60–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 03 वर्ष में प्रदेश में 07 पुलिस महानिदेशक बदल गये तथा वर्तमान में 01–01 माह के लिए पुलिस महानिदेशक बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या प्रदेश में कानून–व्यवस्था की गम्भीर स्थिति को सुधारने के

लिए स्थायी रूप से किसी योग्य पुलिस महानिदेशक की तैनाती पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

दिनांक 15 मार्च, 2012 से अब तक 05 पुलिस महानिदेशक स्थानान्तरित/तैनात किये गये हैं। भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के पुलिस महानिदेशक (विभागाध्यक्ष) के पद पर श्रेष्ठता के क्रम में उत्कृष्ट सेवाओं के आधार पर गठित समिति द्वारा विचार किया जाता है तथा तद्नुसार अधिकारियों की तैनाती की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट में पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने के उपरान्त पानी की सप्लाई न आने विषयक–पत्र, कृत कार्यवाई की जानकारी

61–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में वर्ष 2009–10 में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम स्थाई निर्माण खण्ड कर्वी द्वारा पेयजल योजनान्तर्गत पम्प निर्माण एवं पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने के बाद भी पेयजल की सप्लाई न करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक 298 दिनांक 28–10–2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नकर्त्ता मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 28–10–2013 में जनपद चित्रकूट में वर्ष 2009–10 में पेयजल योजनान्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायत व मजरों में पाइप लाइन एवं पम्प हाउस का कार्य पूर्ण हो जाने के बावजूद भी पेयजल की सप्लाई न किये जाने का उल्लेख किया गया था।

जनपद चित्रकूट के मजरा भिटरिया में पी0वी0सी0 पाइप लाइन के ऊपर सी0सी0 रोड निर्मित हो जाने से विभिन्न स्थलों पर पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण जलापूर्ति बाधित है। सी0सी0 वाले रास्ते पर जी0आई0 पाइप बिछाने के लिये प्राक्कलन विरचित किया जा रहा है।

ग्राम सुरौधा के मजरा सुरजी पुरवा मटियारा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत आच्छादित है तथा इस मजरे में राष्ट्रीय राजमार्ग–76 के किनारे स्थित पाइप लाइन दूरभाष केबिल बिछाये जाने के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसके कारण जलापूर्ति बाधित है। वर्तमान में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसके पूर्ण होते ही उक्त क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को ठीक कराकर जलापूर्ति पुनः चालू की जा सकेगी।

कोलमजरा ग्राम में जल संस्थान चित्रकूट द्वारा पेयजल आपूर्ति संचालित की जा रही है। गुईया खुर्द ग्राम पेयजल योजना में जलापूर्ति की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट धाम मण्डल में कराये गये कार्यों में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्यवाई की जानकारी

62—श्री चन्द्रभान सिंह पटेल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक 302 दिनांक 11—11—2013 जो जनपद चित्रकूट में कार्यवाहक अधिशासी अभियन्ता द्वारा जल संस्थान चित्रकूट धाम मण्डल में कराये गये कार्यों में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां।

प्रश्न में उल्लिखित पत्रांक—302 दिनांक 11—11—2013 शासन के पत्र संख्या—104 एम0एस0/9—3—13—147सीएम/13, दिनांक 02—12—2013 द्वारा आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा को भेजते हुए शिकायती—पत्र में उल्लिखित शिकायतों की किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराने के निर्देश दिये गये। तद्क्रम में आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा द्वारा शिकायती—पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर महाप्रबन्धक, चित्रकूटधाम मण्डल, जल संस्थान, बांदा से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या के अनुसार शिकायती—पत्र दिनांक 11—11—2013 में अंकित आरोप सही नहीं पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला लखनऊ के अन्तर्गत रायबरेली रोड स्थित संस्कृति एल्डिको उद्यान—2 में आवासित अध्यासियों द्वारा कालोनी की सड़क व पट्टी का निर्माण तथा अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाई

63—डा0 रमेश चन्द बिन्द—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला—लखनऊ के अन्तर्गत रायबरेली रोड स्थित संस्कृति एल्डिको उद्यान—2 में आवासित अध्यासियों द्वारा कालोनी की सड़क की पटरी तथा दोनों तरफ की नाली को पाटकर पक्का चबूतरा बना लिया गया है, जिससे उक्त कालोनी में नाली की सफाई ठीक ढंग से नहीं, हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त कालोनी में किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

कतिपय भवन स्वामियों द्वारा रैम्प आदि का निर्माण कराया गया है। जिससे जल निकासी सुचारु रूप से नहीं हो पाती।

अतिक्रमित भाग को चिन्हित कर लिया गया है। पुलिस बल के सहयोग से अवैध अतिक्रमण हटाया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रविन्द्र किशोर भारती उ0प्र0 पुलिस आरक्षी जनपद सीतापुर की सेवाकाल में दिनांक 3–10–2013 को ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु के उपरान्त मृतक आश्रित को नौकरी देने तथा देयकों का भुगतान

64–डा0 रमेश चन्द बिन्द–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रविन्द्र किशोर भारती (पी0एन0ओ0नं0–112666747) उ0प्र0 पुलिस जनपद–सीतापुर की मृत्यु दिनांक 03–10–2013 को ट्रेन दुर्घटना में हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या मृतक के (सेवा अभिलेख में अंकित) एक मात्र वारिसान पत्नी श्रीमती गीता भारती को मृतक आश्रित कोटे में सेवायोजित कर समस्त बकाया देयकों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। जनपद सीतापुर में नियुक्त आरक्षी रविन्द्र किशोर भारती, जो अवकाश पर अपने घर गये थे, वापस आते समय रौजा स्टेशन पर ट्रेन दुर्घटना में दिनांक 03–10–2013 को उनकी मृत्यु हो गयी थी।

कार्मिक की मृत्यु के पश्चात् श्रीमती गीता निगम द्वारा पत्नी के रूप में मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन हेतु प्रार्थना–पत्र दिया गया जिस पर सेवायोजन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सेवायोजन हेतु चरित्र सत्यापन प्रपत्र पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को प्रेषित किया गया था। थाना कोतवाली शहर बिजनौर की चरित्र सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 30–07–2014 में दर्शाया गया कि आवेदिका का उसके निवास स्थान पर निवास न करने तथा आरक्षी के पिता हरि सिंह भारती द्वारा यह शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसके लड़के मृतक रविन्द्र किशोर भारती की शादी श्रीमती गीता पुत्री दया राम सिंह निवासी 16/19 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एन0पी0एल0 कालोनी न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली के साथ दिनांक 12–12–2009 को हुई थी। श्रीमती गीता निगम, उम्र 39 वर्ष ग्राम रोनी पोस्ट विलासपुर जनपद गौतमबुद्धनगर (ग्रेटर नोएडा) से नहीं हुई थी। इस सम्बन्ध में एक वाद न्यायालय सिविल जज सी0डी0 बिजनौर के यहां वाद संख्या–132/2014 श्रीमती गीता निगम बनाम श्री हरि सिंह भारती आदि उत्तराधिकार निर्धारण के सम्बन्ध में विचाराधीन न्यायालय है।

मृतक के पिता हरि सिंह ने शपथ–पत्र में यह भी अंकित किया है कि जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक प्रकरण में पुलिस द्वारा कोई निर्णय न किया जाये।

उत्तराधिकार निर्धारण हेतु प्रकरण माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डी0 बिजनौर के यहां विचाराधीन होने के कारण प्रकरण में प्रचलित कार्यवाई लम्बित है।

आगरा नगर में लायर्स कालोनी के निकट गणेश नगर की सड़क के निर्माण का मामला

65–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में लायर्स कालोनी के निकट गणेश नगर की सड़क जर्जर होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का सी0सी0 निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सड़क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। प्रश्नगत लायर्स कालोनी के निकट गणेशनगर की सड़क निर्माण हेतु हरिपर्वत जोन–1 कक्ष संख्या–20 राकेश यादव के मकान से नन्द किशोर के मकान तक नाली एवं साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग फर्श निर्माण कार्य एवं कमलेश भारद्वाज के मकान से नन्द किशोर बघेल के मकान तक नाली व हाटमिक्स प्लान्ट से सड़क सुधार कार्य का आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर के कमलानगर वृज विहार फेस–2 में पार्क की बाउण्ड्रीवाल, पैदल पथ जर्जर व टूटे मार्ग आदि का तथा समरसेविल लगाने की व्यवस्था कराया जाना

66–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर के कमलानगर वृज विहार फेस–2 में पार्क की बाउण्ड्रीवाल पैदल पथ जर्जर व टूटे होने के कारण नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क का सौन्दर्यीकरण कराते हुए समरसेविल लगाने, बाउण्ड्रीवाल व पैदल पथ का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त प्रश्नगत पार्क के सौन्दर्यीकरण, फुटपाथ एवं बाउन्ड्रीवाल के निर्माण का आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में एन0आर0जी0वी0ए0 योजनान्तर्गत शौचालय एवं स्नानागार आदि के बनाने में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में जांच का आदेश तथा दोषी पाये गये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाई

67—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में एन0आर0जी0वी0ए0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011—12 व 2012—13 में सुलभ शौचालय एवं स्नानागार आदि के बनाये जाने में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में वर्ष 2013 में जांच का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो जांच में कौन—कौन से लोग दोषी पाये गये तथा उन पर क्या कार्यवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच हेतु समिति गठित की गई थी जिसमें नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद, परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्डडी0एस0 एवं मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, इलाहाबाद नामित किये गये थे। उक्त समिति द्वारा एन0आर0जी0वी0ए0 योजनान्तर्गत समस्त निर्मित शौचालयों एवं स्नानागार सम्बन्धी कार्यों की जांच की गयी जिसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गयी। शौचालयों में प्रयुक्त सामग्रियों की जांच इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड रूरल टेक्नालॉजी, इलाहाबाद से करायी गई है, जिसमें प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता विशिष्टियों के अनुरूप पायी गयी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के महानगरों में नगर निगम द्वारा विभिन्न मदों में कराये गये कार्यों के शिलापट्टों पर नाम डाले जाने की नीति की जानकारी

68—श्री सतीश महाना—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में नगर निगम द्वारा विभिन्न मदों में जो कार्य किये जाते हैं उसके शिलापट्ट लगाये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि शिलापट्टों पर नाम डाले जाने की क्या नीति है ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां।

शिलापट्ट पर नाम डाले जाने की कोई नीति नहीं है। नगर निगम निधि से कराये जाने वाले कार्यों में सामान्यतः महापौर तथा क्षेत्रीय पार्षद के नाम के शिलापट्ट लगाये जाने की परम्परा है। सांसद निधि एवं विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्यों में क्रमशः मा0 सांसद, मा0 विधायक के नाम शिलापट्ट लगाये जाने की परम्परा है।

69—श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह—

ख्राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त,

बरेली महानगर में बढ़ती हुई चोरियों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र पर की गई कार्यवाई की जानकारी

70—डॉ0 अरूण कुमार—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली महानगर में बढ़ती हुई चोरियों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0—ख—5/474573 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली को

दिनांक 21–12–2014 को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाई की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जनपद बरेली महानगर में बढ़ती हुई चोरियों के सम्बन्ध में पुलिस पिकेट एवं चीता मोबाइल से लगातार गश्त करायी जा रही है एवं आयोजित गोष्ठी में समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त सम्बन्ध में अंकुश लगाने एवं ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में आने पर कठोर कार्यवाई किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

जनपद आगरा में कैलाश विहार, नेहरू नगर एवं किशोरपुरा में गनी उस्मानी के भवन सं0–1071 से मोड़ घड़ी भदौरिया तक आन्तरिक सड़कों का निर्माण कराया जाना

71–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में कैलाश विहार, नेहरू नगर एवं किशोरपुरा में गनी उस्मानी के भवन सं0 1071 से मोड़ घड़ी भदौरिया तक की आन्तरिक सड़कें विगत कई वर्षों से जर्जर हैं ? क्या सरकार उक्त सी0सी0 सड़कों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

नगर निगम आगरा द्वारा कैलाश विहार में हरी पर्वत जोन–1 में सेंट कोनार्ड के पीछे निर्भय नगर कैलाश विहार में ओ0पी0 ज्वैलर्स से आई0ए0एस0 कोचिंग से होकर दरी फैक्ट्री तक हाटमिक्स से सड़क एवं साइड पटरी का निर्माण कार्य, हरीपर्वत जोन–1 कैलाश विहार में कोठी नं0–33 से मधुरिमा शर्मा से होकर सरदार जी की फैक्ट्री तक हाटमिक्स सड़क व साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग फर्श का कार्य तथा हरीपर्वत जोन–1 कक्ष संख्या–67 निर्भय नगर मुख्य मार्ग पर हाटमिक्स प्लांट से पैच मरम्मत के कार्य कराये गये हैं।

प्रश्नगत कैलाश विहार की अवशेष आन्तरिक सड़कों का हाटमिक्स प्लांट से सुधार एवं साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग टाइल्स लगाने के कार्य हेतु नेहरू नगर की सड़क निर्माण कार्य हेतु हरीपर्वत वार्ड कक्ष संख्या–64 नेहरू नगर मकान नं0–116ए से लेकर मुख्य मार्ग तक हाटमिक्स प्लांट द्वारा सड़क निर्माण कार्य हेतु तथा किशोरपुरा में गनी उस्मानी के मकान से श्रीमती मुन्नी बेगम के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग फर्श निर्माण हेतु आगणन तैयार कराये गये हैं। उक्त कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराये जाने सम्भव हो सकेंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के थाना रुदौली, मवई, पटरंगा, सी0ओ0 सर्किल रुदौली अन्तर्गत बढ़ते अपराधों को रोकने हेतु बाबा बाजार में नये थाने की स्थापना का प्रस्ताव

72–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के थाना रुदौली मवई, पटरंगा, सी0ओ0 सर्किल रूदौली अन्तर्गत बढ़ते अपराधों को रोकने हेतु बाबा बाजार में नये थाने की स्थापना का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त थाने की स्थापना कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद के हिमायूंपुर क्षेत्र में स्थित ग्रीन ऐस्टैंट कालोनी के पार्क में स्थापित दो अवर जलाशय (पानी की टंकी) की स्थापना हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्रवाई की जानकारी

73–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के हिमायूंपुर क्षेत्र में स्थित ग्रीन ऐस्टैंट कालोनी के पार्क में स्थापित दो अवर जलाशय (पानी की टंकी) पर सी0डब्लू0आर0 की स्थापना कराये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क–5 नं0–23386 दिनांक 07–09–2013 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

ग्रीन ऐस्टैंट कालोनी के पार्क में सी0डब्लू0आर0 का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 07–09–2013 द्वारा अनुरोध किया गया है। फिरोजाबाद नगरीय पेयजल योजना का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें गंगा कैनाल के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जानी है। इस योजना की लागत रु0 43281.56 लाख निर्धारित की गयी है, जिसके सापेक्ष रु0 25.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। प्रश्नगत परियोजना में ग्रीन ऐस्टैंट कालोनी, हिमायूंपुर में स्थित अवर जलाशय (पानी की टंकी) के पास 560 कि0ली0सी0डब्ल्यू0आर0 बनाये जाने का कार्य भी सम्मिलित है। कार्यदायी संस्था–उ0प्र0 जल निगम द्वारा उक्त परियोजना का कार्य कराये जाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के वर्तमान सदस्यों व भूतपूर्व सदस्यों के वेतन/पेंशन व अन्य सुविधाएं बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए बढ़ाये जाने की मांग

74–श्री संजय कपूर–

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के वर्तमान सदस्यों व भूतपूर्व सदस्यों के वेतन/पेंशन व अन्य सुविधाएं बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए सरकार बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

विधान सभा के मा0 सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों के वेतन/पेंशन व अन्य सुविधाओं को बढ़ती हुई महंगाई के दृष्टिगत पुनरीक्षित किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नये शस्त्र लाइसेंस जारी करने पर रोक लगी होने के बावजूद शस्त्र लाइसेंस दिलाने का नया आदेश पारित करने की मांग

75–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये शस्त्र लाइसेंस जारी करना प्रतिबन्धित है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में निजी सुरक्षा हेतु जिन लोगों को शस्त्र लाइसेंस की आवश्यकता है, उनको शस्त्र लाइसेन्स दिलवाने के लिए कोई नया आदेश पारित करेगी ? यदि हां, तो कब तब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

आयुध अधिनियम, 1959 तथा शासन से निर्गत विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत शस्त्र लाइसेंस दिये जाने की नीति है, जो सम्पूर्ण प्रदेश में एक समान रूप से लागू होती है। रिट याचिका संख्या–3268 (एम0/बी0)/2012 जितेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक 07–10–2013, 25–11–2013 एवं 06–09–2014 के अनुपालन में शस्त्र लाइसेंस की वास्तविक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये विरासत के आधार पर, अपराध पीड़ित आवेदकों के प्रकरण पर एवं राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभावान खिलाड़ी (शूटर) के लाइसेंस निर्गत किये जाने सम्बन्धी प्रकरणों को छोड़कर नये शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये जाने पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक वर्तमान में भी प्रभावी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लोअर जुडीशियरी में मुंसिफ तथा दीवानी न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पदों को भरने हेतु सरकार की नीति

76–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लोअर जुडीशियरी में मुंसिफ तथा दीवानी न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पदों में से कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने हेतु कोई नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, मैंने कई बार आपकी अनुमति से प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मान्यवर, मुझे एक बार फिर इसमें कोई षडयंत्र लग रहा है, मैं इस शब्द को इस्तेमाल करने के लिए विवश हूं,

श्री अध्यक्ष–

ऐसा नहीं है, इसमें कोई षडयंत्र नहीं है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, पहले सुन तो लीजिए, मैं आपको प्रमाण सहित बता रहा हूं, आज का प्रश्न संख्या–01 जो लगा, यह प्रदेश में दंगों के सन्दर्भ में था, तारांकित प्रश्न संख्या–01 मान्यवर, यह 09–02–2015 को लगा, इसमें तिथि देख लीजिए।

मान्यवर, यही प्रश्न मेरे द्वारा 06–01–2015 को लगा जो 5वें सोमवार को निर्धारित है उसका मुझे ये मिला और जब 5वां सोमवार आयेगा तो कहेंगे कि उत्तरित मान लिया गया। मान्यवर, उस समय कह दिया जायेगा कि उत्तरित मान लिया गया और मेरा प्रश्न दो महीने पहले का लगा हुआ है। जो प्रश्न आया मेरी उसके ऊपर आपत्ति नहीं है लेकिन मेरा प्रश्न जो दो महीने पहले लगा, वह 5वें सोमवार को लगा और जब उसके उत्तर का समय आयेगा तो कह दिया जायेगा कि इस तारीख को इस प्रश्न के नाते से उत्तरित। मान्यवर, मैं तो कहीं का नहीं रहा। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात को मैंने फिर उस दिन लिखित रूप में दिया था और मैं फिर आपके पास लिखित रूप में भिजवा दूंगा। मान्यवर, इसका संज्ञान लेकर, इसकी जांच कराकर कृपापूर्वक इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

मा0 महाना जी, जो हमारे सेक्रेट्री साहब हैं, मैंने इनसे कहा कि यह फाइल निकलवा के, आपको बैठा के उसका निराकरण करेंगे।

श्री रविन्द्र भड़ाना–

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने पश्चिम में हाईकोर्ट बेंच के लिये प्रश्न लगाया था। मेरे प्रश्न को दूसरे मा0 सदस्यों के साथ जोड़ करके उसका विषय ही डायवर्ट कर दिया और एक बेंच का स्थान अपने आपसे ही इंगित करके और उस प्रश्न के साथ मेरा प्रश्न जोड़ दिया तो मा0 अध्यक्ष जी, मेरा आपसे कृपापूर्वक निवेदन है कि मा0 सदस्यों के प्रश्न, उनकी जो मूलभूत चीजें हैं उससे अलग इंगित करके उसमें न जोड़ा जाये। हमारा हाईकोर्ट के लिये कि एक हाईकोर्ट की बेंच पश्चिम में हो, कहां हो यह विषय हमने नहीं लिखा था लेकिन

वह आगरा में, वह अपने आप स्वतः सरकार उसमें रिपोर्ट में लिख रही है तो ये चीजें कृपया आप दिखवा लें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मेरा तारांकित 5वां प्रश्न था कि जस्टिस ऐट डोर के लिये तहसीलों में जिन न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिये थी। मान्यवर, उसमें सरकार ने जवाब दिया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। सरकार के पास यह सूचना नहीं है कि तहसीलों में कितनी अदालतें हैं, कितनी लोक अदालतें कायम हो गयी हैं, लीगल सर्विस अथारिटी ऐक्ट, 1987 के अन्तर्गत कितनी अदालतें बनी हैं ? मान्यवर, यह सूचना नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इसकी सूचना जल्दी दिलवा दें।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, आप हम लोगों को प्रश्न पूछने का अवसर देते हैं तो मेरा आपसे केवल यह अनुरोध है कि अभी जो अन्तिम प्रश्न चल रहा था तो अभी 3 मिनट का समय बाकी था।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, 3 मिनट का समय बाकी नहीं था। अब मेरे ऊपर आरोप मत लगाओ। मेरे सामने एक घड़ी लगी है, आरोप क्यों लगा रहे हैं ?

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने जब कहा कि प्रश्नों का समय समाप्त तो सुई 2 मिनट, 3 मिनट पीछे थी।

श्री अध्यक्ष–

हमारे सामने ये घड़ी है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, यहां दो–दो घड़ियां लगी हैं। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र से मैं एक सुझाव देना चाह रहा था और वह बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था। हमारे यहां चूंकि सफाई का काम हो रहा है। मेरे यहां से राम गंगा और गंगा नदी निकली हैं, वहां पर सफाई का काम चल रहा है। मैं वहां गया भी था तो मैं यह सरकार के संज्ञान में लाना चाहता था कि हमारे क्षेत्र से राम गंगा और गंगा नदी दोनों निकली हुयी हैं। एक डब्लू0डब्लू0एफ0 संस्था है और हमारे यहां शाहजहांपुर की एक एन0जी0ओ0 है वे दोनों मिलकर वहां पर 8 गांवों में कार्य कर रहे हैं तो मैं सरकार से चाहूंगा क्योंकि उनका कार्य करने का तरीका बड़ा अच्छा है और हमारे यहां विनोबा भावे सेवा आश्रम और डब्लू0डब्लू0एफ0 संस्था के साथ मिल करके या उनको अपने साथ शामिल करके इस अभियान में लगायें क्योंकि वे अच्छा कार्य कर रहे हैं। ख्ग ग ग,

श्री अध्यक्ष–

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आप सवाल लगाइये न।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य कुशवाहा जी ने अनजाने में एक बात कही है जो प्रकारान्तर से पीठ पर आक्षेप की तरह से है, उसको आप देखकर निकलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, निकलवा देंगे। अब उनको मैंने कह दिया है। चूंकि अब वह अपना सवाल नहीं उठा पाये हैं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा आपकी पीठ पर कोई आक्षेप नहीं है और मैं ऐसा कर भी नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया मौर्य जी, ये प्रश्नों पर व्यवस्था का सवाल था। आप अपने क्षेत्र की समस्या कह रहे हो तो आपके पास बहुत मौके हैं। तमाम चर्चायें लगती हैं। इस मामले में नियमों में बहुत व्यवस्था है उसमें आप इस मामले को उठा सकते हैं। यहां उठाने का कोई मतलब नहीं है।

ख12.25, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 16–03–2015 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गईं।

पहली सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के कतिपय क्षेत्रों में छलका निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री राजबली जैसल की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव में दिनांक 27–02–2015 को हुई ओला–वृष्टि के पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय की जनपद इलाहाबाद के जमुनापार क्षेत्र के कतिपय इलाकों में बुन्देलखण्ड की भॉति विकास कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथीं सूचना श्री राधेश्याम जी की जनपद अमेठी में स्थापित पोस्टमार्टम हाउस को प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में, पांचवी सूचना श्री संजय कपूर जी की जनपद रामपुर की टाउन एरिया कमेटी में चिकित्सीय सुविधायें बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, छठीं सूचना श्री प्रदीप माथुर जी की जनपद मथुरा में मन्दिरों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर जी की मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शहीद रामचन्द्र इंटर कालेज, देवरिया के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद जी की जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड–ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम बेल्तुआ से

नौरंगपुर पुल तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, नवीं सूचना श्री गजेन्द्र सिंह जी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूप शहर के किसान ज्ञानेन्द्र पुत्र धर्मवीर के लगभग 15 पशुओं की हुई असामयिक मृत्यु का मुआवजा दिलाये जाने एवं गांव में फैली हुई बीमारी की रोकथाम हेतु समुचित उपाय कराये जाने के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना श्री चन्द्रभान सिंह पटेल जी की प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् में नियुक्त अन्तर्जनपदीय स्थानांतरित शिक्षकों की पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं सूचना श्री संजय प्रताप जयसवाल जी की जनपद बस्ती में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, बारहवीं सूचना श्री मनीष असीजा जी की फिरोजाबाद नगर में ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में, तेरहवीं सूचना श्री सतीश महाना जी की कानपुर महानगर के लोहिया ग्राम पूरनपुर की क्षतिग्रस्त गलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, चौदहवीं सूचना श्री सुरेश बंसल जी की विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के वार्ड सं0–6 की जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, पन्द्रहवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान जी की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई– श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सुरेश राणा, श्री सुदेश शर्मा, श्री उमेश पाण्डेय, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री काली चरण सुमन तथा श्री दलवीर सिंह।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गई)

जनपद गाजीपुर के कतिपय क्षेत्रों में छलका का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूं।

हमारे विधान सभा क्षेत्र 374, सैदपुर जनपद गाजीपुर की सबसे बड़ी समस्या विधान सभा से निकली हुयी नहर के इस पार उस पार किसानों को जाकर खेती करना है। हमारे विधान सभा में बहुत विकट समस्या यह है कि किसानों की कुछ जमीन नहर के इस पार तो कुछ उस पार है और अपने खेत को किसान जोताई व बोने के लिये एक–एक कि0मी0 दूर जाकर घूमकर अपने खेतों में आना पड़ता है। जोताई को जो माध्यम से किसानों का बैल या ट्रैक्टर उसे ले जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा जब हम सदस्य अपने क्षेत्र में जाते हैं तो किसान अपने खेत की पीड़ा को बार–बार दोहराया करते हैं। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में किसान भारी मात्रा में खेती करते हैं। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आपके माध्यम से सरकार से निम्न जगहों पर छलका बनाने की मांग करता हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कादर ग्राम सभा के सामने धुवार्जुनताल में दारून तलीसा के सामने तेलयानी बहदियां गोरखा के सामने जमीन संदल और महमूदपुर पाली मन्दिर की दक्षिण तरफ।,

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव में दिनांक 27–02–2015 को हुई ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजबली जैसल–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कोरांव के विकास खण्ड कोरांव में दिनांक 27–02–2015 को सायं 6 बजे से 8 बजे के मध्य अत्यधिक तेज बारिश आंधी, तूफान के साथ ओलावृष्टि होने से विधान सभा क्षेत्र के लगभग 25 राजस्व ग्रामों के किसानों की फसलें अत्यधिक रूप से नष्ट हो गये जिससे किसानों में काफी निराशा आ गयी है। ओलावृष्टि एवं बारिश निम्नांकित ग्रामों चिरांव, चन्दापुर, अमिलियां मानपुर, भवानीपुर, बड़ोखर, हड़िया हरदौल, छापर, पैतिहां, बलापुर, गढ़ियामुरलीपुर, पियरी, संसारपुर, बदऊवां, नेवढ़ियापार, अल्हवां बंशीपुर आदि ग्रामों के किसानों के गेहूं की फसल अरहर, चना, सरसों एवं आलू की खेती नष्ट हो जाने से उक्त ग्रामों के किसानों में सरकार के प्रति काफी आक्रोश एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से किसानों के फसल नष्ट हो जाने की जांच एवं नुकसान का आंकलन सही मायने से कराकर मुआवजा उपलब्ध कराये जाने एवं कार्रवाई /वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद इलाहाबाद के जमुनापार क्षेत्र के कतिपय इलाकों में बुन्देलखण्ड की भांति विकास कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय–

ख्मान्यवर, जनपद इलाहाबाद के जमुनापार क्षेत्र की भौगोलिक स्थित बुन्देलखण्ड की तरह है और बुन्देलखण्ड, चित्रकूट जिले से मिला हुआ है और विन्ध्यांचल पहाड़ के नीचे स्थित है और मध्य प्रदेश का जनपद रीवा भी आपस में मिला हुआ है। कुछ योजनाओं में बुन्देलखण्ड जैसी सुविधायें प्राप्त है।

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। जमुनापार के निम्नलिखित ब्लाकों को बुन्देलखण्ड में सम्मिलित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ब्लाकों का नाम निम्न है :–

(1) मेंधा (2) माण्डा (3) उस्वा (4) कोरांव (5) करछना (6) कौंधियारा (7) जसरा (8) शंकरगढ़।,

जनपद अमेठी में स्थापित पोस्टमार्टम हाउस को प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राधेश्याम–

ख्मान्यवर, लोकमहत्व एवं जनहित के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि जनपद मुख्यालय अमेठी में पोस्टमार्टम हाउस (चीरघर) का भवन बनकर तैयार है। कोई अप्रिय दुर्घटना/घटना में मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के लिये पीड़ित परिवार को जनपद सुल्तानपुर अथवा रायबरेली जाना पड़ता है जिसमें उनको आर्थिक कठिनाइयों के साथ ही साथ काफी असुविधा होती है। जबकि जनपद मुख्यालय अमेठी में पोस्टमार्टम भवन तैयार है, उसे तत्काल स्वास्थ्य विभाग को हस्तानान्तरित कर उसमें आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने तथा पोस्टमार्टम के लिये डाक्टरों की तैनाती कर उक्त पोस्टमार्टम हाउस को चालू किया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद मुख्यालय अमेठी में स्थापित पोस्टमार्टम हाउस को चालू किये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में चिकित्सीय सुविधायें बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में चिकित्सा सुविधा न मिलने से हो रही मौतों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। यह टाउन एरिया अल्पसंख्यक बाहुल्य व बहुत ही पिछड़ी टाउन एरिया है। इसकी आबादी लगभग पचास हजार है तथा इसके आस–पास के पचास ग्रामों का जुड़ाव भी इससे रहता है। यहां पर एक पी0एच0सी0 है जिस पर सिर्फ एक डाक्टर है और वह मरीजों को देख नहीं पाते हैं तथा यहां पर कोई प्राइवेट अस्पताल या अच्छा डाक्टर नहीं है जिसके कारण मरीजों को रामपुर तक पहुंचने में एक घण्टे से अधिक का समय लगता है जिससे मरीजों को तुरन्त चिकित्सा न मिलने के कारण मरीज की मृत्यु हो जाती है। यहां पर प्रत्येक दिन ऐसा होता रहता है यहां पर 30 बेड का अस्पताल व चिकित्सा सुविधा जैसे महिला डाक्टर एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड, स्टाफ आदि की नियुक्ति की मांग काफी लम्बे समय से चली आ रही है मगर सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जा रहा है। जिससे मरीजों की मौत से रोज सड़कों पर जाम लगता रहता है क्षेत्रीय जनता में भारी रोष व नाराजगी व्याप्त है। यदि अविलम्ब इस सम्बन्ध में कोई सार्थक पहल नहीं की गई तो कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

मैं इस अविलम्बनीय व लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्रवाई की मांग करता हूं।,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मथुरा के मन्दिरों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर–

ख्मान्यवर, मथुरा जनपद में स्थित प्रसिद्ध मन्दिरों क्रमशः 1–वृन्दावन स्थित श्री बांके बिहारी मन्दिर, राधा बल्लभ मन्दिर, राधारमन मन्दिर, कात्यायनी मन्दिर, इस्कान मन्दिर, 2–मथुरा में जन्मभूमि के अतिरिक्त द्वारिकाधीश मन्दिर, विश्राम घाट, 3–बरसाना में राधा रानी मन्दिर, 4–बल्देव में श्री बलराम/दाऊ जी का मन्दिर, 5–महावन में चिंताहरण महादेव का मन्दिर, 6–गोवर्धन में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग, दान घाटी मन्दिर, मानसी गंगा आदि प्रमुख ऐसे मन्दिर तथा स्थल है जहां देश–विदेश से लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन वर्षपर्यन्त लगा रहता है मथुरा में आतंकवादी धमकियों एवं सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा बार–बार शासन को एलर्ट करने के मद्देनजर इन प्रमुख मन्दिरों की स्थायी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान किये जाने की महती आवश्यकता है। इस प्रकरण को पूर्व में भी सदन में उठाया था जिसके उत्तर में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा उक्त मन्दिरों में सुरक्षा व्यवस्था प्रदान किये जाने का आश्वासन दिया गया था। किन्तु स्थायी सुरक्षा के संदर्भ में शासन द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इन मन्दिरों में देश एवं विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की जानमाल की सुरक्षा तथा आतंकवादियों की धमकियों को दृष्टिगत रखते हुए मथुरा जनपद के प्रमुख मन्दिरों में स्थायी रूप से आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान किया जाना जनहित एवं लोकहित में अति आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।,

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शहीद रामचन्द्र इण्टर कालेज, देवरिया के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

ख्महोदय, मैं आपका ध्यान लोक महत्व के एक अत्यन्त ज्वलन विषयक की तरफ ले जाना चाहता हूं। याचिका संख्या–39503/2011 मो0 असलम बनाम उ0 प्र0 सरकार व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19–07–2011 के अनुसार शहीद रामचन्द्र इण्टर कालेज बसन्तपुर पूसी देवरिया के परिचारक मो0 असलम को चतुर्थ, पंचम एवं छठे वेतनमान के बढ़े हुए धनराशि का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना की जा रही है।

प्रधानाचार्य द्वारा बकाया धनराशि प्रधानाचार्य के खाते में सी0ए0–90 में है कभी अनुदान न मिलने का बहाना कभी जी0पी0एफ0 में जमा की जा चुकी है का बहाना कभी एन0एस0सी0 ले ली गयी है जिसे मा0 असलम को नहीं दी गयी, सेवा पुस्तिका की सेवा समाप्ति का अंकन है पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। जिला विद्यालय निरीक्षक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

देवरिया के पत्रांक मा0–2/4285–89/ 2013–14 दिनांक 03 सितम्बर, 2013 में स्पष्ट अंकित है कि जिला विद्यालय देवरिया के आदेश दिनांक 30–04–1994 के पश्चात् मो0 असलम समस्त प्रकार की देयता के पात्र है मंहगाई भत्ता देयता बनती है वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया को निर्देशित किया जाता है कि श्री मो0 असलम के समस्त देयता का मूल वेतन पंजिका आदि से मिलान करके वांछित धनराशि का आगणन करके संस्था से भुगतान कराना सुनिश्चित करें। किन्तु न तो मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन हुआ और न ही जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेशों का मात्र बहाना बना–बनाकर प्रकरण को वर्षों से लम्बित रखा जा रहा है।

उक्त के पश्चात प्रताड़ना भी सम्बन्धित को दी जा रही है। इसे किसी प्रकार का कोई भी अवकाश नहीं दिया जा रहा है न ही आकस्मिक अवकाश न ही अर्जित अवकाश जिसका लिखित उदाहरण भी सम्बन्धित के पास है जिसमें अंकित है कि ''आपके आज के अवकाश प्रार्थना–पत्र पश्चात कोई अवकाश देय नहीं होगा भविष्य में यदि आपका कोई आवेदन–पत्र आयेगा तो विचार नहीं होगा हस्ताक्षर प्रधानाचार्य।'' इसके पश्चात् यदि सम्बन्धित ने कोई आकस्मिक अवकाश लिया तो वेतन काट लिया जाता है।

अतः इस प्रकरण पर मो0 असलम के साथ हो रहे अन्याय, मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना, जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया के आदेशों को दर किनार करने के प्रकरण पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश एवं पांचवें, छठे वेतन आयोग के संस्तुतियों के अनुसार डी0ए0, वेतनवृद्धि के साथ एरियर का भुगतान यथाशीघ्र मय ब्याज सहित कराने के लिये प्रकरण के निस्तारण हेतु इसे नियम–301 में उठाने हेतु आपकी स्वीकृति चाहता हूं।,

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम बेल्तुआ से नौरंगपुर पुल तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हू।

जिला–लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम बेल्तुआ से नौरंगपुर पुल तक की सड़क (ल0 लगभग 1.0 किमी0) लोक निर्माण विभाग द्वारा करायी गयी थी जो कि वर्तमान समय में अत्यधिक क्षतिग्रस्त अवस्था में है जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण जनता एवं राहगीरों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई/परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आये दिन क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों के साथ दुर्घटना होती रहती है। उक्त क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यालय द्वारा ;च्ळ 10540008/2014, पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/च्ळ 10540008/2014) आदेश भी दिये गये थे एवं क्षेत्रीय जनता ने उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण किये जाने हेतु कई बार

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्थानीय उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक शासन द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण हेतु कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक जनाक्रोश व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से जनहित में ग्राम बेल्तुआ से नौरंगपुर पुल तक की क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के किसान ज्ञानेन्द्र पुत्र धर्मवीर के लगभग 15 पशुओं की हुई असामयिक मृत्यु का मुआवजा दिलाये जाने एवं गांव में फैली हुई बीमारी की रोकथाम हेतु समुचित उपाय कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गजेन्द्र सिंह–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत ब्लाक–जहांगीराबाद के ग्राम शेखूपुर रोरा में एक गरीब किसान जोगेन्द्र पुत्र धर्मवीर सिंह के परिवार की अचानक पशुओं में आई बीमारी के चलते दिनांक 06–03–2015 से लेकर दिनांक 09–03–2015 तक आठ भैंसा, एक भैंसा व दो की मृत्यु हो गयी है जिससे उस गांव के अन्य किसानों की कई पशुओं के मरने के जानकारी हुई है। ऐसी स्थिति में जिस किसान जोगेन्द्र के 11 पशुओं की मौत से उसका परिवार जिन पशुओं को पालकर जीवन–यापन कर रहा था। आज वह परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है, उसने जो पशु कर्ज लेकर खरीदे थे, पशुओं के कर्ज को चुकाने की स्थिति में नहीं रहा है इन पशुओं की मौत से लगभग 10 लाख रुपये क्षति हुई है उक्त ग्राम में अन्य किसानों के पशुओं की मौत हुई है ऐसी स्थिति में उक्त किसानों की क्षतिग्रस्त के लिये इनको आर्थिक सहायता न मिलने से क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय लोगों में काफी जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से किसानों के मृत पशुओं की क्षतिपूर्ति के लिये इनको आर्थिक सहायता यथाशीघ्र दिलाये जाने की कार्रवाई /वक्तव्य की मांग करता हूं।,

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् में नियुक्त अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरित शिक्षकों की पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

ख्मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण विज्ञप्ति पत्रांक–बे0शि0प0/ 2825/45/2013–14, दिनांक 27–5–2013 के अनुसार प्रदेश भर में लगभग 44 हजार शिक्षक/ शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण हुआ। स्थानान्तरण से पूर्व दिनांक 17 जून, 2013 के समाचार–पत्र में सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद का

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बयान आया था कि अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के बाद बेसिकों की वरिष्ठता लैप्स नहीं होगी। अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के आदेश के बिन्दु 6 में अंकित है कि स्थानान्तरण चाहने वाले अध्यापकों का उनके द्वारा वांछित जनपद में केवल उसी स्थिति में स्थानान्तरण किया जायेगा जबकि उस जनपद से सम्बन्धित बैच के अध्यापक भी समान पद पर कार्यरत हों इसी स्थानान्तरण नियम के आधार पर सहायक अध्यापक पद से पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक पद पर कार्य कर रहे हजारों शिक्षकों की पदोन्नति कर पुनः सहायक अध्यापक पद पर गृह जनपद में स्थानान्तरित किया गया और तर्क दिया गया कि आपके गृह जनपद में आपके वर्ग बैच को पदोन्नति नहीं हुई है। उक्त प्रस्तर से स्पष्ट है कि अन्तर्जनपदीय शिक्षकों से की जानी है और तत्स्थानीय वर्ग बैच के शिक्षकों की सूची में ही नीचे अंकित किये जाने का प्राविधान है। प्रदेश में गतिमान पदोन्नति प्रक्रिया में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरित शिक्षकों को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। जिससे प्राइमरी शिक्षकों का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मेरा सदन के माध्यम से जनहित में बेसिक शिक्षा परिषद् में नियुक्त अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरित शिक्षकों को पदोन्नति प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बस्ती में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जयसवाल–

ख्महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रुधौली जनपद बस्ती में मण्डी समिति द्वारा विगत वर्ष 2002 से पहले कई सड़कों का निर्माण कराया गया था जो वर्तमान में मरम्मत के अभाव में अत्यन्त जर्जर एवं आवागमन लायक नहीं हर गयी है। आये दिन यातायात बाधित होता रहता है। यदि सड़कों को मरम्मत कराने में मण्डी समिति अपने को असमर्थ पा रहा है तो मण्डी समिति द्वारा निर्मित निम्न सड़कों को लोक निर्माण विभाग में स्थानान्तरित करके मरम्मत कार्य कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है :–1–रुधौली भानपुर मार्ग से भितेहरा तक दूरी 3 कि0मी0 निर्माण वर्ष 1994, 2–वोहरा तेलौरा मार्ग से मल्हवार तक दूरी 1.2 कि0मी0 निर्माण वर्ष 2002, 3–रुधौली बखिरा मार्ग से बिजहरडूहा तक दूरी 1.5 कि0मी0 निर्माण वर्ष 2002, 4–रुधौली बखिरा मार्ग से कर्माकला तक दूरी 3 कि0मी0 निर्माण वर्ष 2002, 5–मेंहदावल रुधौली मार्ग से कुड़ही तक दूरी 0.5 कि0मी0 निर्माण वर्ष 1997, 6–वघाडीहा से परसिया हर्रइया मिश्र तक दूरी 4 कि0मी0 निर्माण वर्ष 2002, 7–रुधौली डुमरियागंज मार्ग से थरौली तक दूरी 01 कि0मी0 निर्माण वर्ष 2002, 8–हनुमानगंज पैड़ी मार्ग से औराडीहा होते हुए मुड़बरा तक दूरी 01 कि0मी0 निर्माण वर्ष 2001, 9–बस्ती बांसी मार्ग से बहादुरपुर होते हुए मुड़बरा तक दूरी 01 कि0मी0 निर्माण वर्ष 2001, 10–बस्ती बांसी मार्ग पर घनघटा से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पैड़ी तक दूरी 2 कि0मी0 निर्माण वर्ष 2002, 11–कोहरा, तेलौरा, हनुमानगंज मार्ग तक दूरी 3.5 कि0मी0 निर्माण वर्ष 2001, उपरोक्त प्रकरण जनहित से जुड़ा होने के कारण अति लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।,

फिरोजाबाद नगर में ट्रान्सपोर्टनगर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से नगर फिरोजाबाद की भीषण समस्या से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

नगर फिरोजाबाद में बहुत बड़े पैमाने पर कांच की चूड़ी, ग्लास, बोटल्स, किचिन वेयर, सांइटिफिक उत्पाद, बल्ब सेल, शीट ग्लास आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है।

ये सारे उत्पाद ट्रकों/ट्रालों एवं कंटेनरों के माध्यम से देश एवं विदेशों को भेजे जाते हैं। नगर में कोई ट्रांसपोर्ट नगर न होने के कारण बड़े वाहन शहर के मुख्य मार्गों पर खड़े होकर लोडिंग तथा अनलोडिंग करते हैं। जिसके कारण पूरे नगर में आये दिन गम्भीर दुर्घटनाएं होती रहती हैं एवं जाम की समस्या बनी रहती है। यदि लोडिंग, अनलोडिंग बन्द कर दी जाये तो शहर की मुख्य अर्थ व्यवस्था ही चौपट हो जायेगी।

जब तक नगर फिरोजाबाद में संचालित हो रही औद्योगिक गतिविधियों की ट्रांसपोर्ट लोडिंग, अनलोडिंग की व्यवस्था सुचारु करने के लिये 'ट्रांसपोर्ट नगर' का निर्माण नहीं होगा तब तक उद्योग तथा नागरिक दोनों ही असुविधा का सामना करते रहेंगे।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए फिरोजाबाद नगर की जनता एवं उद्योग को भीषण समस्या से निजात दिलाने हेतु अतिशीघ्र एक ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना कराये जाने की मांग करता हूं।,

कानपुर महानगर के लोहिया ग्राम पूरनपुर की क्षतिग्रस्त गलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश महाना–

ख्महोदय, कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर अन्तर्गत सरसौल ब्लाक की पूरनपुर ग्राम सभा लोहिया ग्राम घोषित हुई थी। पूरनपुर के मजरा मनोहर खेड़ा की समस्त गलियां कच्ची हैं तथा क्षतिग्रस्त हैं। इसके अतिरिक्त मनोहर खेड़ा पुलिया से करविगवां स्टेशन में बहुत बड़ी संख्या में दूध बेचने वाले ग्रामीण कच्चे मार्ग से होकर जाते हैं। बारिश के मौसम में स्थिति और भी खराब हो जाती है। आये दिन कोई

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

न कोई दुर्घटना घटित हो जाती है। ग्रामीणों में उपरोक्त मार्गों के निर्माण को लेकर कई बार प्रशासन से अनुरोध किया गया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पूरनपुर के मजरा मनोहर खेड़ा की समस्त गलियों का निर्माण तथा मनोहर खेड़ा पुलिया से करविगवां स्टेशन तक मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के वार्ड सं0–6 की जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश बंसल–

ख्मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के अन्तर्गत वार्ड नं0–6 अकबरपुर–बहरामपुर में निरंजन प्रजापति के मकान से हरकेश के मकान से होती हुई जो सड़क राकेश कुमार के घर तक जाती है जो पूर्णतयः क्षतिग्रस्त है। जगह–जगह गड्ढे हो गये हैं। हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन रहता हैं जिससे सड़क अत्यन्त जर्जर हो गयी है।

अतः जनहित में जर्जर हालत में जिस सड़क पर चलना भी दूभर हो रहा है, की मरम्मत/नवनिर्माण का अनुरोध करता हूं।

मैं सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय व लोक महत्व की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान–

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से अवगत कराना है कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में बच्चों नवजवानों युवा खेल प्रेमियों के लिये खेल का कोई स्टेडियम न होने से जनपद चन्दौली एवं मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के युवाओं को खेलने के लिये अन्य जनपदों में जाना पड़ता है। जिससे खेल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में भारी असुविधा एवं अवसर नहीं मिल पा रहा है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जनपद चन्दौली में खेल का एक स्टेडियम बनाने की आपके माध्यम से मांग करता हूं।,

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–04–2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)[†]

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[†] छापा नहीं गया।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–04–2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–09–2014 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) ४

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–09–2014 (उप लो0आ0)(स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–03–2011 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) ४

पंचायती राज मंत्री (श्री कैलाश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–03–2011 (उप लो0आ0) (स्पटीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–04–2011 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) ४

पंचायती राज मंत्री (श्री कैलाश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–04–2011 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–02–2012 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) ४

पंचायती राज मंत्री (श्री कैलाश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–02–2012 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष–

---

† छापा नहीं गया।

मद संख्या–7 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–8 लेते हैं।

ख12.32, उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 132वां (एक सौ बत्तीसवां) प्रतिवेदन४४

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 132वां (एक सौ बत्तीसवां) प्रतिवेदन जो ग्राम्य विकास, पर्यावरण, नगर विकास, वन, आवास एवं शहरी नियोजन, लघु सिंचाई, श्रम, विकलांग कल्याण, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, पशुधन तथा गृह (पुलिस) विभागों के वर्ष 1990 से 2010 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 133वां (एक सौ तैंत्तीसवां) प्रतिवेदन४४

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 133वां (एक सौ तैतीसवां) प्रतिवेदन जो उर्जा, सिंचाई, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, लघु उद्योग, पर्यावरण, पंचायतीराज, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, नियोजन, कारागार, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, संस्कृति, संसदीय कार्य, उच्च शिक्षा एवं गृह (पुलिस) विभागों के वर्ष 1992 से 2014 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा (2013–14) का पंचम् प्रतिवेदन४

डा0 धर्म सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2013–14) का पंचम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित कृषि एवं लघु सिंचाई विभाग तथा पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2013–14) का पंचम् प्रतिवेदन४

श्री अजय कपूर–

मान्यवर, मै, सभापति, ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की उक्त समिति (2013–14) का पंचम प्रतिवेदन जो स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष (2004–2005) में उल्लिखित कृषि विपणन एवं कृषि

†† छापे नहीं गये।

† छापे नहीं गये।

विदेश व्यापार विभाग के अधीन कृषि उत्पादन मण्डी समिति, जनपद शाहजहॉपुर, वाराणसी, कानपुर नगर एवं सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2013–14) का षष्ठम् प्रतिवेदन४

श्री अजय कपूर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की उक्त समिति (2013–2014) का षष्ठम् प्रतिवेदन जो स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष (2006–2007) में उल्लिखित चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की आडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूं।

ख12.38, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–13,14 एवं 15 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–16 कार्य–स्थगन प्रस्ताव को ले लेता हूं।

श्री प्रदीप माथुर–

ख्रा ग ग,

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब, अब आप फिर बिना नोटिस, बिना नियम के बोलने लगे। जब आपकी मर्जी होती है, तो आप बोलने लगते हैं। यह कुछ लिखा नहीं जायेगा। अगर आप यह जिद करेंगे तो हम बजट ही पास करा लेंगे, अब कुछ लिखा नहीं जायेगा।

आज दिनांक 16–03–2015 को नियम–311 में प्राप्त एक सूचना को नियम–56 में परिवर्तित करते हुये नियम–56 के अंतर्गत कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा, शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी की है और इसमें बहुत सारे सदस्यों के नाम हैं। उसी के साथ श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री धर्मपाल सिंह, श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) एवं श्री मनीष असीजा की नियम–311 में दी गई सूचना, जिसे सम्मिलित कर दिया गया है। श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, श्री धर्मपाल जी और श्री श्यामदेव राय चौधरी जी आपने एक सूचना नियम–56 में और दी है, इस तरह तो आपकी दो सूचना हो जायेगी, आपको दो नहीं देनी चाहिये थी, दूसरी सूचना पूर्वी उत्तर प्रदेश के

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु प्रदेश के सम्पूर्ण बजट को चार भागों में बांटकर प्रस्तुत किए जाने के संबंध में है। तीसरी सूचना, प्रदेश में बर्ड फ्लू जैसे जानलेवा बीमारी मुर्गियो एवं पक्षियों में पाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह एवं श्री अजय कुमार 'लल्लू' की है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत सूचना श्री राकेश बाबू की है, जो लोहिया ग्राम त्रिलोकपुर विकास खण्ड नारखी तहसील सदन जिला फिरोजाबाद के अंतर्गत पट्टे धारकों के प्लाटों पर दबंगों द्वारा कब्जा किये जाने से संबंधित है। अब माननीय मौर्या जी अपनी बात रखिये।

'श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया हमारी बात सुन लीजिये। उत्तर प्रदेश से अमेठी के सांसद श्री राहुल गांधी जी के घर पर भारतीय जनता पार्टी द्वरा दिल्ली पुलिस भेजी जाती है, उनकी जासूसी कराई जाती है, सरकार ने जासूसी कराई है।

श्री अध्यक्ष–

माथुर जी, नियमों में लाइये, चर्चा कराइये, अब यह नहीं लिया जायेगा। आप कुछ भी बोलिये, लिखा नहीं जायेगा।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह से तो यहां पर भी किसी के खिलाफ जासूसी हो सकती है, माननीय मुख्य मंत्री जी की भी जासूसी कराई जा सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसके विरोध में अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री प्रदीप माथुर, नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने दल के साथ सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में विगत 14–15 मार्च को हुई भारी वर्षा से पूरे प्रदेश के किसानों की फसलें चौपट हो गईं। मान्यवर, इसी सदन और इसी सत्र के दौरान पहली मार्च को भीषण वर्षा हुई। अभी किसान का आंसू पुछा भी नहीं था, ठीक से वह अपना दर्द भूल भी नहीं पाया था कि 14–15 मार्च को फिर से बड़े पैमाने पर भारी बरसात हुई। मान्यवर, इसके चलते गेहूं, मटर, चना, सरसों, लाही, आलू आदि की फसलें बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गईं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रकृति की इस दोहरी मार से किसान बड़े पैमाने पर हताहत हैं। यहां तक कि इस आपदा से आत्महत्या करने के लिये भी किसान मजबूर हो रहा है। मात्र दो दिन के अंदर 14 किसानों की आत्महत्यायें इस बात का साफ संकेत हैं कि इस भीषण आपदा से प्रदेश में पूरा का पूरा किसान त्राहि–त्राहि कर रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि आप जानते हैं कि केवल फसल की बरबादी से ही वह तबाह नहीं हुआ बल्कि दर्जनों जगह पर बिजली गिरने से भी तमाम लोग काल कलवित हुये हैं। दोहरी मार, एक तो प्राकृतिक आपदा से किसान आत्महत्या करने के लिये मजबूर हुआ और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर बिजली के गिरने से लोगों की मौतें हुयीं । मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में किसान इससे बड़े पैमाने पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पीड़ित है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी पिछले दिनों पहली मार्च को हुयी भीषण वर्षा के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिये कुछ धन आवंटित किया था लेकिन इस प्राकृतिक आपदा की दोहरी मार से किसानों की फसल पूरी तबाह हो गयी, आलू 70 फीसदी तबाह हुआ, लाही–सरसों 60 फीसदी तबाह हुआ और गेहूं 50 फीसदी बरबाद हुआ, इसको देखते हुये पूर्व में आवंटित धन पर्याप्त नहीं है इसलिये मान्यवर, आज किसानों की इस गंभीर समस्या को नियम–56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अति महत्वपूर्ण, अविलम्बनीय और लोक महत्व के इस प्रश्न पर सदन की सारी कार्यवाही स्थगित करके चर्चा कराने का कष्ट करें जिससे कि मान्यवर, उन किसानों की पीड़ा पर विस्तार से इस सदन में चर्चा हो और इसकी गंभीरता का संज्ञान लेकर सरकार इस पर उदारमन होकर बड़े पैमाने पर उनको राहत पहुॅचाने का काम करे जिससे कि उन पीड़ित किसानों की आपदा की इस घड़ी में हम सब उनके सहयोगी के रूप में खड़े हो सकें । माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह विगत 10 वर्षों में सबसे बड़ी मार्च के महीने में दो दिन में जो वर्षा हुयी है, यह अब तक की सबसे अधिक वर्षा है। इसीलिये मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है, अविलम्बनीय भी है और पूरे प्रदेश का किसान इससे प्रभावित भी है इसलिये मान्यवर, इस पर चर्चा जरूरी है और आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर आप चर्चा कराने का भी कष्ट करें ।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

देखिये मैं एक चीज बता दूं। माननीय नेता विरोधी दल और खन्ना जी, यह कई जिलों में हुआ है तो सबकी जानकारी सरकार के पास आयेगी और अभी तो यह रात को ही हुआ है। इसलिये अगर आप लोग चाहें तो मैं इस पर एक घन्टे की चर्चा करा दूं जिससे इस पर सरकार का भी वर्जन आ जाय और सभी सदस्य अपने–अपने क्षेत्र की बात भी कर लेंगे, क्योंकि यह गंभीर मामला है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें विचार कर लें वैसे तो आपका जो भी आदेश होगा। मान्यवर, जो बात नेता प्रतिपक्ष ने रखी है, या जो अन्य सदस्य रखना चाहेंगे, सरकार उससे अपने को सम्बद्व करती है। हम भी जोड़ना चाहते हैं आपको और आपको अपने से जोड़ना चाहते हैं। मान्यवर, क्योंकि यह बारिश और ओलावृष्टि रात का ही वाकया है तो इतना समय तो आप देंगे ही, कि रिपोर्ट आ जाय और जो रिपोर्ट आयेगी, आप खुद देखिये हमारी तो रीढ़ की हड्डी हैं किसान और हमारी पूरी राजनीति ही किसान बेज्ड है। हमारे ये जितने साथी है, इसमें 90 प्रतिशत वह लोग हैं, जो किसान परिवारों से आते हैं और किसानों की ही राजनीति करते हैं। हमारे शहर का होने के बावजूद हमारा 40 प्रतिशत वोट देहात का है। तो हम किसान की भलाई के बगैर जिन्दा ही नहीं रह सकते, तो उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जायेगी । जो सहायता ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, वह की जायेगी और अब देखिये कि एक छोटा हाथ है और एक

बड़ा हाथ है, अगर बड़े हाथ की मदद ज्यादा मिल जायेगी तो इसके लिये भारत सरकार से भी आग्रह किया जा रहा है और किया जायेगा कि उनकी तरफ से मदद ज्यादा से ज्यादा आये, ताकि दोनों मिलकर किसानों का भला कर सकें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने चर्चा करने के लिए निर्देश दिये हैं और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी किसानों की गम्भीर समस्या को गम्भीरता से ले करके अपनी सहमति जताई है तो मान्यवर, इस पर आप चर्चा करा लें।

'श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, यह पूरे प्रदेश से जुड़ा एक ऐसा प्रश्न है जो कि सीधे–सीधे प्रदेश के किसानों से जुड़ा है। हम उन बातों को नहीं दोहरायेंगे जो कि मा0 नेता विरोधी दल ने कही हैं। हम दो बातें खास तौर से कहना चाहते हैं नम्बर–एक यह है कि 28 तारीख, 01 तारीख, 02 तारीख, 03 तारीख, चार दिन वर्षा हुई और प्रदेश सरकार ने जनपदों से रिपोर्ट मांगी उस रिपोर्ट के मांगने और देने के तरीके पर आपत्ति है। इसमें पहली आपत्ति यह है कि उन्होंने प्रथमदृष्टया कि किस तहसील में कितनी वर्षा हुई यह मोटे–मोटे तौर तरीके से ऐसे ही भेज दिया उसकी बारीकी से पड़ताल नहीं की गई, मौसम विभाग से उसको क्रास नहीं कराया गया और किसी तरीके से उसको वेरीफाई नहीं कराया गया कि कहां कितनी वर्षा हुई। सरसरी तौर पर जहां वर्षा हुई, उन्होंने कह दिया कि कैसे मृत्यु हुई तो उन्होंने लिख करके भेज दिया। मेरा मान्यवर, इस बात पर विशेष रूप से बल है कि इसमें बारीकी से फसलों का नुकसान ग्राम को यूनिट मानकर इसकी पड़ताल कराई जाएं ताकि सही नुकसान का आंकलन हो सके।

(श्री प्रदीप माथुर एवं श्री दलवीर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपका तो नोटिस में नाम ही नहीं है, आपने नोटिस नहीं दिया इसलिए आप नहीं कह सकते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, नम्बर–दो यह है कि जो मानक आपने तय किये हैं कि 50 परसेंट से ज्यादा जब नुकसान होगा तो तब उसको हम इतना दे देंगे। मान्यवर, विशेष परिस्थिति में हमारी यह मांग है कि नियमों और मानकों को शिथिल करके अगर 1/3 भी नुकसान किसी किसान का हुआ है तो उसके भी आंसू पोछने का काम इस सरकार को करना चाहिए। हम इन दो विशेष बातों पर बल देना चाहते हैं। तीसरी और अन्तिम बात यह है कि इस बार जो जनपद प्रभावित हुए वह हैं, कानपुर, फतेहपुर, औरैया, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, इटावा, अमेठी, उरई, हमीरपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, महोबा, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, सहारनपुर मण्डल और बरेली मण्डल, फिरोजाबाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

अरे, यह क्यों गिना रहे हैं, केवल ग्राह्यता पर बोलिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, ये मण्डल और खास तौर से आगरा मण्डल ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसलिए हम आपसे मान्यवर, विशेष रूप से यह कहना चाहते हैं कि एक सप्ताह में इसकी रिपोर्ट मंगा करके उन लोगों के आंसू पोछने का काम करें और भारत सरकार के मंत्री जी पहले ही इस बात को कह चुके हैं और उन्होंने लोक सभा में भी कहा है, वह भी इस बात के लिए तैयार हैं।

(श्री प्रदीप माथुर, श्री दलवीर सिंह के खड़े होने पर एवं अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

क्या आप बिना नोटिस के बोलेंगे, नोटिस तो आपने दी नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह यह है कि यदि चर्चा होना है तो यह तो चर्चा हो गई, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने भी बात रख दी, नेता भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी बात रख दी, अब नेता लोकदल भी अपनी बात रख दें।

(सदस्य श्री धर्मपाल सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं, आप भी ऐसा कर रहे हैं, कृपया आप बैठ जाएं। यह लिखा नहीं जायेगा, आप पहले मा0 मंत्री जी की बात को सुन लें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, पहले मा0 महाना जी की बात सुन लें।

श्री सतीश महाना–

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि चर्चा हो गई, यदि आपने नियम–56 स्वीकार करके चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया है तो मान लें, चर्चा करा लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप हमें सुनिये, हमें कहने दीजिए हमने तो हाउस की राय जानने की कोशिश की थी, मैंने अभी कोई निर्णय नहीं दिया था।

श्री मोहम्मद आजम खां–

हां, मान्यवर, अभी कोई चर्चा का आदेश थोड़े ही हुआ था।

श्री अध्यक्ष–

हमने तो अभी राय जानने की कोशिश की थी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अभी चर्चा का आदेश थोड़े ही हुआ है, चर्चा तो हो गई, अब क्या चर्चा होगी, इसमें चर्चा किस बात की होनी है। नेता, भारतीय जनता पार्टी मा0 खन्ना साहब ने यह कहा कि इसकी सूक्ष्म जॉच होनी चाहिए।

मान्यवर, बारीकी से, अतिसूक्ष्म जांच हुई है, सूक्ष्म नहीं, अतिसूक्ष्म हुई है अब और अतिसूक्ष्म होगी, कोई किसी तरह की कोताही नहीं बरती जायेगी। अब आपने कहा कि प्रत्येक गांव के तो जाहिर है कि गांव ही नहीं खेतों तक का परीक्षण किया जाता है। मान्यवर, उसके मानक हैं, अब क्योंकि खन्ना साहब तो शाहे जहां, अब शाहे जहां और कहां किसान ? (श्री दलवीर सिंह के द्वारा अपने आसन पर खड़े होकर कुछ कहा गया जो सुनाई नहीं दिया।) तो बताईये, हम और आप तय कर लेंगें न इनसे कोई मतलब जो आपके बगल में (श्री प्रदीप माथुर) खड़े हैं, न इनसे (भा0ज0पा0) मतलब और इनसे तो (ब0स0पा0) कोई मतलब ही नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर अनुरोध है कि एक घण्टे की चर्चा स्वीकार कर लें। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी अपनी जिज्ञासा जाहिर की है, कम से कम चर्चा के लिए इतना समय हो कि सरकार समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट भी दे सके। इसलिए मान्यवर, अच्छा होगा कि एक घण्टे की चर्चा स्वीकार कर लें जिससे इस पर दोनों पक्षों की राय आ जाएं।

'श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, किसान बर्बाद हो गया है, फसलें नष्ट हो गयी हैं इसलिए इसकी ग्राह्यता पर सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

इस पर मैंने माननीय नेता विरोधी दल को सुना, मा0 खन्ना जी को सुना, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना चूंकि ये आकस्मिक घटनायें हैं इस समय इतनी बारिस व ओले नहीं पड़ते हैं, चारों तरफ पूरब से पश्चिम तक फसलों का नुकसान हुआ है, सरकार के पास अभी पूरी जानकारी नहीं आ पा रही है इसलिए मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा और नेता विरोधी दल से भी कि इसमें एक घण्टे की चर्चा करा दी जाएं। किसी दिन करा दी जाएं, आज नहीं, जिससे सारे तथ्य जो माननीय सदस्यों के क्षेत्र के हैं और सरकार का, तथा जो भारत सरकार से सहायता मिलनी है उन सारे विषयों पर यहां चर्चा हो जाएं।

(इसी बीच श्री धर्मपाल सिंह व डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी सदन की वेल में आ गये)

श्री धर्मपाल सिंह (वेल से)–

मान्यवर, यह ठीक नहीं, एक मिनट का समय चाह रहा हूं, आप ग्राह्यता पर सुन लें, किसान बर्बाद हो गया है।

श्री अध्यक्ष–

अब क्यों वेल में आ गये, मैंने इस पर चर्चा स्वीकार कर ली। अब क्या है खन्ना जी, बताईये कि अब क्या रह गया है ? अब आप ज्यादती कर रहे हो। चर्चा मान लिया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। इस बीच सरकार की रिपोर्ट भी आ जायेगी।

(वेल में आये हुए सदस्य वापस अपने आसन पर चले गये।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जो चर्चा स्वीकार होने के बाद चर्चा नहीं कराना चाहते हैं वह किसान विरोधी हैं, मैं इसकी निन्दा करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री धर्मपाल सिंह व डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की पूर्वी उ0प्र0 के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु प्रदेश के सम्पूर्ण बजट को चार हिस्सों में बांटकर प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में। राधामोहन दास अग्रवाल जी आप अपनी बात रखिये।

माननीय खन्ना जी, चर्चा स्वीकार कर ली है तो अब क्या रह गया ? आज महत्वपूर्ण बजट है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बात अगर आप साफ कर दें कि आपने जो चर्चा स्वीकार की है वह नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेता लोकदल सबके कहने से की है, अगर आप अकेले को श्रेय देंगे तो दिक्कत होगी।

श्री अध्यक्ष–

हमने तो सबको कहा है, यह किसने कहा कि हम इन्हीं पर कह रहे हैं, यह तो मैंने कहा नहीं। इसी की लड़ाई थी तो हमें बता दिये होते। हमने तो कहा कि खन्ना जी को सुना।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

यह देखिये, आपकी कृपा हो गयी, अब शांत हो गये। इनको इतना ही चाहिए, किसान का भला नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए बस नाम आ जाएं।

(श्री प्रदीप माथुर के खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

माथुर जी, बैठिये। जब लिखकर देना होता है तो आप देते नहीं हो, जब चर्चा होगी तब आप बोलियेगा, बैठिये। कार्यमं त्रणा समिति में समय तय हो जायेगा।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, ख्रा ग ग,

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

आपने लिखकर के तो दिया नहीं, आपकी तो किसानों के प्रति हमदर्दी थी नहीं अगर होती तो आप भी नियम–56 में नोटिस दिये होते आपने तो दूसरा कुछ दिया है। अब बैठिये।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी ख्वा ग ग,

श्री अध्यक्ष–

अब लिखा नहीं जाएंगा यह सब निकाल दिया जाएंगा। माननीय डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी आप अपनी बात रखिए। यह लिखकर तो देते नहीं हैं जो देगा उसी में घुसेड़ेंगे।

श्री प्रदीप माथुर–

हम रोज लिखकर देते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बहस मत करिए। हम आगे बढ़ गए हैं। आज आपने किसानों पर लिखकर दिया था नियम 56 में आपने नहीं दिया था तो कैसे इस पर बात करेंगें। आप चूक गए तो आप हमसे लड़ रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी माननीय नेता कांग्रेस किसानों के बारे में कोई बात नहीं कह रहे हैं। वह दूसरी बात है वह किसानों के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अगर आप लोग शांत नहीं होंगे तो हम सब स्थगित करके बजट ले लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी आप थोड़ा न्याय कर दीजिए इन्होंने एक आक्षेप लगा दिया है पीठ पर कि आप कांग्रेस के साथ थोड़ा ज्यादती करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्यमंत्री जी मैंने कोई ज्यादती नहीं की। नियम यह है कि नियम–56 में जो नोटिस दी जाती है उसी पर तो विचार होता है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इस गरीब की भी तो सुन लीजिए। वह किसानों के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। आप बात तो समझिए वह किसानों के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। न उन्हें इससे मतलब कि ओला कहां पड़ा बारिश कहां हुई मान्यवर, उनकी परेशानी यह है कि ले देकर एक नाम रह गया है उनके यहां उनकी भी जासूसी हो रही है तो मान्यवर बात तो बुरी है अब देखिए जैसे मैंने कहा कि इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है।

श्री प्रदीप माथुर–

हमें किसानों से क्यों नहीं लेना देना है। मैंने कहा कि पुलिस इंस्पेक्टर को भेजकर राहुल गॉधी जी के यहां यह जासूसी करा रहे हैं। मामला बहुत गम्भीर है। आप इसको महत्ता नहीं दे रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह किसानों से ज्यादा गम्भीर मामला है। किसानों का मामला कोई गम्भीर नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब आप बजट पर जितना बोल पाइएगा बोलिए।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी यह मुद्दा है कि ख्ग ग ग,

श्री अध्यक्ष–

तो आपको इसको नियम–56 में लिखकर देना चाहिए था। अगर आपने लिखकर दिया होता तो मैं इसे स्वीकार करता ।

श्री वसीम अहमद–

इस पर यह लोग एक बार वाकआउट कर चुके हैं दुबारा क्यों उठा रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं माथुर साहब की मदद करना चाहता हूं लेकिन यह मदद चाह ही नहीं रहे हैं। मैं इशारे कर रहा हूं वह इशारे भी नहीं समझ रहे हैं। ऐसा हुआ कि एक मोहल्ले में एक साहब को पूरे मुहल्ले ने घेर लिया और कहा कि देखिए आप कैसे मुसलमान हैं आपका कुत्ता मस्जिद में आ गया तो उन्होंने कहा भाई यह बताओ जानवर था आ गया हमें भी कभी देखा। इनका किसानों से क्या लेना देना कभी किसानों ने इन्हें देखा।

(इसी मध्य कांग्रेस पार्टी के अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गए)

(वेल से)

'श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

यह कहते हैं कि हमने किसानों का 50 हजार रुपए माफ किया लेकिन इन्होंने एक रुपया माफ नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

हम अब इस पर नहीं सुनेंगे। जब नोटिस नहीं है तो कैसे सुनूंगा।

(कांग्रेस पार्टी के कई सदस्यगण सदन के वेल में खड़े होकर बोलते रहने पर शोर)

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय इतना गम्भीर मामला है आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

अब आप अपनी सीट पर चलिये, इससे ज्यादा मैं निवेदन नहीं करूंगा। आप लिखकर देते नहीं हैं और जबरदस्ती बोलते हैं। नहीं अब कुछ नहीं लिखा जायेगा और न ही यह कार्यवाही का अंग माना जायेगा न यह प्रकाशन के लिये होगा। चलिये, चलिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

किसानों की बात पर परसों चर्चा हो गई और हमने अपनी बात रख दी। अगर आप यही चाहते हैं कि रोज–रोज हम अपनी बात को रखें।

श्री अध्यक्ष–

यह आपने परसों कही तो परसों ओलावृष्टि कहीं रात में हुई। देखिये, हमारी बात भी सुनोगे ? देखो कल भीषण वर्षा हुई। हम खुद आये हैं, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था इतनी तेल बारिश हुई। परसों जो व्यापक पैमाने पर हुआ, छोटे पैमाने पर। रात को बड़ी भीषण वर्षा हुई। पूरब से पश्चिम तक तबाही मच गई है, मैं खुद उसमें घिर गया था और यह मामला जब जायेगा तो आखिर यह विधान सभा जन समस्याओं के सुनने का ही तो स्थल है। तो इस पर अगर बात नहीं होगी तो किसानों।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

एक बार चर्चा हो गई।

श्री अध्यक्ष–

आप तो बोल चुके तो अब काहे को बोल रहे हो। आपने आज नहीं दिया है। आज कहां दिया है। आप कहां दिया है, आज तो आपने दिया नहीं तो मैं क्या करूं। चलिये, चलिये। लल्लू जी चलो, बस हो गया।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

हमारे नेता कांग्रेस को अधिकार है अपनी बात रखने का। अन्य लोगों को मौका देते हैं। क्या हम लोग अपनी बात नहीं रख सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

चलिये हो गया, अब उसमें आपका नहीं जोड़ा जायेगा। लल्लू जी हो गया। परसों आपको बोलने का मौका दिया गया था, आपने अपनी बात रखी है। अब आज आपका उसमें नहीं जोड़ा जायेगा, आज नहीं दिया है आपने। अब हमको नियम न समझाइये। चलिये। अरे माथुर साहब चलिये, आगे बढ़ने दीजिये न कार्यवाही चलिये। राधा मोहन दास जी आप बोलिये।

(कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर चले गये)

'डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने....

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आप काफी देर से बार–बार कांग्रेस के नेता से अनुरोध कर रहे थे वापस जाओ, वापस जाओ।

श्री अध्यक्ष–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब चले गये अब न छेड़िये कम से कम फिर न आवें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

लेकिन मान्यवर, जैसी ही संसदीय कार्य मंत्री ने थोड़ा इशारा किया सब वापस हो गये और इशारे–इशारे में ही कहा था कि इशारा समझते नहीं और जब यह कहा तो आ गये और जैसे ही इशारा किया चले गये। मान्यवर, लगता है कि कहीं–कहीं दाल में काला है कुछ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, कुछ लोग कह कर इशारा करते हैं और कुछ लोग सिर्फ ऐसे हैं जो सिर्फ आंख से इशारा करते हैं। माननीय नेता विरोधी दल आंख के इशारे में सब समझ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

एक बज गया है। डाक्टर साहब आप शुरू तो करते हैं। शुरू करिये ना। वह रहने देते आप बोलते।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने पूरे उत्तर प्रदेश के विकास से सम्बन्धित इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे यह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार विकास का समग्र सूचकांक बनवाती है। आप स्वयं पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं इसलिये आप इसे बेहतर जानते होंगे। विकास के सूचकांक में जो पन्द्रह जिलों की सूची है सबसे निचले स्तर की। समग्र विकास के सूचकांक में जो 15 जिले सबसे नीचे हैं, मैं उनके नाम पढ़ देता हूं। मऊ, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, गोण्डा, जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर, देवरिया, आजमगढ़, महराजगंज, कुशीनगर, संतकबीरनगर और अपना शहर। यह 15 सबसे कम विकसित जनपदों की सूची है अध्यक्ष महोदय और सूची में के यह 15 नाम मैंने पढ़ दिये। यह 15 के 15 जनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। यह सूची मेरी अपनी नहीं है, यह स्वयं इनके योजना विभाग के द्वारा प्रकाशित हैं इसमें अध्यक्ष महोदय, जब प्रश्नकाल कुछ दिनों पूर्व चल रहा था और माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया जब इधर से सवाल पूछा गया कि प्रदेश में 2012 से लेकर 2014 तक कितने उद्योग लगाये गये। जवाब आया, 20 उद्योग लगाये गये। कितने मूल्य के ? जवाब आया 61 सौ 64 करोड़ रुपये के। फिर किसी ने प्रश्न किया कि इन 20 उद्योगों में से क्या कोई उद्योग पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी लगा।

क्या सरकार की कोई ऐसी नीति थी जबाव आया सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं थी। प्रश्न यह है कि आपके अपने रिकार्ड कहते हैं कि प्रदेश के 15 जनपद प्रदेश में सबसे पीछे हैं आप सदन में स्वयं इस बात को बताते हैं कि जितने उद्योग आए वह सारे के सारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आए, अगर यह प्रश्न दोनों सही हैं तो मेरा प्रश्न है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास होगा कैसे ? मान्यवर, हर स्तर पर चाहे वह बेसिक शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे बिजली विभाग का मुद्दा हो, चाहे

वह कृषि उत्पादन का मुद्दा हो, चाहे औद्योगिक उत्पादन का मुद्दा हो, यही पांच मुद्दे हैं। सरकार स्वंय इस बात को कह रही है, सरकार के डाकुमेंट हैं, सरकार स्वंय इस बात को कह रही है कि औसतन एक लाख की जनसंख्या पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय सिर्फ 75 हैं। जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 86, मध्य उत्तर प्रदेश में 81 और बुन्देलखंड में 98 हैं अपर प्राथमिक विद्यालय में पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 36 हैं जबकि बुन्देलखंड में 49, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 37 हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 35 हैं। इसी तरह से अस्पतालों के बारे में कहना चाहूंगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक लाख की जनसंख्या पर 2.27 अस्पताल हैं बुन्देलखंड की एक लाख की जनसंख्या पर 3.18 अस्पताल हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक लाख की जनसंख्या पर 28 बिस्तर और बुन्देलखंड में एक लाख की जनसंख्या पर 34 बिस्तर हैं। यह पूरे उत्तर प्रदेश के सरकार के आंकड़ें हैं। बिजली का उपयोग पूरे उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष महोदय 161 किलोवाट आवर्स में लिखते हैं यूनिट में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 375 किलोवाट, ग्रामीण विद्युतीकरण में ग्रामों की संख्या, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 84 प्रतिशत, मध्य, पश्चिम और बुन्देलखंड में 95 से 99 प्रतिशत। न हमने शिक्षा की सही व्यवस्था की, न हमने स्वास्थ्य की सही व्यवस्था की, न गांव तक बिजली पहुंचाई, फल क्या हुआ फल यह हुआ कि जब सरकार ने सकल घरेलू उत्पादन का ऑकड़ा निकलवाया, सरकार के स्वंय के आंकड़े हैं मेरे स्वंय के नहीं, सबसे अधिक सकल घरेलू उत्पादन प्रति व्यक्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है 38,545 रुपये, केन्द्रीय उत्तर प्रदेश का 30,726 रुपये, बुन्देलखंड की चर्चा यहां होनी भी तो चाहिए, प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पादन 36,304 रुपये, पूर्वी प्रदेश का प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 21 हजार 283, ऐसे ही बहुत चर्चा होती है खेती की, मान्यवर, प्रति ग्रामीण व्यक्ति कृषि उत्पादन, बुन्देलखंड प्रदेश में सर्वाधिक 15,490 रुपये, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 15,201 रुपये, केन्द्रीय उत्तर प्रदेश 11,106 रुपये और पूर्वी उत्तर प्रदेश 6,643 रुपये, मैं अन्तिम दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। सीडी रेशियो आप भी जानते हैं कि कितना पैसा जमा किया गया और कितना पैसा निकाला गया उद्योग धन्धों के लिए, बुन्देलखंड में 100 रुपये जमा हुआ तो 52 रुपये निकाले गए स्थानीय उद्योग धन्धे के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 100 रुपये जमा हुआ तो 54 रुपये निकाले गए उद्योगधन्धे के लिए, मध्य उत्तर प्रदेश में 100 रुपये जमा हुआ तो 46 रुपये निकाले गए। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 रुपया जमा हुआ तो 25 रुपये उद्योगधंधों में लगे। गरीब पूर्वी उत्तर प्रदेश का धन निकलकर बाहर जाता रहा। सबसे बड़ी लापरवाही सरकार ने कदाचित सही संख्या में बैंक भी नहीं खोले। मैं अगर आपको बैंक के भी आंकड़े दे दूं तो सबसे कम बैंक अगर जनसंख्या के आधार पर खोले गए हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए खोले गए हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत साफ है, अगर आपके आंकड़े यह कहते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है और आप यह दावे करते हैं कि चालीस प्रतिशत जनसंख्या आपकी ही है आप उसकी चिन्ता करते हैं तो सरकार ने आज तक यह अध्ययन कराने का प्रयास क्यों नहीं किया कि उनके आंकड़े अगर कह रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ है तो सरकार किन नीतियों को बनाए जिसके नाते

यह पूर्वी उत्तर प्रदेश विकसित होकर एक अवसर मैं मानता हूं पश्चिम नहीं हो सकता है लेकिन जो एक औसतन जो प्रदेश का विकास है उसमें आपने क्या किया, एक बात मैं बहुत साफ कह देना चाहता हूं कि जैसे आप स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान बनाते हैं।

यह तो बहुत बार जनसंख्या के आधार पर विकास का नारा दे चुके, लेकिन इन्होंने कभी इसे लागू नहीं किया। कम से कम आप तो कहिये कि हमनें अगर प्रदेश को चार आर्थिक जोनों में बांटा है तो हम जो भी बजट बनायेंगे उसको चार आर्थिक जोनों में बांट देंगे। जनसंख्या के हिसाब से उस बजट का बंटवारा हो जाये। जनसंख्या के अनुसार उन आर्थिक जोनों की अलग कमेटियां बनाकर के उन्हें अपने विकास की आवश्यकताओं को तय करने का अधिकार दे दिया जाये। मा0 अध्यक्ष जी, बहुत आसानी से कोई कह सकता है कि नहीं करेंगे, लेकिन यह समझना चाहिये कि जहां पीड़ा होगी वहीं आक्रोश होगा, वहीं आन्दोलन होंगे और वहीं अलग राज्य की मांग उठेगी। मैं इस सदन में किसी अलग राज्य की मांग नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि अगर यह व्यवस्था ऐसे ही बनी रही और हम लगातार उस क्षेत्र के साथ लापरवाही करते रहे। मैं इस सरकार को उसके लिये जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। हमने यह सिस्टम ऐसा बनाया है कि हम इसको जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि सच्चाई क्या है। अगर इस सच्चाई और इस नाइंसाफी को हम दूर नहीं करेंगे तो मा0 अध्यक्ष महोदय, आज नहीं तो कल वही लड़ाईयां जो सौभाग्य से आज उत्तर प्रदेश में नहीं हैं वही लड़ाईयां इस प्रदेश में भी शुरू होंगी। स्वयं सरकार की यह रिपोर्ट एक चेतावनी है और सरकार को यह बताना चाहिये कि क्या इस रिपोर्ट को वह संज्ञान में लेती है और यदि संज्ञान में लेती है तो क्या इस पर कोई कार्यवाई करेगी?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसका परीक्षण करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैंने मा0 राधामोहनदास अग्रवाल जी को सुना और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम–56 में नहीं आता है इसलिये इसको अग्राह्य करता हूं। मा0 अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप बर्ड फ्लू पर संक्षेप में कह लीजिये, क्योंकि बजट है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, एक बड़े गम्भीर विषय पर आपने हमें नियम–56 के तहत अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिये हम आपके आभारी हैं। बर्ड फ्लू नामक एक बहुत ही खतरनाक बीमारी या यूं कहें कि महामारी की दस्तक हमारे प्रदेश में हो चुकी है। करीब दो हफ्ते पहले अमेठी में इसकी शंका जाहिर की गई थी और बहुत–सी चिड़ियों में इस बीमारी के लक्षण पाये गये थे। उसे जॉच के लिये दूसरे प्रदेश की लैबोरेट्री में भेजा गया और करीब दो हफ्ते बाद उसकी जांच रिपोर्ट दो दिन पहले आई जिसमें यह पाया गया कि बर्ड फ्लू बीमारी का प्रकोप हो चुका है। मान्यवर, अभी स्वाईन फ्लू से यह प्रदेश ग्रस्त था, पूरा देश ग्रस्त है। उससे लड़ने की तैयारी हर व्यक्ति कर रहा है और सरकार

भी कर रही है तब तक यह बर्ड फ्लू की बीमारी का प्रकोप आ गया। यह बीमारी ऐसी है कि कि देश ही नहीं दुनिया में भी इसको लेकर तमाम तरह के अलर्ट जारी हो जाते हैं। जो भी यात्री आज बर्ड फ्लू हो जाने के बाद हिन्दुस्तान से बाहर जाता होगा उसकी तो उस एयरपोर्ट पर निश्चित रूप से गम्भीर रूप से जांच–पड़ताल शुरू हो जाती है। बर्ड फ्लू की की जांच में जो इतनी देर होती है उस कारण से भी इस बीमारी के व्यापक रूप से फैलने की सम्भावना बहुत बढ़ जाती है। प्रदेश सरकार ने जांच के बाद संज्ञान लिया और अगल–बगल के जनपदों और पूरे प्रदेश में गंभीरता से अलर्ट रहने की सूचनायें भी दी हैं। सरकार इस बीमारी से ग्रसित बहुत–से पक्षियों और मुर्गियों को मारकर जलाने/गाड़ने का काम कर रही है, नजर रख रही है, लेकिन अभी भी इसमें आवश्यकता है कि प्रदेश की सरकार इसको और भी युद्ध स्तर पर ले और गम्भीरता से ले और इस पर नजर रखने के लिये डाक्टरों की, इसके एक्सपर्ट्स की टीम तैनात करे। कहीं भी लक्षण दिखने पर इसकी जॉच जल्द से जल्द आ जाये। हम तो यह कहेंगे कि इसी बहाने इस सरकार के द्वारा एक प्रक्रिया शुरू हो कि हमारे प्रदेश में भी इस तरह की जॉच के लिये एक लैब बन जाये ताकि हमें दूसरे प्रदेशों या बाहर से जांच का इंतजार न करना पड़े जिसमें हफ्तों लग जाते हैं। जांच में देरी होने के कारण इस बीमारी के व्यापक होने का खतरा बना रहता है और तीसरा सबसे बड़ा जो इसका आर्थिक पहलू यह है कि जो गॉव में छोटे काश्तकार और किसान होते हैं वह मुर्गियों का पालन कर्ज, उधार और लोन लेकर किसी तरह से करते हैं और बर्ड फ्लू हो जाने के बाद उनकी मुर्गियों का, जो उनकी कमाई का एक माध्यम हैं जिसमें उनकी पूंजी लगी होती है, अपना पता नहीं क्या–क्या बेचारे गरीब किसान बंधक रखकर उसकी लोनिंग कराते हैं, सुरक्षा के कारण, बचाव के कारण उसका नाश कर दिया जाता है तो इस बीमारी से उनके धन की भी हानि होती है और जन की भी हानि होती है। हम सरकार से सिर्फ यह चाहते हैं कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए इसे और गंभीरता से लें, डाक्टरों की बड़ी टीम बनायें, जांच–पड़ताल करें, इसके कारण जो नुकसान हो रहा है, जिन लोगों ने चिड़ियों का पालन कर रखा है, उसकी खेती कर रखी है, उनके नुकसान की भी भरपाई पूरी तरह से की जाएं और यह कहीं पैनिक न हो, कहीं किसी और जगह इसकी व्यापकता न फैले, इसके लिए भी पूरी सतर्कता के साथ दिशा–निर्देश प्रदेश सरकार की तरफ से जाना चाहिए।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' के खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप इसमें क्या बोलेंगे? आपके नेता बोल चुके हैं, उन्होंने पूरी बात रख दी है

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी गंभीरता को देखते हुए, हम आपसे यह अनुरोध करते हैं कि सदन के सारे कामों को रोककर इस पर चर्चा कराई जाएं और इससे होने वाले नुकसान, बजट की मानीटरिंग, इससे बचाव, इससे एलर्टनेश और इसके पालकों को

होने वाली जो हानि है और अगर प्राइमाफेसी कोई ट्रीटमेंट होता हो कि प्राइमरी स्तर पर इनके रोगाणुओं को रोका जा सके और लोगों को इससे बचाया जा सके। अगर कोई टीकाकरण होता हो या बचाव के और कोई माध्यम होते हों तो सरकार व्यापक स्तर पर उनको लागू करे और युद्ध स्तर पर इस पर अमल करे।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' के पुनः खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपके नेता बोल चुके हैं, आज बहुत बड़े–बड़े बजट हैं, उन्होंने पूरी बात बोल दी है। पडरौना में फैला है क्या ? आप बैठिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, विधिवत् रूप से इसका परीक्षण भी होता रहता है और छिड़काव वगैरह जो भी जरूरत होती है, वह करते हैं और अगर कहीं कमी होगी तो उसे और देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री अखिलेश प्रताप सिंह को सुना और मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुना, यह सूचना नियम–56 में नहीं आती है, अतः इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री राकेश बाबू की जो सूचना है, उस पर मैं ध्यान आकृष्ट करता हूं। इनकी सूचना है कि लोहिया ग्राम त्रिलोकपुर विकास खण्ड–राखी, तहसील सदर, जिला फिरोजाबाद के अन्तर्गत पट्टे धारकों के प्लाटों पर दबंगों द्वारा कब्जा किये जाने के संबंध में। इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

ख01.20, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाली परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 56,93,34,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसमें विवाद नहीं है, अतः मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न 31 मार्च, 2016 में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान यह है कि अनुदान संख्या–90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाली परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 56,93,34,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाली परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 23,74,93,40,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत संक्षेप में कुछ बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहता हूं। उच्च शिक्षा का महत्व कितना है, उसको उसी गंभीरता के साथ लेते हुए सरकार ने जो प्रबन्ध किए हैं उसका बहुत सूक्ष्म वर्णन मैं आपकी अनुमति से इस सदन में रखना चाहता हूं। बदलते परिवेश में और विशेष कर 21वीं सदी में जो टेक्नॉलोजी का परिवर्तन हुआ है, आर्थिक परिदृष्य जो पूरी दुनिया का बदला है और ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे देश में उन कारकों के जो प्रभाव पड़े हैं।

मान्यवर इसके कारण एक विशेष स्थिति यह पैदा हो गई है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जो परम्परागत कोर्सेज थे उनसे काम नहीं चलता। आज से बीस साल, तीस साल, चालीस साल, पैंतीस साल पहले और मान्यवर जब आपके छात्र जीवन में उच्च शिक्षा की चर्चा होती होगी तो थोड़े–से विषय थे आर्ट्स पढ़ता है कि कामर्स पढ़ता है अगर पीजी में जाना है तो एल0एल0बी0 में एडमिशन लेगा या एम0ए0 में एडमिशन लेगा इतनी बात होकर के उच्च शिक्षा के बड़े–बड़े केन्द्र होने के बावजूद विषयों की बहुत सीमित स्थिति होती थी। अब समय बदल गया है। अब श्रीमन् ऐसे–ऐसे विषय बच्चे बताते हैं जिनको सुनकर करके जो बहुत प्रबुद्ध लोग हैं उनका अंदाजा ही नहीं होता है कि यह विषय कौन–सा है और अब तक तो हमने इतिहास सुना था और तीन तरह के इतिहास सुने थे अब यह नई चीज कहां से आ गई। इसलिए इस तरह की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर इसलिए भी इसकी आवश्यकता बहुत बढ़ गई है कि हमारे पास शिक्षित स्नातकों की संख्या तो बढ़ गई लेकिन हम उनको आज की तारीख की औद्योगिक आवश्यकताओं से जोड़ना चाहते हैं। जो व्यावसायिक आवश्यकताएं हैं वह दूसरे प्रकार की शिक्षा की हैं। आज की उनकी औद्योगिक आवश्यकताओं के हिसाब से और व्यावसायिक आवश्यकताओं के हिसाब से उनको कैसे जोड़ा जा सके। इसलिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यह प्रयास किया गया है।

श्रीमन् ऑकड़ों को रखने की बजाएं वह इसी किताब में है मैं उसे दोहराना चाहूं तो समय जायेगा लेकिन हम उल्लेख यह करना चाहते हैं कि जहां हमने उच्च शिक्षा के विस्तार के उद्देश्य से जनपद सिद्धार्थनगर में महाराज विश्वविद्यालय की स्थापना की है। जनपद इलाहाबाद में राज विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं वहीं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय जिसकी भारी उपेक्षा होती रही और अनेक लोग जो भावनात्मक तौर पर बहुत सारी बातों को कह कर उससे अपना जुड़ाव प्रदर्शित करते रहे हैं जिन लोगों ने

उसका प्रबन्ध नहीं किया उसके लिए भी विशेष रूप से इस बजट में प्रावधान किया गया है। असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्ध तंत्रों द्वारा महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान दिए जाने की योजना संचालित है। इस योजना में दस करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है क्योंकि असेवित विकास खण्डों में महाविद्यालयों की संख्या कम हो गई है। जब से यह सरकार स्थापित हुई है मा0 श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में असेवित विकास खण्डों में महाविद्यालयों को जो अनुदान दिया जाना था वह इसके पहले दिया गया। थोड़े–से ब्लॉक बच गए थे इसलिए उन विकास खण्डों में भी कर दिया जाएं और सरकार का पूरा प्रयास है कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति होते–होते एक भी विकास खण्ड इस प्रदेश का महाविद्यालयों की स्थापना से अछूता न रह जाएं इसलिए सरकार इसको पूरी तरह से लागू करना चाहती है। एक बड़ा सवाल कई बार सदन में उठता रहा है उनका जिक्र करूं उसके पहले और बात कहना चाहता हूं आजादी से लेकर और 2012 के 15 मार्च कल 15 मार्च 2015 का तीन वर्ष सरकार के पूरे हुए हैं 15 मार्च 2012 के पूर्व तक कुल राजकीय महाविद्यालयों की संख्या मात्र 138 थी और श्रीमन् इन तीन वर्षों में हमने जो महाविद्यालय स्थापित किए उनको छोड़कर 37 राजकीय महाविद्यालय बहुत बड़ी संख्या है प्रतिशत में जोड़ेंगे तो विद्वान लोग जोड़ेंगे। मौर्य जी गणित बहुत अच्छी जानते हैं जोड़ेंगे तो बताएंगे कि 37 प्रतिशत है या 40 प्रतिशत है। आजादी से लेकर 2012 तक राजकीय महाविद्यालयों की संख्या कुल 138 थी और 37 महाविद्यालय हम इसी वर्ष स्थापित करने जा रहे हैं। इस प्रदेश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतनी बड़ी संख्या में महाविद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं। हमने बजट में इसका प्रावधान किया है। एक बात इस सदन में कई बार उठती रही कि हमारे यहां यह अफसोस की बात है कि हिन्दुस्तान के किसी विश्वविद्यालय का नाम दुनिया के स्तर पर दो सौ उच्च शिक्षा संस्थाओं में हमारे किसी विश्वविद्यालय का नाम नहीं है और अपने प्रदेश में भी जब शिक्षा के स्तर पर चर्चा होती है तो अनेक बार माननीय सदस्यों ने इस पर सवाल भी उठाए और इस पर बार–बार चर्चा भी हुई। कि हमारी शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए वह नहीं है। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता था लेकिन मान्यवर, जिनको नहीं कहना चाहिए उन्होंने भी टी0वी0 पर अपना इंटरव्यू देते हुए कह दिया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। मैं इसलिए इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि इस वर्ष हम लोगों ने इसका बंदोबस्त इस तरह से किया है कि देश तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों का अध्ययन करके ऐसा पाठ्यक्रम तय करायें। और यह सिर्फ सैद्धान्तिक रूप से तय नहीं किया इसी वर्ष से मौजूदा वित्तीय वर्ष से हम इसको लागू करने जा रहे हैं।

श्रीमन्, यह काम लगभग हो चुका है लेकिन हम इसी वर्ष से जो नया सत्र शुरू होगा उस सत्र से हम इसको लागू करेंगे। उसका कैरीकुलम भी चेंज करने का काम कर रहे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पूरे देश के स्तर पर हमारे छात्र जो इन महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करके निकलें वह उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें और राजकीय महाविद्यालय और सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों का नियमित परीक्षण

किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। क्योंकि जो नैक है, संस्थाओं का मूल्यांकन जो नैक से कराने की व्यवस्था है उसके न होने के कारण जो स्तर होना चाहिए उसकी पूरी तरह से मानीटरिंग नहीं हो पायी और इसलिए इसको अनिवार्य करने का भी हमने निर्देश जारी किया है। वह हम करने वाले हैं। श्रीमन्, राज्य के विश्वविद्यालयों को आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए 127 करोड़ 46 लाख 72 हजार का बजट प्राविधानित है। राजकीय महाविद्यालयों को आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए 74 करोड़ 17 लाख 50 हजार का बजट प्राविधानित है। आधारभूत संरचनाओं की कमी के कारण भी छात्रों को जो वातावरण मिलना चाहिए या उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो सुविधायें मिलनी चाहिए उन सुविधाओं का अभाव होने के कारण असुविधा भी होती है और स्तर भी गिरता है। उनको ठीक करने की दिशा में हमने इसका प्रबंध किया है। मान्यवर, रिसर्च इनोवेशन एवं क्वालिटी इम्प्रवूमेंट के लिए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ सके और अनुसंधान के कार्य हो सकें। क्योंकि जहां रिसर्च की बात आती है रिसर्च के मामले में उत्तर प्रदेश भी सारी दुनिया के मुकाबले पिछड़ा हुआ है और हमारे देश के दूसरे प्रदेशों में भी यह बात है। मान्यवर, 13 करोड़ का बजट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और रिसर्च इनोवेशन के लिए हमने प्रस्तावित किया है। छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास यथा क्षमता राष्ट्रीय प्रेम राष्ट्रीय एकता सामाजिक समरसता आदि के गुणों के विकास हेतु उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय कैडेट कोर राष्ट्रीय सेवा योजना तथा रोवर्स रेंजर्स को अनुदानित एवं संचालित किया जाता रहा है। श्रीमन्, इसमें भी संख्या में काफी वृद्धि हुयी है और जो हमारी संख्या 2014–15 में थी उससे एक बड़ी संख्या में छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए इसका बजटीय प्रबंध हमने किया है। मान्यवर, प्रसन्नता की बात यह है कि शिक्षा में छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया है। किन्तु उनको जैसा परिवेश और जैसा संरक्षण दिये जाने की आवश्यकता है इसको दृष्टिगत रखते हुए छात्राओं के लिए विशेष प्रयास उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किये गये हैं। श्रीमन्, यह एक नई चीज इन्ट्रोड्यूस की जा रही है हम यह बताना चाहते हैं कि यह कभी इसके पहले नहीं था कि सभी विश्वविद्यालयों में संकायवार, एक संकाय के स्तर पर जो टॉपर स्टूडेंट हो उसको पुरस्कृत करने की योजना इस बजट के माध्यम से धन देकर और इस साल से नई योजना शुरू करने जा रहे हैं ताकि उनको प्रोत्साहित किया जा सके। और यह पहले नहीं था। मान्यवर, राष्ट्रीय सेवा योजना के सामान्य कार्यक्रमों में विशेष शिविरों का आयोजन करके 13 करोड़ 52 लाख 80 हजार का बजट उसके लिए भी प्राविधानित किया है। मान्यवर, विशेष बात यह है कि कई घटनाओं का जिक्र आया। निर्भया काण्ड का जिक्र आया। भारत सरकार ने उसके लिए निर्भया फण्ड के रूप में एक बड़े फण्ड की स्थापना की। उसके बाद भी किया। लेकिन आवश्यकता सिर्फ एक फण्ड के इंतजाम करने की नहीं है। जरूरत यह है कि उनको आत्मरक्षा के लिए तैयार किया जाये। उनका मनोबल ऊचां हो और बेटियों को आत्मरक्षा की कैसी ट्रेनिंग दी जाये, कैसे तैयार किया जा सके कि कोई असहज स्थिति आने पर आत्मरक्षा कर सकें श्रीमन, इसके लिए

इस बार हमने प्रबन्ध किया है और जो नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है इस वित्तीय वर्ष में जो नया सत्र आयेगा उसमें उनकी ट्रेनिंग के लिए और उनकी आत्मरक्षा के लिए तमाम प्रबन्ध किये जायेंगे, जिसमें जूडो, ताइक्वांडो और दूसरी चीजों की ट्रेनिंग का भी प्राविधान है और इसको अनिवार्य बनाने जा रहे हैं जो सभी महाविद्यालयों में छात्राओं को इसकी ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध करना पड़ेगा, इसका समुचित बन्दोबस्त किया। सरकारी राजकीय महाविश्वविद्यालय है, उसमें तो कर ही रहे हैं इसके अलावा भी प्रदेश भर की छात्राओं के लिए यह सुविधा अनिवार्य होगी। छात्रावास की आवश्यकता भी छात्राओं के लिए बहुत है, इसलिए श्रीमन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माणाधीन 26 राजकीय महाविद्यालयों में छात्रावास का निर्माण कराया जायेगा और उसमें 40 प्रतिशत कक्ष छात्राओं के लिए ही आरक्षित रखे जाने का प्राविधान किया गया है। श्रीमन, उच्च शिक्षा में लगभग पैंतीस सौ करोड़ विभिन्न छात्रवृत्तियों में छात्र–छात्राओं को पैंतीस सौ करोड़ रुपया, दूसरे विभागों के माध्यम से यह योजना संचालित है, उसमें भी इसका बन्दोबस्त किया जा रहा है। करीब पैंतीस सौ करोड़ रुपया उच्च शिक्षा में छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का काम कर रहे हैं। श्रीमन, अनेक प्रकार की कठिनाईयों और असुविधाओं के बावजूद भी केन्द्र सरकार से जो हमें योगदान मिलना चाहिए उसके न मिलने के बावजूद, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और जैसी उनकी दृष्टि है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो अभिनव कदम उठाये गये हैं, उनका परिणाम बहुत शानदार देखने को मिलेगा। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो बजट प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है, उसे सर्व–सम्मत से पारित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कटमोशन के लिए प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी का नाम है, वह तो हैं नहीं। इसमें विवाद नहीं होगा। कोई है ही नहीं तो प्रश्न रख दें, चर्चा करेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

यह आवंटित था प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी जी को लेकिन वह नहीं तो डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल भी प्रस्ताव रखेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं। इसे राज्यपाल की सिफारिश अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान की राशि घटाकर 01 रुपये कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना व सुझाव देना।

(श्री प्रदीप माथुर के सदन में उपस्थित होने एवं उनके द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह कैसे सम्भव है? जब डा0 साहब ने शुरू कर दिया तो फिर आप कहिये, माथुर साहब भाषण करेंगे। आपने कटौती का प्रस्ताव रख दिया तो आप बोलिये। बाद में माथुर साहब बोंलेंगे। जब आप नहीं थे, आपके दल का कोई नहीं था, न प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी थी, नम्बर आया और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उनको प्रस्तावित कर दिया, उन्होंने कटमोशन प्रस्तुत कर दिया। अब आप बाद में बोल लीजियेगा। एक विषय पर दो आदमी कैसे कटमोशन रखेंगे। दो लोग कैसे कटौती का प्रस्ताव रखेंगे, राधा मोहन दास जी ने रख दिया अब माथुर साहब आप भाषण भले कर दें पर आपका कटौती नहीं माना जायेगा, आप चर्चा प्रारम्भ कर सकते हैं।

(प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी के सदन में उपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष–

इतना तो सजग रहना चाहिए आप लोगों को। कटौती का प्रस्ताव रख गया है, जो आपको बोलना है, बोलिये।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे उच्च शिक्षा के बजट प्रस्ताव पर कटौती प्रस्ताव रखने का मौका दिया। कल अखिलेश यादव जी की सरकार ने 03 साल पूरे किये।

(इस समय 01 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मदन चौहान पीठासीन हुए।)

और इन तीन साल में पूरे समाचार–पत्रों, मीडिया में बहुत जोरदार तरीके से सरकार की उपलब्धियों का ब्योरा दिया गया, उन उपलब्धियों में और बजट में जो प्राविधान किये गये हैं, उसमें उच्च शिक्षा के सन्दर्भ में भी काफी दावे किये गये मुख्य मंत्री जी द्वारा यह बात कही गई ''डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी'', हम मानते हैं उनकी बात, बहुत अच्छी सोंच है, लेकिन इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, एक प्रदेश का सबसे बड़ा संसाधन क्या होता है, वह होता है मानव संसाधन। हमारी ऊर्जा और हमारी जो ताकत है, वह हमारी जनता है, वह इस प्रदेश में रहने वाले निवासी हैं और अगर हमको अपने प्रदेश को उन्नति की ओर अग्रसर करना है तो वह निश्चितरूप से तभी सम्भव होगा, जब हमारे नागरिक, यहां की जो पापुलेशन है, वह उसके लिए तैयार हो। इस 'ह्यूमन रिसोर्स' के लिए, उसको डेवलप करने के लिए दो चीजों की मूलरूप से आवश्यकता है, प्रथम है शिक्षा जो कि एक अच्छा नागरिक ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान ही नहीं बल्कि भविष्य में प्रदेश के लिए ऊर्जा पैदा करती है और दूसरी आवश्यकता स्किल डेवलपमेण्ट, कौशल विकास। जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, केन्द्र सरकार ने जब यूपीए का कार्यकाल था राईट टू एजूकेशन दिया, शिक्षा का अधिकार कानून दिया। इससे प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा को निस्तारण करने आपके ढांचागत इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए शिक्षा के लिए हर तरह का प्राविधान किया। ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में आये, उस पर अलग चर्चा हो रही होगी और मैं कह सकती हूं कि शिक्षा का जो स्तर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर आना चाहिए वह नहीं आ पा रहा है,

इसके अनेक कारण हैं। कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि 10 हजार करोड़ का नकल उद्योग उत्तर प्रदेश में चल रहा है। हायर एजूकेशन के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश के अन्दर जो विश्वविद्यालय और कालेज हैं उनके कारण हिन्दुस्तान के 06 सबसे ज्यादा कालेजों का प्रदेश हैं, उनमें आता है। हमसे पहले, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, राजस्थान है और भी हैं, लेकिन हम भी 06 में आते हैं। और सच्चाई क्या है, राज्य में 13 विश्वविद्यालय हैं और 26 प्राईवेट विश्वविद्यालय हैं और इन विश्वविद्यालयों के साथ–साथ जो कालेज हैं, उनकी बड़ी संख्या है। जो आंकड़े मैंने देखे करीब–करीब 06 हजार प्राईवेट कालेज हैं और उनमें मात्र 15 प्रतिशत कालेज ऐसे हैं, जो कि राज्य द्वारा पोषित हैं, जिनको राज्य से एड मिली हुई है और इनमें चाहे हमारी यूनिवर्सिटी हों, चाहे कालेज हों, इनमें जो इन्रोलमेण्ट है, जो पंजीकरण है उसमें अण्डर ग्रेजुएट लेविल पर बी0ए0 लेविल पर 80 प्रतिशत पंजीकरण होता है, 11 प्रतिशत ग्रेजुएट स्नातकोत्तर में, 07 प्रतिशत डिप्लोमा, 01 प्रतिशत पी0जी0 डिप्लोमा में होता है। केन्द्र सरकार ने 2012 में ए0आई0एस0एच0ई0, आल इण्डिया सर्वे आफ हायर एजूकेशन, इसको उन्होंने सर्वे करवाया और उस सर्वे में पाया गया कि प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी और कालेज होते हुए भी 12 जिले ऐसे हैं जिनमें जी0ई0आर0 सकल पंजीकरण दर बहुत खराब है और वहां पर कालेजेज व विश्वविद्यालय बनने चाहिए। मैंने पिछले साल के बजट में देखा, इस साल भी देखा, 2012–13 में 2013–14 में कहा गया कि हम इन–इन जनपदों में कालेज बना रहे हैं। अभी बन ही रहे हैं, तीन साल हो गया कालेज बन रहे हैं, एक भी कालेज कम्प्लीट नहीं हो पाया है, एक भी कालेज शुरू नहीं हो पाया है।

मेरा सरकार से एक सवाल है कि अगर आप एक मेट्रो दो साल में बना सकते हैं जो इतना काम्प्लीकेटेड काम है तो क्या हम एक महाविद्यालय की बिल्डिंग साल भर में नहीं बना सकते थे ? क्यों विलम्ब हुआ यह बहुत दुखदाई है। साथ ही साथ ही शिक्षा के स्तर में, क्वालिटी एजूकेशन में, हायर एजूकेशन में हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों से बहुत पिछड़ा हुआ है। उच्च शिक्षा में हम अग्रणी नहीं हैं जबकि हमारे यहां सेण्ट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि हम दुनिया की 1/5 आबादी हैं तो फिर हमारे यहां कहां कमी रह गई। मान्यवर, नैक जो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं मान्यता समिति है उसने कालेजेज या यूनिवर्सिटीज के मूल्यांकन के लिये 4 या 5 आधार बनाये हैं। उसमें यह है कि मूलभूत ढांचा कैसा है, शिक्षक मण्डल कैसा है जिसको फैकल्टी बोलते हैं, शोध का कार्य कैसा है और शिक्षण का कार्य कैसा है। हमें बड़ा अफसोस है कि नैक के मापदण्डों पर यू0जी0सी0 एक्रीडेशन मान्यता के लिये, जो सर्वेक्षण कराता है उसमें उत्तर प्रदेश के मात्र दो राज्य विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त कर सके हैं, एक गोरखपुर और एक लखनऊ विश्वविद्यालय और दोनों बी ग्रेड यूनिवर्सिटीज मानी गयी हैं। ए ग्रेड में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इसके अलावा, वे कालेजेज हैं तो जो राजकीय कालेजेज हैं, डिग्री कालेजेज हैं उनको नैक का कहीं पर भी एक्रिडिशन मान्यता नहीं मिल रहा है। लेकिन जो भी मान्यता नैक की मिल रही है वह प्राइवेट कालेजेज को मिल रही है और

बेनिफिट, (फायदा) भी उन्हीं को मिल रही है क्यों ? क्योंकि 2012 में केन्द्र सरकार का एक कार्यक्रम शुरु हुआ, जिसका नाम है रूसा (त्ै।) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान केन्द्र व प्रदेश के बीच 65 और 35 के अनुपात में यह कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि डिग्री कालेजेज में जो शिक्षण स्तर है शिक्षण का उसको बढ़ाया जा सके। आधार भूत सुविधायें बेटर हों, बेहतर हों। इसके साथ–साथ उन्नतशील कार्यक्रम बनाये जायें। हमारी जो इण्डस्ट्री है, उद्योग है उनके साथ स्टूडेण्ट्स और टीचर्स का 'इण्टरफेस' किया जाये ताकि छात्र/छात्राओं की क्वालिटी बेहतर हो लेकिन हमें बड़ा अफसोस है कि रूसा का जो फण्ड पिछले साल आया, वह इस्तेमाल नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में रूसा की मात्र एक मीटिंग हुयी है और उसका पैसा पड़ा हुआ है। एक बात और भी है कि अगर रूसा का फण्ड आ भी जाये तो वह उन कालेजेज को मिलेगा जिनको नैक की मान्यता है और नैक की मान्यता हमारे सरकारी कालेजेज को तो है नहीं। प्राइवेट कालेजेज को ज्यादा संख्या में है तो इसका लाभ भी उन्हीं को मिलना है। मेरा कथन यह है कि अगर हम कहते हैं कि इस प्रदेश को हमें प्रगति की ओर ले जाना है तो वे इन्स्ट्रूमेण्ट्स तैयार करने पड़ेंगे जो इस प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। हमारे सारे युवा प्राइवेट कालेजेज में नहीं पढ़ सकते हैं इसलिये गवर्नर्मेण्ट कालेजेज का स्तर बेहतर करना होगा, उनका शिक्षण का माहौल बेहतर करना होगा, उनको आधारभूत व्यवस्थायें देनी होंगी जो हम नहीं दे पा रहे हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जी0ई0आर0 बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, अगर हम नैक की स्पेशिफिकेशन्स के अनुसार उन कालेजेज को या यूनिवर्सिटीज को अपग्रेड नहीं करते या उच्च स्तर तक नहीं लाते। अब समस्यायें कहां–कहां हैं? हमारे मुख्य मंत्री जी का एक लक्ष्य है, एक विजन है, वे चाहते हैं कि इस प्रदेश में रोजगार आये, वे चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के बच्चे पूरी दुनिया में जाकर अपना नाम कमायें। वे खुद भी इंजीनियर हैं उनका उच्च शिक्षा में बहुत अच्छा दखल है तो फिर ऐसा क्यों हैं कि पालिसी क्राइसिस है। कहीं न कहीं नीति का निर्धारण सही नहीं है, यदि नीति बनती है तो उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा इसका एक उदाहरण ले लीजिये कि कितनी सीरियस है यह गवर्मेण्ट यानि की कितनी गंभीर है। 3 साल में 11 सचिव बदले हैं उच्च शिक्षा विभाग में। यह बताता है कि आप कितने गम्भीर हैं। तो पालिसी का इम्प्लीमेण्टेशन कैसे होगा। जब तक एक सचिव मीटिंग करता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है। अभी सुना है कि एक ट्रांसफर हुआ है और नया सचिव अभी तक ज्वाइन भी नहीं कर पाया है। दूसरा आप वेबसाइट देख लीजिये, मुझे बोलना था तो मैंने आपकी वेबसाइट देखी। आप यहां पर लखनऊ में एक आई0टी0 सिटी बना रहे हैं और वेबसाइट की पोजीशन यह है कि बैक डेटेड है।

एक भी वेबसाइट आपकी अपडेटेड नहीं है यही स्थिति हर विभाग की है। आप जो इन्फॉर्मेशन आप जो देना चाहते हैं उतनी ही मिल रही है। नैक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जी0ई0आर0 की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, रूसा पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कितने कालेजेज में कितनी वैकेन्सीज हैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो फिर क्या फायदा। अगर हमको इण्टरनेट पर अपनी सरकार की गतिविधियों की जानकारी न मिले

तो फिर मैं कहूंगी कि आप फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एजूकेशन को आगे नहीं ले जा सकती हैं, ये बातें। फिर फैकल्टीज शिक्षक मण्डल देख लीजिए यूनिवर्सिटीज और कालेजेज में शिक्षकों के 12000 पद हैं, उसमें से 50 प्रतिशत रिक्त पड़े हैं। क्या फैकल्टीज चलेगी, कैसे चलेगी ? अभिषेक जी बैठे हैं, ये आई0टी0 में पढ़ा चुके हैं। आपके माध्यम से मैं इनसे पूछना चाहती हूं, आपकी सरकार से पूछना चाहती हूं कि अगर फैकल्टी नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी, क्यों नहीं है फैकल्टी ? ऐसा इस लिये नहीं है क्योंकि अभी गर्वमेंट ने छठे वेतन आयोग के बाद प्रमोशन पॉलिसी ही नहीं बनाई, नियुक्ति की पॉलिसी नहीं बनाई। आप अगर पांच–पांच साल लगा देंगे और वर्ष 2010 से 2015 तक आपके पास पॉलिसी नहीं होगी, नियुक्तियां नहीं होंगी, फैकल्टी नहीं होगी तो विचार करें कि कितना डिमोलाइजेशन है कितने हतोत्साहित हैं अध्यापक लोग, प्राध्यापक लोग, जो अपनी उन्नति नहीं देख पा रहे हैं अपनी सर्विस में। प्रमोशन पॉलिसी भी नहीं है। पोस्ट डिग्री कालेजेज के बारे में कहना चाहूंगी कि जब छठा वेतन आयोग आया तो यू0जी0सी0 द्वारा कहा गया कि पोस्ट डिग्री कालेजेज को प्रोफेसर की पोस्ट दे दीजिए। पोस्ट डिग्री कालेज में रिसर्च करने की सुविधा दे दीजिए। एक संस्थान की काबिलियत उसके शोध के कार्य से होती है ? कि कैसे शोध उस संस्था में हो रहे हैं लेकिन यहां सारे शोध बंद है, क्योंकि कहा कि अभी कम्बाइण्ड टेस्ट द्वारा शोध के स्टूडेन्ट सेलेक्ट होंगे, छात्र चुने जाएंगे लेकिन और वर्ष 2010 से लेकर आज तक वह भी पॉलिसी नहीं बनी कि किस बेसिस पर आप टेस्ट करवाएंगे, सेलेक्शन करेंगे। और प्रमोशन की बात करें तो वह इसलिए रूके हुये हैं कि प्राध्यापकों का असेसमेंट होना है मूल्यांकन है उनकी अकेडमिक एक्टिविटी में उसके कन्ट्रीब्यूशन का मूल्यांकन होना है। मूल्यांकन में रिसर्च कितनी कराई वह भी सम्मिलित है। तो जब रिसर्च के लिए स्टूडेन्ट ही नहीं हैं तो फिर कहां से रिसर्च की क्वालिफिकेशन मिलेगी। इसी लखनऊ में कैपिटल सिटी में हमारी राजधानी में लखनऊ यूनिवर्सिटी पोस्ट डिग्री कालेजेज को शोध करने का अधिकार नहीं दे रहा है, तो यह कैसे चलेगा, इसको आपको बदलना पड़ेगा। मैं बार–बार कहती हूं कि सिर्फ पैसा दे देने से, भवन बना देने से, उच्च शिक्षा का सुधार नहीं होगा। उच्च शिक्षा का सुधार होगा, जी0ई0आर0 से लेकर पूरे शिक्षण मण्डल को बेहतर बनाने से, वातावरण को बेहतर बनाने से, स्टूडेन्ट्स को वह फैसल्टीज दें वह सुविधायें दें, जिससे वह शोध कर सकें, परन्तु ऐसा नहीं हो पा रहा है। हमारे जो प्रोफेशनल कालेजेज हैं, उनका मैं थोड़ा–सा जिक्र करना चाह रही हूं। यू0पी0टी0यू0 में मान्यता प्राप्त 922 कालेजेज हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

इन्सीडेन्टली मैं आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहता था लेकिन टैक्नीकल एजूकेशन डिपार्टमेंट अलग है। यू0पी0टी0यू0 अलग है, टैक्निकल एजूकेशन से सम्बन्धित इश्यू पर अगर बात करेंगी तो वह अलग है। मैं सिर्फ आपकी मद्द के लिए कह रहा था।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

अच्छा मैं इसको स्किप कर दूंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि अगर हायर एजूकेशन में जस्ट ए पासिंग रिफरेन्श यू0पी0टी0यू0 की अगर आप हालत देख लें, इंजीनियरिंग कालेजेज बड़ी संख्या में बंद हो रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में आपके एम0बी0ए0 के कालेजेज, मैनेजमेंट कालेजेज बंद हो रहे हैं, तो अगर हमारी टैक्नीकल एजूकेशन सफर कर रही है, नार्मल (सामान्य) एजूकेशन सफर कर रही है। और हम सिर्फ बी0ए0 पास निकाल रहे हैं, तो हम इस प्रदेश के जरिए कौन–सा मैनपॉवर इस देश को देना चाहते हैं। भारत सरकार ने जो हमारे प्रदेश के लिए सुविधायें दी हैं, जो योजनाएं दी हैं, पूरे प्रदेश के लिए, उसका इस्तेमाल कब करेंगे ? कब हम गंभीर होंगे अपने हायर एजूकेशन को लेकर, कब हम अपनी यूनिवर्सिटीज के स्तर को ऐसा करेंगे कि 'ए' ग्रेड हमारी कोई यूनिवर्सिटी बन सके। एक भी 'ए' ग्रेड यूनिवर्सिटी जिस प्रदेश में न हो और 'ए' ग्रेड डिग्री कालेजेज न हो, तीन साल में एक भी जो हमारे जी0ई0आर0 से वंचित इलाकें हैं, जिले हैं, उनमें कालेज न बन सके तो मैं यह गम्भीर बाते हैं। मैं यह समझती हूं कि इन बातों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। मैं इस बात से तो प्रसन्न हूं कि आपने फण्ड का एलोकेशन किया परन्तु क्योंकि उस फण्ड का एलोकेशन उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, पॉलिसी इम्पलीमेन्टेशन क्राइसेस है, इसलिए मैं यह समझती हूं कि जो बजट में प्रावधान किया गया है अनुचित है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षकों के जो प्रमोशन हैं, उनकी जो नियुक्तियां हैं, उनकी पॉलिसीज को तत्काल इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सिक्स पे कमीशन के अनुसार जो भी प्राविधान हैं उन्हें आप लागू करें इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि जिस प्रदेश में शोध की कमीं हो, जिस प्रदेश में शिक्षण मण्डल की कमीं हो जिस प्रदेश में कालेजेज में माडर्न टीचिंग मैथड्स न हो, इन्टर एक्टिव बोर्डस न हो, एलसीडी न हो वह कालेजेज राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी कम्पीट नहीं कर सकते है। अगर कम्पीट करना है तो मैं आपसे निवेदन करती हूं कि क्वालिटी एजूकेशन पर ज्यादा जोर दीजिए और अपनी वेबसाइट को आप रिन्यू करिये उसको अपडेट करिये। धन्यवाद।

'श्री दलवीर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बहुत शार्ट में 2–4 बात कहने वाला आदमी हूं जो व्यावहारिक क्षेत्र में मैं देख रहा हूं । मैंने अभी माननीय सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने एक सवाल भी रेज किया उन्होंने घोषणा की थी अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी बनाने की एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाने की एक तो मैं चाहूंगा कि सरकार उस पर बताये कि क्या कर रही है। आगरा यूनिवर्सिटी हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे शायद पुरानी है मैं ज्यादा इतिहास नहीं जानता लेकिन मुझे जानकारी हैं मैं उसका छात्र रहा हूं। वहां इस कदर बेकदरी है, इस कदर भ्रष्टाचार और बेइमानी हैं इसे मैं महामहिम साहब को भी अवगत करा चुका हूं माननीय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री जी को भी अवगत करा चुका हूं जिसमें एक उच्च स्तरीय आगरा मंडल के आयुक्त के अधीनस्थ एक जांच कमेटी बनी थी सवाल जब मैंने विधान सभा में डाला जवाब आया कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है यह कहते कहते सवाल डालते डालते यह तीसरा सत्र चल रहा है, कोई जवाब प्रापर वहां से नहीं आया तो मुझे बड़ा दुख होता है जहां उच्च शिक्षा के लिए आप इतना प्रयत्न कर रहे हैं, बजट एलोकेट कर रहे हैं बहुत कुछ प्रयास, भागदौड़ भी कर रहे हैं लेकिन जब तक व्यवस्थाएं व्यवस्थित सरकार नहीं करेगी आगरा यूनिवर्सिटी के दोषी कर्मचारी जो भी हैं चाहे वह छोटे हों चाहे बड़े हों उनको दण्डित नहीं करेंगे तब तक व्यवस्था सुचारू ढंग से नहीं चलेगी। गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी नोएडा में शायद आप भी वहां से ताल्लुक रखते हैं इतनी सुन्दर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है कि मैं खुद वहां देखने गया मुझे वहां जानकारी हुई रजिस्ट्रार और वी0सी0 से मेरी बात हुई उन्होंने बताया कि हमारे 40 लेक्चरर यहां से पलायन कर गये क्योंकि उनकी सेवायें न तो स्थायी की जा रही है और न ही उनकी सेवाओं के संबंध में किसी को कोई चिन्ता है। जो अच्छे प्रोफेसर थे वहां गौतमबुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में सब चले गये और बच्चे जो भी एडमीशन लिये हुए हैं वहां बड़े प्रतिभाशाली बड़े सुयोग्य बच्चे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के कम्पटीशन को कम्पीट करने के बाद वहां उनका दाखिला हुआ है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री या जो भी हमारे चौधरी साहब जवाब दे रहे हैं उनको अवगत कराना चाहता हूं कि इन गम्भीर मुद्दों पर जरूर चिन्ता की जानी चाहिए क्योंकि यह उन बच्चों का भविष्य का सवाल है जो वहॉ कम्पटीशन के बाद एडमीशन लिये हुए हैं। वहां उपयुक्त न तो लेक्चरर हैं न कोई व्यवस्था है न पूरा स्टाफ है यूनिसर्विटी की बिल्डिंग शायद आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी इतनी भव्य बिल्डिंग बनी हुई है जिसका कोई जवाब नहीं है। तीसरा, मैंने एक राजकीय महाविद्यालय अपने मंत्री कार्यकाल में अपने क्षेत्र में बनवाया, ग्रेजुएट तक है तहसील गभाना मेरी खुद की तहसील है मैने बार बार लिखा है लड़कियों के पढ़ने का एक मात्र साधन गभाना है जहॉ पूरे क्षेत्र की लड़कियां पढ़ने आती हैं वहॉ पोस्ट ग्रेजुएट क्लास खोलने के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गयी है बिल्डिंग बनकर तैयार खड़ी है। बहुत आलीशान बिल्डिंग है मैंने जगह दी है नेशनल हाइवे के बिलकुल लगे हुए बिल्डिंग हैं तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी में जो भ्रष्टाचार अंकपत्रों में, सर्टिफिकटों में व्याप्त है उसकी बहुत शीघ्रता से जांच कराकर दोषियों को दण्डित कराने गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर लेक्चरर की कमीं है उसको पूर्ण कराने और गभाना राजकीय विद्यालय में जो एक मात्र विद्यालय है उसमें पोस्टग्रेजुएट क्लास खुलवाने के साथ–साथ अध्यापकों की व्यवस्था करायें इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विपक्ष ने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया। मैंने शुरू में जो निवेदन किया था कि इसको सर्वसम्मति से पारित

किया जाये, तो आपने देखा कि कटौती प्रस्ताव के लिये जिस माननीया सदस्य का नाम पुकारा गया, वह सदन में नहीं थी। डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने तकनीकी तौर पर उसका पाठ कर दिया। तकनीकी तौर पर उन्होंने इस प्रस्ताव को रख दिया और पुनः जब डा0 रीता बहुगुणा जी इस पर अपना भाषण कर रही थीं, तो उन्होंने न पहले सुना कि बजट में क्या प्राविधान किये गये हैं और न वह अपने सवालों के उत्तर में कुछ सरकार से जानना चाहती थी क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता था। जो कुछ कहा गया है अगर उन्होंने सुन लिया होता तो शायद वह अपना भाषण ही नहीं करती, क्योंकि जितने बिन्दुओं का उन्होंने उल्लेख किया है उन सबका प्राविधान बजट में पहले से है। जो बात मैंने कही थी वही सवाल उन्होंने उठाये, इसलिये उनको धन्यवाद कि सरकार की उपलब्धियों को उन्होंने ऐसे प्रश्न के रूप में उपस्थित किया जिसका संज्ञान सरकार ने स्वयं लिया है और उसको पूरा करने की दिशा में काम किया है, इसलिये उसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन आधारभूत सुविधायों की वृद्धि की वह चिंता कर रही थी, उनका हमने पहले ही प्रबंध किया है। मान्यवर उन्होंने कहा कि फैकल्टी नहीं है तो सदन में यह उल्लेख करना जरूरी है कि बहुजन समाज पार्टी की जो पिछली सरकार थी तो पांच वर्ष तक जो चयन का आयोग है उच्च शिक्षा का, उनके पॉच साल तक उस आयोग में कोई बैठा ही नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसलिये जब माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार आई तब उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग ने काम करना शुरू किया और अब सभी रिक्तियों को भरने के लिये बहुत त्वरित गति से कार्यवाही चल रही है, जल्दी से यह सारी रिक्तियां पूरी हो जानी है। फैकल्टी के कम होने की जो सबसे बड़ी वजह है वह यह है कि उस पर इन्हें जरूर जानकारी होनी चाहिये कि चूंकि पांच वर्ष तक पिछली सरकार में जब कुछ हुआ ही नहीं, जब आयोग ही नहीं था तो नियुक्तियां होती कहां से ? इसलिये जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उसको फंक्सलन किया और उसको फंक्सलन करने के बाद तमाम रिक्तियों को भरने की कार्यवाई तेजी से चल रही है, जो आपने एक चिंता व्यक्त की कि

(प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी के बीच में कुछ बोलने पर)

रिक्तियां निकल तो गई। यह पिछली साल बताती, अब यह भी निकल गया आपका औजार। एक साल बाद। जो आपने एक बात की चिंता कि जो जी0आर0ई0 की आपने बात की, उस आधार पर और रूसा की जिस योजना की आपने चर्चा की, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि अब कोई भी विकास खण्ड किसी भी स्थिति में शत प्रतिशत विकास खण्ड सेवित हो जायेंगे। हमने इस बजट में जो प्राविधान किया है और सुनिश्चित किया है कि अब कोई भी विकास खण्ड अछूता रहने वाला नही है, जो विकास खण्ड छूट गये थे इस उच्च शिक्षा से सेवित होने से वह इस वर्ष पूरे कर लिये जायेंगे, हमने उसका बन्दोबस्त किया है। मुझे अच्छा लगता कि अगर आपने सरकार की इस योजना की तारीफ की होती, चूंकि आपने यह सुना नहीं कि विशेषकर लड़कियों की

आत्मरक्षा के लिये जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम हमने कम्पल्सरी करने उठाया है। नैक के बारे में आपकी चिंता जायज है, हमने खुद इसको स्वीकार किया कि हमारे लिये यह शर्म की बात है कि विश्व के दो सौ विश्वविद्यालयों में हमारा कोई विश्वविद्यालय नहीं है, हमारी अपनी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठता महोदय, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव जी, ने कटौती पर बल देने के लिये तैयारी की थी और सम्भवतः ऐसा हो गया कि वह अब कुछ रख नहीं पाई विषय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उनको कुछ प्रश्न पूछ लेने दीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, अब उचित नहीं है, अब वह अवसर निकल गया, अब ठीक नहीं होगा। डाक्टर साहब दिक्कत आयेगी।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

स्पष्टीकरण के रूप में पूछ लेंगी।

श्री अधिष्ठाता–

अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, इसके बाद वह अपना स्पष्टीकरण रख लें।

श्री अम्बिका चौधरी–

ठीक है, आप अपना स्पष्टीकरण पूछ लें, आपकी बात आ जायेगी स्पष्टीकरण में, हम तैयार हैं। श्रीमान्, इस प्रकार जितने सवालों को आपने उठाया है उन सभी सवालों पर सरकार स्वयं कदम उठाने की कार्यवाही करके अपनी चिंता व्यक्त कर रही है। सिर्फ शब्दों में चिंता व्यक्त करने की बात नहीं है बल्कि उन सवालों को सरकार ने स्वयं संज्ञान लेते हुए कि कैसे उन कमियों को दूर किया जाये। नैक वाली बात बहुत महत्वपूर्ण थी और मैंने स्वयं उल्लेख किया था इसका और इसके लिये हम इसको अनिवार्य भी कर रहे हैं सबके लिये। प्राइवेट कालेजेज को कोई नैक का लाभ नहीं मिला है। ...

(इस समय 02 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

वह जो आपकी एक बात थी, वह सही नहीं है कि प्राइवेट कालेज उसका बड़ा लाभ उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है, प्राइवेट कालेज उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की जरूर है कि हमारे राजकीय जो विश्वविद्यालय और कालेज हैं, उनमें इसको अनिवार्य रूप से किया जाय यह हम उल्लेख कर देंगे, उसके लिये निर्देश जारी किये जा चुके हैं। जहां तक सिक्स्थ पे कमीशन के प्रावधान की बात है, सिक्स्थ पे कमीशन को तो हमने उच्च शिक्षा में पूरी तरह से एडाप्ट किया है और सिक्स्थ पे कमीशन के अनुसार सारी सुविधायें, जो उसके पात्र हैं, उनको हम देने का काम कर रहे हैं। अब कोई बात अधूरी है ही नहीं। इसलिये मान्यवर, मेरा पुनः अनुरोध है कि उच्च शिक्षा के इस बजट को, जो मैनें आपकी अनुमति से प्रस्तुत किया है, इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिये और आदरणीय श्री दलवीर सिंह जी ने जो बात कही है, अलीगढ़, आगरा और

नोएडा की, तीन जगहों का आपने उल्लेख किया है, आपने जो बॉतें कहीं हैं, उसको बहुत गंभीरता से देखकर इस संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं यह जानकारी करना चाहती हूं कि उच्च शिक्षा का जो बजट पेश हुआ है, उसमें पिछले साल का परिव्यय तो ज्यादा दिखाया गया है लेकिन पिछले साल ही उपलब्धि कुछ नहीं थी । उपलब्धि जीरो दिखाई गयी है। आपके जो महाविद्यालय हैं, उनके विकास के लिये जो कार्यक्रम बनाये गये हैं, उसमें महाविद्यालयों को तीन भागों में बांटा गया है, यह तीन भागों में बंटवारे का आधार क्या है, वह स्पष्ट नहीं है। आपने कहा है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंदर माडल डिग्री कालेज होगा। यह माडल डिग्री कालेज की कौन सी विशेषतायें हैं, माडल डिग्री कालेज की जो आप छंटाई कर रहे हैं, उसके मानक क्या हैं। क्या डिग्री कालेजों के अंदर, राजकीय कालेजों के अंदर भी यह भेद पैदा किया गया है। आप घोषित करते हैं कि मात्रात्मक और गुणात्मक उन्नति किया जायेगा लेकिन गुणात्मक उन्नति में हम जीरो हैं। आपने दूसरी कैटेगरी में राजकीय महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधायें देने की बात कही है और तीसरी कैटेगरी में कुछ नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की है, समझ में नहीं आता कि बिना किसी आधारभूत व्यवस्था के कोई डिग्री कालेज हो सकता है क्या ? आधारभूत सुविधा तो हर डिग्री कालेज को चाहिये। चाहे वह नया हो चाहे वह पुराना हो। अगर आप नया कालेज खोल रहे हैं और उसमें आधारभूत सुविधाओं की बात नहीं करते हैं तो क्या अब पुराने कालेज में आधारभूत की स्थापना होगी, यह बंटवारा जो है, आपका बड़ा आधारहीन है। हर कालेज में आधारभूत स्थापना चाहिये और बिना उसके कोई डिग्री कालेज नहीं हो सकता और अगर वह डिग्री कालेज है तो आधारभूत सुविधाओं की स्थापना हो चुकी है। यह मानकर हम चलेंगे कि आप इसको बीच में बंटवारा करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जो नये महाविद्यालय खुल रहे हैं, वह कमजोर विद्यालय है। बिना आधारभूत संस्थाओं की स्थापना किये आप डिग्री कालेज बनाते कैसे हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी–

अब हो गया, आपने कई स्पष्टीकरण पूछ लिये । अब यह पूरा भाषण कैसे होगा ?

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

मान्यवर, बजट के अध्ययन करने से ऐसा लगा कि इस बजट में पूर्वी उत्तर प्रदेश की बड़ी उपेक्षा की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, महिलायें जो देश की आधी आबादी कही जाती है, जिनके सुदृढ़ीकरण के बड़े–बड़े नारे दिये जाते हैं, उसकी भी बड़ी उपेक्षा है। जैसे कि 138 महाविद्यालय प्रदेश में हैं, इसमें 42 स्नातकोत्तर के हैं और 96 स्नातक स्तर के हैं। लेकिन महिलाओं के लिये कुल कितने महाविद्यालय हैं, यह इसमें स्पष्ट नहीं हुआ है। आपने राजकीय महाविद्यालय विस्तार कार्यक्रम में 16 महाविद्यालयों का राजकीय महाविद्यालयों के रूप में चयन किया है, इसमें महिलाओं के

केवल चार महाविद्यालय हैं, यह आपका दृष्टिकोण दिखाता है कि आप महिलाओं की एजूकेशन में कितनी रूचि ले रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं अवगत कराऊॅ कि इस पर चर्चा हो चुकी है, मैं उत्तर दे चुका हूं यह स्पष्टीकरण मात्र है।

श्री अध्यक्ष–

जो इनके स्पष्टीकरण हैं, उसका आप उत्तर दे दीजिये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं दे देता हूं । अब भाषण नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष–

ज्योत्सना जी, अब आप बैठ जायें ।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, सदन में किस प्रकार चर्चा होती है और मंत्री जी किस प्रकार झिड़क कर कह रहे हैं कि बैठो–बैठो, यह सदन के अंदर कोई आचरण है। इतनी सीनियर सदस्या बोल रही हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, बैठो–बैठो सुरेश राणा जी। मैं जानता हूं।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

आप कहेंगे कि को–एजूकेशन कर दिया। को–एजूकेशन में महिलाओं को वह सुविधा नहीं मिलती जो महिला महाविद्यालय में मिलेगी। अब महिला महाविद्यालय केवल आप चार खोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह तो आप बजट भाषण कर रही हैं, भाषण तो आपने पहले दिया नहीं, जब उत्तर आ गया तो बजट भाषण का क्या मतलब है।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आपने नये महाविद्यालय खोले। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में 26 महाविद्यालयों को शामिल किया गया है जिसमें पूर्वी उ0प्र0 के केवल दो हैं।

श्री अध्यक्ष–

जब चर्चा हो रही थी तब आपको बोलना चाहिए था, आपने चर्चा में तो भाग नहीं लिया अब स्पष्टीकरण में इतना क्यों पूछेंगी।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

मान्यवर, बनारस के बारे में थोड़ा बोल लें।

श्री अध्यक्ष–

हां, ठीक है, बनारस के बारे में कह लीजिए।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

मान्यवर, वाराणसी महानगर में तीन निजी महाविद्यालय हैं और तीनों दशकों पुराने हैं कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं खुला है,एक निजी अभी नया खुला है। दुःख की बात यह है कि किसी भी निजी महाविद्यालय में बी0कॉम या बी0एस0सी0 नहीं है। दो महाविद्यालयों अभी बी0कॉम खोला गया है। युद्ध के पैमाने पर चेष्टा करने के बाद आपका एक राजकीय महाविद्यालय जिले में खुला। राजकीय महाविद्यालय में बच्चियां चिल्लाती रह गईं कि हमें बी0कॉम0 पढ़ने की सुविधा दी जाएं जो कि नहीं मिला। आश्चर्य यह है कि पूरे वाराणसी महानगर में, बी0एच0यू0 को आप छोड़ दीजिए तो महिलाओं को बी0एस0सी0 पढ़ने की सुविधा कहीं नहीं है। अन्त में एक बात और कहना चाहूंगी कि आप हमको केवल एक नया राजकीय महिला कॉलेज दीजिए जिसमें महिलाओं को बी0एस0सी0, बी0कॉम0 पढ़ने की सुविधा मिले। यह कमी बनारस में बहुत खलने वाली हो गई है क्योंकि बनारस का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्तर बहुत ऊॅचा है इसके बावजूद महिलाओं की पढ़ाई की व्यवस्था बहुत पिछड़ी है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने बहुत सारी बातों को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, दो–तीन बातें आपने महत्वपूर्ण उठाई हैं उन पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा। आपने कहा कि पूर्वांचल की उपेक्षा, मैं तो समझ रहा था कि आप पूर्वांचल के लिए सरकार को धन्यवाद् देंगी, क्योंकि दो विश्वविद्यालय जिनका मैंने उल्लेख किया, सिद्धार्थनगर में विश्वविद्यालय और इलाहाबाद में राजकीय विश्वविद्यालय यह दोनों पूर्वांचल में हैं और आपने पूर्वांचल की उपेक्षा की बात कही है। इसमें कोई पूर्वांचल की उपेक्षा की बात नहीं हैं क्योंकि दोनों विश्वविद्यालय पूर्वांचल में हैं। महिलाओं की बात आपने कही, पहली बार लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए तैयार करने का सारा प्रबन्ध हमने किया। छात्रावासों का जो निर्माण होगा, उसमें 40 प्रतिशत आरक्षण लड़कियों के लिए, अनिवार्य रूप से प्रावधान छात्रावास का प्रावधान किया गया। 40 प्रतिशत मिनिमम छात्रावासों का प्रावधान लड़कियों के लिए गया इसके अतिरिक्त जो छात्राओं के लिए प्रबन्ध किये गये हैं उनको मैंने अपने भाषण में पहले ही बता दिया था, इसलिए उनको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने कहा कि तीन प्रकार के महाविद्यालय समझ में नहीं आते। तीन प्रकार के महाविद्यालय इस प्रकार हैं कि एक राजकीय महाविद्यालय है, दूसरा सहायता प्राप्त यानि कि ऐडेड महाविद्यालय है और तीसरा स्ववित्तपोषित महाविद्यालय है यह तीन प्रकार की कैटेगरी है। आप सब जानती हैं लेकिन आपने पूछ दिया इसलिए मजबूरी में मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं जबकि इसकी आवश्यकता नहीं है। उनकी जो शिक्षण की क्वालिटी यानि कि गुणवत्ता में कैसे सुधार हो, मूल्यांकन उनका हम कैसे करायें इसके बारे में मैं विस्तार से बता चुका हूं, इसको भी दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मेरी विनती है कि इस पर चर्चा पूरा हो चुकी है इसलिए इसको पारित करायें।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

मान्यवर, मेरा एक स्पष्टीकरण है, मैं यह आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आगरा में एक बहुत बड़ा महाविद्यालय है आगरा कॉलेज, आगरा और ऐसे कई महाविद्यालय प्रदेश में भी होंगे जहां पर सरकार ट्रस्ट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेम्बर मनोनीत करती है यानि कि जनता के प्रतिनिधियों को या समाज के लोगों को वहां पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है जिससे कि शिक्षा में वह अपने विचार रख सकें लेकिन पिछले आठ–दस सालों से आगरा कॉलेज में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के कोई मेम्बर सरकार मनोनीत नहीं कर रही है जिससे कालेज के मैनेजमेंट में और इंजीनियरिंग संकाय की गवर्निंग बाडी भी उनकी कोई भागीदारी नहीं हो रही है तो क्या सरकार ऐसा करने जा रही है। दूसरा मान्यवर, यह कि आगरा में बहुत बड़ा महाविद्यालय है आर0बी0एस0 कॉलेज, जो कृषि के शोध और अनुसंधान की दृष्टि से अगर उसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मान्यता मिल जाएं।

श्री अध्यक्ष–

वह तो कृषि विश्वविद्यालय का मामला है, आपने नॉलेज में ला दिया, बस ठीक है।

श्री बब्बन सिंह चौहान–

मान्यवर, चन्दौली जनपद में।

श्री अध्यक्ष–

अब कुछ नहीं बैठिये, चूंकि उन्होंने आगरा का पूछ लिया तो आप भी खड़े हो गये, आप बैठ जाइये, जिद न किया करें, हमको भी कुछ अधिकार है।

श्री बब्बन सिंह चौहान–

चन्दौली जनपद में छात्र–छात्राओं के लिए बी0एस0सी0 की शिक्षा के लिए भी स्कूल नहीं हैं। कोई ऐसी व्यवस्था बन जाएं, कम से हजारों नौजवान वहां पढ़ें, इसको इस बजट में शामिल करवा लें।

अध्यक्ष–

कटौती प्रस्तुत करने वाले मा0 सदस्य हैं नहीं, किससे पूछें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 23,74,93,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–69 व्यावसायिक शिक्षा विभाग

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास (श्री अभिषेक मिश्र)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–69–व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,59,03,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग एक नया विभाग कुछ दिनों पहले सृजित किया गया और यह बखूबी दर्शाता है कि आजकल समाज में जो एक व्यवस्था की जरूरत है, जो शिक्षा में बदलाव की जरूरत है वह इस लेबिल पर इंगित कर रही है कि हमको उसे इण्डस्ट्री से जोड़ना पड़ेगा। जो हमारी कार्यशैली है, जो हमारी एजुकेशन है, उसमें इम्पलॉयबिलिटी जो इम्पलॉयमेंट का कनेक्ट है उससे जोड़कर हमें देखना होगा, उसको डेवलप करना होगा। यह इल्जाम हमारी शिक्षा पर लगता रहा कि हम सिर्फ बी0ए0/एम0ए0 प्रोड्यूस करते हैं और उनको सीधे–सीधे रोजगार से जोड़ने का प्रयास नहीं किया जाता है। तो यह व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग जो है यह इस उद्देश्य से बनाया गया और इसमें मा0 मुख्यमंत्री जी ने जब समाजवादी सरकार बनी तो बहुत ही विजनरी कदम उठाया, एक बहुत ही बड़ा कार्य जैसाकि अभी हिन्दुस्तान के किसी दूसरे प्रदेश

(इस समय 02 बजकर 11 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मदन चौहान पुनः पीठासीन हुए।)

में नहीं किया गया, वह काम किया गया स्किल डेवलपमेंट को एक मिशन मोड के माध्यम से स्थापित करके, यू0पी0 स्किल डेवलपमेण्ट मिशन का नाम दे करके उसको इम्पलीमेंट किया जायेगा। उस स्कीम को, इनरोलमेंट को ओपेन किया गया और मैं आपको यह बताते हुए खुशी महसूस करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के इस मिशन को, समाजवादी सरकार के इस इनीशियेटिव को, लोगों से बहुत प्यार और विश्वास मिला और तकरीबन 46 लाख लोगों ने स्किल डेवलेपमेंट मिशन में रजिस्टर्ड किया उसको पाने के लिए। इसी तरीके से मा0 अधिष्ठाता महोदय, व्यावसायिक शिक्षा में जो आई0टी0आईज का इन्स्टीट्यूशन है उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किया गया है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 217 मुख्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं और 50 संस्थान उनमें से ऐसे हैं जिसमें महिला शाखा स्थापित हैं और संचालित हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 267 आई0टी0आईज हैं जिनकी कुल क्षमता 88,774 सीटों की है। पूरे प्रदेश में 11 स्वतन्त्र रूप से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं के लिए स्थापित हैं एवं सामान्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त है। यह यह दर्शाता है कि इस विभाग में महिलाओं के प्रति जो सजगता होनी चाहिए जो कि समाज का 50 प्रतिशत का एक रेशियो है, उनके इम्पावरमेंट पर जो

ध्यान दिया है समाजवादी सरकार ने, यह इसका परिलक्षक है। प्रदेश में 64 ऐसे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं जो कि स्पेशल कम्पोनेंट सब प्लान के अंतर्गत स्थापित किये गये हैं, उनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जिनको समाज में आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिनको अलग से मद्द करने की जरूरत पड़ती है, हैण्ड–होल्डिंग की जरूरत होती है, ऐसे वर्ग के लिए 70 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है और अन्य पिछड़े वर्ग को 15 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है। प्रदेश के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रदेश में 1560 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनकी प्रशिक्षण क्षमता आज की तारीख में 1,97,820 लोगों की है। प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की ओर निजी क्षेत्र का इतना बड़ा रुझान इस विभाग की महत्ता को और इस विभाग से जुड़े हुए कार्यशैली को, उसकी अच्छाई को दर्शाता है प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लगभग 6 लाख अभ्यर्थी प्रतिवर्ष प्रवेश लेने हेतु परीक्षा में शामिल होते हैं। यह आंकड़े इस विभाग की समाज में विश्वसनीयता और अपेक्षाओं को प्रदर्शित करता है।

अधिष्ठाता महोदय अब मैं यह बताना चाहूंगा कि हम लोगों को जो बजट पिछली साल हाउस ने दिया था उससे हम लोगों ने क्या क्या कार्य किए हैं। पिछले एक साल में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं माननीय मुख्य मंत्री जी इस विभाग को बहुत क्लोजली मानीटर करते हैं और चाहते हैं कि इस विभाग के माध्यम से हम लोगों को स्किल कर दें उनको, हर आदमी तक हुनर पहुंचा सकें। जिससे इसको रोजगार से सीधे–सीधे जोड़ा जा सके। वर्ष 2014–15 में जो काम हमको मिले थे जो हमको बजट मिला था उससे हमने जो प्रमुख कार्य कराए हैं मैं उससे हाउस का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। केन्द्र पुरोनिधानित योजना जो सेंट्रल स्पांसर्ड स्कीम होती हैं उनमें सेन्ट्रल आफ एक्सीलेंस डोमेस्टिक फंडिंग और विश्व बैंक फंडिंग दोनों मिलाकर 10 व 16 कुल मिलाकर 26 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, उनमें उच्चीकरण का कार्य किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चयनित 115 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उच्चीकरण का कार्य कराया गया है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के विस्तारीकरण कार्य के अन्तर्गत नए बहुमंजिला भवन के निर्माण का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। इस सेक्टर में अभी तक रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए, मल्टिपल ट्रेनिंग के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं थी उसके लिए समाजवादी सरकार ने प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण शोध केन्द्र स्टाफ ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च सेन्टर को क्रियाशील किया गया है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में खोले गए 25 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार का कार्य किया गया है। स्पेशल कम्पोनेंट सब प्लान के अन्तर्गत 50 आई0टी0आईज का आधुनिकीकरण सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार किया गया है। पूर्व से संचालित आयोजनेत्तर (नान प्लान) पक्ष के संस्थानों में संचालित निकायों के एककों को सम किया गया है। तथा उनका एन0सी0बी0टी0 जो कि राष्ट्रीय लेविल की संस्था है, जिस तरह से हायर

एजूकेशन में नैक है उसी तरह से हमारे स्किल सेक्टर में एन0सी0बी0टी0 के नवीन मानकों के अनुरूप जो भी साज सज्जा आदि की व्यवस्था करनी थी उसको विभाग ने किया है। स्पेशल कम्पोनेंट सब प्लान के अन्तर्गत स्थापित किए गए सभी आई0टी0आईज के भवन निर्माण को पूर्ण करने के लिए भी धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। ट्राइबल सब प्लान के अर्न्तगत समाजवादी पार्टी की सरकार हमेशा इस बात के लिए सेंसिटिव रहती है समाज के सभी वर्गों के लिए प्रदेश के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना है जिसके लिए ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत स्थापित किए जा रहे आई0टी0आईज बांसगांव गोरखपुर के भवन निर्माण को लगभग पूर्ण कर लिया गया है तथा व्यवसायों के संचालन हेतु वांछित उपकरण एवं साज सज्जा के लिए धनराशि की स्वीकृति जारी कर दी गई है। प्रदेश के सभी आई0टी0आईज तथा निदेशालय को ई कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा गया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए स्थापित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण एवं भवन निर्माण की शेष धनराशि की व्यवस्था एवं आवर्तक व्यय साज सज्जा की व्यवस्था कर दी गई है। प्रदेश के असेवित तहसीलों एवं विकास खण्डों में 20 नए आई0टी0आईज की स्थापना की जा रही है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हम लोग आगे इस साल में कौन–कौन से काम करने जा रहे हैं। प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एक सशक्त भूमिका निभाने के लिए नौजवानों को सीधा रोजगार से जोड़ा जा सके जिससे कि वह फर्ज को पूरा कर सके देश और प्रदेश के प्रति और अपने परिवारों का सम्मान के साथ इज्जत के साथ सर उठाकर पालन पोषण कर सके। नए आई0टी0आई बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही एम्बीसिएस स्कीम रखी है जिसमें इस साल में 20 नए आई0टी0आईज की स्थापना का नया इनीसिएटिव स्थापित कर दिया जाएंगा । व्यवसायों के पुनर्गठन पर हम लोगों ने काम किया है। अधिष्ठाता महोदय जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो हम लोगों ने यह महसूस किया कि बहुत सारे ट्रेड ऐसे चल रहे हैं जिनमें बच्चे बिल्कुल इन्ट्रेस्टेड नहीं हैं। कहीं 6 एडमीशन, कहीं 7 एडमीशन, कहीं पांच एडमीशन हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं जिनमें लोग बड़ी संख्या में लोग और आना चाहते हैं जैसे फिटर है, आटोमोबाइल है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लानिंग है, कंस्ट्रक्सन वर्क की ट्रेड है। उनमें लोग भारी संख्या में एप्लाई करते हैं क्योंकि सीट कम थीं इस वजह से हम उनको नहीं भर्ती कर पा रहे थे। हम लोगों ने एक रेसनलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करके जो पापुलर ट्रेड नहीं थे जिनमें बच्चे एडमीशन नहीं ले रहे थे उन ट्रेड को कम किया है और जिन ट्रेड में पापुलैरिटी थी जिनमें बच्चे काम करना चाह रहे थे जिनमें आज इण्डस्ट्री की डिमांड है कि हमको बच्चे मिल जाएं उनको प्लेस कर दें उनको नौकरी दे दें इस चीज को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र में केन्द्र पुरोधानित योजना के अन्तर्गत स्थापित किए जा रहे एक आई0टी0आई0 तथा दो स्किल डेवलपमेंट मिशन में कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएंगा। भवन निर्माण में जो इस साल हमारे मुख्यमंत्री जी ने 20 आई0टी0आईज दिए हैं उन सारे भवन निर्माण में उनका प्रोग्रेस उनका फण्ड रिम्बर्समेंट डिस्वर्सल सबपे काम करके यह प्रयास

किया जाएंगा कि उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी, उसकी मानीटरिंग अच्छे से हो सके उसके असिसमेंट के लिए विभाग जिम्मेदार रहेगा।

मॉडल आई0टी0आई0 की स्थापना मेरठ में की जा रही है क्योंकि मेरठ एक बहुत बड़ा क्लस्टर है, एक इंडस्ट्रियल हब है हमारा, बहुत पुराना इंडस्ट्रियल हब है अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो कैंची से लेकर स्पोर्टिंग इक्यूपमेंट से लेकर के वहां कपड़े से लेकर कई क्षेत्रों में काम होता रहा है। वहां पर लोकल इन्डस्ट्री की नीड को रिस्पोंड करने के लिये एक मॉडल आई0टी0आई0 का प्रपोजल वहां पर किया गया है जिसकी स्थापना का कार्य इस वर्ष शुरू कर दिया जायेगा। हम लोगों ने इन्वॉयरमेंट के प्रति सजग होते हुए यह भी महसूस किया गया कि क्योंकि वह फाव हैं, दूर हैं आई0टी0आईज0 अधिष्ठाता महोदय। इससे वहां कभी कभी बिजली नहीं पहुंच पाती है इसलिये उन ऐसे इन्स्टीट्यूट्स को आईडेन्टीफाई करके उन पर सोलर एनर्जी का काम किया जायेगा। ऐसे 40 इन्स्टीट्यूशन्स आईडेन्टीफाई किये गये हैं जहां सोलर इनर्जी से काम किया जायेगा। जिससे इन्वायरमेंट सस्टेनबिलिटी का भी ध्यान रखा जा सके और बच्चों की सुविधा का भी ध्यान रखा जा सके जिससे उनकी ट्रेनिंग में बिजली की जो आपूर्ति की जरूरत पड़ती है उसका भी ध्यान रखा जा सके। इस साल में यह कार्य भी शुरू कर दिया जायेगा। एस0सी0वी0टी0 का संचालन राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र को पूर्णताः क्रियाशील किया गया है। स्टेट काउन्सिल फार वोकेशनल ट्रेनिंग। अधिष्ठाता महोदय, यह महसूस किया गया कि बहुत सारे प्रदेश में ऐसे कोर्सेज की जरूरत है, ऐसे ट्रेड्स की जरूरत है, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जरूरत है जिनका भारत सरकार के जो स्टैन्डर्ड प्रोग्राम्स हैं उनमें उनकी संख्या नहीं है। क्योंकि वो ट्रेड शायद उनकी नजर में न आये हों। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिये देना चाहता हूं कि जैसे कन्नौज में परफ्यूमरी का काम बहुत बड़ा काम है, इत्र का जो काम होता है। उसे डेवलेप करने के लिये हमने स्टेट काउन्सिल फार वोकेशनल ट्रेनिंग डेवलेप की है जिससे उसके तहत नये कोर्सेज डेवलेप किये जा सकें। इन्डस्ट्री की कोई भी डिमान्ड आती है। हमें इस नये ट्रेड की जरूरत है, हमने एक प्लेटफार्म को तैयार किया है जिसके तहत इनकी डिमान्ड को लिया जा सकता है उसका कोर्स कन्टेन्ट किया जा सकता है, डेवलेप किया जा सकता है फैकल्टी ट्रेन्ड की जा सकती है। फाइनली उसमें सर्टिफिकेशन के प्रोसेस तक पहुंचा कर के रोजगार से हमारे नौजवानों को जोड़ा जा सकता है। यह बहुत ही एक अहम कदम है। अधिष्ठाता महोदय जो समाजवादी सरकार ने, हम लोगों ने उठाया है। शोध केन्द्र के संचालन में तीन नये व्यवसायों हेतु सी0आई0टी0एस0 के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एन0सी0वी0टी0 से सम्वर्धन प्राप्त कर उनका संचालन किया जायेगा। एक नई स्कीम आ रही है जिससे कि जो हमारे पुराने टीचर्स हैं उनको भी नया सर्टिफिकेशन दिया जाय, नई ट्रेनिंग हो जाय क्योंकि यह महसूस किया जाता रहा है ट्रेनिंग में एज्यूकेशन के फील्ड में कि हमने 30 साल पहले एज्यूकेशन की थी, 20 साल पहले एज्यूकेशन की थी, 16 साल पहले एज्यूकेशन की थी उसकी रिट्रेनिंग नहीं हुई। तो इसके प्लेटफार्म से रि–ट्रेनिंग का मौका भी मिलेगा और नये सर्टिफिकेशन का मौका भी

मिलेगा। इसको भी क्रियान्वित किया जायेगा इस साल में। अनुदेशक भर्ती, जो कि एक फैकल्टी डेवलेपमेंट में एक बहुत इम्पार्टटेंट पार्ट होता है हमारे यहां अनुदेशकों की बहुत भारी संख्या में कमी थी लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम आज ढाई हजार अनुदेशकों की भर्ती आज कर रहे हैं और यह हमारी प्रोसेस ऑन है और बहुत जल्दी से जल्दी उस प्रक्रिया को पूरा करके उन अनुदेशकों को प्लेस करके, उनको ट्रेंन करके अपनी जगह पर पॉजीशन करके उनसे जो टीचिंग का कार्य है उसको शुरू करा दिया जायेगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में मुझको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यह एक बहुत ही सक्सेसफुल बॉडी है और लगभग एक लाख चालीस हजार बच्चे इसमें ट्रेन कर रहे हैं जो मिशन अभी दिसम्बर, 2013 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने लॉच किया था। यह बहुत बड़ा अभूतपूर्व एग्जामपिल रहा है। इस एग्जामपिल को मुझे अभी आपको बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि भारत सरकार की तरफ से एक आयोजन हुआ था जिसमें बहुत सारे प्रदेशों की टीम असम से, नागालैंड से और भी प्रदेशों की टीम उत्तर प्रदेश आई थी इसको स्टडी करने के लिये कि हमने स्कल डेवलेपमेंट मिशन में क्या काम किया है और उसको किस तरीके से दूसरे प्रदेश भी सीख कर के उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं।

उन्होंने हमसे सीखने का प्रयास किया, हमने भी उनसे पूछा कि आप बतायें कि आपके प्रदेश में क्या हो रहा है और उसके लिये दो वे कम्युनिकेशन चैनल इस्टैबलिश करके उनसे सीख के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो उनकी अच्छी चीजें थीं और हमारी चीजें वह सीख कर गये हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, विगत वर्ष 2014–2015 में आयोजनागत प्लान पक्ष में अनुदान संख्या–69 के अन्तर्गत रूपये 319 करोड़ 24 लाख 39 हजार एवं आयोजनेत्तर (नॉन प्लान्ड) पक्ष में रूपये 266 करोड़ 49 लाख 84 हजार कुल रुपये 500 करोड़, 74 लाख, 23 हजार अनुपूरक का सम्मिलित बजट सदन से पारित हुआ था। वित्तीय वर्ष 2015–2016 हेतु वित्त विभाग द्वारा आवंटित अनुदान संख्या–69 के अन्तर्गत आयोजनागत मद में रुपये 346 करोड़ 40 लाख 55 हजार तथा आयोजनेत्तर मद में रुपये 312 करोड़ 62 लाख 53 हजार कुल रुपये 659 करोड़ 3 लाख 8 हजार का बजट प्राविधान संयुक्त में प्रस्तुत है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस सेक्टर की इम्पोर्टेंस को देखते हुए वोकेशनल एज्यूकेशन के डेवलेपमेंट की इम्पोर्टेंस को देखते हुए इस क्षेत्र में हमारी सरकार ने साढ़े बारह प्रतिशत बजट का इन्क्रीज किया है जो कि अपने आप में एक बहुत ही नॉवल स्टेप है, एक बहुत बड़ा जम्प है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट में प्रदेश की व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास के प्रति विश्वास एवं समाज के निर्बल एवं कम आय वर्ग वाली एक महत्वपूर्ण जनसंख्या के उत्थान हेतु समाजवादी समाजवादी सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। मान्यवर, प्रस्तुत बजट पर सदन का अनुमोदन निवेदित है।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0के0 वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, का बहुत–बहुत शुक्रिया, आपने मुझे व्यावसायिक शिक्षा विभाग के बजट के अवसर पर कटौती का प्रस्ताव लाने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद् देता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–69 व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग के द्वारा उपलब्ध इस पुस्तिका का मैंने बखूबी अध्ययन किया, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रदेश में कुल 217 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं। जिसमें 88 हजार 774 सीटें छात्रों के लिए उपलब्ध हैं। साथ ही साथ निजी क्षेत्रों में 1560 से अधिक गैर अनुदानित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। इन संस्थानों की सीट क्षमता एक लाख 97 हजार 820 है। मान्यवर, लगभग तीन लाख के करीब यह संख्या जाती है। इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न आई0टी0आई0 सेल में छात्र एडमीशन लेकर के ट्रेनिंग लेने का काम करते हैं।इसकी जो गवर्निंग बॉडी है एन0सी0बी0टी0, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, सबसे बड़ी विडम्बना है कि इस संस्थान के द्वारा, या इस पुस्तिका में किसी भी पृष्ठ पर इसका अवलोकन नहीं हुआ है कि अभी तक सभी आई0टी0आई0 सेन्टर्स पर कुल कितने छात्रों ने व्यवसायिक शिक्षा लेने का काम किया है और उसमें से कितने स्वरोजगार से सम्बद्ध हैं। कितने सरकारी विभागों से सम्बद्ध हैं।इसका कहीं भी कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। आज पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या बेराजगारी है। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है और यह बहुत बड़ा विभाग भी है पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी को लेकर है और बेरोजगारी का सबसे उत्तम इलाज अगर है तो वह है व्यवसायिक शिक्षा, आप पूरी दुनिया को देखें तो सबसे बड़े पैमाने पर हमारे देश में नौजवान रहता है। सबसे बड़े पैमाने पर नौजवान भारत में रहता है और सबसे बड़े पैमाने पर बेरोजगार नौजवान भी भारत में ही रहता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मा0 सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि देश की तरक्की के लिए, देश की खुशहाली के लिए, जब तक लोगों के हाथों में रोजगार नहीं होगा, जब तक लोगों के हाथों में व्यवसायिक शिक्षा नहीं आएगी तब तक देश और समाज की तरक्की होने वाली नहीं है। मान्यवर, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हमारा आपका वश नहीं होता है पूरी दुनिया की तरक्की के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है टेलेन्ट, टेलेन्ट दुनिया के अन्दर पैदा होता है किसी जाति और मजहब या देश की सीमा के अन्दर नहीं पैदा होता है। दुनिया के किसी भी कोने में पैदा होता है। टैलेंट कैन नाट बी एक्वायर्ड, हम इसे हासिल नहीं कर सकते, यह बाईबर्थ होता है टैलेंट बाईबर्थ होता है इसे हम हासिल नहीं कर सकते, लेकिन बाकी दूसरी जो चीजे हैं। नॉलेज, जो बहुत बड़ी चीज होती है। तीसरी चीज स्किल है। नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम ऐनी इस्टीट्यूशन, उस नॉलेज को लेकर आप उसका इस्तेमाल करके देश को और समाज को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे

बड़ी चीज होती है कि प्लेसमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर पिपुल एट ए पर्टिकुलर प्लेटफार्म। यहां पर उपस्थिति हम सभी लोग बहुत ही क्वालीफाईड लोग हैं।

मा0 मंत्री जी भी प्रोफेसर हैं मैं सम्मान करता हूं। यहां पर सभी लोगों ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा तक की शिक्षा ली होगी या टेक्निकल इस्टीट्यूट में शिक्षा ली होगी, लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि हम सभी लोगों ने यह महसूस किया होगा कि कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, किसी डिग्री कॉलेज का कोई रीडर है या इण्टर कॉलेज का कोई लेक्चरर है, लेकिन हम लोगों ने यह महसूस किया होगा कि चाहे वह टीचर है, रीडर है, लेक्चरर है, लेकिन उसको टीचिंग करना नहीं आता। हमको भी पसन्द नहीं होता, आपको भी पसन्द नहीं होता लिहाजा स्टूडेंट हमेशा शिकायत करता है कि फलां टीचर को, फलां रीडर को, फलां प्रोफेसर को इस सब्जेक्ट को पढ़ाना नहीं आता। उसने नॉलेज एक्वायर किया है नॉलेज को उसने हासिल किया है तब उसके पास डिग्री है। वह किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, लेकिन पढ़ाने की जो कला होनी चाहिये वह उसके अन्दर नहीं है। यहां उचित प्लेसमेंट की कमी है उसकी वजह क्या है ? हमारे सिस्टम में शुरू से जो कैरियर काउंसिलिंग जैसी चीज होनी चाहिये, वह हमने अपनी व्यवस्था में देने का काम नहीं किया है। नॉलेज हमारे पास है, लेकिन उसका सही दिशा में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। स्किल के संबंध में मा0 मुख्यमंत्री जी के विजन का मैं सम्मान करता हूं। मा0 मुख्यमंत्री जी की सोच बहुत अच्छी है। विजन को लेकर जो उनका नजरिया है वह देश और प्रदेश के लिये वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि मा0 मुख्यमंत्री जी का जो विजन है वह इस व्यावसायिक बजट की पुस्तिका में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। स्किल कैन बी डेवलप्ड, स्किल कैन बी एक्वायर्ड, स्किल कैन बी शार्पेन्ड बाई ट्रेनिंग। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें रखना चाहता हूं। स्किल के लिये मा0 मंत्री जी ने बताया। हमारी सोच क्या है ? यह देश नौजवानों का सबसे बड़ा देश है। स्किल की कमी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके लिये ट्रेनिंग की कमी है। वह एक्वायर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अभी इसके पहले मा0 नेता जी की जब सरकार थी। यहां पर सत्ता पक्ष के सारे लोग बैठे हुये हैं। कुछ ऐसे स्किल होते हैं जिसकी काउंसिलिंग हम लोग नहीं करते हैं लिहाजा वह अपने पुश्तैनी और पारम्परिक पेशे में लगे होते हैं। आप उदाहरण ले सकते हैं। कारपेंटरी से जुड़े हुये लोग हैं, लकड़ी का व्यवसाय करने वाले लोग हैं जिन्हें हम लोहार कहते हैं या बढ़ई कहते हैं। लोहे के काम में लगे हुये लोग हैं, सोने के काम में लगे हुए लोग हैं, कुम्हार के काम में लगे हुए लोग हैं उनके अन्दर भी स्किल होती है। जो बढ़ई का काम करता है पुस्तैनी स्किल्ड है हमारे सभी विभागों में प्रायः आप जाते हैं तो फर्नीचर खराब मिलते हैं। फर्नीचर को हमारा विभाग दूसरे व्यवसायिक संस्थाओं से खरीदने का काम करता है, लेकिन जो लोग पारिवारिक रूप से पारम्परिक रूप से उस विभाग के स्किल्ड हैं, उस काम के लिये स्किल्ड हैं उनका स्किल डेवलप करने के लिये हमारी योजनायें उनके पास नहीं पहुंचती हैं उन्हें इन विभागों से सम्बद्ध किया जाना चाहिये। मान्यवर, इसके पहले

जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मा0 नेता मुख्य मंत्री थे, यहां पर बैठे हुए सारे मंत्रीगण जानते होंगे कि उस समय जो लोहार से सम्बन्धित हैं और अन्य जितने भी छोटे–छोटे व्यवसाय से सम्बन्धित लोग होते थे सरकार उनको टूल किट देने का काम करती थी लेकिन आज तक स्किल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन उनके पास तक टूल नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उनके हम स्किल को डेवलेप कैसे कर रहे हैं, उन्हें टूल किट दिया जाना चाहिये ये मेरा सुझाव है। उसका हमारे पास कोई पैरामीटर ही नहीं बन पाया है। हर गांव में आप देख लीजिए, जितने भी मैकेनिक हैं, हर घर की जो जरूरत है, वहां पर रोज वायरिंग खराब होती है, टी0वी0 खराब होता है, ट्रान्सजिस्टर खराब होता है, फ्रिज खराब होता है, घड़ी खराब होती है, ए0सी0 खराब होता है, किसी की कार खराब होती है, किसी की साइकिल खराब होती है, किसी की मोटर साइकिल खराब होती है, अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि जब भी आपकी कार खराब हुई होगी और अगर आपकी कार को किसी मैकेनिक ने ठीक किया होगा तो आप उसमें से देख लीजिए कि 10 परसेण्ट भी ऐसे मैकेनिक नहीं होंगे जो उत्तर प्रदेश के किसी आई0टी0आई0 सेण्टर से प्रशिक्षण ले करके मैकेनिक का काम करता होगा। किसी का स्कूटर खराब हुआ होगा, किसी की दोपहिया खराब हुई होगी, आप गॉव में जा करके देख लीजिए, रूरल से लेकर, सेमी अर्बन तक आप देख लीजिए, हर जगह बड़े पैमाने पर जरूरत है, टू व्हीलर खराब हो रहे हैं, रेफ्रीजरेटर खराब हो रहा है, ए0सी0 खराब हो रहा है, कम्प्यूटर खराब हो रहा है, वायरिंग खराब हो रही है, जितने भी इलेक्ट्रीशियन हैं, इन सभी मैकेनिक को आई0टी0आई0 या अन्य तरीके से स्किल्ड करने की जरूरत है। अधिष्ठाता जी, यह बहुत गंभीर विषय है, ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। यह ऐसा विषय है, इससे देश की प्रगति जुड़ी हुई है, जिनके पास स्किल है, लेकिन उनका हम स्किल डेवलपमेण्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी योजनाओं को और ऐसे विभाग को बनाने का कोई मतलब नहीं है।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि जो एनसीवीटी जैसी उच्च गवर्नेंश बाडी हैं, जिसके द्वारा स्लेबस तय होता है और उसे स्लेबस के अन्दर विभिन्न आई0टी0आई0 सेन्टर पर जितने भी स्टूडेंट जा करके उसमें ट्रेनिंग लेते हैं, कम से कम उसकी एक ऐसी बाडी होनी चाहिए, जो सारे छात्रों का रजिस्ट्रेशन करे कि हमारे पास कितने नम्बर ऑफ स्टूडेन्ट्स आए और कितने छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ और उसमें से कितने स्वरोजगार में हैं, स्वावलम्बी जीवन जीने का काम कर रहे हैं, कितने सरकारी नौकरियों में जा सके हैं और कितने ऐसे हैं जिन्हें अभी ऐसा अवसर नहीं मिल पाया है। इसलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि हमारा व्यावसायिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, वह बाद में शुरू होता है, आज गांव की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो कमजोर आदमी है, जो गरीब आदमी है, जिसके घर में पढ़ाने लिखाने का माहौल नहीं है, जिसके घर में शिक्षा के संस्कार नहीं है, उसके बेटे और बेटियां हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद शिक्षा से विमुख हो जाती हैं और अपने पुस्तैनी पेशे में जा करके, कोई

बढ़ई का काम शुरू कर देता है, लकड़ी का फर्नीचर बनाने का काम करता है, कोई लोहार समाज का है तो वह जाकर लोहार का काम करने लगता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि व्यावसायिक शिक्षा का जो प्रोग्राम है, कम से कम इण्टरमीडिएट स्तर से माध्यमिक शिक्षा में इसको अनिवार्य रूप से इस विषय को सम्मिलित किया जाना चाहिए और वहीं से कैरियर काउन्सिलिंग जैसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किस छात्र के अन्दर कौन सा टैलेन्ट है, कौन सा स्किल है जिससे उसे उस विधा से जोड़ करके उसको रोजगार के रास्ते पर लाया जा सके और जिसके योगदान से देश और समाज को खुशहाली मिल सके। मान्यवर, बहुत बड़ी तादाद में दस्तकार हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन दस्तकारों की बात सुनने वाले लोग नहीं हैं, उनके दर्द को महसूस करने वाले लोग नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार और माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि दस्तकार विकास निगम की स्थापना होनी चाहिए जो दस्तकारों के दुख–दर्द को समझ सके, उनकी कठिनाइयों को समझ सके। मान्यवर, मैं सरकार से मांग करता हूं कि एक दस्तकार विकास निगम अलग से बनाया जाना चाहिए और जो पुस्तैनी पेशे में लगे हुए लोग हैं, जातियों का नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पारम्परिक पुस्तैनी रूप से उस विधा में स्किल्ड हैं, उनको शार्प करने की जरूरत है, उनको दिशा देने की जरूरत है। हमने अभी आपको बताया कि सौ फीसदी हम लोग ऐसे मेकेनिक से मोटर साइकिल ठीक कराते हैं जो इस विधा का जानकार नहीं होता है और कम से कम 80 फीसदी हम लोग ऐसे कार मेकेनिक से अपनी कार ठीक करवाते हैं जो इस विधा के लिए ट्रेंड नहीं होता है।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य अब समाप्त करें।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0के0वर्मा–

मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक विकास खण्ड में आई0टी0आई0 की अवस्थापना की जानी चाहिए।

(कतिपय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

नहीं यह हमारे विकास खण्ड में नहीं हैं। आपके पास मात्र 217 आई0टी0आई0 हैं।

श्री अधिष्ठाता–

बाकी सदस्य भी अपनी बात कहेंगे। अब समाप्त करें।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0के0वर्मा–

मा0 अधिष्ठाता महोदय इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को अन्तिम स्वरूप देते हुए खत्म करना चाहता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

मा0 अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास मिशन पर मा0 मंत्री श्री अभिषेक मिश्रा जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया इस हेतु आपका कोटि–कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर आपके माध्यम से मैं मंत्री जी जिन्होंने लगभग 660 करोड़ रूपये का बजट जिसमें लगभग 12.50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है इसके लिए मैं मा0 मंत्री जी को और अपने मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मा0 मंत्री जी द्वारा प्रारम्भ कौशल विकास मिशन पूरे प्रदेश में ही नहीं अपितु देश में एक अनोखी योजना है। यह बात सही है कि इससे पहले ही सीमित मात्रा में हमारे पास नौकरी के विकल्प थे लेकिन कौशल विकास मिशन के द्वारा ऐसे–ऐसे विकल्प प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो सराहनीय हैं। खासतौर से एक लाख चालीस हजार लोग इसके माध्यम से इस वित्त वर्ष में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। जो बहुत ही सराहनीय कदम है और इस कार्य के माध्यम से बहुत–से बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा। इसके लिए भी मैं मा0 मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। मा0 मंत्री जी ने जैसा बताया 266 आई0टी0आई0 पूरे प्रदेश में हैं। इसमें से 217 ऐसी हैं जिसमें 20 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है और लगभग 50 ऐसी आई0टी0आई0 हैं जो पूरी तरह से महिला आई0टी0आई0 हैं। यह भी सराहनीय कदम है और 64 ऐसी आई0टी0आई0 हैं जिसमें 70 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को दिया जा रहा है तथा लगभग 15 से 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए भी है जो सराहनीय है। 25 आई0टी0आई0 ऐसी हैं जो अल्पसंख्यक क्षेत्र की हैं जिनका उच्चीकरण भी किया जा रहा है। इसके लिए भी मैं इस बजट के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मा0 मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर पूरे प्रदेश के आई0टी0आई0 की ई–कनेक्टिविटी की जा रही है यह एक अनोखा कदम है। ई–कनेक्टिविटी के माध्यम से सभी क्षेत्रों की आई0टी0आई0 को कौन–कौन से ट्रेड चल रहे हैं इसे शेयर करने में तथा इसको बढ़ावा देने में बहुत ही मदद मिलेगी। यह भी एक सराहनीय कदम है। उत्तर प्रदेश में 20 नई आई0टी0आई0 खोली जा रही हैं। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र इलाहाबाद के गंगापार में एक भी आई0टी0आई0 कालेज नहीं हैं। मेरे विधानसभा सोरॉव में पिछले वर्ष ददौली नामक गॉव में भूमि अधिग्रहण करके प्रस्ताव शासन में जा चुका है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से आग्रह करूॅगा कि लैण्ड प्रपोज्ड हो चुकी है और उसको प्राथमिकता पर संज्ञान में लेकर जो 20 प्रस्तावित आई0टी0आई0 हैं इसी में इसको भी स्वीकृत कर दिया जाएं। इलाहाबाद में नैनी आई0टी0आई है वह यमुनापार में है। गंगापार में एक भी आई0टी0आई0 नहीं है। वि0खं0 सोरांव सहित हंडिया में शायद है लेकिन हमारे क्षेत्र में एक आई0टी0आई0 हो जाएंगी तो हमारी फाफामऊ विधानसभा और फूलपुर विधानसभा भी इससे पोषित होंगी। और एक और अपोषित तहसील है फूलपुर तहसील का बहेरिया ब्लाक। बहेरिया ब्लाक का लगभग 70 प्रतिशत हमारे क्षेत्र में आता है। बहेरिया ब्लाक के लिए भी हम प्रपोजल भिजवा रहे हैं। उसको भी अपने संज्ञान में लेने की कृपा करेंगे। मान्यवर, साथ ही हमारे क्षेत्र में जो आई0टी0आई0 ददौली में प्रपोज की जा रही है उसमें

बहुत ही अच्छा होगा यदि एकदम निकटतम 10 किमी0 की रेंज में हैण्डलूम और पावरलूम का क्षेत्र है मऊआइमा । बहुत ही प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है।

अगर उससे संबंधित जो ट्रेड्स हैं। उसको इस आई0टी0आई0 में शामिल कर लेंगे तो निकट ही छात्रों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मान्यवर, हमारी गंगापार की सोरांव विधान सभा बहुत ही अच्छे उपज की भूमि है। यहां पर प्रति हे0 उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। अगर यहां पर खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स भी शुरू कर दिया जाएंगा तो यह भी बहुत ही सराहनीय कदम होगा और बहुत ही निकट बच्चे इससे रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही इस बजट के अंतर्गत सौर ऊर्जा से कई आई0टी0आई0 को पोषित किया जा रहा है।

(इस समय 02 बजकर 48 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यह भी एक बहुत ही सराहनीय कदम है। ऊर्जा के क्षेत्र में आपका व्यावसायिक शिक्षा विभाग संवेदनशील है। महसूस करता है कि ऊर्जा की कितनी कमी है। और अगर सौर ऊर्जा से यह आई0टी0आई0 पोषित हो जायेंगे तो किसी तरह का भी व्यवधान नहीं रहेगा और सुचारु रूप से वह सारी आई0टी0आई0 चल सकेंगी। शिक्षकों को जो नये पाठ्यक्रम सिखाये जा रहे हैं यह भी एक सराहनीय कदम है। साथ ही अंत में मैं सम्पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा के बजट का समर्थन करते हुए और एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि हमारे शानदार मा0 मुख्यमंत्री जी, जो हमारे सेनापति है, हमारे सेनानायक है उनके कुशल सारथी हैं अभिषेक जी। मैं उनको भी बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती विमला बाथम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपने व्यावसायिक शिक्षा के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। मान्यवर, आजकल इंटरनेट का युग है। और हमारे मा0 मंत्री जी भी बहुत काबिल हैं। मैंने इंटरनेट का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आज दुनिया मुटठी में है, क्योंकि एक जमाना था जब मुश्किल से हमारी बात कहीं पहुंचती थी। आज डाक्टर, इंजीनियर, एम0बी0ए0, बी0बी0ए0 हैं फैशन डिजाइनर जो महानगरों में, विशेष रूप से दिल्ली नोयडा की मैं बात करूंगी। जहां निफ्ट से पास आउट होकर बहुत बड़े व्यवसाय के रूप में यह फैशन डिजाइनर अपना काम कर रहे हैं। चूंकि मैं महानगर से हूं इसलिए ज्यादा बात मैं वहां की कर रही हूं। जो कलाकार हैं, पेंटर हैं जो अपनी भावनाओं को कला के रूप में पेंटिंग के रूप में उभारते हैं मैं उनकी चर्चा कर रही हूं। मूर्तिकार, जिनका हमारे भारत में बहुत सम्मान है। ऐसे–ऐसे महान मूर्तिकार भी हुये हैं। आर्टिजन, कालीन उद्योग, कश्मीरी शाल बनाने वाले, अलीगढ़ में ताले बनाने वाले, मुरादाबाद में पीतल का उद्योग चलाने वाले ऐसे अनेक हमारे जो कला व्यवसायी हैं जो व्यवसाय के रूप में अपनी कला का उपयोग करते हैं ऐसे अनेक लोग हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे मार्जिन से कमा रहे हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। ऐसे–ऐसे कलाकार भी पड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में गयी।

मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि वहां 70 देशों के लोग आये हुए थे। माननीय केन्द्रीय मंत्री गंगवार जी भी हमारे साथ थे, या मैं उनके साथ थी। वहां पर मैंने इस चीज को महसूस किया कि बहुत शिकायतें थीं कि आर्टिजन नहीं मिलते हैं, इन सब कामों के लिए। आर्टिजन क्यो नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है। उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती है। गांव के जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, वह भी इस काम को नहीं करना चाहते हैं। मैने वहां ऐसे–ऐसे लाख के बर्तन देखे, ऐसी–ऐसी कीमती पच्चिकारी वहां देखीं, जो वाकई हमारे देश के लिए दुर्लभ चीजें हैं, लेकिन वह कहते हैं कि 06–06 महीने लग जाते हैं एक चीज को बनाने में पर उसका कोई भी मूल्य उस हिसाब से नहीं मिलता और उनको पूरी मजदूरी नहीं मिलती है। कई बार पूरा परिवार लगा रहता है पर फिर भी पेट भर रोटी नहीं खा पाते हैं। इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि आर्टिजन तैयार करने के लिए आप बड़े लेविल पर आई0टी0आई0 खोले, मैं तो मिस्त्री को भी मानती हूं कि वह भी एक आर्टिजन है, वहां भी मैने देखा। अब युग बदल रहा है, पुराने जमाने की बातें नहीं हैं। आज बिल्डिंग भी बहुत हाइ–टैक बन रही है तो आपको चाहिए कि उनको भी ऐसी ट्रेनिंग दी जाये कि जिससे वह अच्छा काम कर सके। अच्छे वर्कमैन बन सके। अभी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो आर्टिस्ट हैं जो किसी तरह पेन्टिंग बनाकर उसे बेचते हैं, अपना पेट भरते हैं, उनके ऊपर बहुत भारी टैक्स लगता है। यह बहुत दुखद है कि एक आर्टिस्ट अपनी पेन्टिंग बनाकर गुजारा करना चाहता है तो उसके और मूर्तिकार के ऊपर टैक्स की भारी मार पड़ती है। अगर वह सही परिप्रेक्ष में अपनी चीज को रखे, अपनी चीज को बेचे तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, या तो नाम मात्र का ही टैक्स लगाया जाये या टैक्स न लगाया जाये तो अच्छा है।

उद्योगों में स्किल्ड लेबर भी नहीं मिलती है। हम अगर प्लम्बर को बुलाना चाहें तो उद्योग क्या हमारे सभी माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, सबके घरो में भी समस्यायें हैं कि आजकल इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलते, कोई पत्थर लगाने वाले नहीं मिलते, आप एक बिल्डिंग बनवाईये तो इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कि ऊब जायेंगे और कहेंगे कि हमें बिल्डिंग नहीं बनवानी। इसलिए क्योकि वहां स्किल्ड लेबर नहीं मिलती। हम फैक्टरी में देखते हैं बहुत कमी है स्किल्ड लेबर की। यह स्किल्ड लेबर कैसे आये? यह सरकार का दायित्व है कि हर क्षेत्र के आई0टी0आई0 खोले जायें और बड़ी संख्या में भर्ती किये जायें और उनको स्टाईपेन्ड वगैरह भी दिया ताकि उनको एक प्रोत्साहन मिले कि हमें यह काम करना है। स्टाईपेन्ड पर मैं विशेष जोर देना चाहूंगी। हमारे उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से क्वालिटी काम की बहुत कमी है। यह हमारे मंत्री जी भी और सभी लोग जानते हैं कि क्वालिटी काम नहीं मिलता है। और जगह हम देखते हैं कि बहुत क्वालिटी का काम होता है पर यहां नहीं मिलता इसलिए क्योंकि उनका प्रशिक्षण नहीं होता है। जब तक आप उनकी प्रॉपर प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं करायेंगे तब तक आपको अच्छा आर्टिजन नहीं मिलेगा। अच्छे आर्टिजन अभी घरों में है, पुस्तैनी काम जैसे पतंग बनाने वाले हैं। इस तरह के और भी कई हैं जिनकी पीढ़ियां पहले काम करती आ रही

थीं पर आज नौजवान नहीं कर रहे हैं क्योकि उन्हें उतना पैसा नहीं मिलता। उनका सरकार की तरफ से एक वेतन तय किया जाये, सुनिश्चित किया जाये कि इससे कम में आप किसी आर्टिजन से काम नहीं करायेंगे। होता क्या है ? उनके बच्चे तक, चाहे कालीन उद्योग में देखिये आप, बच्चे तक लगा लिये जाते हैं जो 18 साल से कम आयु के बच्चों को वैसे भी मानवता के खिलाफ है छोटे बच्चों से काम कराना, वह भी लगा दिये जाते हैं क्योकि मां–बाप कहते हैं। बीड़ी बनाने का काम ले लीजिये। एक तो बाल मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत इसको बिल्कुल रोका जाये। सख्ती से इसका पालन कराया जाये कि 18 साल से कम के बच्चें इसमें इन्वाल्व न हो। हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है, आप देखिये कि व्यवसायी शिक्षा तो हर जगह चाहिए। आप आक्रिटैक्ट देखिये, चलिये वह तो कमा लेते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षा–दीक्षा के लिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो उचित होगा, उसमें बहुत बड़ी–बड़ी फीसें हैं वहां, ये व्यवसायिक शिक्षा जो हमने पहले आपको गिनाई हैं एमबीए, बीबीए यह सब बहुत बड़े–बड़े शिक्षण संस्थाओं से निकलते हैं जहां बहुत बड़ी फीस ली जाती है। जहां एक पढ़ा लिखा बी0ए0 पास हमारा नौजवान नहीं जा सकता है, इसके लिए भी कुछ व्यवस्था की जाय । हम रोज नोएडा में देखते हैं कि जो इंजीनियरिंग कालेज हैं वहां धरना प्रदर्शन छात्र करते रहते हैं, उनका कहना है कि फीस कम करो, वह फीस कम करने की बात करते हैं, बहुत से परिवार ऐसे हैं जो फीस नहीं दे सकते हैं, तो इन कालेजों के ऊपर भी अंकुश लगाया जाय कि फीस एक सीमित मात्रा में ली जाय या तो उनका कोटा फिक्स किया जाय और गरीब परिवार के बच्चों को उस कोटे के अन्तर्गत लाया जाय, यह भी मैं आपसे अनुरोध करूंगी।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अब समाप्त करें।

श्रीमती विमला बाथम–

मा0 अध्यक्ष जी का आदेश हो गया है तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप आर्टिजन को जिन्दा रखिये, उन्हें मरने मत दीजिए पैसे के अभाव में जो आर्टिस्ट हैं उनको पूरा संरक्षण दीजिए और उनके लिए आप कोई ऐसी स्कीम निकालिये ताकि वह अपनी रोजी–रोटी सुविधापूर्वक कमा सकें और अच्छे से अपना जीवनयापन कर सकें, ऐसा अगर होगा तो उत्तर प्रदेश का नाम बहुत बढ़ेगा और आपकी सरकार का भी सम्मान बढ़ेगा। बहुत–बहुत धन्यवाद मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

'श्रीमती रूबी प्रसाद–

मा0 अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने व्यवसायिक शिक्षा के समर्थन में बोलने का मुझे अवसर दिया। आज का जो समय है वह इन्फारमेशन और टेक्नोलॉजी का जमाना है और हमारे उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री जी भी युवा हैं और खुद भी उन्होंने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इंजीनियरिंग किया है, निश्चिततौर पर जो दसवीं पास करने वाले छात्र नौजवान होते हैं, आज के समय में व्यवसायिक शिक्षा की ट्रेनिंग करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बी0ए0, एम0ए0 कर के रोजगार नहीं मिलते और जब तक टेक्निकल एजूकेशन न लें, व्यवसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण न लें, निश्चिततौर पर प्राईवेट सेक्टरों में उनको कोई जगह नहीं मिलती। सबसे पहले मैं मा0 मुख्य मंत्री और मा0 मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने जनपद सोनभद्र जो बहुत ही पिछड़ा दलित, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और पावर के साथ–साथ इण्डस्ट्री का हब भी है। हमारे जनपद सोनभद्र में जो हमारा दुद्धी विधान सभा है वहां पर इतनी इण्डस्ट्री हिण्डाल्को, जे0पी0 सीमेन्ट, एन0टी0पी0सी0 बीजपुर शक्तिनगर यह सारी की सारी वहां इण्डस्ट्री हैं। आये दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे छात्र आई0टी0आई0 कर के पॉलीटेक्निक कर के रोजगार मांगते रहते हैं। निश्चिततौर पर मैं एक सुझाव के तौर पर मा0 मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि जो नौजवान आई0टीआई0 करते हैं, तो आई0टी0आई0 करने के बाद उनकी कनेक्टिविटी जो औद्योगिक संस्थायें हैं, प्राईवेट सेक्टर हैं उनसे उनकी कनेक्टिविटी की जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिल सके और साथ में यह निर्धारित भी करें कि जो हमारे सरकारी संस्थान हैं, उसमें भी इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर रखा जाय।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्रीमती रूबी प्रसाद–

मान्यवर, बस थोड़ा सा समय और दे दें। मान्यवर, आई0टी0आई0 करने के साथ–साथ जब तक बच्चे अप्रिंटिस नहीं करते तब तक उनको उतनी महत्ता नहीं दी जाती, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके अप्रिंटिस की भी व्यवस्था की जाय और जनपद सोनभद्र में हमारे यहां टसर सिल्क जो होता है उसकी जो सांड़िया, कुर्ते बनतें हैं, उनका वहां बहुत अच्छा व्यवसाय होता है, यदि उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाय, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाय तो निश्चिततौर पर टसर सिल्क का व्यवसाय और ज्यादा उन्नति करेगा।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, बस अब हो गया। यह व्यवसायिक शिक्षा है, इसमें बहुत बहस हो गई, यह छोटा सा विभाग है। मा0 मंत्री जी आप अपनी बात रखें।

श्री अभिषेक मिश्र–

मा0 अध्यक्ष जी, कट मोशन प्रस्तुत करते समय मैं यह कहना चाहूंगा और मुझे महसूस हो रहा था कि मा0 सदस्य शायद हमारे विरोध में नहीं बल्कि हमारे पक्ष में बोल रहे थे। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं वरबेटिम कोट कर रहा हूं कि जो हमने संख्यायें बताईं थीं कि जिन संख्याओं में समाजवादी सरकार के आने के बाद अभूतपूर्व वृद्धि हुयी है। उन संख्याओं को दोहरा करके इन्होंने जोर दिया, मैं उनको इस बात के

लिये धन्यवाद देता हूं। इन्होंने साथ ही इस विभाग को सबसे उत्तम इलाज तरक्की के लिये बताया है। मैं इनको धन्यवाद देता हूं और मैं दोहराना चाहूंगा कि सरकार भी इसके प्रति पूरी सेंसिटिव है और उसी गंभीरता से इसको मा0 मुख्य मंत्री जी लेते हैं। इसकी हमेशा हर लेवल पर सपोर्ट और मॉनीटरिंग होती है। एक चीज इन्होंने यहां बहुत अच्छी कही कि मा0 मुख्य मंत्री जी की सोच और विजन बहुत अच्छे हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि हमारे प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री का, समाजवादी पार्टी के मुखिया का कि उनके विजन में, उनकी सोच में जो आप सबने विश्वास जताया है, ये पूरा सदन और हम लोग खासकर आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, एक चीज इन्होंने कही कि टैलेण्ट्स काउंसलिंग के बारे में, उससे पहले इन्होंने कहा कि टैलेण्ट कैन नॉट बी एक्वायर्ड इट इज बाय बर्थ तो आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज चैलेंजिंग।

श्री अध्यक्ष–

अरे, हिन्दी बोलो, ये उत्तर प्रदेश एसेम्बली है।

श्री अभिषेक मिश्र–

मा0 अध्यक्ष जी, उन्होंने अंग्रेजी में बोला इसलिये मैं भी अंग्रेजी में जवाब देना चाह रहा था, अगर आपकी इजाजज हो तो।

श्री अध्यक्ष–

अरे, आपको सब जानते हैं कि आप विद्वान हैं अंग्रेजी के। हिन्दी में बोलिये।

श्री अभिषेक मिश्र–

मा0 अध्यक्ष जी, उसमें टैलेण्ट, नॉलेज और स्किल को जो इन्होंने डिफरेंशिएशन किया वे कि एक ही कण्टिन्युअम पे फैक्टर्स हैं और बिल्कुल टैलेण्ट भी एक्वायर किया जा सकता है, नॉलेज भी एक्वायर की जा सकती है और स्किल भी एक्वायर की जा सकती है। यही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेण्ट की फण्डामेण्टल थ्योरी का जो पहला प्रिमाइस है, जो फाउण्डेशन स्टोन है वह यही है। इन्होंने टैलेण्ट काउंसलिंग की बात कही और मुझको हाउस को बताते हुये खुशी हो रही है कि जो इन्होंने कहा कि होना चाहिये, वह हम ऑलरेडी कर रहे हैं। टैलेण्ट काउंसलिंग हमारे हर स्किल डेवलपमेण्ट मिशन के प्रोग्राम में, हर ट्रेनिंग सेण्टर में टैलेण्ट काउंसलिंग की एक व्यवस्था है। बच्चा जब आता है तो हम उससे पूछते हैं कि आप सेक्योरिटी में जाना चाहते हैं, मशीनरी में या कारपेण्ट्री में और उसकी जो प्रोफाइलिंग है, जो सोच है या उसकी जो पुरानी स्किल कोई हो तो उसके नजरिये से हम लोग उसको गाइड करते हैं, उसी हिसाब से उसको ट्रेन किया जाता है और टैलेण्ट काउंसलिंग हम आलरेडी कर रहे हैं। उसी के साथ–साथ अप्रेण्टिसशिप ऐक्ट भी हम लोगों ने अभी उसको टीथ दिया है, मजबूती दी है। भारत सरकार ने अभी पार्लियामेण्ट में अमेण्ड किया है। हम लोगों ने उसको पूरी तरह से लागू करने के लिये निर्देश और आदेश जारी कर दिये हैं। जहां अप्रेण्टिसशिप पर रोक लगी हुयी थी उसको हम लोगों ने खोल करके अप्रेण्टिसशिप जिससे बच्चे को ऑन द जॉब ट्रेनिंग जरूर मिल सके। ऑलरेडी यह काम सरकार कर रही है। इन्होंने एक बात बहुत

अच्छी और कही कि ट्रैडिशनल वर्कर्स को इस क्षेत्र से जोड़ने की जरूरत है। मुझे यह बताते हुये भी खुशी हो रही है कि ये काम हम आलरेडी कर रहे हैं। ट्रैडिशनल वर्कर्स का जोड़ने का न हम सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि उनको स्किल डेवलपमेण्ट में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था भी है। उनको पैसे देने की व्यवस्था है, कुछ स्कीमों में उनके खाने की व्यवस्था है, वर्दी की भी व्यवस्था है बल्कि साथ ही साथ मा0 अध्यक्ष जी, हम लोगों ने उनके लिये एक नया फ्रेमवर्क बना दिया है कि वहां अगर मान लीजिये कि उनकी 5 साल का एक आर्टिजेन का काम है और मा0 सदस्या जो अभी कह रही थीं शायद उसका भी कुछ हद जवाब हो जायेगा कि उनका स्किल है, जैसे टसर सिल्क में है या कन्सट्रक्शन वर्कर्स में हैं या कारपेण्ट्री में है, उसको वे फार्मल सिस्टम में आकर के, क्रेडिट लेकर के, उसको पढ़ाई में कन्वर्ट करके सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, डिप्लोमा भी ले सकते हैं, डिग्री भी ले सकते हैं। समाजवादी सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था बना दी है कि अगर आप उसमें पीएच0डी0 तक भी करना चाहें तो आज की तारीख में आप पीएच0डी0 भी कर सकते हैं। मुझे यह बताने में खुशी हो रही है। आप कारपेण्ट्री, प्लम्बरिंग, कन्सट्रक्शन वर्क में किसी भी लाइन में आप वह काम कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेण्ट टूल्स और इक्विपमेण्ट्स की आपने बात कही कि नहीं हैं उस जगह में। मैं मा0 सदस्य को न्योता देना चाहूंगा कि किसी दिन हमारे साथ स्किल डेवलपमेण्ट सेण्टर चलें। अगर कल वक्त दे दें तो कल ही स्किल डेवलपमेण्ट सेण्टर है लखनऊ में मैं इनको दिखा दूं।

ये जो जिम्मेदारी है ये जो प्राइवेट सेक्टर के स्किल डेवलपमेण्ट सेण्टर्स हैं उनकी है। उनमें ऑलरेडी एन0सी0वी0टी0 का पूरा फ्रेमवर्क इम्प्लीमेण्ट हो रहा है, पूरी तरीके से हो रहा है। एन0सी0वी0टी0 अभी एक नई संस्था बनाई है भारत सरकार ने जो कि पहले नहीं थी। उसका भारत सरकार ने एक मैनडेट किया है फेज्ड मैनर में कि हर साल इतने कोर्सेज, इतने यूनिट्स एन0सी0वी0टी0 से सर्टिफाई कराये जायेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, मुझे आपके माध्यम से हाउस को बताने में खुशी है कि उन सबका शब्दशः पालन किया जा रहा है। पहले कराये जा चुके हैं, इस साल भी उसका प्रपोजल है। इसी तरीके से आपने इण्टरमीडिएट लेवेल की बात कही कि हमें बच्चों को शुरू से पढ़ाना चाहिये। समाजवादी सरकार मुझे विश्वास है कि जब स्कूलों के और बाकी बजट आयेंगे माध्यमिक शिक्षा के और बेसिक शिक्षा के तो आपको और बतायेंगे इस बारे में लेकिन मुझको बताये हुये खुशी है कि कक्षा 9 से यह प्रोविजन किया जा रहा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग में जो आदमी आगे बढ़ना चाहे उसको स्कूल के लेवेल से ही वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जायेगी, व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जायेगा, स्किल किया जायेगा जिससे कि वे आगे चल करके रोजगार से जुड़ सकें और पूरे मान–सम्मान के साथ अपना परिवार चला सकें। मा0 अध्यक्ष जी, दस्तकार विकास निगम की आपने बात की मुझको यह बताते हुये खुशी है कि बोर्ड ऑफ कन्स्ट्रक्शन वक्रर्स ऑलरेडी एक संस्था है। बाकी स्किल की बात अभी मा0 सदस्या ने की थी जिसमें इन्होंने कहा, कालीन विकास उद्योग और आर्टिजन्स की बात कही। मुझको बताते हुये खुशी है कि कल जब हमारी सरकार का तीसरा साल

पूरा हो रहा था, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कालीन इण्डस्ट्रीज के विकास के लिए नई योजनाओं की शुरूआत और उनको सम्मान देने का काम कल ही माननीय मुख्य मंत्री जी के सरकारी आवास, 5 कालीदास मार्ग पर किया गया है। आज अखबारों में आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी योजनाएं शुरू की हैं। आपने जो सुझाव दिये हैं, उनको हमने ऑलरेडी मान लिया है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कट मोशन का प्रस्ताव रखते हुए इन्होंने एक बात कही कि ''हर विकास खण्ड में स्थापित कर दिया जाएं।'' तो अगर हर विकास खण्ड में स्थापित होना है माननीय अध्यक्ष जी, तो कट मोशन का प्रस्ताव न करके इनको हमारे बजट का सर्पोट करना चाहिए था (मेजों की थपथपाहट)। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर बजट नहीं देंगे तो कैसे बनाएंगे। आप हमें सपोर्ट करिए, सर्वसम्मति से पास कर दीजिए तो हम वहां भी बनवा देंगे। एक और माननीय सदस्या ने बात कही थी, माननीय अध्यक्ष जी, इंटरनेट के युग की, मुझको बताते हुए इस बात की खुशी है, मैंने अभी अपने बजट अभिभाषण में भी कहा कि हम लोगों ने अपने सारे सेन्टर्स को, जितने भी हमारे आई0टी0आई0 इस उत्तर प्रदेश में हैं और जितने हम बनाने जा रहे हैं, सबको ई–कनेक्टिविटी इन्श्योर कर दिया है। इंटरनेट की जो ताकत है, उसको हमारी सरकार ने आपने स्वयं भी देखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजीटल डिवाइज ब्रिज करने के प्रोग्राम चाहे वह लैपटॉप डिस्टीब्यूशन का, चाहे वाई–फाई को पंचायत तक पहुंचाने का हो, हर लेविल पर हमारी सरकार काम कर रही है। अभी जो नये शहरों में बाजारों को और शहरों को वाई–फाई से जोड़ने का काम किया जा सकता है, उसमें भी प्रयास कर रहे हैं। ये काम हमने ऑलरेडी कर दिया है। आपने फैशन डिजाइनर्स की बात आपने कही, रेमण्ड का एक बहुत अच्छा सेन्टर हमने लखनऊ में स्थापित कर रखा है। मैं माननीय सदस्या को उसमें इनवॉइट करना चाहूंगा कि वक्त दे दें और देखें वहां पर किस तरह से बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, किस तरह लड़के–लड़कियां जो छोटे–छोटे घरों से आते हैं। अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, मैं सिर्फ जो सवाल आये हैं उनके जवाब दे रहा हूं, जिससे स्पष्टीकरण की गुन्जाइश न बचे उसमें। एक बात आखिर में आपने जो बहुत अच्छी कही थी वह यह कि इण्डियन हैण्डीक्राफ्ट एण्ड गिफ्ट फेयर एक्सपो मार्ट की, जिसमें शायद गंगवार साहब के साथ आप थी, जिस दिन गंगवार साहब थे, उसके एक दिन पहले के कार्यक्रम का चीफगेस्ट मैं स्वयं था और मैंने स्वयं वहां पर उनकी सारे स्टॉल्स् लगभग साढ़े तीन–चार घंटे घूमकर देखे और मुझको कहते हुए खुशी है माननीय अध्यक्ष जी, कि वहां पर जो सबसे बड़ा ग्रुप जो बायर्स का था, वह चाइना से आया था। लोग सोचते हैं कि चाइना से सामान आता है, हम चाइना से सामान मंगाते हैं, जबकि वहां पर चाइनीज जो बायर्स टीम आई थी, हमने उससे बात की मैंने पूछा कि हम लोग तो सोचते हैं कि चाइना ही सब कुछ देता है, आप उत्तर प्रदेश से क्या ले रहे हो?

उनका कहना था कि चाइना में मशीन का सामान बहुत अच्छा मिलता है लेकिन उत्तर प्रदेश में हाथ का जो हुनर है, जो कारीगरी है और जो क्वालिटी है, उसका कोई जोड़ नहीं है। सबसे बड़ी परचेज आज की तारीख में एक बिलियन डॉलर के आसपास

की, मुझको वहां के ई0डी0 ने बताया कि हम चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश की खासियत है, उसी एक्जीविशन की जिसमें आप ने देखा। यह सच है कि बहुत खूबसूरत सामान था, उसको हमने एक और चीज की है अध्यक्ष जी, कि जितनी एसोसियेशन वाले थे, हम लोगों ने व्यावसायिक शिक्षा विभाग में जितने इण्डस्ट्रीज हो चाहे वह ग्लॉस की हो, चाहे पीतल की हो, चाहे कैंची की हो, चाहे कपड़े की हो, चाहे रेशम की हो, चाहे चिकनकारी की हो, चाहे जरदोजी की हो, चाहे आरी की हो, चाहे मुर्री की हो, चाहे कांच की हो सबको बुलाकर हमने कहा है कि आप हमें बताइये कि किस तरह की ट्रेनिंग की आपको जरूरत है। हम बच्चे को ट्रेण्ड करना चाहते हैं, पैसा हम दे देंगे, आई0टी0आई0 हम खोल देंगे। आप हमें बताइये, मैं खुशी से आपको बता रहा हूं कि बहुत सारी एसोसियेशन जैसे– मुरादाबाद की पीतल है, फिरोजाबाद की कांच उद्योग है, उन्होंने पलट कर रिस्पॉन्सेज भी भेजे हैं, जवाब भी भेजे हैं कि इस तरह की ट्रेनिंग वह करने जा रहे हैं। उस काम का भी हम इस साल में पूरा कर देंगे। अगली बार सदन में आएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम यह खुशखबरी सदन को देंगे, आपके माध्यम से (मेजों की थपथपाहट)। माननीय अंतिम बात कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि सैलरी फिक्स करने की बात जो माननीय सदस्या ने कही उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी मिनिमम वेजेज एक्ट एक भारत सरकार द्वारा प्रस्थापित एक्ट है, जिसको उत्तर प्रदेश की और हिन्दुस्तान की सारी असेम्बलीज फॉलो करती हैं। वह एक्ट आलरेडी एम्लाइड जो बढ़ाने का काम करना है। वह हमें मार्केट डेवलप करके करना होगा। एक विचार के लेविल पर एक संस्थागत का इकट्ठा करके करना होगा। उसमें समाजवादी सरकार कमीटेड है, माननीय मुख्य मंत्री जी का विजन है, दुनिया में हर लेविल के आर्टीजेन्स को उन्होंने देखा है, और उसी लेविल पर उसे डेवलप करना चाहते हैं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही चतुराई से सारे विषय पर अपनी बात रखी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए, बस थोड़ी–सी बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष–

केवल एक स्पष्टीकरण करो।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा–

केवल एक स्पष्टीकरण पूछना है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल एक स्पष्टीकरण लूंगा। मैं भी माननीय मंत्री जी का सम्मान करता हूं, मेडिकल ग्रेजुएट के साथ–साथ, मैं साइंस का ग्रेजुएट रहा हूं और साइकोलॉजी को मेडिकल में पढ़ा है। टैलेन्ट कॉन नॉट वी एक्वायरड.....

श्री अध्यक्ष–

इसको हिन्दी में बोले, यह विधान सभा है।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0के0 वर्मा–

इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 20 नये आई0टी0आई0 खोलने का इरादा है। हम लोग चाहते हैं कि उसका मानक क्या है, उसके पैरामीटर क्या हैं, किन क्षेत्रों का चयन हो रहा है, वह सदन में और इस पुस्तिका में स्पष्ट होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, यही हो रहा है कि जहां पर इडस्ट्री है वहीं पर इंडस्ट्री लगायी जा रही है। हमारे इलाहाबाद की धरती पर कई विश्वविद्यालय हैं वहां पर फिर से विश्वविद्यालय लगा दिया गया इसके पहले हमने पूर्व के सदन में प्रतापगढ़ के लिए विश्वविद्यालय की मांग की थी।

श्री अध्यक्ष–

आप विश्वविद्यालय में कहां चले गये उच्च शिक्षा पर तो बोले नहीं आप।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0क0 वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, एक जानकारी मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा स्किल्ड डेवलपमेन्ट प्रोग्राम में 46 लाख लोग रजिस्टर्ड किये गये लेकिन माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि कितने लोग स्किल्ड किये गये।

'श्री विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं एक छोटा सा सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा ज्यादा समय नहीं लूंगा। फतेहपुर में आई0टी0आई0 है और वह फतेहपुर का आई0टी0आई0 बहुत ममय से अपग्रेडेशन मांग रहा है। वहां पर यदि अपग्रेड करेंगे और खासकर मैं समझता हूं कि जितने भी पिछड़े जिले हैं इनमें यदि आई0टी0आई0 को अपग्रेड किया जाय तो उनका जो स्किल्ड डेवलपमेंन्ट का सेट होगा तो मार्केट के अन्दर बहुत कम्पटीटिव होगा क्योंकि उनके लिए जो नौकरी है वह उनका मेनसेट है और वह नौकरी दिल्ली के लोगों से या और किसी क्षेत्र के लोगों से यदि कोई स्किल्ड सेट उनको 25000 रूपये में किसी इम्पलायर को मिल रहा है तो छोटे जनपद का स्किल्ड सेट का आदमी 10 हजार और 15 हजार में कर लेगा उससे क्या होगा कि एक कम्पटीशन बढ़ेगा मार्केट के अन्दर। उस दिन यहां संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए थे और उनकी भी यह चिन्ता थी सारे सदन और सारे देश की यह चिन्ता है कि हम चाइना के कम्पटीशन में कैसे अपने माल को कम पैसे में मार्केट में लेकर आये तो यह भी एक बड़ा कारण होगा। दूसरा एक बहुत छोटा सा मेरा सुझाव आपके इस कौशल विकास से संबंधित यह है कि बहुत सारे लोग आलरेडी उद्योग और छोटे उद्योग और सेल्फ इम्पलायड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जो लोग सेल्फ इम्पलाएड हैं, हो सकता है उनके लिए आपको कौशल विकास की एक ऐसी विधा का निर्माण करना पड़े क्योंकि निरन्तर अपग्रेडेशन मांगती टेक्नालॉजी जिस तरह से बदल रही है और जो चेंज आफ फेस है वह बहुत तेज हो गया है तो कुछ कारण से रात्रि में अगर इन इंस्टीट्यूट को चलाने की व्यवस्था की जा सके तो आपका खर्चा भी कम होगा और जो टीचर्स हैं वहां के उनको आप बोनस भी दे सकते हैं उनको कहीं जाकर कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसी प्रोमाइसेस से डबुल हो जायेगा आपका आउटपुट और जो लोग 5 साल 10 साल बाद बाहर होने वाले उस रेस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से टेक्नोलॉची की इनोवेशन की रेस से वह वापस उस रेस में आ जायेंगे। यह मेरा एक छोटा सा सुझाव था।

'श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं आपने आई0टी0आई0 में कांच उद्योग के लिए।

श्री अध्यक्ष–

भाषण तो किया नहीं है स्पष्टीकरण पूछोगे, पूछो जल्दी पूछो।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कांच के बहुत बड़े क्षेत्र में आई0टी0आई0 का अभी तक कोई काम नहीं हुआ। आपने खुद नोटिस में लिया है तो फिरोजाबाद में विशेष रूप से अगर कांच की कारीगरी के लिए अगर आप संस्था खोलेंगे तो यह बहुत ठीक होगा।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ पूछना नहीं, बल्कि मेरी एक शिकायत है, जो वहां पर हुई है कहना चाहती हूं कि सिकन्दराबाद ब्लाक में एक अल्पसंख्यक आई0टी0आई0 और वहां उसका कार्य भी आरंभ कर दिया गया। आधी–आधी बाउण्ड्री भी बन गई, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात उसको हटा लिया गया और वह दूसरी जगह ट्रांसफर कर दी गई, चूंकि सरकार का इतना पैसा उसमें लग चुका था और उसके बाद इसको वहां से हटा दिया गया, मेरा माननीय मंत्री जी आपसे यह कहना है कि चूंकि सिकन्दराबाद ब्लाक में भी कम से कम 80 हजार अल्पसंख्यक रहते हैं, तो वहां पर जरूर आई0टी0आई0 बनवाने का काम करें।

व्यावसायिक एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)–

माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर दो बातें आई हैं एक फतेहपुर आई0टी0आई0 की अपग्रेडेशन नाइट शिफ्ट की और दूसरी जो माननीय सदस्या ने बात कही है इसको दिखवा लिया जायेगा और जो उचित कार्यवाही होगी वह की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना कटमोशन वापस ले रहे हैं ?

(कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं लिये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–69–व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–69–व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,59,03,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकति की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

रु2.10, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या–75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

'बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,23,09,79,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या– 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,43,39,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा जो है यही मूल शिक्षा है। बच्चों को अक्षर का ज्ञान से लेकर समाज में प्रवेश कराने का काम प्राथमिक शिक्षा से ही होता है, इसलिये यह सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मानी गई है और बराबर माननीय सदन एवं माननीय सदन के सदस्य इस बात पर हमेशा चिंतित रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा को कैसे बढ़िया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में तब्दील करके जो अभिभावक कम पैसे वाले हैं, जो अपने बच्चों को अपनी कमाई का अधिक पैसा खर्च करके पब्लिक स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनका पैसा बचे और प्राथमिक शिक्षा को ऐसी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने की व्यवस्था हो कि प्राथमिक शिक्षा एक मजबूत शिक्षा के नाम से उभरे इस समाज में। जैसे हमारे यहां 113350 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं, 46133 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, अपवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिये कक्षा–6 से 8 तक की आवासीय शिक्षा देने हेतु 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित हैं। प्राथमिक विद्यालयों में 173000 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में 106000 शिक्षक तैनात हैं। इन प्राथमिक विद्यालयों में एक करोड़ बत्तीस लाख तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चालीस लाख छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं। प्रदेश में साक्षरता मिशन के अंतर्गत 49921 लोक शिक्षा केन्द्र संचालित हैं जिनमें 94000 प्रेरक संविदा पर कार्यरत हैं। इन संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिये विभाग ने बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिये हैं जैसे, राय जी आप बात बाद में करिये प्राथमिक शिक्षा पर अगर चिंतित हैं तो पहले सुनिये और सुझाव दीजिये। हमेशा जब से प्राथमिक शिक्षा का इतिहास है, तब से आज तक बच्चे टाट–पट्टी पर नीचे बैठकर पढ़ते हैं और वह हीन भावना से ग्रसित होते हैं और बराबर इस बात की मांग भी आती रही है कि बालकों को हीन भावना से कैसे ऊपर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उठाया जाये, तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि उस व्यवस्था को बदलकर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हम कुर्सी–मेज की व्यवस्था करके बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे जिससे वह हीन भावना से ऊपर उठ सके और इसके बाद दूसरे चरण में हम प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी कुर्सी–मेज की व्यवस्था करेंगे। सभी विद्यालयों में से लगभग अधिकांश में शौचालय का निर्माण हो चुका है और हैण्डपाइप की भी व्यवस्था कर दी गयी है। 7,889 विद्यालयों में जिनमें शौचालय नहीं था, उनमें शौचालय बनाने का काम प्रारम्भ हो चुका है। जिन विद्यालयों में हैण्डपाइप नहीं लगे हैं, उनमें केन्द्र सरकार से हैण्डपाइप के लिये केवल प्रति हैण्डपाइप 15 हजार रुपया आवंटित किया गया था, उसमें हैण्डपाइप लग नहीं सकता । इसके लगाने में पठारी और देहात क्षेत्रों में जो और लागत आयेगी, 54 हजार पठारी में और 45 हजार देहात में, तो उसके हिसाब से हमने पैसा मांगा है तो जल्दी ही यह पैसा वहां से आ जायेगा और सभी स्कूल हैन्डपंप से सेचुरेट हो जायेंगे। सबसे बड़ी बात है कि गुणवत्ता पर नजर रखने के लिये हमने अधिकारियों की मानीटरिंग की व्यवस्था कर दी है। इसके लिये खंड शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, डायरेक्टर, सचिव, विशेष सचिव और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, सब प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं और शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये बराबर प्रयास कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मध्याह्न भोजन हमारे यहां एक बहुत बड़ी योजना है, जिसमें दो–ढाई करोड़ बच्चों को प्रतिदिन भोजन देने की व्यवस्था की गयी है, इसके अन्तर्गत हमने अधिकांश विद्यालयों में किचेन की व्यवस्था कर दी है, बर्तन की व्यवस्था की गयी है और रसोई बनाने के लिये 40 हजार रसोइयों की नियुक्ति भी मानदेय के आधार पर की गयी है और सभी छात्र–छात्राओं को स्वच्छ भोजन मिले, इसकी पूरी व्यवस्था की गयी है और प्रदेश में आइडिया बेस्ड प्रणाली विकसित की गयी है जो प्रतिदिन बच्चों के भोजन की निगरानी करता है कि कितने बच्चे भोजन किये, शुद्व भोजन था कि नहीं था, श्रीमन्, यह योजना इतनी सफल है कि भारत सरकार ने तो इसकी सराहना की ही है, पूरे देश में आइडिया प्रणाली लागू करने की योजना केन्द्र सरकार चलाने जा रही है। हमने इसमें और भी सुधार लाने के लिये जो देश क्या दुनिया में मशहूर है अक्षयपात्र संस्था, बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने में। यह संस्था पहले अपने यहां मथुरा–वृन्दावन में संचालित हो रही थी, फिर चार जनपदों के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनसे आग्रह किया, उन्होंने इनको ले लिया है, जिसमें कल ही लखनऊ में अक्षयपात्र के किचन का माननीय मुख्य मंत्री जी ने उद्घाटन किया है और उसके माध्यम से पूरे लखनऊ में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जायेगी । एक बड़ी चिन्ता सदन कर रहा था, हम भी चिन्तित थे, जब से हम इस विभाग की जिम्मेदारी संभाले हैं कि प्राथमिक स्कूलों में छात्र–छात्राओं की संख्या कम होती जा रही है। उसका कारण था ठीक से पठन–पाठन का न होना, गुरूजनों का पढ़ाई में मन न लगाना, अन्यत्र कामों में लगे रहना या हमारा जुलाई से स्कूल खुलता था और पब्लिक, प्राइवेट और मिशनरी स्कूल

अप्रैल में ही नोमीनेशन करते थे तो हमने भी बच्चों की संख्या बढ़ाने की दृष्टि से एक अप्रैल से ही सीजन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। अब प्राथमिक विद्यालयों में भी एक अप्रैल से ही बच्चों का नामांकन किया जायेगा। अभी जो हमारी एन0सी0ई0आर0टी0 संस्था है, उसने प्रथम बार इस प्रदेश में एक सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ किया है कि कितने छात्र–छात्राओं का बौद्विक स्तर ऊंचा है, कितने का बौद्विक स्तर कम है, कितने बच्चों का सामान्य से कम है, उस सर्वेक्षण के अनुसार हम बच्चों को शिक्षा देने में सक्षम करायेंगे और यह देश में पहला उत्तर प्रदेश है जिसमें यह व्यवस्था लागू की जा रही है 17 डायट्स में विकलांगजनों के लिए और पूर्व में पूर्णतः शौचालयों की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। 70 डायट्स और 701 निजी महाविद्यालयों के माध्यम से, 70 हमारे डायट हैं और 701 निजी महाविद्यालयों को हमने बी0टी0सी0 ट्रेनिंग के लिए अनुमति दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय है, हमारे 70 डायट तो कर ही रहे हैं, 701 निजी स्कूलों को हमारे विभाग ने हमारी सरकार ने मान्यता दे करके उनको बी0टी0सी0 पढ़ाने के लिए उनको छूट दी है, जिसके माध्यम से ये काम कर रहे हैं। मान्यवर, विश्व बैंक की टीम आई थी उत्तर प्रदेश में और इस बात की उसने सराहना किया है अवस्थापना सुविधाओं की और शिक्षकों की उपलब्धता की और उसने देश में उत्तर प्रदेश के इस ग्राफ को माना है तथा विद्यालयों की स्थापना और शिक्षकों की भर्ती के लिए पूरे देश में उत्तर प्रदेश को नम्बर–1 माना है। अब श्रीमन् बार–बार इस बात की चर्चा होती थी सदन में कि बड़ी भारी कमी है शिक्षकों की, थी भी। इस सरकार के पहले किसी सरकार ने न तो हिम्मत जुटाई और न ही यह उसके पास कार्ययोजना थी कि प्राथमिक शिक्षा को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। हमारी सरकार आने पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पर इच्छाशक्ति दिखाई और नियुक्ति की प्रक्रिया प्राथमिक स्कूलों में खोली। बी0टी0सी0 प्रशिक्षित शिक्षक 1 लाख 8 हजार 170 शिक्षक भर्ती हुए, प्रशिक्षु शिक्षक 44 हजार भर्ती हुए, शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया है 58 हजार 903, अंशकालिक अनुदेशक की 31 हजार भर्ती की गई है, साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रेरक की 61 हजार भर्ती की गई है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 756 नियुक्तियां की गई है, महिला समाख्या में 26 नियुक्ति की गई है। कुल 2 लाख 13 हजार 822 नियुक्तियॉ अब तक प्राथमिक शिक्षा में की जा चुकी हैं जो कि पूरे हिन्दुस्तान में किसी भी स्टेट के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत् सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के 15 पदों को भरा गया है, जिला समन्वयक के 25 पदों को भरा गया है। विशेषज्ञ/वरिष्ठ विशेषज्ञ के एक–एक पदों को भरा गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त मा0 सदन को मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि शिक्षकों की निम्नानुसार भर्ती की कार्यवाही अभी विद्यमान है। 2 लाख 13 हजार 822 नियुक्तियां तो हो चुकी हैं, लेकिन जो होना है वह दो–तीन महीने में पूरे हो जायेंगे, प्रशिक्षित शिक्षक 22 हजार 825, उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणित और विज्ञान के शिक्षक 29 हजार 304, बी0टी0सी0 शिक्षक 15 हजार, शिक्षामित्रों का समायोजन 97 हजार, अंशकालिक अनुदेशक 10 हजार, इस तरह कुल 1 लाख 74 हजार

159 श्रीमन्, यह दोनों मिला करके 3 लाख 87 हजार 981 शिक्षकों की भर्ती केवल तीन साल में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा में हमारी सरकार में मा0 मुख्य मंत्री जी की प्रेरणा और उनकी अगुवाई में की गई है। अब मान्यवर, शिक्षकों की कमी जो है, उत्तर प्रदेश में खत्म हो जायेगी। श्रीमन्, इतनी व्यवस्था हमने प्राथमिक शिक्षा के लिए किया है। पिछली बार हमने लगभग 68 हजार शिक्षकों का उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर किया है और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से और अध्यक्ष जी, हमारी मंशा है और मैं यह मानता हूं कि जब तक प्राथमिक शिक्षा मजबूत नहीं होगी तब तक माध्यमिक शिक्षा मजबूत नहीं होगी और जब तक माध्यमिक शिक्षा मजबूत नहीं होगी, उच्च शिक्षा की मजबूती की परिकल्पना करना बेकार है। बजट तो आ गया उनका, वैसे पहले आना चाहिए था प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद आना चाहिए माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद आना था उच्च शिक्षा और उसके बाद आना था व्यावसायिक शिक्षा, ऐसे बजट आना चाहिए था, लेकिन आपका निर्णय है उस पर मैं कुछ नहीं कहता। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि पूरा सदन चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए हमारा सहयोग किया है आज इसका नतीजा यह निकला है कि जहां छात्र संख्या घट रही थी, अभी मैं बलिया जनपद में दौरे पर गया था, हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पिछले साल से इस साल 33 प्रतिशत छात्रों की संख्या बढ़ी है और हम आशा करते हैं कि सारे हमारे मा0 सदस्य जिस मनोयोग से प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए अपना सहयोग देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। पिछले सदन में कहा था और आज भी कह रहा हूं कि वह दिन दूर नहीं कि लोग अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल से निकाल करके प्राथमिक विद्यालय में करायेंगे इसलिए कि एक तो पढ़ाई निःशुल्क, किताब–कापी निःशुल्क, ड्रेस निःशुल्क, भोजन निःशुल्क। यह सारा निःशुल्क होने के बावजूद भी कुछ गड़बड़ियों के कारण अभिभावकों में अविश्वास पैदा हो गया था अपने बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए कतरा रहे थे लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आप की कृपा और पूरे सदन का सहयोग, हम लोगों की मेहनत और गुरुजनों का अपने कार्यों के प्रति समर्पण, आज गुरूजन भी इस बात को महसूस करने लगे हैं कि हम अगर स्कूलों में जाकर नहीं पढ़ाते हैं तो हमारी ईमेज समाज में अच्छी नहीं है। हमारे अधिकारी स्कूलों में बार–बार सर्वेक्षण कर रहे हैं, स्कूलों में चेकिंग कर रहे हैं उससे एक वातावरण बना हुआ है कि अब प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होने लगी है, गुरूजन स्कूल जाने लगे हैं, बच्चों को पढ़ाने लगे हैं। अभी इधर से माननीय सदस्य कहेंगें कि ये नहीं आता, वो नहीं आता, पहाड़ा नहीं आता है, मैं मानता हूं कि नहीं आता है क्योंकि पढ़ाने की जो व्यवस्था थी वह चरमरा गयी थी चाहे जिस कारण से चरमरा गयी हो श्रीमन्, लेकिन मैंने सदन से सहयोग मांगा, सदन ने सहयोग दिया, सभी हमारे माननीय सदस्य अपने–अपने स्कूलों का निरीक्षण किये, अध्यापक लोगों से बात की और हमने जो पत्र लिखा केवल माननीय सदस्यों को ही नहीं लिखा, जिला पंचायत अध्यक्षों को लिखा, राज्य सभा के मेम्बरों को लिखा, उत्तर प्रदेश के लोक सभा सदस्यों को लिखा, ब्लाक प्रमुखों को लिखा, प्रधानों तक को लिखा कि प्राथमिक शिक्षा जो चरमरा गयी है उस शिक्षा को मजबूत बनाने में आप सबका

सहयोग चाहिए। मुझे प्रसन्नता है अध्यक्ष जी कि सभी ने इसमें सहयोग दिया और आज स्थिति यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है, शिक्षार्थियों की नामांकन संख्या भी बढ़ रही है, हमारी अवस्थापना सुविधायें भी मजबूत हो रही है और शिक्षा की गाड़ी बढ़िया तरीके से चल पड़ी है और अगर सदन का इसी तरह से सहयोग रहा तो 2017 तक उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा मजबूत हो करके देश का नेतृत्व करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बजट प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं और माननीय सदस्यों से सुझाव मांगता हूं, उनके सुझावों के समाधान की दिशा में हम काम करेंगे। बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, बेसिक शिक्षा इतना महत्वपूर्ण विभाग है कि यह पटरी से उतरा तो प्रदेश की बहुत सारी चीजें पटरी से उतर गई। आज समाजवादी पार्टी की सरकार को तीन साल पूरे हो गये जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने पहले बजट में यह इच्छा दिखाई थी कि बेसिक शिक्षा को सुधारने की दिशा में हम काम करेंगे मुझे लगता है कि इसी उद्देश्य से माननीय मुख्य मंत्री जी ने सबसे ज्यादा बेसिक शिक्षा में मंत्री भी बनाये। लेकिन जब हर वर्ष यह बजट आता है और इस बजट की पुस्तिका हम लोगों को मिलती है और इसके साथ साथ जब हम लोग क्षेत्र के गांवों में जाते हैं स्कूलों का माहौल देखते हैं तो कहीं पर ऐसा नहीं लगता कि सुधार बहुत तेजी से हो रहा है। अभी हम लोगों के हाथ में एक अफसर की रिपोर्ट आई उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान के अन्दर शिक्षा में शायद सबसे पीछे कोई प्रदेश है तो वह उत्तर प्रदेश है। इस आय–व्ययक 2015–16 का जो भारी भरकम बजट माननीय मंत्री जी ने रखा है इस बजट का अगर वाकई में सही इस्तेमाल हो साथ ही साथ जो माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बल दिया कि मानीटरिंग हम करा रहे हैं लेकिन जो मानीटरिंग जमीनी स्तर पर है वह हो नहीं रही है। स्थिति यह है कि माननीय मंत्री जी स्वयं यह स्वीकार कर रहे थे कि कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को कक्षा 2 का जो पाठ्यक्रम है उसके उत्तर देना नहीं आता।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैंने कहा था कि इधर के लोग यह कहेंगे। मैंने इस बात को कहा था और आप कह ही दिये।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

इससे भी एक शर्मशार करने वाली बात है कि तमाम सोसल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप आई हमारे जो अध्यापकगण हैं उसके पास मीडिया के लोग गये और उनसे जब प्रश्न किया कि हमारे प्रदेश का सी0एम0 कौन है हमारा डी0एम0 कौन है, हमारा पी0एम0 कौन है, सी0एम0 बड़ा होता है या डी0एम0 बड़ा होता है ऐसे प्रश्नों के जवाब जिस तरह से हमारे गुरुजनों ने दिये हैं उसको देखकर लगता है कि वह कतई शिक्षा के प्रति गम्भीर नहीं है। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करूँगा कि आपको इसमें बहुत निगरानी करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी तभी यह शायद सुधार की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी परसों हमारे क्षेत्र में हमारा ब्लाक जो जलालाबाद है वहां पर ब्लाक की बैठक थी उसमें सभी ब्लाक स्तरीय अधिकारी बुलाए जाते हैं वहां पर बेसिक शिक्षा की जानकारी देने के लिए अधिकारीगण आए हुए थे वहां सदस्य लोग जब सवाल कर रहे थे उन्होंने जब बात रखी तो उसके बाद जब हमें अपनी बात रखने का अवसर मिला तो मैंने वहां पर जो ए0बी0आर0सी0 थे ए0बी0आर0सी0 में जो अध्यापक होते हैं मैंने उनसे सीधे पूछा कि आप जलालाबाद में रहते हैं आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं उन्होंने बताया कि मेरा एक बेटा तीसरे में है एक छठे में है तो मैंने कहा कि वह उसी विद्यालय में पढ़ते हैं जहां आप पढ़ाते हैं उन्होंने कहा कि हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते जो अध्यापक वहां अध्यापन का कार्य कर रहा है उसको स्वयं भरोसा नहीं है कि हम सरकारी विद्यालय में हम अपने बच्चों को पढ़ाएं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे अधिकारियों की लम्बी चौड़ी टीम है चाहे वह जिला स्तर पर हो या मण्डल स्तर पर हो, ब्लाक स्तर पर हो वह लोग भी यहां के जो निर्देश जाते हैं माननीय मंत्री जी चाहते होंगे कि वह समीक्षा करें औचक निरीक्षण करें लेकिन वह इससे लगता है कि बचते हैं जो मण्डलीय टीम है उसका तो मैंने कभी निरीक्षण पढ़ा ही नहीं और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मंडल पर बैठे अधिकारी हैं वह एक तरह से बस वहां पर वॉच डॉग की तरह बैठे हैं न तो वह निरीक्षण करते हैं न करना चाहते हैं क्योंकि इसके पीछे जो कारण है राजनैतिक हस्तक्षेप, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर हम किसी विद्यालय में गये और किसी अध्यापक के खिलाफ कार्यवाही की तो कार्यवाही तो हम नहीं कर पायेंगें लेकिन हमारा बोरिया बिस्तर जरूर बंध जायेगा। मान्यवर, इसमें भी माननीय मंत्री जी को उनको यह ताकत देनी पड़ेगी कि आप जाकर सही काम को देखिये और जो नहीं पढ़ाता है उसके खिलाफ कार्यवाई करिये, आपका बाल बांका नहीं होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। अगर यह ताकत उनको दी जाये तो शायद मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा कदम होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां पहले भी एक बार कटमोशन रखा था जब माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2012–2013 में बजट रखा था। मैंने यह मांग रखी थी कि जो हमारी पुलिस सेवा है वह बहुत ही अनिवार्य सेवा है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी बेसिक शिक्षा है।

हमारे जो बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं उनकी अगर सही शिक्षा नहीं होगी तो मान्यवर, आज जो प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब होती है उसमें कहीं न कहीं बेसिक शिक्षा भी दोषी है। मैंने आपसे अनुरोध किया था कि जो यूनियन है उसको भी बन्द किया जाय, खत्म किया जाय। कई सारे अध्यापक यूनियन बनाकर बी0आर0सी0 में बैठे रहते हैं, बी0एस0ए0 कार्यालय में बैठे रहते हैं और वहां दबाव बनाकर अनैतिक कार्य करवाने का काम करते हैं लेकिन कभी स्कूल जाने का काम नहीं करते। इसमें क्या कठिनाई है, मैं नहीं जानता, लेकिन इस पर एक बार विचार होना चाहिए। माननीय मंत्री जी को इस पर सोचना चाहिए क्योंकि आज इतना भारी बजट और जैसा कि जो मुख्य बजट आया है माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया था उसमें जो प्रस्ताव आया है कि 9,977 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा के लिये प्रस्तावित हैं और इस बजट का रिजल्ट क्या आ रहा है यह शायद किसी से छिपा नहीं है। आज हमारे प्राइमरी स्कूलों में जो कमजोर, पिछड़े वर्ग के बच्चे, दलित समाज के बच्चे और अल्पसंख्यक समाज के बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे उनको वजीफा देने की व्यवस्था बहुत सालों से चली आ रही थी। पता नहीं क्या मजबूरी है, मैं नहीं जानता लेकिन माननीय मंत्री जी ने, इस सरकार ने इस वजीफा को बन्द करने का काम कर दिया। तमाम ऐसे बच्चे जो वहां पर पढ़ते थे उनको वजीफा देने का काम सरकार ने नहीं किया। हमारे प्रदेश के अंदर जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि तमाम अध्यापकों की भर्ती की गई लेकिन इसके बावजूद अध्यापकों की कमी है और अगर माननीय मंत्री जी ने अभी सदन को आश्वासन दिया है कि दो तीन महीने के अन्दर हम इस कमी को पूरा कर लेंगें तो मैं आपको शुभकामना देता हूं कि यह कमी जल्दी से पूरी कर ली जाय क्योंकि आज भी प्रदेश के अंदर 30 से 35 परसेन्ट स्कूल बन्द चल रहे हैं अध्यापकों के अभाव में। वहां अध्यापक नहीं हैं और अध्यापकों के अभाव में जब स्कूल नहीं चलेंगें तो स्कूल सफेद हाथी दिखाई पड़ रहे हैं। कई जिलों से इस बारे में हमारे पास बात आई है, माननीय सदस्यों से भी मुझे इस बारे में जानकारी दी गई। अभी कुछ दिन पहले एक तारांकित प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने स्वंय यह स्वीकार किया था कि प्रदेश के स्कूलों में किताबें जो फ्री में दी जाती हैं उनकी जो सप्लाई ली गई वह मानक के अनुरूप नहीं थीं, अधोमानक पुस्तके थीं। मैंने आपके माध्यम से उस दिन भी यह सवाल उठाया था और स्वंय माननीय मंत्री जी ने सदन को जानकारी दी थी कि अमेरिका जैसा विकसित देश जहां पर पुस्तकों को एक बच्चा पढ़ता है और जब वह क्लास पास करता है तो उन पुस्तकों को स्कूलों में जमा करा लेते हैं। नया बच्चा आता है और उन्हीं पुस्तकों को उन नये बच्चों को दिया जाता है और यह साइकिल चलती रहती है। मान्यवर, आप तो जानते हैं अभी हमारे विधान सभा में जब आपने यहां अधिवेशन किया तो यहां से यह घोषणा की गई कि हम सचिवालय को पेपरलेस बनाना चाहते हैं क्योंकि कागज जो आता है, कागज को बनाने के लिये हमको तमाम हरे पेड़ काटने पड़ते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से भी जो किताबें हमारे पास हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और इस पर माननीय मंत्री जी ने स्वंय बताया भी था कि हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसको अवश्य लागू कराया जाय जिससे कि इन किताबों को दोबारा बच्चे इस्तेमाल कर सकें और जो अधोमानक

किताबें जिन्होंने सप्लाई की हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाई की जाय। जिससे दुबारा वह ऐसी हरकत न कर सकें।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो तमाम अपनी उपलब्धियां बताई हैं इसके अन्तर्गत मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जब 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो माननीया बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए कई ऐसे निर्णय लिए गए थे जो आज इस सरकार ने अपने सीने पर पत्थर रखकर लागू करने का काम किया। मान्यवर, विशिष्ट बी0टी0सी0 के अन्तर्गत 88 हजार अध्यापकों की भर्ती बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुई थी। बी0टी0सी0 2001 एवं बी0टी0सी0 2004 के जितने भी लम्बित प्रकरण थे उनका निस्तारण भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में किया गया था। निजी बी0टी0सी0 कालेजों को सम्बद्धता देकर, बी0टी0सी0 प्रशिक्षण कराया गया बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, उर्दू बी0टी0सी0 शिक्षकों की नियुक्तियां भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने कराईं। प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक से अंग्रेजी पढ़ाने का काम भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार द्वारा 2008 से शुरू कराया गया। क्योंकि इससे पहले कक्षा एक के बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी। मान्यवर, स्नातक शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण कराकर शिक्षक बनाने का निर्णय तथा प्रथम बैच में साठ हजार शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण प्रारम्भ बी0एस0पी0 की सरकार में कराया गया । मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत जो कन्वर्जन कास्ट है उसको बढ़ाया गया बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, पहले रसोइयों को वेतन कन्वर्जन कास्ट से ही बच्चों की संख्या के आधार पर दिया जाता था। उस व्यवस्था को समाप्त कर बच्चों के आधार पर रसोइयों की संख्या बढ़ाई गई तथा उनके मानदेय वेतन की व्यवस्था अलग से की गई। रसोइयों का वेतन एक हजार प्रतिमाह किया गया बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। सभी बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है या नहीं यह सुनिश्चत करने हेतु आई0बी0आर0एस0 व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था के तहत प्रधान अध्यापकों, सहायक अध्यापकों के मोबाइल से सूचना एकत्र की जाती थी। यह भी हमारी सरकार ने लागू कराया था। मान्यवर, मिड डे मील में खाना पकाने के बर्तन और खाना पकाने हेतु रसोई गैस की व्यवस्था कराई गई। ब्रान्डेड मसाले नमक तथा तेल आदि के इस्तेमाल का प्राविधान किया गया। प्रत्येक दिन के हिसाब से मील निर्धारित किया गया यह बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किया।

(शोर)

उच्च प्राथमिक विद्यालयों और कक्षों का निर्माण कराया गया। प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्युतीकरण का निर्णय भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में लिया गया था। सभी प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अग्निशमन यंत्रों को स्थापित कराया गया। यह निर्णय भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कराया गया।

श्री अध्यक्ष–

यह तो उस बजट में आया होगा जब आपकी सरकार रही होगी। आगे बताइए।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि पिछली सरकार गम्भीर नहीं थी। अगर गम्भीर न होती तो इतने जो निर्णय लिए गए यह कैसे लिए गए। उन निर्णयों को आपकी सरकार सही तरीके से चला नहीं पा रही है

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप करें। बहुत लोग बोलेंगे।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, पेयजल हेतु प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व्यवस्था की गई। (शोर) समस्त बालिकाओं और अनुसूचित जाति के बालकों को ड्रेस दी गई जिसकी पूर्व में कीमत 90/–रुपये थी। सभी बालक बालिकाओं को दो–दो ड्रेस देने दिए जाने का निर्णय लिया गया और छात्र ड्रेस के नाम पर 200 रुपये का प्राविधान कराया गया।

श्री अध्यक्ष–

सुझाव दें।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

72 हजार 825 लोगों को टी0ई0टी0 कराकर अध्यापक बनाया जिसकी अभी नियुक्ति चल रही है। यह हमारी सरकार का निर्णय है और यह निर्णय तब हुआ जब तमाम अभ्यर्थियों को, क्योंकि आप नियुक्ति नहीं कर रहे थे, तो उनको उच्च न्यायालय जाना पड़ा और जब वह उच्च न्यायालय गये तब सरकार को झुकना पड़ा और आज मा0 उच्च न्यायालय के आदेश पर टी0ई0टी0 पास अध्यापको को बनाया जा रहा है जो भर्ती हो रही है। यह मा0 न्यायालय के आदेश से बनाया जा रहा है।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों के द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मौर्य जी, यह सब बातें जो आप कह रहे हैं यह सब आपकी सरकार की तरफ से जो किताब बंटी होंगी उसमें आयी होंगी। आगे कुछ सुझाव दीजिये। जो आपने किया वह किया, यह तो पुरानी बातें हो गयीं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष जी, आपके निर्देशन में इस सदन को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का हमारा पूरा प्रयास है। सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यगण जिस तरीके से बीच–बीच में अवरोध पैदा कर रहे हैं तो मा0 मंत्रीगण को इस बात का अहसास होना चाहिये कि उनको भी बजट प्रस्तुत करते वक्त बोलना है, स्पष्टीकरण पर भी बोलना है। क्या आप चाहते हैं कि यही व्यवधान आपके साथ भी किया जाये ? मान्यवर, मैं चाहता हूं कि जब आप बोलते हैं तो हमारे विपक्ष के सभी मा0 सदस्यगण बहुत ही धैर्य के साथ और शांतिपूर्वक पूरी बात सुनते हैं और जब कोई जवाब देना भी होता है और आपके आदेश से जब हमारे मा0 सदस्यों को बोलने का मौका मिलता है तो अपनी बात रखते हैं। इसमें

सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मा0 सदस्यों को बोलने का मौका मिलता है। इसलिये हम यह चाहते हैं कि जब उनको बोलने का मौका मिले तो उन्हें जो भी कहना है कह लें, लेकिन बीच में इस प्रकार कटौती प्रस्ताव में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। इसलिये मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है उस बात पर विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, लेकिन एक बात और है कि जिस बात का आप उल्लेख कर रहे हैं। सरकार वह गयी, सरकार के जाने के बाद जब पहला बजट आया तब तक उल्लेख करते तो बात पता चलती, लेकिन उसी बात को 2012 में दोहराना और उसी को 2015 में दोहराने का न तो कोई सन्दर्भ है और न ही कोई अर्थ है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष महोदय जी, मा0 चौधरी साहब तो बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं और जो बजट रख रहे हैं हम समझते हैं वह आपसे भी वरिष्ठ होंगे, हमसे भी वरिष्ठ हैं तो चौधरी साहब, सूरज को दीपक नहीं दिखाना चाहिये। चौधरी साहब सक्षम हैं अपनी बात रख लेंगे, लेकिन यह बात रखने की आवश्यकता क्यों ? जब आप 2012 में वही कहानी, 2013 में वही कहानी, 2014 में वही कहानी और 2015 में वही कहानी कह करके अपनी पीठ थपथपायेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमें सही तथ्य रखने पड़ेंगे। चूंकि हमारे किये–कराये पर आप अपना सिर, आप अपनी छाती पीटना चाहते हैं इसको हम आंख मूंद करके, गूंगे–बहरे–अंधे बन करके यहां केवल तमाशा देखने नहीं आये हैं, बल्कि हम सही बात कहने आये हैं तो जो सही बात है अगर वह रखी जा रही है और यदि कहीं प्रतिकार है तो जब आपको कहने का मौका मिलेगा तब आप जो कुछ कहना हो कह लीजियेगा।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों के द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने का व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत रहें। कुशवाहा जी, आप जल्दी खत्म कीजिये। इस पर बहुत लोग बोलेंगे।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, मैं सरकार के लोगों, जो इस तरह से चिल्ला रहे हैं से यह कहना चाहूंगा कि आप सत्ता में हैं। "फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। यह हौसला नहीं है तो फिर बेअसर रहो।" तो आप सरकार में बैठे हैं तो चोट तो आप पर की जायेगी। धीरज से सुनिये। मा0 अध्यक्ष महोदय, अभी मा0 मंत्री जी ने अपने भाषण में यह बात रखी कि मैं सी0बी0एस0ई0 की तर्ज पर 01 अप्रैल से नया सत्र लागू करूंगा। अभी मा0 मंत्री जी ने यहां पर यह बात रखी। अच्छी बात है। चूंकि जब कंपटीशन चल रहा है तो इन सरकारी स्कूलों को भी उसी श्रेणी में लाकर खड़ा करना पड़ेगा जिसमें और संस्थायें जो दूसरे बोर्ड हमारे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि

आज 16 मार्च हो गई है और बच्चों के जो 01 अप्रैल से स्कूल चलाये जायेंगे उनको जो पाठ्य पुस्तकें देनी हैं उन पाठ्य पुस्तकों की छपाई की जो सरकार की नीति है वह नीति ही अभी तक डिसाइड नहीं हो पायी है, पुस्तकें आना तो बहुत बाद की बात है तो कैसे मा0 मंत्री जी 01 अप्रैल से सत्र चलायेंगे ? मुझे लग रहा है कि फिर वही जुलाई–अगस्त में किताबें आ पायेंगी और फिर कहीं वही अधोमानक शिकायत आ गई, क्योंकि अभी किसी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है, कार्रवाई नहीं की गयी है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि चूंकि अभी 15 दिन का समय है, 15 दिन में यह सुनिश्चित करा लें, अगर अप्रैल से सत्र चलाना है तो पुस्तकों की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, पुस्तकें हमारे पास आ जायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ सुझाव तैयार किए हैं, मैं समझता हूं कि मा0 मंत्री जी अगर इनको अमलीजामा पहनायेंगे तो अवश्य ही बेसिक शिक्षा आगे बढ़ेगी। अभी सर्व शिक्षा अभियान के तहत मा0 मुख्य मंत्री जी की तरफ से हम लोगों को एक पत्र भी भेजा गया है, सबको मिला होगा, लेकिन यह जो पत्र मिला है, इसके माध्यम से जिलों में कोई कार्यवाई होती नजर नहीं आ रही है कि जिससे 01 अप्रैल से हम सत्र को सही तरीके से चला सकें। मान्यवर, जो प्राइवेट विद्यालय हैं, वहां के जो मानक हैं, उनको लागू करने का काम आपको भी करना पड़ेगा और छात्र अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति प्रत्येक विद्यालय में हो, छात्र अनुपात प्राथमिक स्तर पर 30:1 और जूनियर स्तर पर 40:1 का लागू किया जाएं। अधिकतर शिकायत रहती है कि शिक्षक स्कूल नहीं जाते हैं और कई शिक्षकों की मेरे पास जानकारी मिलती है कि वह 7–8 दिन में जाते हैं और सारे साइन करके चले आते हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि शिक्षक विद्यालय में नियमित तथा ससमय उपस्थित हों, इसके लिए बायोमैट्रिक प्रणाली लागू की जाएं। शिक्षा कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य शिक्षकों से न लिए जायें, राष्ट्रीय कार्यक्रम और निर्वाचन के कार्य को छोड़कर। एम0डी0एम0 तथा भवन निर्माण जैसे कार्य शिक्षकों से न लिए जायें और जिस तरह से कल लखनऊ के अन्दर अक्षयपात्र की शुरूआत आपने की, चार जिले और लिए हैं, मैं चाहूंगा कि इसको पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएं क्योंकि अक्षय पात्र ही एक ऐसी संस्था है, जो मिड–डे–मील की गुणवत्ता को सही कर सकती है और वही सही मायने में पहुंचा सकती है। मान्यवर, निजी विद्यालयों के समकक्ष बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को लाने के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया करायी जायें, शुद्ध पेयजल, चहारदीवारी, शौचालय, आवश्यकतानुसार भवन तथा फर्नीचर। अभी मा0 मंत्री जी ने फर्नीचर की बात की, मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आपने यह अच्छा कदम उठाया है, अच्छी बात है और आज का जो युग है, आज कम्प्यूटर का युग है। आज नर्सरी के बच्चे भी कम्प्यूटर चला लेते हैं। सरकार की यह प्राथमिकता रही है कि हम गॉव के बच्चों को शहरी बच्चों के बराबर लाकर खड़ा करेंगे। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आधुनिक कम्प्यूटर शिक्षण व्यवस्था हेतु समुचित विद्युत आपूर्ति भी सुनिश्चित कराई जाएं और प्राइमरी स्कूलों में कम्प्यूटर की शिक्षा भी लागू करायी जाएं। शैक्षिक सत्र–2006–07 तथा 2008 से विद्यालयों का विद्युतीकरण करने का कार्य शुरू कराया गया। मैं चाहता हूं कि जहां–जहां भी यह नहीं हो पाया है, इसको

सुनिश्चित कराकर विद्युतीकरण कराया जाएं। बेसिक शिक्षा परिषद के सभी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक नियमित लिपिक भी रखा जाए, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी में अभिलेखों के मेंटीनेन्स तथा एमडीएम की व्यवस्था और अन्य कार्य हों। बाल–गणना, जनगणना विभाग की बैठकों को ब्लाक स्तर पर करना सुनिश्चित कराया जाए। उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का प्रतिवर्ष शैक्षणिक मूल्यांकन कराया जाएं क्योंकि शैक्षणिक मूल्यांकन नहीं होता है तो उनको लगता है कि सैलरी मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, वह हर समय सोचते रहते हैं कि कब कौन सा वेतन आयोग लागू हो रहा है, उनको पढ़ाई में रुचि नहीं रहती है। उनकी शिक्षा अभिरूचि तथा उनका शैक्षिक ज्ञान तभी बढ़ेगा, जब ऐसा मूल्यांकन कराने की व्यवस्था की जायेगी। मान्यवर, व्यवस्था में सुधार के लिए ब्लाक स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी, जो एबीएसए हैं, इनका कार्यालय स्थापित हो। इनको ब्लाक संसाधन केन्द्र कहा जाता है। वर्तमान में खण्ड शिक्षा अधिकारी को बीडीओ के समान राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दे दिया गया है। यह गजटेड अफसर हो गए हैं, लेकिन मान्यवर, इनके पास न तो स्टाफ है, न इनके पास वाहन है, अगर इनके पास वाहन नहीं होगा, स्टाफ नहीं होगा तो जैसा अभी मा0 मंत्री जी कह रहे थे कि हम स्कूलों का निरीक्षण करायेंगे तो निरीक्षण करने वह कैसे जा पायेंगे ? इसलिए मैं चाहूंगा कि इनको वाहन उपलब्ध कराया जाएं, जैसे बी0डी0ओ0 को दिया जाता है, उसी प्रकार से इनको भी दिया जाये और जिम्मेदारी तय हो कि रोजाना 8 से 10 स्कूलों में जाकर निरीक्षण करें। मान्यवर जब तक यह नहीं होगा सुधार संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अब संक्षेप करिए।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर संक्षेप कर रहा हूं आपके आदेश से मैंने कई बिंदु हटा दिए हैं। ब्लॉक स्तर पर छः समन्वयक विषयवार तथा न्याय पंचायत स्तर पर एक समन्वयक शिक्षकों को नियुक्त कर दिया जाता है। इससे विद्यालयों का शिक्षण कार्य प्रभावित रहता है। वहीं शिक्षकों के समन्वयक बने होने से ब्लॉक मुख्यालय पर रोजाना मित्रों की भॉति शिक्षक विद्यालय जा कर वही बैठकर समय व्यतीत करते रहते हैं। शिक्षकों के समूह बने रहने से अधिकारी भी दबाव में रहता है और विभागीय निर्देशों का पालन नहीं हो पाता। इसलिए ब्लॉक स्तर पर लगाए गए समन्वयकों को उनके मूल पद पर भेजा जाए जिससे वह जिस स्कूल में शिक्षक हैं वहां का कार्य प्रभावित न हों। समन्वयक पद पर बेरोजगार स्नातक बी0एड0 धारक तथा टी0ई0टी0 उत्तीर्ण पात्रों को नियुक्त कर दिया जाए। जो भी नियुक्ति का मानक रखा जाए इसमें युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और विद्यालयों का शिक्षण कार्य भी सुचारू रूप से संचालित होगा। विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति पंजिका की तुलना में रजिस्ट्रेशन तो बहुत हैं लेकिन उनकी उपस्थिति नगण्य रहती है। अच्छे मेधावी छात्रों को अभिभावक सरकारी स्कूलों में भेजने से कतराते हैं। इसका कारण शिक्षा का माहौल तथा शिक्षकों की तमाम खामियों से भरा होना है। आवश्यकता है अभिभावक

संघ बनाया जाए। जैसे प्राइवेट स्कूलों में पेरेंटस मीटिंग होती है उसे यहां भी लागू करने की जरूरत है। अभिभावक संघ बनाकर प्रभावी किए जाएं। मासिक मीटिंग हो उसमें खुले मन से समस्याओं तथा कमियों पर विचार कर एक अच्छा माहौल तथा अच्छी शिक्षण व्यवस्था पर प्रयास शुरू किए जाएं। अभी ग्रामीण शहरी सभी बेसिक स्कूलों में केवल एम0डी0एम0 के सहारे छात्र उपस्थिति हो पा रहे हैं। सरकारी मिलने वाले प्रोत्साहन निःशुल्क ड्रेस पुस्तकें अथवा अन्य किसी अवसर पर नामांकित सभी छात्र भले ही शत–प्रतिशत उपस्थित हों किन्तु शिक्षण के समय न तो छात्र स्वयं तथा न ही अभिभावक बच्चों को विद्यालय भेजने में रूचि दिखाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें। कुशवाहा जी बहुत समय हो गया।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर सीबीएससी की तर्ज पर बेसिक शिक्षा के स्कूलों को संचालन की तैयारी करने परन्तु उनको समकक्ष व्यवस्था एवं स्थानीय वातावरण प्रदान करने की समस्या यह प्रयोग संभव है। मान्यवर जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें बी0एस0ए0 तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर शिक्षकों का जाना बंद किया जाए। स्कूलों समय पर प्रतिदिन ब्लॉको में आठ–दस स्कूलों का निरीक्षण शैक्षणिक व्यवस्था पर किया जाए। निरीक्षण के विषय अनुसार प्रारूप तैयार किया जाए और प्रारूप के आधार पर कक्षावार विषय के क्रम के निरीक्षण में मिले खामियों पर शिक्षकों का मूल्यांकन कर दण्डित किया जाए या अच्छा कार्य किए जाने पर उन्हें पुरस्कृत भी किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त कर दें और लोग भी बोलेंगे।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर दो तीन बिन्दु और रह गए हैं आपकी अनुमति हो तो बता दें। हम तो कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं आपने कहा सुझाव दो तो मैं सुझाव दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

सुझाव चार पन्ना है तो और लोगों को कब मौका मिलेगा ?

(कुछ सदस्यों द्वारा बोलने पर शोर)

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

तो फिर यहां आने की जरूरत क्या है। मान्यवर शैक्षिणक सत्र के समापन से पहले कार्यरत समस्त शिक्षकों की शैक्षणिक व्यवस्था एवं छात्र शिक्षण अभिरूचि सम्बन्धित परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा में आए परिणाम के अनुसार शिक्षकों को आर्थिक लाभ, विद्यालय लाभ, नियुक्ति पदोन्नति होनी चाहिए। और सत्य के बीच में जो स्थानांतरण और सम्बद्धीकरण है इसको पूर्णतया बंद करना चाहिए। मान्यवर प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों की भॉति बेसिक शिक्षा परिषद का स्तर बनाने के लिए मिश्रित ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षणशाला आयोजित करनी चाहिए ताकि शिक्षण कार्य तथा शिक्षक अभिरूचि सम्बन्धी

विचारों का आदान–प्रदान हो सके और नया शिक्षक उसे सीखकर अमल कर सके। मान्यवर मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि विद्यालय सुव्यविस्थत संचालित होने की पूर्ण जिम्मेदारी खण्ड शिक्षा अधिकारी की रखी जाएं। यह तय कर दिया जाएं कि किसकी जिम्मेदारी है। यदि ब्लॉक के अंदर कोई स्कूल बंद रहता है या शिक्षक जिम्मेदारी से कार्य नहीं करता है तो एबीएसए के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही तय होनी चाहिए। इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। बेसिक शिक्षा में व्यापक सुधार हेतु प्रतिवर्ष नए–नए प्रयोग शुरू किए जाते हैं किन्तु सभी असफल हो जाते हैं। कारण कि प्रयोगों की असफलता की समीक्षा नहीं होती और न ही प्रयोग का कोई अधिकारी जिम्मेदार बनाया जाता है। एक सिस्टम निश्चित समय तक लागू किया जाये तथा किसी अधिकारी को जिम्मेदार बनाया जाये तब समीक्षा में उसका प्रतिफल अवश्य दिखायी पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी और साथ में उनके तीन राज्य मंत्री हैं। आप स्वयं भी प्रदेश के अंदर औचक निरीक्षण करने का काम करिये जो अभी तक हमें दिखायी नहीं पड़ा। हमारे जनपद में तो कोई निरीक्षण करने आया नहीं और जब आप औचक निरीक्षण करेंगे तो अधिकारियों पर दबाव रहेगा कि पता नहीं कब कहां मा0 मंत्री जी आ जायें और जब तक यह डर नहीं बनेगा तब तक बेसिक शिक्षा में कोई सुधार कहीं दिखायी नहीं पड़ता है। पहले गांव से निकले हुए लोग बड़ी–बड़ी सर्विसों में जाते थे। तमाम ऐसे लोग यहां पर हैं जो प्राइमरी से ही पढ़कर निकले हैं। लेकिन आज प्राइमरी से बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं। वह चपरासी और क्लर्क भी नहीं बन पायेंगे आज यह हालात हैं। इन हालात को सुधारने के लिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी इस पर पूरी इच्छाशक्ति से काम करें। जिस तरह से मा0 मंत्री जी ने कहा कि सदन उनका सहयोग कर रहा है। यहां पर हम लोग किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना करने नहीं आये हैं। यहां हम लोग इसलिए आये हैं कि प्रदेश की हालत सुधरे, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुधरे और शिक्षा व्यवस्था सुधारने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। और उसमें हम लोग सहयोग करने में कहीं पीछे नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अभय सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बेसिक शिक्षा विभाग के बजट के समर्थन पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए आपको धन्यवाद प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आज हमें यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि हमारे काबिल साथी ने, जबकि पूरा देश, पूरा प्रदेश हर कोई इसलिए परेशान है कि किसी तरीके से बच्चों की बेसिक शिक्षा अच्छी तरीके से हो और उस पर भी इन्होंने कटौती का प्रस्ताव कर दिया। हम इसलिए बहुत दुखी हैं और सदन को इसके लिए दुखी होना चाहिए। इसलिए दुखी हैं। हम लोग जो यहां बैठे हैं चाहे इधर बैठे हुए लोग हों चाहे उधर बैठे हुए लोग हों सब किसी के भाई होंगे, उनके बच्चे होंगे और सब चाहते होंगे कि उनके बच्चों की प्राथमिक शिक्षा अच्छी हो। आपको तो यह कहना चाहिए था कि आपको तो और बजट बढ़ाना चाहिए।

यह बहुत ही दुख का विषय है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि कटौती का प्रस्ताव करते हुए आपने सबसे पहले यह शुरू किया कि शिक्षा का स्तर पटरी से उतर गया। तो हम अपना एक संस्मरण बताना चाहते हैं। जब मैं नया–नया विधायक हुआ। एक गॉव पहुंचा धन्यवाद करने के लिए कि भईया आप लोगों ने जिता दिया। तो गॉव के लोगों ने कहा कि भईया एक चीज चाहिए। तो हमने कि आपको क्या चाहिए तो उन्होनें कहा कि हमारे यहां कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है एक सरकारी बिल्डिंग बनवा दो। तो हमने कहा कि किस बात के लिए सरकारी बिल्डिंग चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक स्कूल बनवा दो। तो हमने कहा कि स्कूल बनवा दें तो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि उसमें बारात रूकेगी। नया–नया विधायक बना था। उसके पहले पांच साल बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। तो शिक्षा का स्तर जो पटरी से उतरा था उस गांव के एक भोले भाले नागरिक ने बताया कि किस तरह से शिक्षा का स्तर पटरी से उतरा हुआ है। उन्हें स्कूल नहीं प्राइमरी स्कूल एक बारात घर के रूप में चाहिए था। इस तरीके से पिछली बहुजन समाज पार्टी की सरकार में शिक्षा का स्तर पटरी से उतर गया था। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। प्राथमिक शिक्षक अल्पवेतनभोगी होता है। बहुत कमजोर होता है। शहरों में रहने वाले ज्यादातर लोग तैयारी करते हैं कि हमको आई0ए0एस0 बनना है, पी0सी0एस0 बनना है, सी0ए0 बनना है। लेकिन गॉव के गरीब मजदूर और किसान के परिवार के लोग होते हैं वह सोचते हैं कि किसी तरीके से मेरा बेटा पढ़ जाये, बढ़ जाये और प्राइमरी में मास्टर बन जाये। ऐसे गरीब परिवारों के लोग वह लोग प्राथमिक शिक्षक बने। कोई कुशीनगर पोस्ट था, कोई देवरिया था, कोई गाजियाबाद था, कोई बुलन्दशहर था। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने सरकार बनते ही उनका स्थानान्तरण अपने जिले में करने का काम किया इसके लिए हमारे मंत्री जी बहुत–बहुत बधायी के पात्र हैं। ऐसे लोग जिनकी पत्नियां दूर थीं। बेचारे अपना काम धन्धा छोड़कर पत्नियों को सेटल कराने के लिए मोटर साईकिल से लेकर सुबह जाते थे शाम को पत्नी को पढ़वाकर लौटते थे। मां–बाप की तबियत खराब थी तब भी वह दूर थे। लेकिन वह स्थानान्तरण होकर आये इसके लिए हम एक बार फिर से इस सदन के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी को, मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी को बहुत–बहुत बधाई देते हैं। उसके बाद जब वह स्थानान्तरण होकर आये तो महिलाओं के लिए हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने विशेष व्यवस्था किया कि कोई महिला इंटीरियर के विद्यालयों में पोस्ट नहीं होगी। जो भी महिला पोस्ट होगी मेन रोड पर पोस्ट होगी। रोड से 100–200–500 मीटर के अंदर पोस्ट होगी। अंदर पोस्ट करने वाले सारे बी0एस0ए0 के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएंगी। यह हमारे यहां स्पष्ट रूप से निर्देश हो गये हैं। हम आपसे कहना चाहते है जिस तरीके से हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने सरकार बनने के बाद प्राथमिक शिक्षकों के प्रति मानवता से संवेदनशीलता से काम लिया, इसके लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत–बहुत बधाई के पात्र हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि पूर्व की सरकार थी, शिक्षक हुआ करते थे और साल भर स्थानान्तरण उद्योग चला करता था।

बी0एस0ए0 को अधिकार था जिसकी इच्छा हो एप्लीकेशन ले, उनका नेता फोन करें तुरन्त सुबह फोन किया और शाम को ट्रान्सफर हो गया। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने अधिकारियों की नकेल कसने में, करेपशन रोकने में बहुत शानदार काम किया जो उन्होनें उनके अधिकार सीमित कर दिये, और सिर्फ स्थानान्तरण सत्र में स्थानान्तरण हो रहा है, बाद में किसी भी प्रकार का कोई स्थानान्तरण, नहीं हो सकता प्राथमिक शिक्षक का। किसी भी दल का विधायक चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो। वह बिल्कुल निश्चिन्त तरीके से, बिना भयभीत होकर, बिना दबाव के काम कर रहा है, पढ़ा रहा है, इसके लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। हम आपसे बताना चाहते हैं अभी हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि किस तरीके से हमने इंगलिश मीडियम में पढ़ाने की बात शुरू की। हम लोग लगातार विद्यालय में जाते हैं, बच्चो के साथ बैठकर भोजन करते हैं, भोजन की गुणवत्ता चेक करते हैं, शिक्षकों से पूछते हैं पिछले साल कितने बच्चे आपके यहां थे ? इस साल कितने बच्चें हैं ? और संख्या कम क्यों हुई? हर जगह हम लोगों ने जब बात–चीत की तो पता चला कि मजदूर का बेटा हो चाहे किसान का बेटा हो वह मजदूरी करते हैं लेकिन उसके बाद भी उनकी यह प्राथमिकता होती है कि उनका बेटा उच्च शिक्षा पाये चाहे उसके लिए उन्हें 1000 रूपये फीस देनी पड़े या 1500 रूपये देनी पड़े। जगह–जगह आप लोग देख रहे हैं कि कुकुरमुत्ते की तरीके से छोटे–छोटे स्कूल खुल गयें हैं, कोचिंग सेन्टर के नाम पर स्कूल चला रहे हैं, एफिलिएशन कहीं और से हैं। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने इसको देखकर सख्त निर्णय लिया और ऐसे सारे इल्लीगल स्कूलों को बन्द कराने का काम किया, कार्यवाई करने का काम किया और जो समाज के अन्दर से निकल कर लोगों की भावनायें आ रही थी कि हमारे बेटे को इंगलिश पढ़ना चाहिए, हमारे बेटे को ऐसे स्कूल में जाना चाहिए जहां फर्नीचर होना चाहिए। जैसे और अफसरों के बेटे पढ़ते हैं, पूंजीपतियों के, सामन्तवादियों के बेटे पढ़ते हैं, हमारे परिवार के बेटे को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। उसमें इन्फीरिआरिटी काम्पलेक्स नहीं होना चाहिए हमारा बेटा भी अच्छे माहौल में पढ़े, अच्छे संस्कार में पढ़े। उसको पूरा करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी पूरे प्रदेश में फर्नीचर उपलब्ध करा रहे हैं और हर जिले में 05–05 इंगलिश मीडियम स्कूल शुरू करने जा रहे हैं। हमारे जिले फैजाबाद में हम लोगों ने बी0एस0ए0 से बात की, हमारे विधायकों ने बात की, पवन पाण्डे जी ने बात की और हमारे यहां तो हर ब्लाक में 05 इंगलिश मीडियम स्कूल शुरू होने जा रहे हैं। हम आपसे बताना चाहते हैं माननीय मुख्य मंत्री जी अक्षयपात्र योजना की शुरूआत की उसके लिए विपक्ष के विधायक जी ने पारित किया इसलिए आपको भी हम धन्यवाद देना चाहते है कि हमारे मुख्य मंत्री जी द्वारा किये गये कार्यों की आपने सराहना की। एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से केन्द्र सरकार ने हम लोगों के साथ भेद–भाव किया, सर्व शिक्षा अभियान में 4000 करोड़ रूपये बचत की कटौती की, एम0डी0एम0 में 3000 करोड़ रूपये बचत की कटौती की, नये विद्यालय 03 साल से हम लोगों को केन्द्र सरकार ने नहीं दिया। चहारदिवारी जो

उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बनना अतिआवश्यक होता है 02 सालों से नहीं दिया हमारी प्रदेश की सरकार को। हम बताना चाहते हैं और जो केन्द्र में सरकार है उसके ही दल के लोग यहां विधायक के रूप में बैठे हुए हैं। आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी सहयोग कीजिये और अपने दल की ओर से लिख कर दीजिये कि प्रदेश में अच्छा माहौल है और अच्छी पढ़ाई हो रही है और आप सब लोग यहां से 73 सांसद हो कर गये हैं। जिस लैपटाप को 03 साल तक झुनझुना बताते रहे, आज कह रहे हैं कि उसकी प्राथमिक शिक्षा में आवश्यकता है अभी आपने कहा, जिस लैपटाप को तीन साल आप झुनझुना बताते रहे हैं, अब कह रहे हैं प्राथमिक शिक्षा में उसकी आवश्यकता है, हम आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी की नीतियों से सहमत हैं और उनकी बातों को समझ रहे हैं, बस राजनीतिक दलों के बन्धन की वजह से आप लोग हमारा विरोध करते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आपको यह बताना चाहते हैं कि कितने नौजवानों को हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने नियुक्त किया बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने नौकरी दिया, हिन्दुस्तान में कहीं पर भी किसी सरकार ने इतने समय में किसी को नौकरी नहीं दिया। इतनी बड़ी संख्या में नौकरी देने के लिए उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री, हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री दोनों बहुत–बहुत बधाई के पात्र हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने हमें बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सिनोद कुमार शाक्य 'दीपू'–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद । मान्यवर, मैं मा0 मौर्या जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यहां पर बैठे हुए आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण बजट बेसिक शिक्षा का है। मान्यवर, मेरा भी मानना है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण बजट है जिससे उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा तय होगी तो वह प्राथमिक शिक्षा का बजट है, जैसा कि मा0 मंत्री जी ने कहा, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को बताना चाहता हूं, शायद उनके पास इस बात की जानकारी रही होगी कि स्कूलों के अन्दर छठे, सातवें, आठवें के बच्चे को सही से गिनती लिखना नहीं आता, पहाड़ा लिखना नहीं आता, शायद यह जानकारी उनके पास है, मेरे पास तो पक्का जानकारी है मान्यवर, मैं आपको इससे आगे की बात बताता हूं, आज उत्तर प्रदेश के अन्दर परीक्षाएं चल रही हैं, उन परीक्षाओं में प्राथमिक शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है, हमारे यहां पर एक जगह ड्यूटी लगाई गई, उस ड्यूटी पर इतना लिखवाया जाता है कि यहां पर आपके परिवार का कोई सदस्य परीक्षा तो नहीं दे रहा है, उसमें पॉच में से दो टीचरों ने इतना नहीं लिख पाया, उन शब्दों को गलत लिखने का काम किया मान्यवर, ये उत्तर प्रदेश के बच्चों को पढ़ाने का काम क्या करेंगे। मान्यवर मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश की शिक्षा को सुधारने के लिए यह सदन प्रतिबद्ध है और इस सदन के सारे लोग यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा सुधरे तो मान्यवर इस सदन के माध्यम से मेरा यह सुझाव है कि एक कानून पारित होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जितने शिक्षा विभाग के टीचर हैं, जितने कर्मचारी हैं, जितने अधिकारी हैं, इन सब के बच्चों को इन स्कूलों में

पढ़ाना अनिवार्य रूप से कर दिया जाय मान्यवर तो सौ प्रतिशत इस स्कूल की शिक्षा बेहतर हो जायेगी। मान्यवर, इस सदन में बैठे हुए सारे सदस्य, सारे कर्मचारी, दर्शकदीर्घा में बैठे अधिकारी, ऐसी क्या बात है मान्यवर जो उन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। अगर इस सदन के माध्यम से मा0 मंत्री जी यह बात कहते हैं कि इस सदन में मान्यवर कि उस शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी है तो ऐसी कौन सी बात है मान्यवर, इनके किसी परिवारों के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ने नहीं जाते हैं, अगर ऐसा एक दिन हो जायेगा, इस बात की अनिवार्यता हो जायेगी, तो यकीन मानिये, वह मॉडल स्कूलों से अच्छे स्कूल हो जायेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, इस सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि मान्यवर यह बजट बहुत महत्वपूर्ण है, इस बजट में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, इस बात का इस सदन से कानून पारित होना चाहिए ताकि अधिकारी, कर्मचारी एवं नेताओं के बच्चे उन प्राथमिक विद्यालयों से पढ़ कर निकलें, उनकी प्राथमिक शिक्षा उन विद्यालयों में हो तो उत्तर प्रदेश तरक्की और प्रगति के रास्ते पर जायेगा। मान्यवर, आपने बड़े महत्वपूर्ण बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं ।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा, जानदार, शानदार और वजनदार उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के बजट पर....

श्री अध्यक्ष–

उतना ही वजनदार आपका भाषण भी है।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी–

यह तो आपकी कृपा है श्रीमन्, मा0 मैं कटमोशन बड़े ध्यान से सुन रहा था, उस पर कुछ तो रोशनी आनी चाहिए सदन में। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें मौका दिया। श्रीमन्, मा0 मंत्री जी के द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हूं। बहुजन समाज पार्टी के हमारे साथी ने इस सदन में बस बजट पर जो कट मोशन रखा तो उससे लगता था कि ये पूरी तैयारी करके और बजट की जानकारी करके नहीं आये। आप पिछली सरकार की बात कर रहे थे कि हम शिक्षकों की भर्ती कर रहे थे, मिड–डे–मील दे रहे थे, उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे थे, प्राथमिक शिक्षा को आगे ले जा रहे थे। मान्यवर, मुझे उस पर एक बात याद आती है कि उस जमाने में मैंने इसी सदन में एक सवाल उपस्थित किया था और मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जवाब आ रहा था। मैंने अनुपूरक प्रश्न किया और यह पूछा था कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम और अकलियत के बच्चों के लिये प्राइमरी स्कूलों में टीचर की व्यवस्था आपकी सरकार कब करेगी ? मान्यवर, ये निरुत्तर हो गये, जवाब नहीं दे पाये इसी सदन में। आज जब यह सरकार गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम और अकलियत के बच्चों के लिये, उनकी तरक्की, फला–ए–बहबूद के लिये एक अच्छा बजट प्रस्तुत करके, शिक्षा का एक माहौल बना करके प्रदेश को आगे बढ़ा रही है तो उसकी आलोचना की जा रही है। मुझे तो यह लगता है कि उस जमाने में मैंने कहा था कि महसूस ये होता था कि ये दौर–ए–तबाही है उस सरकार में कि

महसूस ये होता है कि ये दौर–ए–तबाही थी।
शीशे की अदालत में, पत्थर की गवाही थी।।

मान्यवर, मान्यता की बात की जा रही है। बी0टी0सी0 की मान्यता जब दी जाने लगी तो कैसे दी जाने लगी। मान्यवर, उच्च न्यायालय का आदेश आया और उस पर उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कालेजों को बी0टी0सी0 की मान्यता जारी करने के लिये कहा गया। बार–बार कण्टेम्ट हुआ तब वह जारी हुआ और जब वह पत्रावली बन करके निदेशक महोदय के वहां से शासन आती थी तो मात्र एक चिड़िया बैठाने के लिये प्रशासनिक विभाग जब भेजता था तो वह दस्तखत करने के लिये उसकी कितनी कीमत लगायी जाती थी, मैं उस पर इस सदन में ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता। मान्यवर, उस समय ऐसी ऐसी बातें थीं कि जो शिक्षकों के ट्रांसफर हो रहे थे उस सरकार में वे कैसे हो रहे थे। जो जिलों में बी0एस0ए0 बनाये जा रहे थे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त किये जा रहे थे तो मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बगैर सुविधा शुल्क दिये, बगैर भारी रकम चुकाये मनमाने जिले में पोस्टिंग नहीं हो रही थी। आज जब इस सरकार में नेता सदन मा0 मुख्य मंत्री जी ने, समाजवादी सरकार की मंत्रि परिषद् ने, योग्य और बहादुर मंत्री और उनके साथी मंत्रियों को उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है तो आईना दिखाने का काम किया जा रहा है। आज इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ। आप केवल ऑन लाइन एप्लीकेशन दे दीजिये, ऑन लाइन एप्लीकेशन दे दीजिये, च्वाइस लिख दीजिये और आपको पता चल जायेगा कि हमारा ट्रांसफर हो गया। मान्यवर, कोई सुविधा शुल्क नहीं, बी0टी0सी0 प्राइवेट कालेजों की मान्यता में कोई पैसा नहीं। इसके अलावा, जितने भी उर्दू मुअल्लिम के अध्यापक रखे गये उसमें एक रुपया किसी से नहीं लिया गया। मान्यवर, आज भी जितने शिक्षक रखे जा रहे हैं तो अपने बहादुर मंत्री जी की तारीफ करूंगा श्री राम गोविन्द चौधरी जी की। आप हम लोगों के नेता हैं, आदर्श हैं। मैं इनकी बहादुरी की तारीफ करूंगा कि पूरे विभाग में न पोस्टिंग में पैसा, न ट्रांसफर में पैसा, न मिड डे मील में कमीशन और सारी व्यवस्था अच्छी चल रही है। मान्यवर, यह जो बजट है उत्तर प्रदेश के उन गरीबों, मजलूमों और किसानों के बेटे जो गांव से निकलकर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके लिये यह लाया गया है। इससे उत्तर प्रदेश की बेहतरी, फला–ए–बहबूद और तरक्की होगी। मा0 अध्यक्ष जी, हमारी बात मा0 सदस्यों को बहुत अच्छी लगी इसलिये हमारी तारीफ कर रहे हैं। एक बार फिर हम अपने मंत्री द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करते हुये आपका शुक्रिया अदा करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

हम ये सदन को बता दें कि इस पर 5 बजे मतदान होगा इसलिये कम समय में अधिक से अधिक लोग बोल लीजिये।

'श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मेरे केवल दो सुझाव हैं, जो मैं इसमें रखना चाहती हूं। आज यह बात माननीय मंत्री जी ने कही और मैं बिल्कुल इस बात से अपने आपको सम्बद्ध करती हूं कि बेसिक शिक्षा, हमारी शिक्षा प्रणाली की नींव है और अगर यह नींव नहीं मजबूत रहेगी तो हम आने वाले भविष्य में जो बच्चे पढ़ कर निकल रहे हैं, हम उनको मजबूत नहीं बना पायेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत आज वहां के इन्फ्रास्ट्रेकचर की है। माननीय मंत्री जी, इस बात के लिए चिंतित हैं और उन्होंने अपने बजट में इसके लिए प्राविधान भी रखा है। फर्नीचर को लेकर उन्होंने बताया कि नये फर्नीचर आएंगे और सारी सुविधाएं भी प्राइमरी स्कूलों को दी जाएंगी। आज जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या जो बच्चों के सामने आ रही है कि इस आधुनिक युग में, कम्पेटिव युग में, जब ये प्राइमरी स्कूल के बच्चे पढ़कर बाहर निकलते हैं, उनके सामने जो कम्प्यूटर एजूकेशन का अभाव है, वह एक सबसे बड़ी दिक्कत का सामना आज ये बच्चे कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि कम्प्यूटराइजेशन इन स्कूलों में होना चाहिए, पर कम्प्यूटराइजेशन कैसे होगा, जब बिजली नहीं होगी। बिजली की एक सबसे बड़ी समस्या है। आज पूरा प्रदेश बिजली के अभाव से जूझ रहा है, हम सब लोग इस बात पर कई बार इस सदन में भी चर्चा कर चुके हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी को हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने समय–समय पर इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है और नई–नई परियोजनाएं भी ला रहे हैं। कुछ सुधार हुआ है बिजली में और कुछ आगे होगा, इसकी हम सब उम्मीद करते हैं। मेरा सुझाव है कि जो सौर ऊर्जा है इससे यदि हम अपने स्कूलों में बिजली की व्यवस्था कर दें तो सोलर पैनल लगा दें तो सोलर पैनल से कम्प्यूटर भी चल सकते हैं। आज अगर सबसे बड़ी चीज है, हम शुद्ध पानी के लिए हैण्डपम्प दे देते हैं। माननीय मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने केन्द्र सरकार से हैण्डपम्प की डिमाण्ड की है। अगर उस हैण्डपम्प को भी हम सोलर पैनल से जोड़ देते हैं, जो सोलर पम्प आप लोगों ने ऑलरेडी अपने बजट में ले रखा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सोलर पैनल पर बहुत सारा बजट दिया है और काम भी कर रहे हैं। अगर वह पम्प भी सोलर पैनल से जोड़ दिये जाएं तो उससे पानी की व्यवस्था भी हो जायेगी। इसके अलावा जो टायलेट्स हैं, जिसकी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पानी नहीं होता है, तो उससे वह भी आच्छादित हो जाएंगे। तो यह मेरा एक छोटा सा सुझाव है। दूसरा माननीय मंत्री जी से मैं इतना ही कहना चाहती हूं, पीठ के माध्यम से कि कई सारी दिक्कतें आज शिक्षकों के अभाव की वजह से इन स्कूलों में आ रही हैं। आज यह शिक्षक जो नहीं हैं, अलग–अलग काम उनको दे दिये गए हैं, कुछ विद्यालय बनवा रहे हैं। कुछ अलग–अलग चीजें उनको दे रखी हैं, तो अगर शिक्षकों को केवल शिक्षा के कार्य में ही रखें तो वह बेहतर होगा और हमारा जो एक पूरा माहौल है, बेसिक शिक्षा का इसमें हम सुधार ला सकें। इसमें नई–नई चीजें ला सकें, यही हम सब उम्मीद कर सकते हैं कि इस बजट में इसको हम जोड़ सकते हैं।

श्री रोशन लाल वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, केवल एक मिनट में अपनी बात रखना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, केवल सुझाव देना है।

श्री अध्यक्ष–

अभी आपको बुलवा देंगे, क्यों परेशान हैं? अभी बोल लीजिएगा।

'श्री सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मानवता का बोध और मनुष्यता की महत्वाकांक्षा जगाये बिना किसी भी समाज में आर्थिक क्रांति लाना असंभव–सा है। एक अवरूद्ध और गतिहीन अर्थव्यवस्था में द्रुतगति लाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वांछनीय है, जिसकी कड़ी यह प्राथमिक शिक्षा है। माननीय हमारा शिक्षा मंत्री जी ने जिस ढंग का सराहनीय कदम उठाया है कि लगभग तीन लाख अध्यापकों की भर्ती कर दी है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और शिक्षा की कमी की वजह अध्यापकों का न होना था, जिसको इन्होंने भर्ती कर दिया, इसके लिए इनको मुबारकबाद प्रस्तुत करता हूं (मेजों की थपथपाहट)। साथ–ही–साथ अतिरिक्त कक्षों की व्यवस्था, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, ये तमाम जितनी भी सुविधा की चीजें होनी चाहिए, उन सबको आपने मुहैया कराया है। हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो चीजें विस्मृत कर दी गई थीं और जो केवल रहस्यवादी भूल–भुलैया में विचरण करती थी, उसको आपने यथार्थ की धरती पर लाया है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद।

आपने इस शिक्षा जगत को अपनी मेधाशक्ति से अलग अगोचर कन्दराओं से उतारकर वास्तविक धरती पर प्रवाहित किया है और आप निश्चितममेव शिक्षा जगत के प्रयोगवाद के जनक बन गये हैं मैं आपकी पुनः बहुत भूरि–भूरि प्रशंसा करते हुए आपकी तारीफ करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

'श्री पूरन प्रकाश–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि प्रदेश के इतने महत्वपूर्ण शिक्षा के बजट पर हमको कटमोशन रखने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, अगर हमारी नीव मजबूत है तो 100 मंजिल खड़ी कर लीजिएगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिल्डिंग को लेकिन अगर हमारी नीव कमजोर है तो बिल्डिंग एक मंजिल भी नहीं चल पायेगी। आज हमारे प्रदेश के अन्दर साढ़े तीन खरब बेसिक शिक्षा पर हमारे माननीय मंत्री जी ने बजट रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, हालात यह है कि आप ग्रामीण अंचल में देखें। माननीय मंत्री जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बहुत विस्तार से रखी हैं लेकिन वहां चलकर देखा जाये तो वास्तविक धरातल पर कही कुछ नहीं है। मान्यवर, क्या कारण है कि ग्रामीण अंचल में हमारे स्कूल, चूंकि माननीय मंत्री जी ने हमारे स्कूल का हवाला दिया है वहां पर आप देखेंगे, वहां पर 100 बच्चे हैं और बराबर में एक स्कूल बनता है प्राइमरी स्कूल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनता है उसमें 400 बच्चे हैं जबकि हम वहां पर अपने यहां खाना भी दे रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं किताबे भी दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, कही न कहीं व्यवस्था में कमी है। माननीय अध्यक्ष जी इतना ही नहीं आगे शौचालय की बात कही, हैण्डपम्प की बात कही माननीय मंत्री जी ने। माननीय मंत्री जी, जब पानी खारा है जिस एरिया में, पानी कडुवा है, पक्षी पीकर मर जाता है तो वहां पर कौन सा हैण्डपम्प सक्सेज होगा। माननीय मंत्री जी, मैं तो सुझाव के रूप में 4–6 बाते रखना चाहता हूं। अभी आप आये कहे कि 3 लाख शिक्षक भर गये, मान्यवर, बीसों लाख शिक्षक है प्रदेश में और उन बीसों लाख शिक्षक के अनुपात में देखा जाये तो बच्चों की संख्या नगण्य है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, माननीय सदस्यगण बैठे हैं, अधिकारीगण बैठे हैं मान्यवर, 10 परसेन्ट भी अगर हमारे परिवार के बच्चे हमारे भाई है, चाचा हैं, हमारे परिवार के बच्चे 10 परसेन्ट भी हमारी प्राइमारी पाठशालाओं में पढ़ रहे होते तो आज यह स्थिति नहीं आती कि बच्चे नहीं है, मान्यवर, हम नहीं भेजते हैं। मान्यवर, हम कहें कुछ भी बड़ी बड़ी बाते कहें लेकिन हमारे मंत्री जी बैठे हैं, राज्य मंत्री जी बैठे हैं आप भी अपने परिवार पर हम भी अपने परिवार पर निगाह डाले तो हमारे बच्चे भी वहां पर नहीं जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है, क्या कारण है, माननीय मंत्री जी आपको देखना पड़ेगा। इतना ही नहीं अभी हमारे मंत्री जी ने कहा था माननीय अध्यक्ष जी, भोजन की व्यवस्था परसों एक अच्छे विकल्प की शुरूआत हुई, अक्षयपात्र अच्छा है हम मानते हैं हमारी मथुरा की संस्था है वृन्दावन में।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी खाने की बात आ रही थी अभी आपके रिकार्ड में है मथुरा का रिकार्ड आप मंगा लें जो बच्चों को खाना दिया गया था वह बासी खाना था बच्चों को तो दूर जब वह फेका गया था तो 4 बकरी और 2 गाय मर गयी थीं उस खाना को खाने के बाद यह रिकार्ड है। अभी मैंने प्रश्न भी डाला था माननीय मंत्री जी आपने अपने जनपद की बात कही कि 33 प्रतिशत बच्चे बढ़े हैं आखिर क्या कारण है कि आपके यहां 33 प्रतिशत बढ़ रहे हैं और हमारे यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 33 प्रतिशत कम हो रहे हैं तो कही न कहीं कोई कमीं है यह देखने का काम सरकार का है यह हमारा काम नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हमें देखना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिक शिक्षा का इतना बजट अगर खर्च हो रहा है तो वास्तव में वह उस पर्सन तक पहुंचे उस नीव तक पहुंचे जो अभी तैयार हो रही है। आखिर क्या कारण है कि हमारे स्कूल के बच्चे जो आते हैं वह कम्पटीशन में नहीं आ पाते हैं वहीं बच्चे दूसरे प्राइमरी स्कूल में पढ़कर आई0ए0एस0 आई0पी0एस0 में और दूसरी नौकरियों में आ रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने शिक्षकों की बात कहीं, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके शिक्षक 20 लाख हैं और इन शिक्षकों के परिवार अपने बच्चों को आपके विद्यालयों में भेज दें तो बच्चों की संख्या बहुत बढ़ जायेगी। वैसे आपकी मर्जी है, आप मंत्री हैं। अभी मैं माननीय मंत्री जी को एक और सुझाव देना चाहूंगा कि जो आपके ग्रामीण अंचल के विद्यालय हैं उनमें अभी भी आपके शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं। आप माने न माने आपने बहुत भर्ती भी कर ली है, लेकिन आपको मैं सुझाव दे रहा हूं कि हम गये थे और हमारे साथ आपके बी0डी0ओ0 भी थे, हमने वहां पर देखा था कि रजिस्टर के नीचे हेडमास्टर की एप्लीकेशन आगे की तारीख की पड़ी मिली थी कि साहब मैं आज छुट्टी पर जा रहा

हूं। मैं मानता हूं कि इसमें आप जो कण्ट्रोल कर रहे हैं, वह बहुत अच्छी बात है आपने सुधार लाये हैं, लेकिन इसमें अभी और सुधार की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप नींव में सुधार नहीं करेंगे, तब तक मूल सुधार नहीं हो पायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक और चीज जो आ रही है अभी आपने कहा था कि शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं हो रहे हैं, आपने शिक्षकों के स्थानान्तरण बंद कर रखे हैं लेकिन बी0एस0ए0 के माध्यम से मेज के नीचे से थैली दे दीजियेगा और काम हो जायेगा। ऊपर से एप्लीकेशन जायेगी, यहीं पर रह जायेगी और कहा जायेगा कि मई में होगा। 18 स्थानान्तरण अलीगढ़ में हुये हैं, आप रिकार्ड निकलवा लीजियेगा, नहीं तो रिकार्ड मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। 18 तो अलीगढ़ में हुये, मथुरा में अलग हुये। हमारा सुझाव देने का काम है, आप मानो न मानो, आप सरकार में हैं, सत्ता में है, लेकिन मेरा काम सुझाव देना है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्रीमती इन्द्राणी देवी–

माननीय अध्यक्ष जी, बेसिक शिक्षा विभाग के बजट के समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये हम आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देते हैं और बताना चाहते हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की जो सोच, विचार और सपना है वह शिक्षा विभाग के बजट में हमें देखने को, सुनने को और हमारे क्षेत्र में लागू होने को देखने का जो मौका मिला। आज समाजवादी पार्टी के युवा नौजवान मुख्य मंत्री और हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री और उनके सहयोगी माननीय मंत्रीगणों के द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है, उस बजट के समर्थन में जो अवसर मिला इसके लिये आपको मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा क्षेत्र हमारा जनपद श्रावस्ती नेपाल बार्डर की सीमा से आता है और वहां से मैं एम0एल0ए0 चुनकर आती हूं। हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो योजनायें चलाई जा रही है, बहुत अच्छी योजनायें हैं। आज हम लोग गांव में जाते हैं और वहां के अध्यापक और जो अधिकारी और जो गांव के गरीब नेपाल बार्डर अंचल जिसे तराई एरिया कहा जाता है, वहां के बच्चे विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय के बच्चे और उनके गार्जियन (मां–बाप) भी आज हमारे युवा मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी को और युवा मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिये देते हैं कि क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी ने शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी पाते–पाते हमारे गरीब अंचलों के बच्चों को ड्रेस और अच्छा खाना देने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, पूर्ववर्ती सरकार बसपा की थी तब उन सरकारों में हम लोग देखते थे और सुनते थे कि न तो बच्चों को अच्छा ड्रेस पढ़ने के लिये दिया जाता था और न खाना खाने की अच्छी व्यवस्था थी । आज मैं अध्यक्ष जी को और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अच्छा खाना और अच्छे रसोइयों का इंतजाम किया है, इसके अलावा हमारे माननीय मंत्री जी ने एक और अच्छा काम किया है, शिक्षा विभाग में आनलाइन नौकरियों का विज्ञापन देने का, शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त करने का । अभी हमारे विपक्ष की माननीय सदस्या बिजली के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बारे में बता रही थी, मैं उनको बताना चाहती हूं कि बिजली की व्यवस्था हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी हमारे विद्यालयों के लिये पहले ही कर दिये थे और आज सभी विद्यालयों का विद्युतीकरण हो गया है। विशेषकर हमारे जनपद श्रावस्ती में बिजली की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहती हूं कि आप बड़े फर्क से जनपद श्रावस्ती को घूम लीजिये, वहां 24 घन्टे बिजली की व्यवस्था चल रही है। चाहे शहर के लोग हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, सभी के लिये 24 घन्टे बिजली की आज इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे माननीय राज्य मंत्री जी के द्वारा और माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा की गयी है। हमारा जिला नेपाल बार्डर से मिला हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्रीमती इन्द्राणी देवी–

माननीय अध्यक्ष जी, आज विद्यालयों में इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, आज शिक्षक 10 बजे विद्यालय जाते हैं और 4 बजे वह आने का काम करते हैं। हमारी सरकार ने बहुत ईमानदारी से, बहुत निष्पक्षता से चाहे वह विपक्ष के माननीय सदस्य हों, चाहे हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों, सबका काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी केवल सरकार ही नहीं चला रहे हैं बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो उन्हें भरोसा दिया है 2012 में, उसको देखते हुये आम समाज को लेकर, गरीब, मजलूम, नौजवानों, महिलाओं को लेकर आज पूरी ईमानदारी दिखा रहे हैं, इसके लिये अध्यक्ष जी मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें। अब आपका समय हो गया।

श्रीमती इन्द्राणी देवी–

अध्यक्ष जी, मैं एक किसान परिवार से आती हूं और हम अपने क्षेत्र में बेहतर शिक्षा व्यवस्था देखते हैं। चाहे हमारे राज्य मंत्री जी गोंडा के योगेश प्रताप जी हों, चाहे पंडित सिंह जी हों, हम लोग जब उनसे बात करते हैं तो तत्काल काम होता है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्रीमती इन्द्राणी देवी–

मैं विपक्ष के सदस्यों को बताना चाहती हूं कि बहुत सी सरकारें आई, आप कहते हैं कि बी0एस0ए0, बी0आर0सी0 नेता बने हैं, हमारी सरकार में यह नेता नहीं बने हैं, बल्कि यह काम करने का वायदा किये हैं, नेता तो आपकी पार्टी के विपक्ष के लोगों ने बनाया, हमारे जो युवा मुख्य मंत्री जी हैं, वह इंजीनियर हैं। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के जो मिनिस्टर बने थे, वह टीचर थे, उन लोगों ने सारी व्यवस्था खराब की है। हमारे नौजवान युवा मुख्य मंत्री जी सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर रहे हैं। आपने हमें बजट के

समर्थन मे बोलने का मौका दिया, उसके लिये हम आपका आभार व्यक्त करते हुये अपनी बात समाप्त करते हैं।

श्री अगयश राम सरन वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बेसिक शिक्षा आय–व्ययक 2015–2016 पर हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं और आपका कोटि–कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मैं मा0 नीरज मौर्या द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का भी पुरजोर समर्थन करता हूं। मान्यवर, प्राइमरी शिक्षा पद्धति गुरुकुल प्रणाली में निहित रही है और इस प्रकार से कालान्तर में मन्दिरों, मठों, आश्रमों तथा मस्जिदों में शिक्षा का विकास उन्नयन हुआ करता था जिसका स्वरूप आज भी देखने को मिलता है। मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से व्यापक स्तर से प्राचीन शिक्षा पद्धति अब भी जीवित है। मान्यवर, 1858 में केन्द्र सरकार के अधीन एक म्योर सेन्टर कॉलेज इलाहाबाद में स्थापित किया गया था जिसमें कि प्राइमरी शिक्षा से ले करके विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था थी लेकिन 1917 में सिलेन्डर कमीशन की अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को पृथक कर दिया गया और बाकी शिक्षा व्यवस्था को अलग कर दिया गया। मान्यवर, भारत के संविधान के अनुच्छेद–45 में स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है कि 14 वर्ष के बालक–बालिकाओं के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा 10 वर्षों के अन्दर कर देंगे, यह प्रतिबद्धता भारत के संविधान जो 1950 में लागू हुआ उसमें की गई है। अगर इसमें 10 वर्ष जोड़ दिये जाएं तो 1960 तक शिक्षा व्यवस्था अनिवार्य एवं निःशुल्क हो जानी चाहिए थी। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था है वह सर्वव्यापी होनी चाहिए, सर्वस्पर्शी होनी चाहिए एवं सर्वग्राही होनी चाहिए। लेकिन आज जो हमारे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में 1 लाख 13 हजार 627 प्राइमरी विद्यालय हैं, जिसमें कि 2.61 करोड़ छात्र हैं, इसी प्रकार से 45 हजार 749 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें 92.15 लाख बालक–बालिकाएं शिक्षार्थी हैं। इनमें जो पद सृजित हैं, प्राइमरी स्कूलों में 4 लाख 22 हजार 127, जूनियर हाईस्कूल में 1 लाख 61 हजार 597 पद सृजित हैं लेकिन इनके विरुद्ध प्राथमिक विद्यालयों में केवल 2 लाख 66 हजार 1 और जूनियर हाईस्कूलों में 1 लाख 6 हजार 89 शिक्षकों की नियुक्ति है। इसी प्रकार से मैं अपने जनपद के बारे में बताना चाहूंगा, हमारे जनपद पीलीभीत में 1230 प्राथमिक विद्यालय हैं और 570 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इसी प्रकार से मैं अपने जनपद के बारे में बताना चाहूंगा, हमारे जनपद पीलीभीत में 1230 प्राथमिक विद्यालय हैं और 570 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप 1818 से शुरू किये हैं तो जनपद कहां आ पायेगा। अभी 5 बजे मतदान कराना है, अब आप माध्यमिक शिक्षा पर बोल लीजिएगा।

श्री अगयश रामसरन वर्मा–

इसी प्रकार से मैं अपने जनपद के बारे में बताना चाहूंगा, हमारे जनपद पीलीभीत में 1230 प्राथमिक विद्यालयों में 558 हेड मास्टर, 1390 सहायक अध्यापक हैं और 570 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर हाई स्कूलों में 356 हेडमास्टर और 901 सहायक अध्यापक हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारे यहां लगभग डेढ़ सौ प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आपका टाइम समाप्त हो गया, अपने क्षेत्र की बात तो पहले बताये नहीं। मा0 मुन्ना जी आप बोलिये।

(सदस्य श्री अगयश राम सरन वर्मा के लगातार बोलते रहने एवं सदस्य श्री सत्यवीर मुन्ना के भी लगातार बोलते रहने पर)

श्री सत्यवीर मुन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपने विद्वान प्राथमिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आप इन्हें शान्त करा दीजिए, इनका पढ़ा हुआ मान लिया जाएं।

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं मानते हैं तो आप बोलते रहिये नहीं तो हम किसी दूसरे का नाम पुकारते हैं।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

मान्यवर, आज प्राथमिक शिक्षा के विषय में पूरा सदन चिन्तित है और पक्ष और विपक्ष से तमाम विचार आये लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा अपने माननीय मंत्री जी को।

(श्री अगयश राम सरन वर्मा के बोलते रहने व उनका माइक बंद होने के कारण कुछ नहीं दे रहा था।)

श्री अध्यक्ष–

मुन्ना जी, आप बोलिये वह नहीं मानेंगे। वर्मा जी, आपका टाइम खत्म हो गया है, अब बैठ जाईये।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह सराहनीय है और विपक्ष द्वारा प्राथमिक शिक्षा को लेकर जो चिंता व्यक्त की गयी है उस पर मैं यह कहना चाहूंगा कि एक अंग्रेजी में कहावत है, उसका हिन्दी अनुवाद भी कर दूंगा। ''कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज बेस्ट एड़वरटाइजमेंट'' अर्थात उपभोक्ता की संतुष्टि ही सर्वोत्तम प्रचार है। यह जो एक कांसेप्ट है, एक संकल्पना है, इसको प्राथमिक शिक्षा में अपनाने की आवश्यकता है। हम तमाम माननीय सदस्य यह चिंता व्यक्त करते हैं कि हमारे भी बच्चे पढ़ने चाहिए, मा0 मंत्रियों के भी बच्चे पढ़ने चाहिए। लेकिन अगर अपने अंदर झांक करके देखें तो शायद इक्का–दुक्का, हमारे बगल में माननीय विधायक जी बैठे हैं, बताने लगे कि मेरे बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़े उसी से वह बढ़े और आज इंजीनियर हो गये। इसके लिए

बधाई के पात्र हैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी। जिस तरह के नये–नये संशोधन वह विभाग में ला रहे हैं इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, मध्याह्न भोजन के माध्यम से...

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिये, पांच बजे इस पर मतदान कराना है।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

अध्यक्ष जी, अभी तो शुरू किया है।

श्री अध्यक्ष–

अभी माध्यमिक शिक्षा है, उस पर बोल लीजिएगा।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, हाथ जोड़कर आपसे आग्रह है। मध्याह्न भोजन के माध्यम से ढ़ाई करोड़ से अधिक बच्चों को भोजन दिया जा रहा है। इसी की कड़ी में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा ''अक्षय पात्र'' संस्था के माध्यम से लखनऊ में यह योजना शुरू की गयी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि इलाहाबाद जैसे ऐतिहासिक शहर में भी अक्षय पात्र संस्था द्वारा मध्याह्न भोजन की योजना शुरू की जाएं। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालय में नामांकन जो 01 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है यह भी एक सराहनीय कदम है। अन्य जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी तुलना में हमें और बेहतर करना होगा।

श्री अध्यक्ष–

अब आप खत्म करिये।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कुछ विद्यालयों में हैण्डपम्प रि–बोर की आवश्यकता है, पेयजल की समस्या है, इस ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हमारे सोरांव विधान सभा में कुछ विद्यालयों में चहारदीवारी की कमी है, इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। साथ ही चौकीदारों की भी प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति की जाएं, इसके लिए भी आग्रह करना चाहूंगा। हमारे सोरॉव विधान सभा के अन्तर्गत पड़रैया एक गांव है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिये, मंत्री जी से मिलकर कह लीजिएगा।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

वहां पर विद्यालय के ऊपर हाईटेंशन लाइन गयी हुई है माननीय मंत्री जी उसका संज्ञान ले लें।

श्री अध्यक्ष–

अब माध्यमिक शिक्षा में बोलना, अब आप बैठ जाईये। श्री रोशन लाल वर्मा जी एक मिनट में अपनी बात रख लीजिए। मुन्ना जी, अब बैठ जाईये, इसीलिए आपको टाइम नहीं मिलता है, जब कह दिया जाएं तो बैठ जाईये।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

अन्त में मैं बहुत ही अच्छी स्थानान्तरण नीति के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इसी के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री रोशन लाल वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे मा0 नीरज मौर्या द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बल देने का मौका दिया मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत छोटे–छोटे दो सुझाव देना चाहता हूं कि..

श्री अम्बिका चौधरी–

अध्यक्ष जी, आपने इनको 01 मिनट का समय दिया था वह एक मिनट हो गया।

श्री अध्यक्ष–

जो भी सुझाव हैं वह आप जल्दी दे दीजिए।।

श्री रोशन लाल वर्मा–

हम यहां पर 403 सदस्य चुनकर आते हैं और जो चीज हमारे 403 सदस्यों को पसन्द नहीं है वह हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में जो बच्चों को ड्रेस दी जाती है जो बच्चों को ड्रेस दिया जाता है उसका कलर खाकी किया गया है जो पुलिस की वर्दी में है । अध्यक्ष जी उसकी क्वालिटी भी बहुत खराब है मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस खाकी वर्दी का कलर चेंज कर दीजिए जिससे बच्चे उसको मन से पहन सकें।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाएं।

श्री रोशन लाल वर्मा–

यहां पर 403 विधायक हैं कोई भी खाकी का कलर पहनकर नहीं आते हैं। इसलिए कलर चेंज करवा दीजिए। अध्यक्ष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री कुंवर कौशल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि बजट हर साल बढ़ रहा है अध्यापक बढ़ रहे हैं बच्चे घट रहे हैं तो बच्चों को

कैसे बढ़ाया जाय मेरा सुझाव है मंत्री जी से कि जो भी मास्टर भर्ती हुए हैं जो भी शिक्षा मित्र नए हुए हैं इनको एक ब्लाक से 70 कि0मी0 या 100 कि0मी0 की दूरी पर रखा गया है अगर इन शिक्षा मित्रों को निर्देशित किया जाएं कि आप अपने ग्राम सभा के नजदीक आना चाहते हैं तो हर स्कूल में कम से कम 50 बच्चों का एडमीशन करवाएं जिससे लड़कों का एडमीशन भी हो।

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी बात समाप्त। अब श्री नीरज मौर्य जी अपनी बात रखें।

श्री कुंवर कौशल सिंह–

अध्यक्ष जी जो कुर्सी मेज बननी है मेरी सिफारिश है मंत्री जी से जैसे बिल्डिंग बनाने में मास्टर कहते हैं कि सरकार ने हमको बोझा दे दिया है इस तरह का कुर्सी मेज बनाने का बोझा मास्टरों को न दिया जाएं। यह मेरा सुझाव है।

श्री अध्यक्ष–

कहां आप मास्टरों की वकालत कर रहे हैं।

श्री राम लाल अकेला–

माननीय अध्यक्ष जी आप एक मिनट मुझे भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

अब नहीं । अकेला जी बैठ जाएं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी मेरे द्वारा जो आज कटौती प्रस्ताव रखा गया है उसमें कई माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और दोनों तरफ के सदस्यों ने जो चर्चा की उसमें यह बात निकलकर आई कि कहीं न कहीं सारा सदन इस बात से सहमत है कि शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है उस पर सबने चिन्ता भी जताई तो जो मैंने अपनी बातें रखी हैं उन्हीं को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस तरह के जो मैंने सुझाव दिए हैं उसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो छूट गई थी कि अधिकारियों को मजबूत करने की जरूरत है और उनसे काम लिया जाएं। जैसे जिले का जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आए दिन कोर्ट कचेहरी व अन्य कामों में उलझे रहते हैं और जिले के जो अन्य उच्च अधिकारी हैं वह भी उनको अन्य कामों में लगा देते हैं मैं चाहूंगा कि बी0एस0ए0 को क्लास वन में लाकर उससे अच्छा काम लिया जाएं क्योंकि बेसिक शिक्षा का विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। मान्यवर, अभी कई सदस्यों ने यहां पर जो बातें रखीं उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं लखनऊ राजधानी है राजधानी में कल अक्षयपात्र योजना लागू हुई लेकिन राजधानी के अन्दर सुदूर गांव में शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है एक उदाहरण मेरे पास एक प्रकरण आया था मोहनलाल गंज का मोहन लाल गंज के जो ए0बी0एस0ए0 हैं वह महिलाओं को सी0सी0एल0लीव मिलती है उसके लिए भी उनसे सीधे तौर पर पैसे की मांग होती है और जो शिक्षा मित्र चयन करके अध्यापक बनाए गए हैं उनको जो एरियर मिल रहा है

खुले तौर पर उसमें पैसा लेने का काम हो रहा है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं और उस ए0बी0एस0ए0 से मैंने भी बात की थी लेकिन जो उसकी शैली थी उसको यहां कहना ठीक नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाया हूं और अंत में यह कहते हुए कि जो पूरे सदन का लब्बो–लवाब निकला है कि आज उत्तर प्रदेश के अन्दर मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा कि– बिना गुरू के चल रहे गांव–गांव स्कूल, और कागज पर ही पक रहा हर दिन मिड–डे–मील। मान्यवर, मंत्री जी सख्ती करें वरना जो आज अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं इनको किसी दिन बहुत ज्यादा अपच होगी क्योंकि माननीय मंत्री जी की इच्छा है लेकिन जैसा मैंने कहा कि उसमें सख्ती लगाने की जरूरत है और मैं अंत में यह कहते हुए कि इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सही मायने में उस दिन सुधरी हुई मानी जायेगी जिस दिन माननीय मंत्री जी के घर का बेटा, इनका पोता, इनका नाती या इनके परिवार के बच्चे उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ना शुरू कर देंगे। उसी दिन इस प्रदेश की व्यवस्था हम सुदढ़ मानेंगें। (मेजों की थपथपाहट) मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए आपका आभार प्रकट करता हूं धन्यवाद।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अध्यक्ष जी, हमने जो बजट प्रस्ताव पेश किया उस पर जो कटौती का प्रस्ताव माननीय मौर्या जी ने रखा है, उनको मिलाकर 8–9 लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये और श्रीमन् मैंने शुरू में ही कहा था कि इसमें एक ही मूल मंत्र है कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधारी जाय और शिक्षा की गुणवत्ता सुधर जाय, बेहतर हो जाय, टीचर लोग बेहतर शिक्षा देने लगें, स्कूल में उनकी हाजिरी सौ प्रतिशत सुनिश्चित होने लगे तो निश्चित रूप से अभिभावक जो अपना पैसा खर्च करके दूसरे विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वह प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिये विवश होंगें। इसके लिये मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं कि मैंने जब से इस विभाग का चार्ज लिया है, हम हो हमारे राज्य मंत्री हो, ईमानदारी से हम लोग इसमें सुधार की दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिये श्रीमन्, हमने बी0एस0ए0 से खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वय, ए0बी0आर0सी0 सभी लोगों को निर्देश दिया गया है कि आप लोग दो–दो विद्यालय को गोद लेकर आदर्श विद्यालय के रूप में उसको विकसित करेंगें इससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और प्रदेश भर में 7 हजार विद्यालय चयनित हुए हैं। दूसरा जो आपने कहा कि मास्टर नहीं हैं, अब हम क्या कहें। नेता विरोधी दल नहीं हैं, वह आपके ही भर्ती किये हुए हैं। हमारे भर्ती किये हुए मास्टर नहीं हैं। हमने जो मास्टर भर्ती किये हैं गुरूजनों की, उनसे जो सवाल पूछेंगें वह जवाब देंगें। (मेजों की थपथपाहट) फिर भी सारी जिम्मेदारी सबकी है। और इसके लिये मैंने सदन का सहयोग चाहा है और सदन में सहयोग भी दिया है उसमें सुधार करने के लिये। कक्षा 1 से श्रीमन्, पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में दो विद्यालयों में इंगलिश मीडियम से पढ़ाई करने की व्यवस्था श्रीमन्, अगले सत्र से होगी। (मेजों की थपथपाहट)कक्षा 1 से जो आप कह रहे हैं।

'श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय मंत्री जी ने इस बात के लिये वो किया माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे साथी ने एक बात कही। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में वर्षों से यह सवाल होता रहा है हाउस में और तीन साल में मान्यवर, माननीय मंत्री जी की नीयत अच्छी हो सकती है, इनकी इच्छा शक्ति अच्छी हो सकती है लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है ? मान्यवर, धरातल पर एक बी0एस0ए0 एक जनपद पर, अब सुन लीजिये। माननीय मंत्री जी ने अनुमति दे दी है मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

इतना बोलने के लिये नहीं दी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

एक जनपद में मान्यवर, बेसिक शिक्षा अधिकारी सबसे ज्यादा पैसा ड्रा करने वाला अधिकारी है और किस स्तर का अधिकारी है क्लास–टू। क्लास वन भी नहीं है। नम्बर दो मान्यवर, आज की तारीख में मैंने दो बार कहा कि प्रिंसिपल साहब जो दस किलो आलू रोज अपनी मोटर साइकिल पर ले जाते हैं लाद कर आखिरकार उनको इससे मुक्ति कब मिलेगी ? वह कौन सा दिन आयेगा। तीन साल में इन्होंने एक भी निर्णय लिया होता। एक भी निर्णय ऐसा नहीं लिया जिससे यह लगता कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था गुणात्मक है। इस हाउस का एक भी मेम्बर, एक भी सदस्य अपने बच्चों को इस विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहता। उसका नाती, उसका पोता, उसका भांजा कोई नहीं पढ़ना चाहता। हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठिए। खन्ना जी बैठिए।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर)

श्री वसीम अहमद–

आपने बजट में कटौती की है।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

आप बाल दिवस को मनाओगे महिला दिवस, टीचर्स डे को मनाओगे बाल दिवस यह है आपकी देन।

श्री अध्यक्ष–

बैठिए अब। आपके कैबिनेट मंत्री जवाब दे रहे हैं।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता भारतीय जनता पार्टी, हम सोच रहे थे कि हमको कोई सुझाव देंगे। यह भाषण देने लगे मैं तो यह कह रहा हूं कि हमेशा हम लोगों को यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चिन्ता रही है कि कैसे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाएं। जहां तक आपने प्रधानमंत्री जी की बात की, केन्द्र शिक्षा विभाग ने अभी बजट पेश किया है सर्व शिक्षा अभियान में पांच हजार करोड़ की...(शोर)

कटौती मिड मील में किया है। मौर्य जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा मैं उनको बधाई देना चाहता हूं उन्होंने सुझाव भी अच्छे दिए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ड्रेस हमने दिए हैं किसको ड्रेस दिया, अनुसूचित जाति, जनजाति, बी0पी0एल0 सूची में जो लोग थे इन्हीं को ड्रेस दिया। जब से हमारी सरकार आई है मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी मुख्य मंत्री हुए हैं उन्होंने कहा कि हम दो तरह की व्यवस्था नहीं करेंगे। जितने भी लड़के क्लास में चाहे जिस जाति धर्म वर्ग के पढ़ते हों सबको हम ड्रेस देंगे। (मेजें थपथपाई गईं)

एक साथी ने कह दिया, मैं तो उस अधिकारी से पूछूंगा मेरा शुरू से दो चीजों पर ध्यान है कि शिक्षा में गुणवत्ता बढ़े और शिक्षा से भ्रष्टाचार समाप्त हो। ऐसा किसी शिक्षा मंत्री ने किया हो तो बता दें। मैंने बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक बुलाई और उनसे इस बात को कहा, कि शिक्षा से भ्रष्टाचार खत्म करना है। अगर तुम्हें लड़की की शादी करनी हो कोई घर में बीमार पड़ गया हो तुमको पैसे की आवश्यकता हो तो हम चार मंत्री हैं हम अपना चार–चार महीने की तनख्वाह तुमको देंगे, लेकिन शिक्षा विभाग में भ्रष्टचार नहीं होना चाहिए। (मेजें थपथपाई गईं)

मैंने इतिहास में पहली बार बी0एस0ए0 का सम्मेलन किया और मैंने उनसे कहा कि शिक्षा से हमको भ्रष्टाचार को खत्म करना है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमारा मंत्रिमंडल मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और इस तरह की बात अगर कोई अधिकारी करता होगा तो चाहे किसी का भी संरक्षण प्राप्त हो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाई करने में रामगोविन्द चौधरी पीछे नहीं हटेंगे। हमने भर्ती भी की, हमेशा सदन कहता रहा कि शिक्षकों की कमी है अब शिक्षकों की कमी नहीं है, अब कमी क्या है, गुरुजन पढ़ाने में मन लगायें मैं तो शिष्य रहा हूं अध्यापक नहीं हुआ हूं। जो अध्यापक होता है उसकी गुरू की पदवी होती है। बार–बार उनके सम्मेलनों में भी मैंने इस बात को कहा है कि अगर गुरू जी आप तनख्वाह लेते हैं तो केवल तनख्वाह और नौकरी नहीं है आपकी समाज के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। समाज बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। समाज में जागरूकता बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। यदि हम प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनायेंगे तो निश्चित रूप से समाज भी बढ़िया बनेगा। हम लोग हमेशा इस प्रयास में लगे रहते हैं और लगे भी हैं। हमारे अधिकारी भी हमेशा निरीक्षण पर जाते हैं। हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की दिशा में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षकों की जितनी कमी थी जब से बेसिक शिक्षा बना है और आज तक, जितनी तीन साल में भर्ती हुयी है शिक्षा विभाग के इतिहास में कभी इतनी बड़ी भर्ती नहीं हुयी है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने सबसे अधिक रोजगार बेसिक शिक्षा में दिया है। आपने कितनी भर्ती की है मैं नहीं जानता हूं। आपके पास आंकड़े हों तो बताईये कि कितनी आपने भर्ती की है ? हमनें आपको आंकड़ा बताया है। आप कटौती

प्रस्ताव कम पिछली सरकार का बजट पढ़ रहे थे। कटौती कम, सुझाव कम, आप अपनी पिछली सरकार का बजट पढ़ रहे थे। वह तो पिछला बीत गया हम अपना पढ़ रहे हैं। हमारे बजट में क्या कमी है ? हमारी व्यवस्था में क्या कमी है ? हमको क्या करना चाहिये, कौन–सा सुधार करना चाहिये, इस पर मा0 सदस्यों के सुझाव आने चाहियें। मैं इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि हमारा कोई भी मा0 सदस्य चाहे वह पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, अगर किसी भी अधिकारी को प्रमाणित तौर पर कहेगा कि यह भ्रष्टाचार में लिप्त है तो मैं कतई उसको बख्शूंगा नहीं, चाहे उसको कितने ही बड़े आदमी का संरक्षण क्यों न प्राप्त हो। मैंने तो आप सभी को पत्र भी लिखा है, दो–दो बार लिखा है, तीन–तीन बार लिखा है। सोलह जनपद में टीचरों की इतनी भर्ती हो गयी कि सोलह जनपद में आवश्यकता से अधिक टीचर हैं। गणना तो होती नहीं है इनके कमी है कमी है कहते–कहते मैंने इतनी भर्ती कर दी कि अब हो रहा है कि कहां कम हैं कहां अधिक हैं। टीचर हमनें पूरा भर्ती कर दिया और जो बाकी है वह दो–तीन महीने में पूरी हो जायेगी। अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे को पढ़ायें। हमारा बच्चा तो पढ़कर के पास हो गया है, लेकिन जब उस बच्चे का बच्चा होगा तो मैं निश्चित रूप से उसे प्राईमरी स्कूल में पढ़वाने का काम करूँगा और प्राईमरी स्कूल में ही पेड़ के नीचे और मिडिल स्कूल में जब आठ किलोमीटर दूर पढ़ने गया तो दो कमरे थे और केवल दीवार खड़ी थी। दस–दस मिलोमीटर दूर जाकर हम लोगों ने खर–पतवार, बांस काटकर उसको छाकर के पढ़ा है, मैं उस प्राईमरी स्कूल का पढ़ा हूं। पता नहीं मौर्य जी आप किस स्कूल के पढ़े हैं ? पढे हैं, धन्यवाद आपको। अराधना मिश्रा जी ने कम्प्यूटर की बात कही। इस पर भी कम्प्यूटर कुछ स्कूलों में हैं और अगर बजट में इसकी व्यवस्था हो सकती है तो उसको हम दिखवायेंगे, बाकी स्कूलों में कैसे हो सकता है इसके संबंध में भी हम बात करेंगे। लब्बोलुआब यही है कि हमारी सारी मशीनरी, सारे अधिकारी शिक्षा व्यवस्था को दुरूस्त करने में लगे हुये हैं। हमारे सचिवालय के सारे अधिकारी लगे हैं सचिव, विशेष सचिव और जितने भी लोग हैं वह भी भ्रमण पर जाते हैं। हमारे निदेशालय के सभी अधिकारी भ्रमण पर जाते हैं। हमारा जो बी0एस0ए0 है वह भ्रमण कर रहा है, ए0बी0एस0ए0 लोग भ्रमण कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ए0बी0आर0सी0 की जो बात आयी उसमें जरूर कुछ सोचने की बात है। ए0बी0आर0सी0 लोगों को इसलिये बनाया गया कि वह मास्टर लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि कैसे पढ़ाया जायेगा, लेकिन वह ऑफिस में आकर बैठकर दिन भर कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन आपकी ही सरकार ने उनके खिलाफ कार्यवाई की थी। आपकी ही सरकार थीं, लेकिन यह फिर सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लेकर चले आये तो जहां न्यायालय का आर्डर हो गया उस पर हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं, लेकिन ए0बी0आर0सी0 लोगों का जो काम है उनको उस काम पर निश्चित रूप से लगाया जायेगा। आईये, पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य मिलकर के इस बुनियादी शिक्षा की नींव को मजबूत करने के लिये बिना किसी दोषारोपण के एक साथ मिलकर बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करके विकास किया जाये। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बजट प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,23,09,79,03,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,43,39,21,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख05.18, कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 मार्च, 2015 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 17 मार्च, 2015 से 27 मार्च, 2015 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 18 मार्च, 2015 को उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें ली जाये।

2–दिनांक 17 मार्च, 2015 के लिये निर्धारित वित्तीय वर्ष 2015–2016 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी अनुदान संख्या–12 की मद दिनांक 19 मार्च, 2015 को ली जाय।

3–दिनांक 19 मार्च, 2015 के लिये निर्धारित वित्तीय वर्ष 2015–2016 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी अनुदान संख्या–24 की मद दिनांक 25 मार्च, 2015 को ली जाय।

4–दिनांक 16 मार्च, 2015 को श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुरेश कुमार खन्ना एवं अन्य मा0 सदस्यगण द्वारा दिनांक 14 एवं 15 मार्च, 2015 को हुई तेज बारिश एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुई भारी क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में

नियम–56 के अन्तर्गत दी गई सूचना, जो मा0 अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य की गयी है, पर दिनांक 20 मार्च, 2015 को एक घण्टे की चर्चा निर्धारित कर दी जाय।

5–तद्नुसार दिनांक 17 मार्च, 2015 से 27 मार्च, 2015 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :–

मार्च, 2015

17 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
18 बुधवार	1–वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2–उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारण।
19 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
20 शुक्रवार	1–असरकारी दिवस (आधा दिन)। 2–विधायी कार्य (आधा दिन)। 3–दिनांक 16 मार्च, 2015 को श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुरेश कुमार खन्ना एवं अन्य मा0 सदस्यगण द्वारा दिनांक 14 एवं 15 मार्च, 2015 को हुई तेज बारिश एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुई भारी क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–56 के अन्तर्गत दी गई सूचना, जो मा0 अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य की गई है, पर एक घण्टे की चर्चा।
21 शनिवार 22 रविवार	बैठक नहीं होगी।
23 सोमवार 24 मंगलवार 25 बुधवार 26 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
27 शुक्रवार	1–वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। **2–3.00 बजे अपराह्न** उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश विषय प्रस्ताव जिसको मा0 मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

ख07.4, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री महबूब अली)–

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 87,63,91,33,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाएं। मान्यवर जैसा कि यह बात सही है कि किसी भी राष्ट्र समाज की पहचान वहां की शिक्षा व्यवस्था से होती है। माध्यमिक शिक्षा जैसा कि अभी बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बेसिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में सेतु का काम करती है। शिक्षा ही वह आधार है जो जाति धर्म क्षेत्र सम्प्रदाय एवं भाषा की विषमता को दूर करती है एवं समाज में समन्वय स्थापित करती है। शिक्षा मानव का विकास कर एक सशक्त एवं सुन्दर आदर्श समाज का निर्माण करती है। यह बात सही है कि हिन्दुस्तान हमारा देश प्राचीन काल में विश्व गुरू रहा है। यह बात भी सही है कि टाइम्स हायर सेकेंडरी हायर एजूकेशन मैगजीन लंदन के द्वारा हिन्दुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम या किसी भी इदारे का नाम आज तक शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर नहीं है। यह बात भी सही है कि पिछली सरकारों को बीस साल से जो शिक्षा का स्तर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए था उस पर काम नहीं किया गया। जैसा कि आप महसूस करते हैं कि पिछली सरकारों ने शायद बड़े पैमाने पर शिक्षा में ऐसे काम किए हैं जिसने संभवतः उसकी गुणवत्ता और पारदर्शिता को किसी भी स्तर पर आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। जब से हमारी सरकार मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में बनी हॉ लगातार शिक्षा में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा जैसा कि मैंने बताया अगर देख लिया जाएं तो मान्यवर आप भी कहीं पढ़े हैं हम भी कहीं पढ़े हैं लेकिन पिछले बीस सालों से सामाजिक ज्ञान का जिस तरह से शिक्षा में अभाव हुआ है यह कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि पूरी तरह से आज अगर कोई पढ़ाने वाला टीचर हमारे जैसे बहुत–से लोग यहां सदन में बैठे हैं जो कहीं न कहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पढ़े हैं लेकिन उनके सामने से कोई टीचर निकल जाएं तो वह भूल जाएंगे कि हमारी औकात क्या है सिर्फ इतना याद रखें

कि इस गुरू जी की औकात की बदौलत तेरी औकात है। इनका योगदान है तेरी औकात को यहां तक भेजने में उसे बनाने में। लेकिन कहीं न कहीं पिछले वक्तों में पूरी तरह से उस पर काम नहीं किया गया। मैंने बहुत गम्भीरता से आई0आई0टी0 में, आई0ए0एस0 में, आई0पी0एस0 में, आई0एफ0एस0 में सिविल सर्विसेज में उनके रिजल्ट देखे हैं। जो प्रतिशत प्रदेश का होना चाहिए था वह बहुत नीचे हो गया। जो प्रतिशत प्रदेश का होना चाहिए था वह प्रतिशत बहुत नीचे गया है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है अगर उसमें काम होता तो निश्चित ही उसके नतीजे कुछ और होते। आज हमारी सरकार बड़े पैमाने पर इस पर काम कर रही है और हम यकीन दिलाते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है।

(इस समय 05 बजकर 26 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजबली जैसल पीठासीन हुए।)

आज जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वह दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है। और हमारा लक्ष्य है कि इस बोर्ड का पढ़ने वाला बच्चा हिन्दुस्तान की हर बड़ी कुर्सी तक पहुंचे। हमने माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाये हैं। जब से हमारी सरकार बनी है हमने बालिकाओं की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अनेक कदम उठाये हैं। माध्यमिक शिक्षा में लगातार प्रगति हो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2015 में आय–व्ययक के अनुदान संख्या–72 के अंतर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में कुल उन्यासी अरब बाइस करोड़ सत्तवान लाख रूपये की व्यवस्था की गयी है जो पिछली गत सरकारों से 13.28 प्रतिशत अधिक है। आयोजनागत पक्ष में हमारी सरकार द्वारा 21 अरब 36 करोड़ 94 लाख रूपये की व्यवस्था की गयी है जो पिछली गत सरकारों की अपेक्षा 37.27 प्रतिशत अधिक है। इस पर बड़े पैमाने पर काम ही नहीं, योजनायें जमीन पर हैं। अब उस पर काम चल रहा है। आज राजकीय इंटर कालेज की बात करें। आजादी के बाद से लेकर आज तक कितनी सरकारें आयीं चली गयीं, राजकीय स्कूल जो जीर्णशीर्ण हो चुके हैं उस पर कोई काम नहीं किया गया। हमारी सरकार बनने के बाद मा0 मुख्य मंत्री जी के दिशा निर्देशन में हमने उसमें क्लीन स्कूल और ग्रीन स्कूल की व्यवस्था की है। और जिसमें हमने 100 विद्यालयों में 50 करोड़ रूपये लगाकर प्रति विद्यालय 50 लाख रूपये देने का काम किया है। राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे उधर के साथियों की मांग आ रही थी। कम्प्यूटर में भी आ रही थी व्यावसायिक में भी आ रही थी हमारी सरकार इस पर काम कर रही है और हम कहना चाहते हैं कि उसमें हमने 214.34 करोड़ रूपये का प्राविधान हमने अपने बजट में किया है। असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबंध तंत्र द्वारा कन्या विद्यालय खोलने हेतु 10 लाख रुपये प्रति विद्यालय की दर से द्वितीय किस्त के रूप में कुल 50 लाख रुपये का प्राविधान हमने किया है। इसी प्रकार असेवित विकास योजनान्तर्गत निजी प्रबंध तंत्र द्वारा कन्या विद्यालयों की स्थापना हेतु 10 लाख रुपये प्रति विद्यालय की दर से द्वितीय किस्त के रूप में कुल 100 लाख रुपये का प्राविधान हमने किया है। मान्यवर, व्यावसायिक शिक्षा की योजनांतर्गत कुल 992 माध्यमिक विद्यालयों में 2200 अतिथि विषय विशेषज्ञों द्वारा

अध्यापन कार्य किया जा रहा है। हाई स्कूल स्तर के अतिथि विषय विशेषज्ञ को 8000 और इण्टर के विषय विशेषज्ञ को 10000 रुपये की व्यवस्था की है जिसमें 21 करोड़ रुपये का हमने बजट में प्राविधान किया है।

मान्यवर कन्या विद्या धन के अन्तर्गत मेधावी छात्र को लगातार हमने पहले पिछली सरकार से, हमने घोषणा–पत्र में भी हमने कहा था जो बच्ची पढ़ना चाहती है या वह अभिभावक जो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन गरीब है अपने बच्चे को आगे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कहीं न कही यह महसूस करते हैं कि वह बच्चियां आगे बढ़े। सरकार ने निश्चय किया है कि बच्चिया पढ़े और उसका दायित्व सरकार ने अपने ऊपर लिया है। ऐसे बच्चियों को हमने लगातार कन्या विद्या धन के रूप में दिया और आज भी मेधावी छात्राओं को 30 हजार रुपये प्रति छात्रा को लाभान्वित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 300 करोड़ रुपये का प्राविधान हमने अपने बजट में किया है।

कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण मेधावी छात्र–छात्राओं को निःशुल्क लैपटाप योजना से लाभान्वित करने हेतु हमने 100 करोड़ रुपये का प्राविधान इस बजट में किया है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016 में कुल 21.35 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, जो हमारे मुख्य मंत्री जी की घोषणा के उपरान्त खर्च होगा। मान्यवर, वर्तमान में प्रदेश में संचालित विद्यालयों की जीर्ण–शीर्ण अवस्थायें जैसा मैंने कहा है, उनका पुनर्निर्माण, पुनर्जीवित करने के लिए 05 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। नवसृजित जनपदों में जिला स्तर पर जिला विद्यालय निदेशक कार्यालय अभी कई जनपद ऐसे हैं जिसमें जिला कार्यालय हमारे जिला विद्यालय कार्यालय अभी नहीं बने है, उसमें हमने 07.34 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। मान्यवर, कई जनपद अभी बाकी हैं, 7 जनपद अभी बाकी हैं, जिनमें पुस्तकालय नहीं हैं। इसमें हमने 01 करोड़ 76 लाख रुपये का प्राविधान किया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लागू किया गया है, इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है हाईस्कूल स्तर के छात्र–छात्राओं को 05 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक स्तरीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना। वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभिन्न राजकीय हाईस्कूलों की स्थापना के लिए कुल 200 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार बलिका छात्रावास भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत शैक्षिक दृष्टि से पिछले 680 विकास खण्डों में एक माडल स्कूल की स्थापना किये जाने की व्यवस्था हमने की है। इस योजना के अन्तर्गत माडल स्कूल भवन निर्माण के लिए 400 करोड़ रूपये की हमने अपने बजट में व्यवस्था की है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में आजाद इण्टर कालेज बहराइच के लिए एक अलग से हमने व्यवस्था की है। विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए 2015 में कुल 15.88 करोड़ रुपये की व्यवस्था हमने की है। ई–लाइब्रेरी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 6.32 करोड़ रुपये की व्यवस्था हमने की है। मान्यवर यह बजट है और हमने सोचा बहुत से लोगों का इधर से सुझाव आयेगा, बड़ी लम्बी–लम्बी बाते करेंगे और कहेंगे कि हां बजट तो हमने सुन लिया

लेकिन सुझाव कोई भी नहीं आया कि हमारी सरकार करना क्या चाहती है? हमने शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए बड़े पैमाने पर काम किये हैं। प्रदेश में याद कर लीजिये बहुत से लोग यहां बैठे हैं, किस तरह से मान्यताऐं मिलती थीं। सरकार बनने के बाद हमने 2013–14–15 में लगातार मान्यतायें हमने दी हैं 2634 मान्यतायें हमने एक सिगनेचर से एक साथ इकट्ठा मान्यतायें दी थी जिसमें आप लोग भली भांति जानते हैं मान्यतायें किस तरह से मिलती थी। मान्यवर मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि आज हम कटिबद्ध हैं। 01 करोड़ 29 लाख 68 हजार 698 बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं और हर हालात में पूरी तरह से महसूस करते हैं आज उनके रख–रखाव, उनको शिक्षित और हमने पहले भी कहा है कि नकल से अकल नहीं आ सकती है, इसलिए हमारे किसी भी स्टूडेण्ट ने जो आज का नौजवान है, कल का हिन्दुस्तान है, बिना अकल से ही वह आगे बढ़ नहीं सकता है, बात कर लीजिएगा, आपकी बात का हम जवाब देंगे। प्रदेश में हमारी आलोचना उस वक्त भी लोगों ने की जब हमने सत्र परिवर्तन किया, हमारी बहुत से लोगों ने आलोचना की जब हमने समय परिवर्तन किया कालेजों का, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया और निर्णय लेने के पीछे कारण है कि जो पहले समय था कालेजों के खुलने का वह था 09 बजकर 50 मिनट, हमने उसका समय किया 08 बजकर 50 मिनट, 09 बज कर 50 मिनट पर स्कूल खुलने के बाद 04 बजे स्कूल बन्द होता था, तब बच्चे घर जाते थे, मां–बाप की निगाहें गेट पर लगी रहती थीं कि मेरा लाल अभी आया नहीं, मेरी बेटी अभी आई नहीं।

हमारी सरकार की हर तरह से जिम्मेदारी थी कि बेटा और बेटी अभिभावक के पास सुरक्षित और समय से पहुंच जाय, इसलिए हमने समय परिवर्तन किया, बच्चा 08 बजकर 50 मिनट पर स्कूल जाय और 02 बजकर 50 मिनट पर बच्चा वापस अपने घर आ जाय और आने के बाद अपना जो भी कहीं होमवर्क उसे मिला है, उसे भी वह कर ले। मान्यवर, हमने निर्णय लिया और सत्र परिवर्तन किया, बच्चा एक्जाम देता था मार्च में, अगला सत्र शुरू होता था जुलाई में, हमने निर्णय लिया कि अगला सत्र अब अप्रैल में शुरू होगा, लोगों ने कहा पूरे प्रदेश में मुझसे कहा गया मंत्री जी ने नकल कर लिया, सरकार नकल कर रही है, किसकी नकल कर रही है, इल्जाम लगा कि सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, आई0सी0एस0सी0 बोर्ड के पैटर्न पर, हमने आज तक सुना है कि बड़े की नकल तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन आज तक छोटे की नकल किसी ने नहीं की, सवा दस लाख बच्चे देश में पढ़ाते हैं और हम 01 करोड़ 39 लाख बच्चे प्रदेश में पढ़ाते हैं, हम नकल नहीं करते हैं, हमने बच्चों को हर हालात में यह महसूस किया चार महीने लगातार बच्चा पठन–पाठन नहीं करेगा, पाठशालाओं के बीच में बैठकर तो यह भी सुनिश्चित नहीं कि इतने टाईम के अन्दर कोई घातक हथियार उसके हाथ में होगा, जब किताबें नहीं होंगी तो निश्चित ही यह मान लीजिए किसी भी कीमत पर आने वाले एक्जाम का जब वक्त आयेगा, तो आने वाले वक्त में वह शार्ट नोट और गाईडों से एक्जाम देने का प्रयास करेगा। इसलिए हमने ऐसा सिस्टम किया कि मार्च में एक्जाम दे और अप्रैल से उसका अगला सत्र शुरू हो जाय, यह हमने सुनिश्चित किया है, उसी के आधार पर प्राइमरी में

भी यह व्यवस्था लागू करने के लिए हमने मा0 मंत्री जी से बात की, मा0 मंत्री जी ने भी उसी वक्त इसे लागू किया, क्योंकि उसके बगैर भी काम नहीं चल सकता था, क्योंकि बच्चे जब उधर से आयेंगे तभी माध्यमिक में आयेंगे। आज मान्यवर, हमने प्रदेश में यह बात कही है, आप कहेंगे बजट कहां है, हमने ऐलान किया बायोमीट्रिक सी0सी0टी0वी0 कैमरों का, बात आती है विपक्ष की तरफ से हमने उसमें प्रदेश में पैगाम दिया और उस पर काम भी लोगों ने किया, बायोमीट्रिक अगर आपको देखना हो तो चलिये बहुत से ऐसे जनपदों में बहुत से ऐसे कालेजों में बायोमीट्रिक सिस्टम हो गया है, सी0सी0टी0वी0 कैमरी लग गये हैं, हम इसको चेक करायेंगे। मान्यवर, प्रदेश में राजकीय इण्टर कालेज बालक/बालिकाओं में अधिकांश पद रिक्त थे, टीचर नहीं थे, कर्मचारी कम थे और यह भी कह देने में संकोच नहीं है कि सरकार नहीं थी समाजवादी पार्टी की, लेकिन हमें तोहफे में मिला एक ही स्कूल में टीचर भी वही, प्रिंसिपल भी वही, घण्टा बजाने वाला भी वही, ये तोहफे में मिला हमें। इसलिये हमने एल0टी0 ग्रेड के टीचर्स की व्यवस्था की। आज 6645 टीचर्स की व्यवस्था हम तत्काल कर रहे हैं। मान्यवर, प्रदेश में शासकीय विद्यालय के लिये हमने आयोग को निर्देश दिये हैं और उसमें भी 6028 टीचर्स की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की है हमने। तत्काल उसमें एग्जाम वगैरह हो गये उसमें सबका काम चल रहा है।

मान्यवर, ऐसा ही नहीं टीचर्स की बात सही है कि हमारा टीचर किसी भी कीमत पर बहुत से प्रदेशों में काबिल टीचर की बात छोड़िये हिन्दुस्तान में इतना काबिल टीचर नहीं होगा जितना काबिल हमारा टीचर है। हमने उसे प्रोत्साहित करने के लिये, हमने उसे उत्साहित करने के लिये, हमने उसे सुनिश्चित करने के लिये और हमने ये भी कि सामाजिक ज्ञान कैसे हो, बच्चे आगे कैसे आयें, हमने उन्हें प्रेरित किया। अब बच्चों में कहीं न कहीं सामाजिक ज्ञान कैसे बढ़े, उसके लिये हमने टीचर्स से अनुरोध किया। मैंने 19 संघों के सहारे जिसे आज तक इतिहास में किसी ने नहीं बुलाया, उनके साथ बैठने के बाद में हमने तुरन्त 19 संघों को जो शिक्षा पर काम कर रहे हैं, उनका भी लक्ष्य है। हमने उनसे कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता और आगे कैसे बढ़े, किस तरह से सुधार हो, आप लोग हमें सुझाव दो। उनके सुझाव के उपरान्त मैंने प्रेयर के वक्त सुबह हर हालात में किसी महापुरुष पर जिससे बच्चों में सुधार हो, वे नैतिकता के गुण सीखें, यह एहसास हो कि हां, बच्चा स्कूल के प्रांगण से निकलने के बाद उसका आचरण अच्छा रहे इसलिये हमने प्रेयर के वक्त किसी भी महापुरुष पर एक भाषण या कोई भी कहीं न कहीं संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर उसे बताया जाये। ऐसा नहीं है कि टीचर्स को हमने काम ही बताया बल्कि हमने टीचर्स के लिये भी कोशिश की है और हम उस पर भी काम कर रहे हैं। जो टीचर्स हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार या हमारे प्रदेश पुरस्कार से सम्मानित किये गये हैं। हमारी सरकार ने यह किया है कि ऐसे टीचर्स के लिये उनका सेवा विस्तार हमने 5 साल के लिये बढ़ाने का काम किया है। आज हमारी सरकार प्रदूषण दूर करने के लिये ऐलान किया कि पूरे प्रदेश के अन्दर हर कालेज प्रांगण में हर बच्चा यह सुनिश्चित करेगा किसी भी तरह से एक फोटोग्राफ लाकर स्कूल में जमा करायेगा। वह

अपने घर में लगाये या स्कूल के प्रांगण में लगाये एक पेड़ लगायेगा यह भी हमने सुनिश्चित किया। मैंने खुद इसकी शुरुआत की राजकीय इण्टर कालेज में पेड़ लगाया था। आज हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश के अन्दर आज तक जिसे किसी ने नहीं सोचा। एक भी सैनिक स्कूल नहीं था और हमने उस चीज का तय किया कि हर हालात में प्रदेश के अन्दर सैनिक स्कूल हों तो कहीं न कहीं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। सैनिक स्कूल अगर कहीं बनेगा तो बड़े पैमाने पर वे लोग जो आज शायद कहीं किसी दूसरे बोर्ड की तरफ भाग रहे थे, मैं तो कहूंगा कि वे वहां रूकेंगे और उनको वही शिक्षा मिलेगी जो वे कहीं दूसरे किसी बोर्ड में महसूस करते हैं कि हां, दूसरे किसी भी बोर्ड के द्वारा मिल रही है इसलिये हमने तीन नये स्कूल स्थापित कर दिये हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भाषण है, हमने कर दिये हैं। प्रदेश में अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों का पदनाम कहा जाता था, एल0टी0 ग्रेड को कहा जाता था कि सहायक अध्यापक। आखिर किसका सहायक है वह, टीचर तो वह भी है। वह सहायक कहां का है, किसका सहायक हो गया इसलिये उसके आगे से हमने सहायक हटाया है। अध्यापक नाम देने का काम किया है कि उसके सम्मान में किसी कीमत पर कमी न आये। हमने उसको यह सम्मान देने का काम किया है। माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक बालिकाओं को उनकी आत्मरक्षा के लिये हम 100 प्रतिशत करने जा रहे हैं। हम शत प्रतिशत बच्चों को बच्चों को हम जूडो कर्राटे सिखाने जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर हम प्रदेश की हर बच्ची को हम जूडो कर्राटे सिखायेंगे ताकि वे स्वावलम्बी बनें, आत्मनिर्भर हों। किसी भी कीमत पर कहीं न कहीं जो बच्चियों के साथ आने वाली दुश्वारियां हैं। आप भी जो लॉ एण्ड आर्डर, लॉ एण्ड आर्डर कहते हैं, उस पर भी निश्चित ही गिरावट आ जायेगी इसलिये मैं पूरे सदन से ऐसे वक्त में कहना चाहूंगा कि शिक्षा पूरी तरह से एक मन्दिर की तरह से है। भाषण प्राइमरी पर बहुत हो गये, मेरे ख्याल से प्राइमरी में और माध्यमिक में दोनों ओर जिस तरह से काम हुआ है, आप सुझाव लिखकर दे दीजियेगा लेकिन कहीं न कहीं अगर बीच की पार्टी का हिसाब लगा लिया जाय तो इन्होंने नौजवान जेल में भेजे, बच्चे जेल में भेजे जब इनकी सरकार थी। हथकड़ियां लगाई हैं।

(कोई बैठा भी है सुनने के लिये की एक आवाज आई)

हां, बैठे हैं, दो चार सुन रहे हैं, सब। मुझे कुछ नहीं कहना है उनके बारे में बहरहाल आज पूरा प्रदेश जानता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं इस प्रकार कि स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार द्वारा उपरोक्त वर्णित महत्वाकांक्षी ओर सहयोगी योजनाओं में प्राप्त बजट व्यवस्था करते हुए इस माध्यमिक शिक्षा को मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिये कटिबद्ध है और इसके लिये हर संभव प्रयास किया जा रहा है मैं चाहूंगा कि सर्वसम्मति से और बिना कटौती के इस बजट का पास किया जाये। यह बहुत खराब होगा यदि इसमें कटौती करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये शिक्षा पर भी गंभीर नहीं है, जितने विपक्ष के लोग बैठे हैं बिना कटौती के

सर्वसम्मति से इस बजट को पास कर देंगे तो ये कलंकित होने से बच जायेंगे। धन्यवाद।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांगी गई राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मंत्री जी तो कह रहे हैं कि सुझाव लिखकर दे दो और यह कह रहे हैं कि कोई आलोचना न करे और न सुझाव दे लेकिन मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अगर आलोचनाओं और सुझावों को सुनेंगे तो मैं समझता हूं कि जो उनकी इच्छा है उसमें और इजाफा होगा, वह उसकी और अच्छी तरीके से सही कर पायेंगे। माननीय मंत्री जी ने अभी स्वयं अपने भाषण में यह स्वीकार कि पिछले 20 वर्षों से माध्यमिक शिक्षा में बहुत गिरावट आई है, लेकिन वह 20 वर्षों की गिरावट को इन तीन वर्षों में सुधार की दिशा में कोई कदम बढ़ा हो, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। मान्यवर, जिस तरह से बेसिक शिक्षा का जितना महत्व है, उससे कहीं कम माध्यमिक शिक्षा का महत्व नहीं है, क्योंकि हाईस्कूल और इण्टर में जब छात्र आते हैं, वह किशोरावस्था में जब वहां पहुंचते हैं तो वहीं से उनके जीवन का उद्देश्य शुरू होता है कि हमको आगे क्या बनना है, क्या करना है ? इसलिये हाईस्कूल और इण्टर की पढ़ाई अगर सही नहीं होगी तो शायद वह भटक जायेंगे और जैसा मंत्री जी बता रहे थे कि कानून व्यवस्था खराब हो रही है, हाथ में कुछ और पकड़ लेंगे। मान्यवर, राजकीय विद्यालयों की बात माननीय मंत्री जी ने की। एक समय था जब हम लोग हाईस्कूल में पढ़ते थे, तो जी0आई0सी0 में एडमीशन कराने के लिये बच्चे परेशान रहते थे। वहां एडमीशन नहीं होते थे। आज के समय कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा जी0आई0सी0 की तरफ जाना नहीं चाहता है। जी0आई0सी0 विद्यालयों में अध्यापकों की कमी, रख–रखाव की कमी और भी कई अव्यवस्थायें हैं, शायद उस पर नजर सरकार की गई होगी। अभी माननीय मंत्री ने बताया कि हम 50–50 लाख रुपये उन कालेजों को देने जा रहे हैं। उनको क्लीन और ग्रीन बनाने जा रहे हैं। अच्छी बात है लेकिन अगर इस पैसे को वहां भेजने के बाद, उसकी सही मानीटरिंग नहीं की गई, सही तरीके से उसकी देख–रेख नहीं की गई तो मान्यवर, जिस तरह से बुरा हाल आज जी0आई0सी0 का है, उसी तरीके से इस पैसे का भी बंदरबांट हो जायेगी और काम नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को इस पर बड़ी कड़ी नजर रखने की जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश के अन्दर जो कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड की परीक्षायें इस समय चल रही हैं।

माननीय मंत्री जी ने सत्र को सुधारकर जो यह परीक्षाएं फरवरी और मार्च में करायी हैं मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूं जिससे सत्र आगे नियमित हों। मान्यवर, यह जो परीक्षाएं आज हो रही है पूरे प्रदेश में लोग जानते हैं कि हम नकल को रोकने में

कामयाब नहीं हो पाये और बहुत से अखबारों में मीडिया में यह बात आई कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जब माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं तो नकल माफियाओं का कारोबार 10 हजार करोड़ रुपये से भी ऊपर का है इसमें कहीं न कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है बहुत सख्ती के साथ । मान्यवर, इसी में व्यावसायिक शिक्षा भी जुड़ा हुआ है दुनिया के कई देशों में एक बार हमारी एक कनाडा के टीचर से भेंट हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे यहॉ जब हाईस्कूल में बच्चा पढ़ने आता है तो पढ़ाई के साथ उसको हम किसी रोजगार से भी जोड़ते हैं। आज हमारे यहां बेरोजगारों की संख्या बड़ी तादाद में बढ़ी है बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया था बन्द कर दिया आपने।

बेरोजगारों की यह जो संख्या बढ़ रही है आप उनको माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई के साथ–साथ किसी रोजगार से जोड़े। आज सरकार स्किल्ड डेवलपमेन्ट की बात कर रही है लेकिन यहॉ मुझे जो लिजटरेचर मिला, जो यह किताब मिली इसमें जिस तरह का जो ट्रेडों में लोगो के सिखाने की या पढ़ाने की बात की है शायद यह बहुत पुरानी बातें हो गयी । आज कोई भी बच्चा यह सोचकर पढ़ाई नहीं करेगा कि हमको टेलीवीजन बनाने का काम सीखना है मजबूरी में भले ही वह गांव में दुकान खोल ले लेकिन उसका लक्ष्य यह नही होगा इसलिए आज के इस युग में हमको नई नई टेक्नोलॉजी लाकर उन नौजवान बच्चों को जो हाईस्कूल इन्टर में पढ़ने जा रहे हैं उनको सीधे पढ़ाई के साथ–साथ हम ऐसे रोजगार से भी जोड़े ताकि जब वह इन्टर पास करने के बाद अपनी डिग्री की पढ़ाई करने जायें, आई0आई0टी0 करने या और कुछ करने जायें तो हमारे गांव का नौजवान गांव का रहने वाला बच्चा जो इन विद्यालयों में पढ़ने जाता है तमाम ऐसे परिवार हैं जो शायद पैसे के अभाव में बाद में उनको ग्रेजुएशन नहीं करा पाते हैं लेकिन अगर आप जोड़ देंगे इनको रोजगार से तो वह अपने पैसे अपनी कमाई से आगे की शिक्षा भी कर लेगा इसलिए इसमें मैं समझता हूं कि बल देने की जरूरत है, जोर देने की जरूरत है। मान्यवर, आज कम्प्यूटर युग है इन्टरनेट का युग है हर हाथ में मोबाइल है। सरकार ने लैपटाप की योजना शुरू करी कुछ नौजवानों को लैपटाप मिले लेकिन गांवों में इन्टरनेट न होने के कारण वह लैपटाप खिलौना बन गये । आज जिस तरह से समय बदल रहा है लैपटाप की आवश्यकता उन बच्चों को भी है जो आगे निकल रहे हैं लेकिन अब यह योजना सरकार ने बन्द कर दी है। हाईस्कूल पास बच्चों को टेबलेट देने की बात कही गयी थी लेकिन शायद टैबलेट तो बंटा ही नहीं । मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो बच्चियां पढ़ना चाह रही हैं उनको हम 30 हजार रुपया पहले कन्या विद्या धन के माध्यम से देते थे। जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो हर इन्टर पास बच्ची को सावित्री बाई फुले शिक्षा योजना के तहत 25 हजार रुपये और एक साइकिल देने का काम किया जाता था पता नहीं आपको क्यों बुरी लगी योजना आपने उस योजना को बन्द कर दिया नाम बदल दिया हम साइकिल भी दे रहे थे आप तो साइकिल ट्रेड बना रहे हैं साइकिल का

प्रचार कर रहे हैं, साइकिल हम दे रहे थे आपने पता नहीं क्यों बन्द कर दिया इन्टर पास प्रत्येक बच्ची को दिया जाता था।

जन्तु उद्यान मंत्री (डा0 शिव प्रताप यादव)–

मान्यवर, सब बच्चियों को नहीं दिया जाता था।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, मैं पिछली बार भी एम0एल0ए0 थ और मैने अपने जिले में अपने हाथ से कितने बच्चियों को साइकिलें और चेके बांटी हैं। आप रिकार्ड निकलवा लीजिए इन्टर पास प्रत्येक बच्ची को दिया जाता था। प्रत्येक बच्ची को आप शायद पिछली बार पता नहीं सदन में थे कि नहीं थे मुझे नहीं पता लेकिन मैंने खुद अपने हाथों से बांटा है और प्रत्येक बच्ची को और आपने उस योजना को बन्द करके कन्या विद्या धन नाम दिया। फिर उसको भी बंद कर दिया आपने। आज आप कह रहे हैं कि हम उस बच्ची को देंगे जो पढ़ने में अच्छे नम्बर लायेगी, अच्छी पढ़ाई करेगी, यह आपने अभी बजट में कहा है।

(सत्तापक्ष की ओर से 'सबको नहीं दिया जाता था' की आवाजें)

मान्यवर, यह पहले चल रहा था और सावित्री भाई फुले शिक्षा मदद योजना में इसको बेहतर करके लाया गया, स्कूल जाने में लड़कियों को साइकिल दी गई, हमने सबको दिया जिन्होंने इण्टर पास किया सबको दिया। अकेला जी पिछली बार आप सदन में नहीं थे, इसलिये आपको जानकारी नहीं है। आप पहले पुराने रिकार्ड निकलवा कर पढ़ लें।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग शांत रहें। इन्हें कटौती का प्रस्ताव रखने दें, जब आपका नम्बर आयेगा, तब आप अपनी बात रख लीजियेगा।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इनको जानकारी नहीं है। आज तो आर0टी0आई0 है आप इसको निकलवा लें और आप सरकार में बैठे हैं। एक–एक बी0पी0एल0 बच्ची को देने का काम किया गया था और मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है इसमें वो अपनी इस योजना को, उसका नाम कन्या विद्याधन हो या वो जो भी रखे लेकिन वह जरूर लागू करें और जिस तरह से हमारी सरकार बच्चियों को साइकिल दे रही थी, उसी तरह वह साइकिल उपलब्ध कराने का काम करें यह मेरा सुझाव है और मैं चाहूंगा कि इसको मंत्री जी आज ही स्वीकार करें। मान्यवर, अभी मैं एक टी0वी0 पर सर्वे देख रहा था। इण्टर पास करने के बाद जो बच्चे अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लोगों को पढ़ने का बड़ा क्रेज है और दिल्ली यूनीवर्सिटी के अंदर और तीन–चार ऐसे कालेज हैं, वहां पर एडमिशन किस तरह से होता है कि वहां पर एक कालेज में उन बच्चों का एडमिशन हुआ कि जिनके

शत–प्रतिशत नम्बर आये। ऐसी कड़ी प्रतिस्पर्द्धा में उत्तर प्रदेश बोर्ड के बच्चे किस तरह से बाहर जाकर अपने आपको स्थापित करेंगे, कैसे वह वहां प्रवेश पायेंगे ? शायद यह भी एक कड़ी चुनौती है सरकार के लिये और हम सबके लिये। इसको हम लोगों को जैसे आपने अभी बताया कि हमारे अध्यापक बहुत अच्छे हैं, तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अध्यापक अच्छे नहीं हैं, आपने उनका इन्टरव्यू लिया होगा, उनको आपने तभी सेवा में लिया होगा, लेकिन वह अध्यापक वाकई में अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी का निवर्हन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यह देखने की जरूरत है, क्योंकि जो आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग है, इसके अंतर्गत जिले में मात्र एक डी0आई0ओ0एस0 होते हैं और उनके अतिरिक्त आपका कोई ऐसा अधिकारी नहीं होता है जो जाकर ब्लाक में या और जगह पर उसकी जांच करें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं कि राजकीय इण्टर कालेज तथा जो एडेड इण्टर कालेज हैं, में वर्तमान में सृजित विषयवार पदों की अपेक्षा एक चौथाई से कम शिक्षक इस समय कार्यरत हैं, 80 से 85 फीसदी शिक्षकों के पद खाली रहने के कारण से कई विषयों की पढ़ाई चौपट है तथा विषय शिक्षक विद्यालयों में न होने से छात्रों का भविष्य अंधकारमय है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा शिक्षकों के विषयवार पदों की नियुक्ति का जिम्मा है किंतु सरकार की लचर व्यवस्था के चलते सालों तक चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है तथा नवनियुक्ति में भी एडेड कालेजों की जो प्रबन्ध कमेटी हैं उनकी पूरी मनमानी तथा पूरी अथारिटी होने के कारण लेटलतीफी बनी रहती है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस व्यवस्था को सुदृढ़ करके टीचरों की कमी को पूरा कराया जाये। सरकारी तथा स्ववित्तपोषित इण्टर कालेज में शिक्षकों के साथ शिक्षणेत्तर कर्मचारी भी कम हैं, जिनके कारण विद्यालय कार्य प्रभावित रहता है। स्ववित्तपोषित तथा सरकारी कालेजों में आर्थिक व्यवस्था न होने से संसाधनों की भारी कमी है, शुद्ध पेयजल, शौचालय, चहारदीवारी, फर्नीचर, रंगाई–पुताई। माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकारा है कि बिल्डिंगों की दशा बहुत खराब है। वित्त विहीन मान्यता प्राप्त कालेज की प्रबन्ध कमेटी अपने निजी संसाधनों से उक्त व्यवस्थायें संपादित करती है। सी0बी0एस0ई0 की तर्ज पर अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं उनकी नकल नहीं कर रहा हूं क्योंकि वह हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि कोई हमसे कितना भी छोटा क्यों न हो, लेकिन अगर उसके अंदर कोई अच्छाई है तो उसको ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है। हम यह सोचे कि वह हमसे बहुत छोटे हैं, इसलिये उनकी अच्छाई हम नहीं लेंगे तो यह बात कहीं पर मैं समझता हूं कि मानने लायक नहीं है। सी0बी0एस0ई0 की तर्ज पर प्रदेश सरकार शैक्षिक सत्रों के संचालन का समय परिवर्तन कर रही है, किंतु सी0बी0एस0ई0 के जो स्कूल हैं वहां की भॉति पाठ्यक्रम व संसाधन मुहैया नहीं करा पा रही है और जब तक वह व्यवस्था आप लागू नहीं करा पायेंगे, तब तक आप द्वारा उसकी तर्ज पर

शैक्षणिक सत्र बदलने से शायद यह बात बनने वाली नहीं है। माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, पुरानी पद्वति की परम्परा तथा गत सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता पर संचालित है। यू0पी0 बोर्ड से सी0बी0एस0ई0 का कार्य क्षेत्र भी 1/5 है । तो आपको जो उनकी सुदृढ़ व्यवस्था है, उसको लागू करने में, जानकारी करने में क्या दिक्कत है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का यू0पी0 बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड होने के बावजूद भी तमाम विद्यालय सी0बी0एस0ई0 और आई0सी0एस0ई के प्रदेश में चल रहे हैं और उसमें तमाम बच्चे पढ़कर निकल भी रहे हैं। एडेड तथा वित्तविहीन मान्यता प्राप्त कालेजों में सरकार द्वारा एकरूपता न बना पाने के कारण शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिये शिक्षा को समवर्ती सूची से हटाकर मुख्य सूची में सम्मिलित कर अपनी जिम्मेदारी तय करें और बेसिक शिक्षा की भांति जैसे कि आपके यहां जिलों में डी0आई0ओ0एस0 है, इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा में भी ब्लाक या तहसील स्तर पर एक निरीक्षणकर्ता अधिकारी नियुक्त हो, तांकि प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त हो सके क्योंकि कालेजों में वहां तो ए0बी0एस0ए0 हैं लेकिन यहां आपके पास कोई अधिकारी जाने वाला नहीं है । रिक्त सभी पदों पर विषय अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया सुदृढ़ की जाय ताकि प्रत्येक विषय का शिक्षक कार्यरत हो, इसके अलावा नियुक्ति का समय भी तय किया जाय । मान्यवर, यह जो अव्यवस्थायें हैं, इनको माननीय मंत्री जी ने स्वंय अपने भाषण में स्वीकार भी किया है, तो मैं चाहता हूं कि आज माननीय मंत्री जी सदन को आश्वस्त करें कि आने वाले समय में माध्यमिक शिक्षा को सुधारने के लिये माध्यमिक शिक्षा यहां के बच्चों को गुणवत्तापरक मिले, उस पर रात–दिन काम करेंगे और रात दिन काम करने के बाद जहां–जहां पर अधिकारियों की आवश्यकता है, जहां–जहां पर कर्मचारियों की, शिक्षकों की कमी है, उसको दूर कराने के लिये सदन को यह भरोसा देंगे, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद।

श्री जाहिद बेग–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने माध्यमिक शिक्षा के बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समय का ध्यान रखें। माननीय अध्यक्ष जी ने सदस्यों के लिये 5 मिनट का समय निर्धारित किया है।

'श्री जाहिद बेग–

बस दो मिनट में समाप्त कर दूंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, साइकिल से आते हैं, दिक्कत होती है। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपको बधाई देना चाहता हूं । माननीय अधिष्ठाता जी, इधर काफी तीन सालों के अंदर माध्यमिक शिक्षा में बहुत तेजी से सुधार हुआ है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा की रीढ़ होती है और जब रीढ़ मजबूत होती है तो आगे उच्च शिक्षा में उसका लाभ मिलता हैं। उस कड़ी में हमारे मुख्य मंत्री जी ने हमारे शिक्षा मंत्री जी ने लैपटाप वितरित करने का काम किया है जबकि हमारे नेता विरोधी दल ने बताया है कि लैपटाप की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। शायद उन्होंने बजट में पढ़ा नहीं था कि इस बजट में 300 करोड़ की व्यवस्था लैपटाप के लिये की गयी है। यह इस बात का प्रमाण है कि माध्यमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिये सरकार कितनी गंभीर है। इसके अलावा कन्या विद्याधन की योजना भी चल रही है। माननीय अधिष्ठाता जी, आज हमारी सरकार बहुत तेजी से माध्यमिक शिक्षा के सुधार की तरफ काम कर रही है और पूर्व में बगल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थीं, इन्होनें छात्रों को हथकड़ी पहनाने का काम किया था और जब हमारी सरकार आई तो हमने बच्चों को लैपटाप देने का काम किया है। आज पूरे प्रदेश में बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं और इसके लिये बिजली बहुत जरूरी है। आज पूरे प्रदेश में बिजली की कहीं कोई शिकायत नहीं आ रही है। हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने और हमारे मा0 शिक्षामंत्री जी ने पूरे प्रदेश में शिक्षा के काम के लिए गांव हो या शहर हो बिजली की व्यवस्था की है इसलिए मैं अपने मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, वह दिन बड़े शर्म का दिन होता है जब कोई गुरूजन जेल जाता है, आपकी सरकार में आपके शिक्षामंत्री जेल गये थे इससे बड़ा दुर्भाग्य कभी हो नहीं सकता। आप सुझाव दे रहे थे कि पैसा कहीं और न चला जाएं, आप इतिहास देख लीजिए वह आज भी जेल में हैं, जमानत नहीं हुई है यह इस बात का प्रमाण है कि कौन सरकार चलाता है कौन पैसा खाता है। इसी के साथ मैं मा0 शिक्षामंत्री जी के बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माध्यमिक शिक्षा के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका आभार प्रकट करती हूं। मान्यवर, शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन है और शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित कर उसे समाज में रहने लायक बनाती है और मैं समझती हूं कि माध्यमिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है जिसके द्वारा यह तय होता है कि बच्चा दसवीं और बारहवीं करने के बाद कौन से क्षेत्र की पढ़ाई करेगा। क्योंकि बारहवीं क्लास के बाद ही यह तय किया जाता है कि वह मेडिकल साइड में जायेगा या टेक्निकल साइड में जायेगा या सिविल एग्जाम की तैयारी करेगा। अगर उसे किसी भी क्षेत्र में जाना हो तो उसे बारहवीं क्लास से गुजरना पड़ता है। मान्यवर, मैंने इसी सत्र में एक प्रश्न सरकार से किया था कि बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना में आपने क्या किया। उत्तर आया कि हमने पश्चिम जिले के गौतमबुद्ध नगर और बुलन्दशहर आदि कई जिले लिये हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, आपने बेटी बचाओ में भ्रूण हत्या पर रोक लगाने का जो कार्य किया है वह अच्छा है उसके बाद जो बेटी पढ़ाओ का मेरा प्रश्न था उस पर मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आज हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो कई गांव के बीच में एक इंटर कॉलेज होता है। मैं समझती

हूं कि बेटियों के लिए कोई कॉलेज अलग से बनाया गया हो ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है। कन्याओं के कॉलेज की उपलब्धता बिल्कुल नगण्य है। इसका परिणाम होता है कि बच्चियां जब शहर में पढ़ने के लिए जाती हैं तो वह सुरक्षित नहीं रह पाती हैं। अभी मेरे विधान सभा में एक बच्ची सुबह साढ़े सात बजे पढ़ने के लिए जा रही थी और तीन–चार लोगों ने उसे पकड़ लिया। सौभाग्य से वह बच गई लेकिन उसके साथ कोई भी दुष्कर्म हो सकता था और मैं समझती हूं कि इसी असुरक्षा की वजह से 70 प्रतिशत लड़कियां जो गांव में निवास करती हैं उन्हें आठवीं कक्षा के बाद लोग अपने घरों से निकलने नहीं देते हैं। असुरक्षा ही एक कारण है कि आगे उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। और मैं समझती हूं कि एडेड विद्यालयों में तो शिक्षकों की पढ़ाने में बिल्कुल रुचि नहीं होती। वहां प्राईवेट मैनेजमेंट होते हैं और राजनीति ज्यादा होती है। इसी वजह से वहां पढ़ाई नहीं हो पाती और जब राजनीति होती है, एक–दूसरे की टांग खिंचाई होती है तो बाद में राजनीति की वजह से वहां प्रशासक नियुक्त हो जाता है और जब प्रशासक नियुक्त हो जाता है तो वहां कोई पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि कम से कम दो गांवों के बीच में एक इण्टर कॉलेज जरूर स्थापित करें जिससे कि बेटियों की सुरक्षा हो सके। व्यक्तियों और संस्थाओं को सरकार की तरह कालेज खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएं। एडेड विद्यालयों में जो चुनाव की प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएं जिससे वहां पर प्रशासक की नियुक्ति न करनी पड़े।

श्री अधिष्ठाता–

सोलंकी जी, अब समाप्त करिये।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

मैं समझती हूं कि आज पब्लिक स्कूलों में इतनी अच्छी सुविधायें हो गयी हैं कि वहां अच्छा टीचर उपलब्ध है, विद्यार्थियों के लिए अच्छा फर्नीचर उपलब्ध है, वहां अच्छी पढ़ाई मिलेगी। मैं आपको बताना चाहती हूं कि एक दिन मैं जा रही थी वहां बारहवीं तक स्कूल की छुट्टी हुई और मैं आधे घण्टे तक सड़क पार नहीं कर पायी। इतने बच्चे जा रहे थे और हमारे स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए आते ही नहीं क्योंकि वहां टीचर्स उपलब्ध नहीं है, अच्छा फर्नीचर उपलब्ध नहीं है। कन्याओं के लिए अलग शौचालय होना चाहिए वह वहां नहीं है, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन कि वहां पर मूलभूत सुविधायें होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

सोलंकी जी, आपका समय समाप्त हुआ, अब बैठिये। सत्यवीर मुन्ना जी।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माध्यमिक शिक्षा विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया इस हेतु आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री, माध्यमिक शिक्षा के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और माननीय मंत्री जी ने 80 अरब रुपये का योजनागत बजट प्रस्तुत किया है।..

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

अधिष्ठाता जी, मैं कन्याओं की बात रख रही थी कम से कम इतना गम्भीर विषय है तो मुझे थोड़ा समय दिया जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मुन्ना जी, एक मिनट रुक जाईये, बिमला सिंह सोलंकी जी को अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। सोलंकी जी समय का ध्यान जरूर रखिये।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

मेरी विधान सभा क्षेत्र में न्याय पंचायत चोला, धनौरा तथा बराल में राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज खोलने का अनुरोध करती हूं। किसान इण्टर कालेज खानपुर में कामर्स तथा साइन्स विषयों की मान्यता प्रदान करने की माननीय मंत्री जी से मांग करती हूं। माननीय मंत्री जी, एक जैन इण्टर कॉलेज हमारे सिकन्दराबाद में है और उसके लिए बार–बार आपसे निवेदन किया और आपके प्रमुख सचिव से भी कहा कि वहां 6 टीचर्स के पद खाली हैं, अगर अल्पसंख्यकों के प्रति भी आप लोगों का यह नजरिया रहेगा तो वहां पर कैसे पढ़ाई हो पायेगी तो मेरा आपसे निवेदन है कि वहां भी उनको अनुमति देने की कृपा करेंगे। इतना गंभीर विषय है इसमें अगर आप गम्भीरता दिखायेंगे तो मैं समझती हूं कि इसमें जरूर सुधार आयेगा। आदरणीय राजनाथ सिहं नकल विरोधी कानून लेकर आये थे....

श्री अधिष्ठाता–

सोलंकी जी, अब समाप्त करिये।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

ऐसे ही आपको इच्छाशक्ति दिखाने की जरूरत है। 10 करोड़ रुपये से ज्यादा का जो नकल का धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है, नकल धड़ल्ले से की जा रही है इस पर रोक लगायी जानी चाहिए क्योंकि बच्चों के भविष्य का प्रश्न है यदि नकल से बच्चे पास होते हैं तो कहीं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में उन्हें एडमीशन नहीं मिलता, पता नहीं क्यों अगर आप यू0पी0 से 12वीं पास करके गये हैं तो लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है...

(इस समय 06 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

माध्यमिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बच्चे के जीवन को स्थापित करने की शिक्षा है इसे गम्भीरता से लेना चाहिए। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

अध्यक्ष जी मैं अपनी बात को अपने क्रम में ही आगे बोलता हूं कि जो योजनागत व्यय में और क्रमशः माननीय मंत्री जी ने 80 अरब रुपए से ऊपर और 21 अरब रुपए आयोजनेत्तर व्यय में लगभग 13 और 37 प्रतिशत की जो वृद्धि की है यह स्वतः ही अपने आप प्रतीत करता है कि वह माध्यमिक शिक्षा में बेहतर बजट और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित हैं। मान्यवर, क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल योजना बहुत ही शानदार है मान्यवर, मैं भी माध्यमिक शिक्षक रहा हूं मैं इलाहाबाद के मोतिहां इण्टर कालेज में जो हंडिया तहसील में है वहां पर मैं जायोग्राफी का टीचर था मैं आग्रह करता हूं माननीय मंत्री जी से कि पब्लिक इण्टर कालेज मोतिहां इलाहाबाद को इस क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल योजना में ले लें । और वहां पर 50 लाख की लागत से मान्यवर मैं आपका

विधायक हूं आपका साथी सदस्य हूं अगर आप पब्लिक इण्टर कालेज मोतिहां को इस योजना से पोषित कर देंगे तो यह बहुत बड़ा उदाहरण होगा इस हेतु मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मान्यवर, 300 करोड़ रुपए मेधावी छात्राओं को कन्या विद्या धन के रुप में दे रहे हैं मेधावी छात्राओं के लिए यह भी माध्यमिक शिक्षा को सुधार करने में एक बेहतर कदम होगा। 100 करोड़ की लैपटाप योजना के माध्यम से आप माध्यमिक शिक्षा को और बच्चों को बेहतर रिजल्ट और अच्छी शिक्षा प्रेरित करने के लिए उनके लिए लैप टाप योजना चला रहे हैं यह भी एक अच्छा कदम होगा मान्यवर, तीन सैनिक स्कूल की आपने अपनी योजना में व्यवस्था की है इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। सबसे बड़ी चीज जो आपने माध्यमिक स्कूलों में जूडो कराटे को आवश्यक किया है यह एक बहुत बड़ा कदम है। इजराइल जैसे तमाम विकसित देश हैं जहां पर जूडो कराटे कम्पल्सरी होता है आपने उत्तर प्रदेश में इसको अनिवार्य रूप से शुरू करके एक सराहनीय काम किया है। मान्यवर, मैं आपको और अपनी सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे सोरांव विधान सभा में लगभग करोड़ों की लागत से एक माडल स्कूल कमलानगर बनकर तैयार हो गया है और माननीय मुख्य मंत्री जी सहित हमारे द्वारा उसका उद्घाटन भी कर दिया गया है निवेदन है कि इसी सत्र से अगर उसका परिचालन शुरू हो जाता है तो यह हमारी विधान सभा सोरांव के लिए बहुत ही बेहतर होगा। सोरांव और मऊ आइमा दो ब्लाक अपोषित हैं वहां के लिए माडल स्कूल के प्रपोजल जा चुके हैं अगर उसको भी संज्ञान में लेकर अगर उसको भी धन आवंटित कर दें, तो सोरांव और मऊ आइमा में भी माडल स्कूल स्थापित हो जाएंगे। मान्यवर, सोरांव में हमारी विधान सभा के अन्तर्गत तीन ब्लाक हैं बहरिया, मऊ आइमा और सोरांव इन तीनों गंगा पार के इलाके में एक भी जगह राजकीय कन्या इण्टर कालेज नहीं है मैं आपसे आग्रह करता हूं गंगा पार खासकर सोरावं विधान सभा में राजकीय कन्या इण्टर कालेज के लिए कोई प्रयास हो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं अन्त में मैं माध्यमिक शिक्षा के बजट पर उसकी भूरि–भूरि प्रसंशा करते हुए आपकी बात का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद ।

'श्री सुरेश बंसल–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे माध्यमिक शिक्षा विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं अपने आप को नीरज मौर्य से सम्बंधित करते हुए सरकार को इस शिक्षा के विषय में दो सुझाव देना चाहता हूं। सरकार के जो आंकड़े हैं उसमें राजकीय सहायता प्राप्त व अशाासकीय उच्तर माध्यमिक विद्यालय जो आपने अपने प्रदेश में बताए हैं छात्रों के लिए 17, 578 हैं और छात्राओं के लिए 5172 हैं अध्यक्ष जी हम समाज में नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और चाहते हैं कि उनको बराबरी का दर्जा मिले जब यह विद्यालय ही नहीं होंगे तो हमारी बेटियां शिक्षा कहां से प्राप्त करेंगी सरकार से अनुरोध करूंगा कि बेटियों के लिए माध्यमिक विद्यालय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अवश्य बढ़ाए जाएं। वहीं से हमारी बेटियां उच्च शिक्षा के बाद इंजीनियर डाक्टर सी0ए0 वगैरह बन सकती हैं। इसी प्रकार जो सरकार ने आंकड़े दिए हैं कि पिछले वर्ष एक करोड़ छत्तीस लाख तिरपन हजार दो सौ पचास छात्र छात्राएं इन्हीं स्कूलों में पढ़ीं अध्यक्ष जी संख्या में इससे कई गुना छात्र हैं जो इन स्कूलों में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। वह प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, जो कि सी0बी0एस0ई0 से संबंधित हैं और वह अपनी मनमानी करते हैं। कोई भी गरीब व्यक्ति जिसकी आय 10 हजार रुपये माह तक हो वह इनमें अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। एडमिशन के नाम पर, किताबों के नाम पर, ड्रेस के नाम पर बहुत पैसा लेते हैं और प्रत्येक वर्ष शहरों में आन्दोलन होते हैं। यह 50–50 प्रतिशत तक फीस में वृद्धि करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि कोई ऐसी गाइड लाइन जरूर तय की जाय कि आप एक वर्ष में इससे ज्यादा फीस नहीं बढ़ायेंगे। इसी के साथ–साथ जब यह आपके आदेश हैं कि इसमें गरीब बच्चों के लिये कुछ परसेन्टेज होना चाहिए। जब उनसे कहते हैं, हम भी यदि कहते हैं कि इनका एडमीशन करो तो कहते हैं कि एडमिशन पूरे हो चुके। इसके साथ–साथ अध्यक्ष जी, सरकार ने वर्ष 2014–2015 में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के लिये 1675 लाख रूपये का प्राविधान किया था परन्तु अब तक सिर्फ 298.79 कुल की स्वीकृति मिली है। मेरा आपसे कहना है कि मैं गाजियाबाद से आता हूं और मेरे क्षेत्र में एक विजयनगर क्षेत्र ऐसा है जिसकी आबादी 7–8 लाख के करीब है और वहां सब गरीब लोग रहते हैं और वह ऐसा क्षेत्र है जिसके एन0एच0 24 इधर है और उधर की तरफ नोएडा है। परन्तु उसमें छात्रों के लिये कोई भी न तो हाई स्कूल है, न इन्टर कालेज है सिर्फ सबको सी0बी0एस0ई0 में जाना पड़ता है। जो गरीब लोग हैं वह पैसे के अभाव में उनमें शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। मैं अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन करूंगा कि गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र में कम से कम एक इन्टर कालेज छात्रों के लिये जरूर दिया जाय। इसके साथ–साथ गाजियाबाद के केलाभट्टा में, जो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है, जिसकी आबादी लाखों में है उसमें एक जूनियर हाई स्कूल है, उसके पास 10 हजार से भी ज्यादा अधिक जगह है परन्तु शिक्षा का कोई भी प्रबन्ध नहीं है। यदि अध्यक्ष जी वहां पर एक इंटर कालेज या हाई स्कूल बना दिया जाय तो अल्पसंख्यक समाज के बच्चे उसमें शिक्षा प्राप्त कर सकेंगें। इन्हीं के लिये आपको धन्यवाद देता हूं और सरकार से भी कहना चाहता हूं कि मेरे सुझावों को जरूर सम्मिलित कर लें।

श्री हेमराज वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने माध्यमिक शिक्षा के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत–बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वास्तव में बहुत ही सराहनीय बजट है और इस बजट से हमारे प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा और सुदृढ़ होगी और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रदेश और आगे बढ़ेगा और माध्यमिक स्तर के जो हमारे बच्चे हैं, बालक बालिकाएं हैं उनको एक बेहतर शिक्षा और बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान होगी। माननीय मंत्री जी ने बजट में जो–जो प्राविधान किये हैं जैसे क्लीन स्कूल, ग्रीन स्कूल वास्तव में इस योजना से हमारे

प्रदेश के विद्यालयों में पर्यावरण के प्रति एक अच्छी सोच हमारे बालक बालिकाओं में विकसित होगी और पर्यावरण के प्रति उनमें जो सोच होनी चाहिए और जिस तरह से अपने प्रदेश को स्वच्छ बनाना है, इस विषय में, इस क्षेत्र में काफी उससे बल मिलेगा। माननीय मंत्री जी ने बालिकाओं को जूडो कराटे सिखाने की जो व्यवस्था की बात कही है, वास्तव में इससे हमारी बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान होगी, वह आत्म निर्भर बन पायेंगी और उन के सामने कोई मुसीबत खड़ी होगी तो ऐसी कठिन परिस्थिति में वह डटकर मुकाबला कर पाने में सक्षम होंगीं। माननीय मंत्री जी ने बालिका छात्रावास योजना का जो जिक्र किया है उससे निश्चित तौर पर इस बालिका छात्रावास योजना में जब छात्रावास होंगें तो हमारे प्रदेश की जो बालिकाएं हैं उनकी सुरक्षा में और मजबूती आयेगी और माननीय मंत्री जी ने जो मॉडल स्कूल का प्राविधान किया है, वास्तव में मॉडल स्कूल मैं तो चाहता हूं कि प्रत्येक ब्लाक में कई कई मॉडल स्कूल बनें लेकिन जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने शुरूआत की है और मॉडल स्कूल हमारे प्रदेश में बन रहे हैं निश्चित तौर से इससे शिक्षा में और गुणवत्ता आएगी। मा0 मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वास्तव में यह बहुत ही सराहनीय बजट है मैं कुछ सुझाव इसमें जोड़ना चाहता हूं जैसे कि हमारा जो पाठ्यक्रम है माध्यमिक शिक्षा का और वास्तव में यह हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट के जो छात्र छात्रायें होते हैं यही समय होता है उनका लक्ष्य निर्धारित करने का। एक अच्छी सोच विकसित करने का, यह अच्छा समय होता है,मैंने देखा है कि हमारे प्रदेश में, प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में जो हमारे पूर्वज जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया या आजादी के पहले का जो हमारे देश का इतिहास रहा है कहीं न कहीं उसमें हमारे देश के प्रदेश के बच्चे समझने में जानने में पीछे रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से, कि हमारे देश का जो गौरवमयी इतिहास है जो अंग्रेजों की गुलामी से पहले का, हजारों वर्षों का, उस इतिहास को एक मजबूती के साथ हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए और हमारे प्रदेश के बच्चों को जानकारी होनी चाहिए।कि हमारा देश हजारों साल तक शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक सम्पन्नता और व्यापार के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे रहा है। हमने पूरी दुनिया को बहुत सी चीजें कृषि करना हम लोगों ने सिखाया है, व्यवसाय करना हम लोगों ने सिखाया है यह सारी चीजें जो हैं इनका बहुत मजबूती से हमारे इतिहास में इसका समावेश होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री हेमराज वर्मा–

मैं आधे मिनट में समाप्त करूंगा। मान्यवर हमारे जनपद पीलीभीत में, हमारा जनपद कृषि उत्पादन के क्षेत्र में बहुत अग्रणी जनपद है। हमारे जनपद में जरूरत है कृषि विज्ञान से माध्यमिक स्कूल खोलने की। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जनपद में भी और अन्य जनपदों में भी कृषि विज्ञान से इण्टर कालेज खोले जाएं। माननीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं जिस तरह से हमारे मा0 मंत्री जी ने बजट पेश किया है वास्तव में बहुत सराहनीय बजट है। निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश के

बच्चे माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत–बहुत धन्यवाद्।

'श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय मौर्य जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया बहुत धन्यवाद्। माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने काफी बातें बताई उसमें चाहे जूडो कराटे हो चाहे महामहिम राज्यपाल और मा0 मुख्य मंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पॉच साल के विस्तार की बात हो, हालांकि यह विषय नहीं है लेकिन हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जिस तरह चार लाख लोगों की भर्ती कराने में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास किया है। उसी तरह माध्यमिक शिक्षा में पिछले दस–बारह वर्षों से अध्यापकों की भर्ती की जो गति है वह चींटी की तरह है और वहां छात्र संख्या बहुत अच्छी है लेकिन वहां पर अध्यापक नहीं हैं उस पर सरकार कतई गम्भीर नहीं है, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि शिक्षकों की भर्ती पर जोर दे। दूसरा मा0 अध्यक्ष जी हम सब लोग कहते हैं आधी से ज्यादा आबादी पुरुषों की है 51 परसेन्ट, 49 परसेन्ट आबादी के बारे में हमारी सरकार की नीयत अच्छी हो सकती है लेकिन उसका खाका बनाने का काम सरकार ने नहीं किया है आज हमारी बहनों के लिए लड़कियों के लिए जो स्कूलों की संख्या है पिछले बीस वर्ष में मॉडल स्कूल प्राइवेट सेक्टर में, या माण्टेसरी स्कूल या सी0बी0एस0ई0 के स्कूल बहुत खुले हैं लेकिन सरकार द्वारा प्रोत्साहन देकर लड़कियों के स्कूल खोलने की पहल नहीं की गई है।

मा0 अध्यक्ष जी, 49 परसेन्ट आबादी के लिये स्कूलों की जो व्यवस्था है चाहे वह माईनॉरिटी के लोगों की संस्थायें हों, चाहे दलितों की संस्थायें हों, चाहे वह दूसरे लोगों की संस्थायें हों, जो लोग लड़कियों के डिग्री कॉलेज खोलना चाहते हैं उसके विषय में सरकार का प्रचार और प्रसार बहुत धीमा है।

श्री अध्यक्ष–

यह उच्च शिक्षा नहीं है, माध्यमिक शिक्षा है।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहा हूं। मैं इण्टर कॉलेज की बात कर रहा हूं। माध्यमिक शिक्षा में ही इण्टर कॉलेज आते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप डिग्री कॉलेज कह रहे थे।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

मान्यवर, लड़कियों का इण्टर कॉलेज खोलने के संबंध में सरकार ज्यादा संवेदनशील नहीं है। शिक्षा ऐसी बड़ी धरोहर है। इससे ही जात–पात और धर्म से ऊपर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उठकर आदमी अपने रसूखात और अपने व्यापार की तरफ जाता है। अभी हमारी मा0 सदस्या बिमला सिंह सोलंकी जी ने कहा, इससे ही यह होता है कि इण्टर करने के बाद मुझे बी0ए0 और एम0ए0 करना है या बी0टेक0, एम0टेक0 या एम0बी0ए0 करना है। मेरा कहना है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम दिल्ली के स्कूलों में जाते हैं तो वाकई में यह अच्छी बात है कि हमारा यू0पी0 बोर्ड, इलाहाबाद दुनिया में सबसे बड़ा बोर्ड है, लेकिन इसकी परसेंटेज जब 65 आती है तो हम दिल्ली और एन0सी0आर0 के स्कूलों में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। उसके लिये मेरा आग्रह है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में बी0टेक0, एम0टेक0 या एल0एल0बी0 की वह संस्थायें हैं उसमें हमारे जो लोग माध्यमिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों में पढ़ेंगे उन्हें कोई परसेंट 5 परसेंट या इस तरह की या इनमें पढ़ने वाले बच्चों को इंटरव्यू या सर्विस में आप इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि उनको पांच मार्क्स अलग से दिये जायेंगे तो इनमें ज्यादा लोग रूचि दिखायेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, सरकार ने एस0सी0, ओ0बी0सी0 और माईनॉरिटी के छात्रों की जो छात्रवृत्ति इण्टर कॉलेजों में खत्म कर दी है और लोग सी0बी0एस0ई0 की तरफ भाग रहे हैं। अभी हमारे एक मा0 सदस्य ने कहा जिसे मा0 मंत्री जी ने इग्नोर कर दिया कि वह हमारे छोटे भाई हैं। सी0बी0एस0ई0 का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वह हमारे यहां खत्म होता जा रहा है। मा0 नीरज कुशवाहा साहब ने यह बात कही कि बेसिक शिक्षा की तरह खण्ड स्तर पर भी एक अधिकारी की व्यवस्था यदि आप करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार में मान्यताओं के नाम पर लूट का काम नहीं हुआ, हालांकि मेरी बात मा0 मौर्य जी को बुरी न लगे। (सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूं कि तत्कालीन सरकार में सब्जेक्ट की मान्यता, कक्ष की मान्यता, कक्ष की बढ़ोत्तरी, जिस तरह क्षेत्रीय कार्यालयों में लूट के अड्डे बने, वह इस सरकार में और इन मंत्री के कार्यकाल में नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

मा0 अध्यक्ष जी, जहां तक नकल की बात है, मैं पिछले एक महीने से देख रहा हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 मंत्री जी की तरफ से नकल की बदनामी को दूर करने के लिये बहुत प्रयास हुये और सरकार इसमें सफल भी हुयी है, लेकिन उतनी सफल नहीं हुयी है जितना होना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये, आपका समाय समाप्त हो गया है।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, आपने मुझे माध्यमिक शिक्षा के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं और अपने आप को अपने साथी मा0 सदस्य श्री नीरज कुशवाहा जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए मा0 मंत्री जी को दो

सुझाव देना चाहूंगा। मान्यवर, वैसे तो सबको शिक्षा मिले यह दायित्व सरकार का बनता है, लेकिन संसाधन के अभाव में सरकार प्रदेश के छात्र–छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में वित्त विहीन विद्यालय जो अपने निजी संसाधनों से चलते हैं वह शायद सरकार के दायित्व को पूरा करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन वित्त विहीन विद्यालयों में जो अध्यापक कार्य कर रहे हैं उनके बारे में आज तक न तो किसी सरकार ने सोचा है और वहां का जो प्रबन्ध तंत्र होता है वह उनका शोषण करता है। उनको मात्र दो–ढाई हजार रुपये देकर उनसे पूरा महीना कार्य लिया जाता है उनसे पढ़वाने का काम करते हैं, वहीं हमारे जो इण्टर कॉलेज चलते हैं उनमें सरकार 60 हजार, 80 हजार और 01 लाख रुपये तनख्वाह देकर उनसे काम लेती है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सरकार के घोषणा–पत्र में भी था कि मान्यता प्राप्त वित्तविहीन जो माध्यमिक विद्यालय हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं, हम उनको एक निश्चित मानदेय देने का काम करेंगे लेकिन सरकार ने अभी तक इस घोषणा को अमलीजामा पहनाने का काम नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन वित्तविहीन विद्यालयों में अध्यापक कार्य कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वह अपने बच्चों को पढ़ाने में भी असमर्थ हैं। इसलिए इन विद्यालयों के अध्यापकों को एक निश्चित वेतनमान देने का काम सरकार करे, ऐसा मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। मान्यवर, अभी जैसे सरकार ने नया सत्र अप्रैल से आहूत किया है, उसके कारण एक विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है, पहले सत्र जुलाई से होता था तो गत सत्र में स्कूलों ने जुलाई से फीस लिया था और अब सत्र को पूरा करने के लिए वह जून तक की फीस ले रहे हैं। अगला सत्र अप्रैल से शुरू हो रहा है तो अब अप्रैल से फिर फीस मांगी जा रही है तो अभिभावकों और प्रबन्ध–तन्त्र के सामने यह विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है कि हम तीन महीने की एक्स्ट्रा फीस क्यों दें? पहला सत्र जो था वह जुलाई से जून तक का था, उसके हिसाब से वह जून तक की फीस ले रहे हैं तो सरकार इसको भी स्पष्ट करे कि वह फीस कब से ली जायेगी ? मान्यवर, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मा0 माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी के बजट पर बोलने का हमको मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं इस बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। हमारे तमाम नेताओं ने माध्यमिक शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा तथा अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का विवरण यहां दिया। मैं सदन में बताना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा का गार्जियन, परिवार अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना समय देता है और इंग्लिश मीडियम का गार्जियन अपने बच्चे को कितना समय देता है ? उसका होमवर्क कौन कराता है, उसका बाप कराता है, उसके ऊपर ट्यूशन लगता है लेकिन हमारे यहां माध्यमिक शिक्षा में जो लड़के पढ़ते हैं, न तो उसका गार्जियन पढ़ाता है और न उसको कोई ट्यूशन मिलता है।

तब भी हमारी माध्यमिक शिक्षा बहुत अच्छी है। हम इसलिए कहना चाहते हैं कि हम लोग प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा के हैं। आज आप किसी भी अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में जाइये, पहले उनको डोनेशन दीजिए, एडमिशन कराने के नाम पर उनको पंखा दीजिए, उनको पैसा दीजिए, परन्तु हमारे माध्यमिक शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं है। मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अब अपने क्षेत्र की कुछ बातों को माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में कुंवर पटी जी0जी0आई0सी0 कालेज है, जिसकी बाउन्ड्रियां नहीं हैं और उसमें अध्यापकों की कमी है, मैं मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इन विद्यालयों में बाउन्ड्री की कमी है। हमारे क्षेत्र में सुरवां दलापुर इण्टर कालेज, जी0आई0सी0 है, जिसमें 1700 बच्चे हैं। वहां के अध्यापक दूसरी जगह पर अटैच हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि उन अध्यापकों को हमारे सुरवां दलापुर स्कूल में पुनः वापस कर दें। इसी तरह से मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी टाउन एरिया है, वह मुस्लिम बाहुल्य टाउन एरिया है, उसमें एक भी लड़कियों का इण्टर कालेज नहीं है, उसमें भी एक कन्या इण्टर कालेज की स्थापना के लिए आपके माध्यम से मांग करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

'श्री विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं इस बजट के विरोध में और नीरज जी के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष जी, प्राथमिक शिक्षा एक बीज की तरह होती है, जमीन में डालने के बाद, पानी में डालने के बाद सभी अनुकूल परिस्थितियों के बाद वह एक पौधे का स्वरूप लेती है और माध्यमिक शिक्षा तक आते–आते वह एक ऐसी स्थिति तक पहुंच जाती है, कबीर जी की एक लाइन है, पूरा दोहा तो नहीं कहूंगा, समय बचाने के लिए कि 'रसरी आवत–जात ते, सिल पर परत निशान।', एक ऐसी व्यवस्था में मस्तिष्क पहुंच जाता है, वैज्ञानिक तौर पर भी जब बच्चा सब कुछ ग्राह्य करने के लिए, उसका मस्तिष्क तैयार हो जाता है। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, मैं सुझाव के साथ कहना चाहूंगा मंत्री जी। मंत्री जी देख लें इस तरफ तो हमें भी बड़ी सांत्वना मिले। बैंकिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नित नए आयाम बढ़ रहे हैं। हम लोग जानते हैं देश में एक बड़ी पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी चल रही है। इसको समाप्त करने के प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर हों प्रादेशिक स्तर पर भी हो रहे हैं और भी व्यवस्थाएं इसके लिए बन रही हैं। बैंकिंग की व्यवस्था में नए–नए कानून बनते जा रहे हैं और जो नए–नए कानून बन रहे हैं ये बहुत बाद में आकर ग्रेजुऐशन के बाद और उसके बाद जब बैंकों से हमारा पाला पड़ता है मुझे लगता है हम सब इसके भुगतभोगी रहे होंगे कि तब जा कर हम लोगों को बैंकिंग कैसे होती है बैंकिंग के कानून क्या हैं बैंकिंग से कैसे पैसा निकाला जाता है क्या–क्या योजनाएं बैंक की होती हैं इसके विषय में तब जानकारी मिल पाती है। मेरा यह निवेदन मंत्री जी से मान्यवर आपके माध्यम से है कि एक नये करिकुलम पर शोध चल रहा है वह पाठ्यक्रम लागू करने की योजना है। इस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर भी यदि शोध हो तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग की व्यवस्था को छोटे बच्चों को यदि समझाकर कि किस तरह बैंकों से जुड़कर और उनके कानूनों का पालन करते हुए आपको आगे बढ़ना है तो मैं समझता हूं एक और विधा उनके गुणों के साथ उनको मिलेगी जो बड़ी आसानी से उनको दी जा सकती है। इसके लिए कोई रेगुलर कोर्स चलाने की भी जरूरत नहीं है। एक महीने दो महीने का क्रैश कोर्स इसके लिए इनफ है। इसके अलावा लीगल पर मेरा दूसरा सुझाव है। एक समय था जब यह पढ़ा दिया जाता था कि लाल बत्ती आएगी तो खड़े हो जाना है पीली आएगी तो रूकना है हरी आएगी तो चलना है। कानून व्यवस्था अब इससे कहीं ज्यादा बड़ी हो गई है। लोकतंत्र में सी0आर0पी0सी0 और आई0पी0सी0 एक महत्वपूर्ण चीज हो गए हैं। शायद कानून की गैर जानकारी के कारण एक अनऑफिशयल सर्वे आया है कि 15 से 18 प्रतिशत लोग कानून की जानकारी के अभाव में गलतियां करते हैं। यदि बच्चों के अंदर कानून की जानकारी हम अभी से देने लगें तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में 12वीं के पश्चात ग्रेजुएशन के पश्चात वह इस तरह की गलतियां करने से बच जाएं। यह दो मेरे सुझाव हैं।

श्री अध्यक्ष–

बस बहुत हो गया अब समाप्त करें।

श्री विक्रम सिंह–

मान्यवर, इसी से जुड़े दो और विषय हैं। कोई विषय अलग नहीं है और बहुत जल्दी–जल्दी खत्म कर देंगे। कम्प्यूटर की जो व्यवस्था है कई लोगों ने कहा एक बहुत बड़ा देश में डिजीटल डिवाइड पैदा हो रहा है। हम ग्रामीण और अरबन व्यवस्था की बात करते हैं नगरीय व्यवस्था की बात करते हैं, आर्थिक पक्ष में भी एक बहुत बड़ा डिवाइड हो रहा है लेकिन जब शैक्षणिक पक्ष में यह चला जायेगा तो यह समाज में कई पीढ़ियों तक चला जायेगा। इस डिजीटल डिवाइड को खत्म करने के लिए क्योंकि आप लोग पहले ही 15 लाख लैपटाप बांट चुके हैं और उससे क्या लाभ या हानि हुई है उसका ऐसेसमेण्ट आप लोग कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में लैपटाप बांटने की जगह यदि हर स्कूल को एक कंप्यूटर देकर बच्चों को मामूली शिक्षा भी यदि दे दी जाएं तो लिटरेसी का मतलब क ख ग सिखाना नहीं रह गया है आने वाले समय में बीस, पच्चीस वर्षों के बाद, पंद्रह वर्षों के बाद उस कौम को तैयार कर रहे हैं। वह कौम जब बारह वर्षों के बाद निकलेगी उस समय दुनिया के अंदर कंप्यूटर के हिसाब से लड़ना पड़ेगा। कंप्यूटर यदि शिक्षा का अभिन्न अंग नहीं बनेगा तो आपके शिक्षण पद्धति मात्र पर उंगली उठेगी। मैं समझता हूं कि हर स्कूल में माध्यमिक स्कूल में लैब होने चाहिए और कम से कम प्राथमिक स्कूल में एक कंप्यूटर भी यदि हो जायेगा सोलर के साथ जो आप लगा रहे हैं तो आपके बच्चों को उसका लाभ मिलेगा। आधुनिकता का प्रार्दुभाव हो रहा है। पाश्चात्य तरीके से बहुत सारी विधाएं हमारे देश के अंदर टेलीविजन, मैगजीन और पढ़ाई के माध्यम से आ रही हैं। नेट हमारे पास उपलब्ध हो गया है। इस दुष्प्रभाव के कारण सबसे ज्यादा वही वर्ग दुष्प्रभावित है जिसकी हम सब चिन्ता करते हैं वह गरीब वर्ग है,

बेसहारा वर्ग है गांव में रहने वाला ग्रामीण वर्ग है उसके बच्चे हैं क्योंकि ज्ञान के प्रति उनके नए–नए द्वार खुलते हैं और ज्ञान के प्रति जब द्वार खुलता है तो अज्ञानता और ज्ञान के बीच की धारा वह समझ नहीं पाते हैं। नशा और मूल्य इन दोनों की शिक्षा होना माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर बड़ा आवश्यक है। नशे के खिलाफ जरूर होना चाहिए। सामाजिकता का मंत्री जी ने कहा कि हम पेड़ लगवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त कर दें अब पाठ्यक्रम बन गया है।

श्री विक्रम सिंह–

मान्यवर खेल की तरह आगे चलकर वह इस विषय में कुछ करने लगेंगे। यह विषय उनके जींस में चला जायेगा जिससे हम पिछले कुछ वर्षों से दूर हो गए हैं। धन्यवाद।

और इससे हम लोग जुड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री विक्रम सिंह–

इसी के साथ मैं कटौती पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

'श्री गुलाम मौहम्मद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बजट में जितने भी प्रोवीजन किये गये हैं वह माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए किये गये हैं। चाहे मॉडल स्कूलों की स्थापना हो चाहे असेवित ब्लाक में कन्या कालेजों की स्थापना हो और यहां तक कि न्याय पंचायत स्तर पर भी कन्या विद्यालय की स्थापना बालिकाओं के लिए छात्रावास की योजना और इसी तरह से हर मामले में बजट को आगे बढ़ाया गया है और शिक्षा में सुधार के लिए काम किया गया है। सच्चाई अगर हम स्वीकारें तो हालात यह हैं कि जो राजकीय विद्यालय हमारे सबसे अच्छे विद्यालय हुआ करते थे। जमाने की करवट के हिसाब से देखा जाये तो आज इंगलिश मीडियम के नाम पर छोटी–छोटी दुकानें खुली हैं और जूनियर क्लासेस में हमारे बच्चे उन्हीं मोहल्लों में छोटी–छोटी दुकानों में रुक जाते हैं। वह बहुत ही अच्छी यूनिफार्म, इंगलिश मीडियम के नाम पर बच्चों को वह वहां रोक लेते हैं और माध्यमिक विद्यालयों का चलना दूभर हो गया है। जब राजकीय विद्यालयों का जिक्र किया गया तो यह सच्चाई है कि हमारे यही माध्यमिक विद्यालय सबसे अच्छे विद्यालय हुआ करते थे लेकिन आज जगह–जगह पर कान्वेट्स कालेज खुल गये हैं। आज सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं फिर भी यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहना चाहता हूं कि यही वह विद्यालय हैं जिनमें हमारे गरीब बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं। अगर हमारे इन विद्यालयों का वजूद खत्म हो जाये तो हमारे उस सर्वहारा के लिए शिक्षा की कोई जगह न बचे। इतनी महंगी शिक्षा हो गयी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी हमारे यही विद्यालय सबसे अच्छे विद्यालय हैं यहां से काबिल लोग निकलते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री गुलाम मौहम्मद–

माननीय अध्यक्ष जी, बस एक–दो सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। माध्यमिक शिक्षा में उर्दू भाषा के लिए भी कहा गया है। मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो त्रिभाषा फार्मूला हमारा अब तक लागू है और उर्दू के विकास के लिए एक निदेशालय और निदेशक होता है। तो जो कालेज हैं जहां उर्दू पढ़ने वाले बच्चे इण्टरमीडिएट कालेज में हों वहां उर्दू शिक्षकों का इंतजाम किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री गुलाम मौहम्मद–

मान्यवर, हमारे देहात के जो विद्यालय हैं वहां बड़ी दिक्कत यह आती है कि न वहां पर कामर्स साइट है या सांइस है सिर्फ आर्ट साइट को लेकर बच्चे पढ़ रहे हैं। चाहे कानूनों को शिथिल करना पड़े उन विद्यालयों में किसी तरह से भी करना पड़े वहां कामर्स और साइंस के विषय को भी इन्ट्रोड्यूज किया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। शुक्रिया।

श्री राजेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से आपका संज्ञान चाहूंगा। आपने एक बात रखी कि एक करोड़ 36 लाख परीक्षार्थी दुनिया के सबसे बड़े इस बोर्ड में आप दे रहे हैं। इस बात से आप भी वाकिफ हैं कि एक करोड़ 36 लाख पंजीकृत हैं परीक्षा तो दे रहे हैं लेकिन यह एक करोड़ 36 लाख आपके विद्यालयों में पढ़ते नहीं हैं। छोटे–छोटे कोचिंग सेन्टर खुले हैं, छोटे–छोटे उन्होनें अपने सेन्टर्स बनाये हैं, वह आपके यहां पंजीकृत करा देते हैं, उस पंजीयन से आपकी संख्या बढ़ तो जाती है। दुनिया के सबसे बड़े बोर्ड आप हो जाते हैं तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जो मानक है, वह उचित ही होगा मैं यह नहीं कहता इन लोगों ने मानक बनाया होगा तो उचित ही बनाया होगा मगर आज की जो परिस्थिति है, आपने समय बदला है सारी चीजें बदली हैं तो क्या मानकों में थोड़ी ढ़ील देंगे कि यह जो विद्यालय हैं जो विभिन्न कुछ कर्जों को लेकर चलाते हैं और आपके यहां पंजीकृत कराकर सर्टिफिकेट आपका लेते हैं, विद्यालय वह चलाते हैं। कम डिग्री वाले

शिक्षकों को रख लेते हैं। मैं यह चाहूंगा कि अगर आपकी सरकार इस मानक में थोड़ी ढील करे तो कम से कम अन्य छोटी जगह के छोटे स्कूलों को मान्यता आप दे लें तो वो विद्यालय भी पात्र होंगे और वह परीक्षा दे सकेंगे और पढ़ाई करा सकेंगें। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर अवश्य विचार करे। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आपने समूह 'ग' की भर्तियां जो सरकार ने खोली हैं, अभी यह पता चला है कि समूह 'ग' की भर्तियां अन्य विभाग की खुली हैं, माध्यमिक शिक्षा के समूह 'ग' की भर्तियों पर रोक अभी भी जारी है। स्वाभाविक है कि जो अनुदानित विद्यालय हैं वह प्रभावित हो रहे हैं, उनका यह है कि जब सरकार नहीं खोल रही है तो तमाम ऐसे अनुदानित विद्यालय हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके कार्यालय प्रभावित हो रहे हैं तो क्या अन्य जैसे शिक्षक की भर्ती आपने खोल दिये हैं, राजकीय का आपने खोल दिया है तो क्या अनुदानित विद्यालयों पर भी आप जो समूह 'ग' की भर्ती पर पिछले 03 साल से रोक लगी है, उसे खोल देंगे ? उससे तमाम विद्यालयों का भला हो जायेगा, तमाम बेरोजगार नौजवानों का भला होगा। मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी ? आखिरी बात मैं माननीय पण्डित सिंह जी को माननीय मंत्री जी को केवल याद दिलाना चाहता हूं कि जब वह चुल्लूपाल की धरती पर गये थे, एक माडल स्कूल की घोषणा करके आये थे। जमीन का प्रस्ताव ग्राम पंचायत में भिजवा दिया है। आपके इस वायदे को याद दिलाना चाहता हूं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय मंत्री जी के बजट पर जो मैंने कटौती प्रस्ताव रखा, उस पर बल देता हूं और माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो अभी कन्या विद्या धन या हमारी सरकार द्वारा चलाई गयी सावित्री बाई फूले शिक्षा मदद योजना चलाई जा रही थी, उसे पुनः जरूर चलाये जाने का कार्य करें क्योंकि आज बच्चियों की शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है और उनको जो सुविधायें दी जा रही थी उससे हमारे ग्रामीण परिवार की जो बच्चियां है वह अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकेंगी और साथ ही साथ जो वित्त विहीन विद्यालय चल रहे हैं वित्त विहीन विद्यालय के लोगों को मानदेय देने की बात भी सरकार की तरफ से कही गयी थी लेकिन जो बजट आया है इसमें कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको लागू कराने का काम करें और जो तमाम हमारे विपक्ष के साथियों ने सत्ता पक्ष के साथियों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दियें उनको भी सम्मिलित करने का काम करें जिससे कि जो मंत्री जी की मंशा है कि माध्यमिक शिक्षा को अच्छा करना चाहते हैं, उसे ऊपर ले जाना चाहते हैं और जो उन्होनें अपने भाषण में कहा कि भारत कभी विश्व गुरू होता था तो पुनः हमारा देश, हमारा प्रदेश विश्व गुरू बने, इस पहल में यहां से आज आगे बढ़ने की मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री महबूब अली–

मान्यवर, नीरज जी ने कुछ अच्छे प्रस्ताव रखे हैं और भी माननीय सदस्यों के द्वारा जो सुझाव आयें हैं, उन सुझाव को गम्भीरता से लेकर अगर कोई विधिक बाधा नहीं है तो उसका परीक्षण कराकर, कार्यवाही की जायेगी। जहां तक नीरज जी आपने दो

क्वेश्चेन किये हैं कि वित्त विहीन टीचर्स के मानदेय से सम्बन्धित, वित्त विहीन कालेजों, स्कूलों के जो टीचर्स हैं, उसके आंकड़े मंगवाये जा रहे हैं, इन्तजार करिये, हमारे वायदे में भी है, हमारे घोषणा–पत्र में भी है, उस पर कार्यवाही चल रही है। आपने दूसरी बात कही, सावित्री बाई फूले योजना, यह बात सही है कि हो सकता है आपके हिसाब से वह बहुत अच्छी योजना हो सकती है, लेकिन अगर कहीं मेरे अनुभव से पूछो तो आपको लगेगा कि ऐसा तो नहीं था, इधर के मा0 सदस्यों के द्वारा भी राय आई थी, सावित्री बाई फूले योजना के तहत साइकिलें आपने बांटी थीं, गांव नोट कर लीजिए, गांव है फतेहीखानशाह ब्लाक है जोया मेरे जनपद का नाम है अमरोहा, दो ऐसी बच्चियों को साइकिल दी गई थीं, जिनके खिलाफ एफ0आई0आर0 हुई थी और उनकी साइकिलें वापस कराई गईं, उनके पैसे वापस लिये गये, तो किसी एक बिरादरी के लिए योजना आपने चलाई, समाजवादी पार्टी एक बिरादरी के लिए नहीं पूरे समाज की हर गरीब की, पिछड़े की हर व्यक्ति की पार्टी है, इसलिए ऐसी योजनाएं अपने पास रखिये जो किसी एक जाति के लिए निकलती हों। जहां तक हमारे दूसरे बी0जे0पी0 के साथी ने कहा कि हर ब्लाक में हमारी बहन बोल रही थीं कि एक हमारा मॉडल कालेज हो, हमने ऐलान किया है, इस बजट में भी व्यवस्था है, लेकिन यह राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 680 ब्लाकों में है। मॉडल कालेज बना रहे हैं, लेकिन शायद हमें याद है और बहन को भी हम याद दिलायेंगे 05 सितम्बर, शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, हमारे देश में और शिक्षा दिवस के रूप में जब मनाया गया था, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से एक ऐलान हुआ कि हमें लाइट दिखाओ, हम बेपनाह खुश थे उस दिन कि आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कुछ मिलने वाला है, लेकिन उसी दिन हमने कहा था कि मैं हर हालात में अपनी बात भी कहूंगा, हां मैंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि हमारा आज का नौजवान कल का हिन्दुस्तान है, आज पढ़े और आगे बढ़े और दुनिया की बड़ी कुर्सियों पर पहुंचे, मैंने उस दिन कहा था, लेकिन उसी दिन मैंने भाषण से पहले यह कहा था कि उनकी मीठी बातें भी हम सुनवायेंगे, आपने कहा कि माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 903 ब्लाक हैं, ज्यादा नहीं है, यह सब में हो सकता था, जबकि हम पांच किमी0 पर उच्च माध्यमिक और सात किमी0 पर इण्टर कालेज हम कर रहे हैं, लेकिन उनका भाषण ज्यादा लम्बा नहीं है, मैं एक मिनट में करता हूं, वह भाषण था– ''भाइयों और बहनों जब हम पढ़ते थे, तो हम भी बहुत शरारती थे, जब दो बच्चे करीब से गुजरते थे, उन पर हम स्टेपलर लगा दिया करते थे।'' क्या प्रधानमंत्री जी, बतेरा हो गया झूठ बोलकर कुर्सी हासिल कर ली, क्या उस वक्त स्टेपलर था, मैं भी पढ़ा हूं और मुझसे बड़े हैं प्रधानमंत्री जी, उस समय टिन की पिन आलपिन भी नहीं थी। हम चाहेंगे आप उनसे 903 ब्लाकों के लिए माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत घोषणा करा लें, तो अच्छा रहेगा। जहां तक आपने नकल की बात हमसे कही, आपने कहा कि ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन बच्चों में फर्जीवाड़ा होता है, हमने बच्चों के एडमीशन के लिए ऑन लाइन व्यवस्था की है, उससे छः लाख पचहत्तर हजार बच्चे हमारे कम हुए, उससे पारदर्शिता आई और ऑनलाइन के बाद जब हमने एक्जाम कराया, पुराने रिकार्ड आप उठा कर अपनी गवर्नमेण्ट के देख

लीजिएगा। आप बहुत कह रहे हैं, आप नकल याद कर लीजिये। हमारे काम करने की शैली, 2634 मान्यतायें और किस तरह से आपका था। आज जो पूरे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का जितना भी बजट है, वह हमने अपनी तरफ से सारे डी0एम0 को भेज दिया। मैंने कहा कि डी0एम0 कार्यदायी संस्था तय करे, गवर्नमेण्ट तय नहीं करेगी लेकिन आज जक तुमने जो किया उसमें लोग जेल में हैं। मैंने डी0एम्स को भेज दिया, मैं नहीं तय करूंगा। (विपक्ष से डर गये की आवाज) नहीं, डर नहीं गये, हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं पारदर्शिता क्या होती है। ऐसा नहीं है, हम किसी भी कीमत पर डरते नहीं हैं। हम जिन चीजों से नफरत करते हैं तो हम उन चीजों से दूर रहें इसलिये हमने सख्ती की और सख्ती करने के बाद रिजल्ट सामने आये। हम चाहते हैं कि आज का नौजवान जो किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहा था। नकल से किसी भी तरह से अगर कहीं कहीं, किसी भी परीक्षा में बैठता था बच्चा और उसमें नहीं आ पा रहा था इसलिये हमने इसे पूरे जोर से रोकने की कोशिश की जिसके परिणाम हैं, आप देख लीजिये।

(सदन में शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्यों से आग्रह है कि आप शोर न करिये। आप मा0 मंत्री जी का भाषण सुन लीजिये। मा0 मंत्री जी, आप भी संक्षेप करिये, आगे एक बजट और है।

श्री महबूब अली–

आप अपनी सरकार का एक प्रतिशत उठा लीजिये नकल के सम्बन्ध में। नकल के लिये 4 प्रतिशत बच्चों ने एग्जाम छोड़ा था। हमारी सरकार तीन साल से है पौने नौ प्रतिशत बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया 2012–13 में, 2013–14 में और 2014–15 में पता है 10.50 प्रतिशत बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया। 10.50 प्रतिशत बच्चों ने, पौने सात लाख बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया, सात लाख रजिस्ट्रेशन, यह है पारदर्शिता, इस तरह से है गुणवत्ता। हम करना चाहते हैं इसलिये हम कहना चाहते हैं कि कटौती वापस ले लीजिये और हम चाहते हैं कि इसे थोड़ा संशोधित कर दीजिये वापस न ले तो। अध्यक्ष जी, आप ही व्यवस्था कर दीजिये कि इसे घटाकर इतना बढ़ा दिया जाये तो हमें खुशी होगी कि तुम शिक्षा के हित में कुछ करना चाहते हो। अगर यह हो कि इसमें एक रुपया कम न करके एक सौ करोड़ रुपये और बढ़ा दिये जायें तब हमें खुशी होगी कि आप शिक्षा के हित में गम्भीर हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सभी सदस्यों से चाहे वह सत्ता पक्ष की तरफ से प्रस्ताव आये हैं, चाहे विपक्ष की तरफ से जो प्रस्ताव आये हैं। वे हमको दे दें उस पर हर कोशिश की जायेगी, हर कार्यवाही की जायेगी। यहां के बहुत साथियों ने कहा कि बजट में पिछली बार लैपटाप कहां चले गये थे तो हम कहना चाहेंगे कि पिछले 2014 में हम उन बच्चों को भी लैपटाप दे रहे हैं। हमारे पास कुल 33206 लैपटाप हमारे पास, हमारे गोदाम में सुरक्षित हैं। हम प्रदेश के बच्चों को दे रहे हैं और लगातार बॉट रहे हैं, पांच–सात जिलों में तो अभी बंट गये मा0 मुख्यमंत्री जी उसमें थे। इसलिये मैं पूरे सदन का शुक्रगुजार रहूंगा कि आज माध्यमिक शिक्षा का बजट जो

इतना गम्भीर है, बहुत गम्भीर है अगर आप इस तरह से शिक्षा के मामले में महसूस कर लें। ये कोई मजाक, हंसी, सत्ता या विपक्ष की बात नहीं है। अगर आप यकीनन शिक्षा के मामले में गम्भीर हैं तो पूरा सदन एकजुट होकर इसको पास करे। अगर आप में से बहुत से लोग यह महसूस करते हैं कि इसकी गुणवत्ता कैसे बढ़े, इसकी पारदर्शिता लायें तो कोई पुलिस नहीं, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं, सिर्फ अगर यह सारा सदन तय कर ले कि हमें गुणवत्ता लानी है, सुधार करना है तो ये सदन में ही बैठे हुये लोग गुणवत्ता सुधार देंगे क्योंकि इन्हीं के कालेज हैं। अपने आप नकल बन्द हो जायेगी, हम यह बात पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं। हम यह भी कहना चाहते हैं कि आने वाले तीन साल बाद यानी हमारी सरकार से 2017 तक बच्चा इण्टर करने के बाद जब वह बी0ए0 कर लेगा तो निश्चित ही आप मान लीजिये कि हमारा प्रतिशत चाहे आई0ए0एस0 में हो, चाहे आई0पी0एस0 में, आई0एफ0एस0 में हो, सिविल सर्विसेज में हो, आई0आई0टी0 में हो रिजल्ट में प्रतिशत निश्चित ही बढ़ जायेगा। जिस तरह से हम सब इसकी गुणवत्ता पर माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर काम कर रहे हैं। मैं पुनः आपसे सहयोग की उम्मीद करते हुये पूरे सदन से चाहूंगा कि इस बजट को सर्वसम्मति से, ध्वनिमत से पारित किया जाये।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने सदन में बात रखी है। मैंने अपने हाथों से आंकड़ों को, पिछड़ों को, दलितों को और मुसलमान भाइयों की बच्चियों को साइकिल और चेक देने का काम सावित्री बाई फूले योजना के तहत किया है और आप सरकार में बैठे हैं। आप वहां से रिकार्ड निकलवा लीजिये, सर्व समाज के लोगों को मिला है। मान्यवर, जिस तरह से माननीय मंत्री जी अभी आपने पूरे सदन में देखा कि जिस तरह से देश के प्रधान मंत्री जी ने हाथ चलाकर ख्ग ग ग, बोलकर सरकार बनाई और मंत्री भी उन्हीं पदचिन्हों पर चलने लगे और इन्होंने भी उसी तरह से लोगों को गुमराह करने का कमा किया। बहुजन समाज पार्टी से सर्वशिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विभाग का कोई भी मंत्री जेल नहीं गया, दूसरे मदों में जो गये थे, वह अब बरी हो गये हैं। आप इसे उठाकर देख लीजिये ये गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी, ऐसा कोई गलत आरोप न लगायें, तमाम ऐसे ब्लैकलिस्टेड.....

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्य एक साथ विरोध करने लगे)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

श्री रंगनाथ मिश्र, माध्यमिक शिक्षा विभाग के ही मंत्री थे।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

लेकिन वह शिक्षा विभाग के प्रकरण में जेल नहीं गये थे, और जिस प्रकरण में जेल गये थे, उसमें बरी हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अब हो गया। मैं प्रश्न ले रहा हूं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांग के अधीन बजट की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 87,63,91,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख7.11 बजे, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 16,73,27,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा और आदेश होगा तो मैं संक्षेप में इसको रख दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

आप संक्षेप में रख दें।

श्री अम्बिका चौधरी–

अन्यथा मैं तो यह समझ रहा था कि ये जिस प्रकार की कल्याणकारी योजनायें सरकार लेकर आई है इन दोनों विभागों में, इस पर बगैर किसी कटौती के सर्वसम्मति से इसको पारित होना चाहिये, किन्तु जैसा आपका आदेश होगा।

श्री अध्यक्ष–

आप संक्षेप में रखें।

श्री अम्बिका चौधरी–

अभी बहुत संक्षेप में रख देता हूं, बाकी आगे जैसी चर्चा जायेगी। अगर आ गई तो, यदि मौर्या जी चाहेंगे तो नहीं आयेगी। माननीय अध्यक्ष जी, समाज के असहाय,

सुविधाहीन, कमजोर वित्तीय स्थिति वाले, निशक्त जनों के लिये, विकलांग कल्याण विभाग से विकलांग जन विकास विभाग से मान्यवर, अनेक योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसमें निशक्त बालक–बालिकाओं को शिक्षण, उनके प्रशिक्षण, उनकी अपंगता के कारण जो उनकी कठिनाई है, उस कठिनाई को दूर करने के लिये उपकरणों की सहायता, इससे जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद के लिये पेंशन, इस प्रकार की अनेक योजनायें संचालित की जाती हैं।

श्रीमन् मैं सिर्फ एक पंक्ति में यह बजट का उल्लेख कर देना चाहता हूं कि पिछले वर्ष के मुकाबले प्लान में आयोजनागत पक्ष में 22 प्रतिशत ओर नान प्लान में 2 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए मान्यवर, इस साल का बजट हम विकलांग कल्याण का लेकर के आये हैं। पिदले वर्ष यह राशि 484.6742 करोड़ थी जो इस साल 529. 9498 लगभग 530 करोड़ का बजट हम लेकर के इसमें आये हैं। मान्यवर, इसमें 25 संस्थायें उन बालकों के विकलांगों के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए चलाने का काम हम करते हैं जिसमें 16 शैक्षिक संस्थायें और 9 संस्थायें ऐसी हैं जिसमें प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, 3 वर्ष से 7 वर्ष की आयु वर्ग के विभिन्न विकलांगता से ग्रस्त जो बच्चे थे, जैसे नर्सरी में भेजने से पहले आज कल प्रीपेटरी स्कूल्स का चलन है सामान्य बच्चों के लिए जैसे पहले छोटे बच्चों को हम भेज देते हैं उसमें सिर्फ जैसे प्ले वे स्कूल या प्रीपेटरी स्कूल इस तरह से अलग अलग नाम देकर के रखते हैं तो हमने इस साल तय किया है कि प्रत्येक मण्डल में कम से कम एक बचपन डे केयर सेन्टर की स्थापना सरकार करेगी जो 3 से 7 साल के बच्चों के लिए हम यह योजना चलाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप भिज्ञ हैं पूरा सदन जानता है गोरखपुर में एक विशेष प्रकार की विकलांगता का अभिशाप हम झेल रहे हैं इन्सेफ्लाइटिस के कारण बाकी तरह की विकलांगता तो है वह प्रकृतिजन्य है उसके बारे में सबकी संवेदनाएं हैं लेकिन गोरखपुर के इलाके में विशेष तौर से उसके आस पास के जनपदों में माननीय अध्यक्ष जी आपका जनपद भी प्रभावित है, हमारे जनपद तक ज्यादा प्रभाव नहीं है लेकिन थोड़ा प्रभाव आता है तमाम पूर्वान्चल के जिलों का किन्तु केन्द्र गोरखपुर है। तो गोरखपुर में इन्सेफ्लाइटिस से प्रभावित जो बच्चे हैं वह जीवित अगर बच जाते हैं तो भी उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि उनके मनोविकास केन्द्र की स्थापना इस बजट में कर रहे हैं विशेष तौर पर जो इन्सेफ्लाइटिस बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उसके लिए यह एक नई व्यवस्था लेकर इस बजट में आये हैं।

श्रीमन्, दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए दो इन्टरमीडिट कालेज खोलना चाहते हैं इसके लिए 4 करोड़ की व्यवस्था हमने बजट में इस साल की है और सिर्फ दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए मान्यवर, हम दो नये इन्टरमीडिएट कालेजेज इस बजट में स्थापित कर रहे हैं ।

श्रीमन् गोरखपुर में पहले से राजकीय श्रवण बाधित बालिकाओं के शिक्षण के लिए एक वहां विकलांग बच्चों की मदद के लिए विद्यालय था एक ओर विद्यालय, चूंकि भूमि हमारे पास वहां उपलब्ध है और एक केन्द्र पर यह व्यवस्था करने में सहूलियत है

इसलिए श्रीमन्, वहां पर गोरखपुर में श्रवण बाधित बालिकाओं के शिक्षण के लिए हम एक इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना कर रहे हैं 2 करोड़ रुपये का प्राविधान हमने उसके लिए भी करने का काम किया है। मान्यवर, यह कौशल विकास मिशन जिस तरीके से सरकार ने बहुत प्राथमिकता पर लिया है माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके माध्यम से प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने की एक ऐसी अभिनव योजना शुरू की है जिसकी आज अभी चर्चा बजट में हो रही थी, अभिषेक मिश्र जी ने बताया कि 46 लाख लोगों का पंजीकरण हुआ है किन्तु विकलांग बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है उनको सामान्य तौर पर जो कौशल विकास केन्द्र हैं उनसे काम नहीं चल सकता था इसलिए आगरा में इसके भवन निर्माण के लिए हमने एक करोड़ रूपया देकर के विकलांग बच्चों के कौशल विकास का हमने अलग से प्रबन्ध किया है।

मान्यवर, राजकीय मूक बधिर विद्यालय गोरखपुर में पहले से जहां विद्यालय हमारा चलता है वहां एक करोड़ सत्तर लाख रुपया देकर के छात्रावास का एक भवन बनाने का प्राविधान भी हमने इस बजट में किया है। मान्यवर, सभी मण्डलों पर समेकित माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की एक ऐसी परिकल्पना है जो इसके पूर्व नहीं थी पिछले वर्ष आपके सम्मुख मैं यह लेकर के आया था समेकित 3 विद्यालयों की स्थापना हमने किया एक इलाहाबाद में एक औरैया में और एक कन्नौज में। यह समेकित विद्यालय में उनका छात्रावास भी है और सभी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त जो बच्चे हैं उनका एक समेकित रूप से सभी प्रकार का प्रबन्ध किया जा सके इसके लिए यद्यपि एक विद्यालय की स्थापना में 15 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च होने हैं जैसा इस्टीमेट बनेगा वहां के लोकल का तीन की स्थापना हमने पहले किया था और तीन नये समेकित विद्यालयों की स्थापना का प्राविधान इस बजट में हम लेकर आये हैं। श्रीमन्, इसमें हमने जो पिछली साल स्थापित किया था उसके लिये भी बजट का प्रावीजन किया है ताकि उसका काम आगे चलता रहे, इस प्रकार 15 करोड़ उसके लिये और नये की स्थापना के लिये इस वर्ष के खर्च किये जाने के लिये तीन समेकित विद्यालयों के खर्च किये जाने के लिये 12 करोड़ का प्राविधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, शारीरिक विकलांगता दिखाई पड़ती है, लेकिन मानसिक विकलांगता भी बहुत पीड़ादायक है। मानसिक मन्दित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित विकलांगजन के लिये, जो बिल्कुल निराश्रित हैं, कई मामलों में हम देखते हैं कि ऐसा उदाहरण मिलता है कि लोगों की संवेदनशीलता शून्य हो जाती है, मां–बाप और गरीब कमजोर लोग कई बार या कई ऐसे लोग जो अपने बच्चों को विकलांग हो जाने की स्थिति में भारस्वरूप समझकर निराश्रित छोड़ देते हैं, उनको कहीं प्लेटफार्म पर ले जाकर, कहीं चौराहे पर ले जाकर छोड़कर चले जाते हैं, अच्छे–खासे लोग छोड़कर चले जाते हैं। अपनी पैदा की हुई औलाद को भी निराश्रित छोड़कर चले जाते हैं, इस प्रकार के मानसिक मन्दित और मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित विकलांगजन के लिये आश्रयगृह और प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन के लिये भी स्वैच्छिक संगठन काम करते रहते हैं, जो ले आते हैं। छोटे बच्चों को कई बार स्टेशन पर से ले आते हैं लिथड़े हुये तमाम लोगों को लेकर आते हैं, हम लोगों ने देखा है और

आपने भी अपने सार्वजनिक जीवन में देखा होगा, उनकी सहायता के लिये पॉच करोड़ रुपये का प्राविधान हमने किया है जो हम इन संस्थाओं को देने का काम करेंगे और पिछले वर्ष जिन लोगों ने किया है, उनका काम बहुत अच्छा रहा है। श्रीमन्, राज्य सरकार द्वारा पात्र विकलांगजन एवं उसके सहयात्री को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है और इस हेतु 29 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है ताकि उनकी यात्रा में कोई व्यवधान नहीं हो ऐसी व्यवस्था हमने की है। डिस्लेक्सिया अटेन्सन डेफिसिट हाईपर एक्टीविटी अंग्रेजी में बोल रहा हूं, क्योंकि इसकी हिन्दी ठीक से तरजुमा करना मुश्किल है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लोग सामान्य बच्चे समझते हैं, कहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा तेज है, जबकि वह रोग से ग्रसित है, वह तेज नहीं है, हाईपर एक्टीविटी उसकी है तो वह तेजी से काम करता है दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है, आप चाहे कितना भी उसको रोकने का प्रयास कीजिये वह रुकेगा नहीं। अगर आपने पकड़ कर रोक लिया तो वह जोर से चिल्लायेगा, हाथ–पैर हिलायेगा। नाच रहा है तो नाचता रह जायेगा, नाचते–नाचते गिर पड़े, लेकिन अगर आप रोकने की कोई चेष्टा करें तो वह बिल्कुल आपको दांत से काट लेगा, हाथ से मार देगा। आप समझते हैं कि हमारा बच्चा बहुत तेज है, लेकिन यह उसकी तेजी नहीं है, बल्कि यह उसकी मानसिक विकलांगता है। आगे चलकर जब वह बड़ा होता है तब उसका प्रभाव समझ में आता है क्योंकि छोटे बच्चे को तो लोग समझ नहीं पाते हैं, उसकी पहचान के लिये हमको बहुत प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता थी, कभी इसके पहले व्यवस्था नहीं हुई थी, पहली बार हमने प्रशिक्षित लोगों का इंतजाम किया है जो डिस्लेक्सिया अटेन्शन डेफिसिट हाईपर एक्टीविटी के बच्चों की पहचान करने का काम करेंगे ताकि समय रहते उनका उपचार हो जाये क्योंकि बड़े रहने पर उनका उपचार संभव नहीं होता है। यह बन्दोबस्त हमने किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, विकलांगजनों की पेंशन के लिये, असीजा जी बैठे हैं इन्होंने अभी सवाल पूछ दिया और मुझे खुशी है कि इस सूबे के मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने कभी किसी सवाल पर अपना मन छोटा नहीं रखा और अपने साथियों को भी मंत्रि–परिषद् के साथियों को काम करने वालों को इतनी आजादी दे रखी है कि अगर कोई बात जरूरी हो तो अगर वह कोई बात कह दे तो उस बात को पूरा करने में अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की सरकार पीछे रहने वाली नहीं है। असीजा जी के सवाल पर सीधा आश्वासन नहीं था, लेकिन मैंने वो बात कमिट कर ली और आज बजट के दिन दोहराना चाहता हूं कि मैंने जब आपसे कह दिया था तो इस सदन में दोहरा कर कहता हूं कि हमारे पास आज की तारीख तक एक–एक पात्र विकलांग व्यक्ति जो पेंशन का अधिकारी है, एक भी नहीं बचेगा हण्ड्रेड परसेण्ट को पेंशन देने का काम करेंगे, हम बजट में यह प्राविधान लेकर आये हैं। श्रीमन्, यह लगभग 09 लाख की संख्या हो जा रही है। कृत्रिम अंग सहायक उपकरण अनुदान योजना में चार करोड़ रुपये का प्राविधान किया है, शादी पुरस्कार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2.10

करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। इसमें स्थिति यह है कि दोनों में से एक विकलांग है तो 15 हजार रुपये देते हैं, अगर लड़की विकलांग है तो 20 हजार देते हैं और अगर दोनों विकलांग हैं तो 20 हजार रुपये देते हैं। इस प्रकार हम उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं ताकि विकलांग लोग भी शादी विवाह करके सामान्य लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकें, इसलिये उनके प्रोत्साहन के लिये हमने यह राशि बजट में रखी है। एक विशेष बात हुयी माननीय अध्यक्ष जी और मुझे इस सदन को बताते हुये बहुत ही प्रसन्नता है कि पूरे देश के पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री प्रणव मुखर्जी जी ने पुरस्कार जो दिया, वह उत्तर प्रदेश को इसी वर्ष 26 जनवरी को दिया है और वह पुरस्कार इसलिये दिया कि विकलांगजन को कई बार असुविधा होती है। मान्यवर, इससे पहले कागजों में बात चलती थी कि बैरियर फ्री प्रीमसेस का इंतजाम किया जाय । बैरियर–फ्री का तात्पर्य यह हुआ कि ऐसी जगह, जहां उसकी व्हील चेयर चली जाय, जहां सीढ़ियों की ऐसी बाध्यता नहीं हो, लिफ्ट तक उसकी व्हील चेयर चली जाय और प्रत्येक जगह उसका प्रवेश हो सके । माननीय अध्यक्ष जी, आपको स्मरण होगा कि निर्वाचन आयोग ने मतदान के समय इस बात को कहा था कि सभी पोलिंग स्टेशन को बैरियर फ्री बनाने के लिये रैम्प बनाया जाय तो वह बच्चों के लिये नहीं था बल्कि मतदान के समय आयोग ने निर्देश दिया था तो हमने इस बात के लिये शासनादेश निर्गत किया, वह बात तो अलग है लेकिन शासनादेश निर्गत किये जाने के अलावा 25 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया कि सभी सरकारी बिल्डिंगों को बैरियर फ्री बनाया जाय, उनके रैम्प के लिये । मान्यवर, इनको सिपडा योजना से आच्छादित करके यह बंदोबस्त करने का हमने प्रबन्ध किया और इस वर्ष मान्यवर, वहां जो 2014 का राष्ट्रीय विकलांगता पुरस्कार इसी बैरियर फ्री अरेन्जमेंट के लिये उत्तर प्रदेश को मिला। मान्यवर, यह सूचना इस सदन में मुझे देते हुये बहुत प्रसन्नता है ।

श्रीमन् शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में है। इसकी स्थापना आपने किया, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने, लेकिन इसकी स्थापना करके आपने उसको छोड़ दिया और स्थापना करके सोचा ही नहीं, कि इसमें क्या बंदोबस्त किये जाने की जरूरत है। स्थापना के लिये धन्यवाद, यह अच्छी सोच थी। लेकिन यह सरकार आते ही, आपने कर दिया तो हम उसको मिटायेंगे, आपने किया तो उसको रोकेंगे, क्यों इसको आगे करो, क्यों इसको पीछे करो, यह सोच न रखते हुये हमने सारे वह प्रबन्ध किये, जिससे यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन इसको मान्यता दे। अभी पिछले दिनों उसके चेयरमैन आये और यू0जी0सी0 के मानकों पर पूरा खरा उतरने के कारण यू0जी0सी0 ने उस यूनिवर्सिटी को मान्यता देने का काम किया, शामिल करने का काम किया है, मान्यवर, यह हमारी उपलब्धि है। श्रीमन्, यू0जी0सी0 से अवस्थापना और शैक्षिक कार्यक्रमों के लिये अब हमें उसकी राशि मिल सकेगी। अभी तक यू0जी0सी0 हमें कुछ देती ही नहीं थी क्योंकि उसके पैरामीटर्स पर हम कहीं थे ही नहीं। फैकल्टी थी नहीं, खाली कुछ बिल्डिगें बन गयीं और जो डिपार्टमेंट्स खुलने थे, उनका भी बंदोबस्त नहीं था और एक और बड़ी विशेष बात, माननीय मुख्य मंत्री जी स्वंय उसकी कार्य परिषद् के

अध्यक्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मैनें उसकी बैठक कराई, मुख्य मंत्री जी ने उदारतापूर्वक उन सारी चीजों को स्वीकार करने का काम किया जिसके इस्तेमाल से विश्वविद्यालय को हमने राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय का दर्जा तो दिया ही, यह देश का पहला राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इसको बनाने का काम किया, यह कोई छोटी बात नहीं है । हमारे तमाम साथी है जो देश और दुनिया जानते हैं, उन सबके बीच में यह कहना चाहता हूं कि यह माडल ऐसा है, हमारा यह शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में रिहैबिलीटेशन के लिये यूनिवर्सिटी या शिक्षण संस्था की जो परिकल्पना है, उस पर हमने इसे सिर्फ वर्ल्ड क्लास ही नहीं बनाया, दुनिया में अपने ढंग का हमारा इसका एक बहुत ही विशेष स्थान है, इसको तमाम लोगों ने स्वीकार किया है और वह इसलिये हुआ कि माननीय मुख्य मंत्री जी की इस पर दृष्टि है और इस विभाग में मान्यवर, सारे इंतजाम करके विश्वविद्यालय को हमने इस दर्जे का बनाने का काम किया । मान्यवर, उसमें कई नये कोर्सेज शुरू किये गये हैं और आश्चर्य होगा कि उसका स्तर वहां ले जाया गया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में मौर्य जी सीटें खाली रह गयीं लेकिन शकुन्तला मिश्र विश्वविद्यालय में सीट खाली नहीं रही, पूरी की पूरी सीटें भर गयीं । बन्दोबस्त पहले भी था कि 50 प्रतिशत उस पर रिजर्वेशन रहेगा विकलांगजन के लिये, लेकिन उनके लिये फीस माफ थी, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने माननीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी को, उन्होंने कहा कि सिर्फ फीस माफ करने से ही काम नहीं चलेगा और फीस करने के अलावा उसकी हास्टल की फीस भी माफ और उसकी मेस की फीस भी माफ, उसका कोई खर्च नहीं लगेगा। मान्यवर, वह स्नातक में प्रवेश ले करके परास्नातक और पी0एच0डी0 और आगे की जो दूसरी पढ़ाई करना चाहता है वहां तक उसकी मेस की फीस माफ है। किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में मेस का पैसा फ्री नहीं है, अकेले शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में मेस का भी खर्चा सरकार उठाती है, यह बन्दोबस्त हमारी सरकार ने किया है। श्रीमन्, इसमें कई नये कोर्सेज चालू किये गये, एक अनूठा कोर्स है जो आप सबकी दिलचस्पी का विषय होगा। पांच वर्ष का जो एल0एल0बी0 का कोर्स है उसमें बी0ए0 के साथ एल0एल0बी0 हो जाती थी लेकिन बी0कॉम0 के साथ एल0एल0बी0 कराने वाला यह पहला सेंटर है जिसमें बी0कॉम0 के साथ पांच साल का एल0एल0बी0 कोर्स हमने शुरू किया है।

इस बजट में लॉ फैकल्टी के लिए लॉ क्लासेज चलाये जाने के लिए जो बिल्डिंग अलग से बननी है उसके पैसे का भी प्रावधान हमने कर दिया है, लॉ क्लासेज तो शुरू हो गये हैं लेकिन हम उसका भवन अलग से बनवा रहे हैं। सेंटर फॉर इण्डियन साइन लैंग्वेज एण्ड डेफ स्टडीज की स्थापना की गई है। इसके लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन लैंग्वेज एण्ड डेफ स्टडीज की स्थापना की गई है। मान्यवर, इसके लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन लैंग्वेज एण्ड डेफ स्टडीज, यूनिवर्सिटीज ऑफ लैंकशायर यूनाइटेड किंग्डम के साथ एम0ओ0यू0 हमने साइन किया है और इस विधा के जो बड़े विशेषज्ञ हैं, ऐसे लोगों को हमने बुलाया और उनको विजिटिंग प्रोफेसर

रख करके इस विषय पर आगे करने का काम किया है और उन्हें सम्मानित करने का भी काम किया है। संगीत के क्षेत्र में रवीन्द्र जैन जैसी बड़ी हस्ती को हमने विजिटिंग प्रोफेसर भी बनाया और दूसरे मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनको मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस साल यश भारती से भी सम्मानित करने का काम किया है। हम मॉडल ले करके आये हैं कि एक विकलांग व्यक्ति अपने क्षेत्र में ना सिर्फ दो सौ से ज्यादा फिल्मों का संगीत देने वाला व्यक्ति बल्कि लोगों को दीवाना कर देने वाला विकलांग व्यक्ति हो सकता है, उसको सामने रख करके हमने विजिटिंग प्रोफेसर बनाने का काम किया है। मा0 अध्यक्ष जी, हमारी दूसरी भी योजनाएं हैं, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी चार वर्षीय का पैरा मेडिकल कोर्स यह हम लाने जा रहे हैं, आगे ये कोर्सेज हम ले आयेंगे। बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एवं ऑथोटिक्स, सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन एण्ड डेवलपमेंट स्टडीज, सेंटर फॉर जर्नलिज्म एण्ड मॉस कम्यूनिकेशन, सेंटर फॉर बिहैवियरल एण्ड कॉग्निटिव साइन्सेज, सेंटर फॉर ऑटिज्म एण्ड मल्टी–डिसएबिलिटी स्टडीज, दूरस्थ शिक्षा केन्द्र एवं केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना, ब्रेल प्रेस की स्थापना, कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना, जिसमें विकलांग जन के लिए अत्याधुनिक कृत्रिम पैर, हाथ एवं अन्य उपकरण बनाकर दिये जायेंगे क्योंकि ये बाहर से आते हैं तो बड़े मंहगे हो जाते हैं और उसके लिए जयपुर मॉडल और तमाम सजेस्ट करते हैं। हम यह प्रबन्ध करने जा रहे हैं कि यह समस्त उपकरण अपने यहां बनेंगे। एक और बात है जो सिर्फ परिकल्पना के स्तर पर हैं, उन्हें अभी हम इस बजट में नहीं लाये हैं लेकिन परिकल्पना के स्तर पर है। यह परिकल्पना के स्तर पर है लेकिन हम उसका उल्लेख करना चाहते हैं कि अमेरिका में एक शोध हुआ है और उस शोध के आधार पर ऐसे अंग लगाये जायेंगे जो दिमाग से सेंसर से कनेक्ट करके उंगलियों का मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट सामान्य की तरीके से करेगा। अगर वह विकलांग है और उसे कृत्रिम अंग लगाया गया है तो जैसे हमारे शरीर के अपने अंग काम करते हैं इस तरह का काम कर सकेगा, इसके बारे में इस परिकल्पना को आगे ले जाने की हमारी योजना है, इस बजट में चूंकि बाकी की चीजें नहीं थीं अभी वह स्टडी के स्तर पर हैं। श्रीमन्, इस प्रकार से मैंने संक्षेप में उल्लेख किया, बहुत तरह की इन सारी योजनाओं को ले करके हम आ रहे हैं और मैं चाहता यह हूं कि एक ऐसे विषय पर जिसमें दो मत हो ही नहीं सकते हैं ऐसे लोग निःशक्त लोग जिनकी प्रतिभा को अगर संवारने का काम किया जाएं तो वह साधारण से ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। मैं एक घटना का उल्लेख करके इस पर अपनी बात समाप्त करूंगा कि विकलांग जनों के एक बच्चों के कार्यक्रम में मैं गया और आजकल आप लोग भी जहां जाते हैं तो एक चलन हो गया है कि रिकार्डेड गाने पर बच्चे अपनी प्रस्तुति करते हैं। गाना बजता रहता है और बच्चे उस पर डांस करते रहते हैं एक–एक भंगिमा उनकी होती रहती है। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल मूक और बधिर हैं, उनको पता नहीं कि क्या बज रहा है लेकिन उनका मूवमेंट इतना एक्यूरेट था कि जितना सामान्य बच्चे जो रिकार्डेड गाने में नाचते हैं उनके स्टेप्स आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन अपनी ट्रेनिंग और जो इन्स्ट्रक्टर हैं, उसके इशारे पर और

इशारे में जो उनको समझाने का काम करते हैं उनके इशारे का प्रभाव ऐसा अद्भुत चमत्कृत कर देने वाला था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने ही कार्यक्रम किया है, इसी में वह रिकार्डिंग हो रही है, रिकार्ड बज रहा है और वह नाच रहे हैं ऐसा नहीं लगा। ऐसा मैंने अनेक बार देखा है, ऐसी प्रतिभा उनमें है। तो ऐसे लोगों की हिफाजत के लिए सरकार ने बहुत गम्भीरता से चिन्ता की है और उन्हीं का बजट ले करके आया हूं। इसलिए मेरा आग्रह है कि कम से कम इस बजट को सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए, शेष बातें जैसी आवश्यकता होगी मैं कहने का काम करूंगा।

(कटौती प्रस्ताव हेतु ब0स0पा0 के श्री कालीचरन सुमन व भा0ज0पा0 के डा0 अरूण कुमार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कटौती के लिए कालीचरन सुमन जी का नाम हमारे पास आया है। माननीय मौर्य जी, अरूण कुमार जी कह रहे हैं कि हम रखेंगें, इसको कौन रखेगा ?

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

यह तो सुमन जी को आवंटित हैं।

श्री काली चरन सुमन–

मौर्या जी, पिछड़ा वर्ग का मैं रख लूंगा, मा0 अरूण कुमार जी को रख लेने दीजिए।

डा0 अरूण कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–79– समाज कल्याण विभाग (विकलॉग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की ओलाचना करना तथा सुझाव देना।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपकी योजनायें काफी अच्छी हैं, मैं हर चीज को गलत कहने का आदी नहीं हूं, न हमारी पार्टी हर सही चीज को गलत कहने की आदी है। आप बहुत सी योजनायें अच्छी लाये हैं लेकिन मैं कुछ थोड़ी सी बातें आपसे कहना चाहूंगा। जब भी हैण्डीकैप की बात करते हैं, विकलांग की बात करते हैं तो हमारा इरादा होता है कि ज्ञान बढ़े, कौशल बढ़े, विकलांगजन का रोजगार एवं सम्मान बढ़े। हमारा सबसे पहला कहना यह है कि विकलांग आदमी को जो आपने 300 रुपये पेंशन की है, इसको कम से कम 1000 रुपये प्रतिमाह किया जाएं, 300 रुपया कुछ नहीं है, 300 रुपये में वह दोनों वक्त की चाय भी एक महीना नहीं पी सकता। आपने सभी को पेंशन के लिए आश्वस्त किया है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं मैं आपको बधाई देता हूं लेकिन इसको 300 रुपये से 1000 हजार रुपया अवश्य कर दें। विकलांग की शादी पर जो आपने 20 हजार रुपया किया है। मेरा कहना यह है कि अगर दोनों लोग विकलांग हैं तो उनको 50 हजार रुपया दिया जाएं ताकि वह कहीं पर खोखा रख लें, कहीं कोई छोटी दुकान कर लें, कुछ काम करने की स्थिति में

हो जांए। अगर आप ऐसा कर देंगें तो उन्हें बहुत आसानी हो जायेगी। मूक बधिर विद्यालय में सीट्स बढ़ाइये। वहां पर दिक्कत होती है खासतौर से स्पीच थेरेपिस्ट की वहां पर दिक्कत रहती है। आपने जो शकुन्तला मिश्रा मूक बधिर विश्वविद्यालय में स्पीच थेरेपिस्ट का कोर्स शुरू किया है इस तरह से यह एक अच्छा कदम है लेकिन स्पीच थेरेपिस्ट आपको तुरन्त चाहिए। मूक बधिर विद्यालयों में इनकी कमी है और हमारे बरेली में ही एक जूनियर हाईस्कूल है इसको कम से कम हाईस्कूल तक करा दीजिए और वहां पर बच्चों के स्पोर्टस और उनके कम्पटीशन्स, ड्रामा वगैरह इस तरह के कार्यक्रम और ज्यादा होने चाहिए। दूसरी चीज मैं यह भी कहूंगा कि हमारे जो हैण्डीकैप होते हैं उन्हें विकलांगता का सर्टीफिकेट लेने में और जहां विकलांगता दिख रही है दूर से कि पैर कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, इसके लिए आपने पी.एच.सी. के मेडिकल आफिसर को अधिकृत कर दिया है यह अच्छी बात है। लेकिन बहुत से विकलांग ऐसे हैं जिनके कान में परेशानी है या मेंटली हैण्डीकैप हैं, उनको विकलांगता का सर्टीफिकेट बनवाने में बहुत दिक्कत होती है। मण्डल स्तर के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पीटल हैं उन पर भी आडियोमीटरी की एबेलिबिलटी नहीं होती है और उनको लखनऊ आना पड़ता है। उस समय तक उनके पास विकलांगता का सर्टीफिकेट भी नहीं होता है और उनको रेलवे में कोई कन्सेशन नहीं मिलता और यहां पर आते हैं तो कहा जाता है कि यह काम बुधवार के दिन होगा या शुक्रवार के दिन होगा तो उनको दो–दो, तीन–तीन दिन तक रूकना पड़ता है जिससे उन लोगों को तो बहुत परेशानी होती है। मैं चाहता हूं कि आप इसका ऐसा इंतजाम कर दें कि आडियोमेट्री की व्यवस्था अगर हर डिस्ट्रिक अस्पताल में न हो तो मण्डल स्तर के अस्पताल में जरूर होनी चाहिए ताकि विकलांग जनों को आसानी रहे। आंखों के विकलांग के लिए मैं यही कहूंगा कि ब्रेल लिपि को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसको ट्रेनिंग देने वाले लोगों को बढ़ावा मिलना चाहिए साथ ही साथ ऐसे लोगों को हाई स्कूल, इण्टर बी0ए0 आदि के लिए विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए मेंटली हैण्डीकैप के लिए फिजियोथेरेपी रिहैबिलटेशन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारे पास मेंटली हैण्डीकैप के लिए खासतौर से ट्रेनिंग दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं यह भी चाहूंगा कि कौशल विकास केन्द्र कम से कम हर जनपद में होना चाहिए यह एक ही छत के नीचे हो जिसमें ऑख वालों के लिए अलग व्यवस्था हो कान के लोगों का व जो मूक बधिर हों उनके लिए अलग व्यवस्था हो अन्य तरह से जो फिजिकल हैण्डीकैप हों उनके लिए अलग व्यवस्था हो सबसे जरूरी चीज यह है कि अगर हम उनके कौशल का विकास करें रोजगार के काबिल बना दें ताकि वह कुछ न कुछ काम कर सकें तो मैं चाहता हूं कि हर जिले में कम से कम एक ऐसा सेन्टर हो और हमारे जो विकलांग जन होते हैं उनके स्पोर्ट्स स्टेट लेबिल पर हों ताकि इन लोगों का प्रोत्साहन हो हमारे विकलांग तरक्की करें उनको भी पूरा सम्मान मिले। विकलांग लोगों का जो रिजर्वेशन है वह भी पूरा किया जाय बहुत सी जगहें होती हैं जहां विकलांग जन का कोटा होता है लेकिन विकलांग जन को नौकरी नहीं मिल पाती है। इसी के साथ साथ मैं यह कहूंगा कि प्रत्येक मण्डल में बचपन डे केयर सेंटर और जापानीज इन्सेफ्लाइटिस के लिए अलग से सेंटर खोल रहे हैं वह अच्छी बात है बचपन

डे केयर सेंटर जो मन्द बुद्धि वाले बच्चों के लिए होता है उसके लिए आप अगर रुवेला वैक्सीनेशन दे दें तो मन्द बुद्धि के बच्चे पैदा होना कम हो सकते हैं। इन बच्चों के बारे में आप अपने एक्सपर्ट से राय लें कि जो प्रिगनेंट मदर हैं उनके लिए या पहले वैक्सीनेशन होना चाहिए साथ ही साथ जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए जो आप गोरखपुर में सेन्टर बना रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चे इन्सेफ्लाइटिस के हो जाते हैं वह मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हैण्डीकैप होते हैं लेकिन इससे प्रभावित जो बच्चे हों उनका तो इलाज हो देखभाल हो लेकिन उन क्षेत्रों में जो एपेडमिक एरियाज हैं वहां के लिए जापानी इन्सेफ्लादटिस का वैक्सीनेशन हो साथ ही साथ उस एरियाज में मास्क्वीटो नेट दिए जाएं जिसमें इन्सेक्टीसाइड लगा हो ताकि मच्छर न काटें क्योंकि यह जापानी इन्सेफ्लाइटिस क्यूलेक्य मास्क्वीटो के काटने से होता है मच्छर कम काटेगा तो यह बीमारी कम होगी। बाकी आप शकुन्तला देवी विश्वविद्यालय में जो आप कोर्सेज शुरू कर रहे हैं वह अच्छे हैं और वह बहुत जरूरी हैं मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी विभिन्न कोर्सेज जो आपने बढ़ाए हैं पढ़ाने के लिए लोगों को वहां पर तैयार कर रहे हैं वह एक अच्छा कार्यक्रम हैं मैं समझता हूं कि न केवल यू0पी0 का यह विश्वविद्यालय देश का अकेला विश्वविद्यालय है यह बहुत अच्छी बात है इसकी ज्यादा से ज्यादा तरक्की होनी चाहिए। साथ में मैं यह भी कहूंगा कि शारीरिक रूप से जो अक्षम हैं उनके लिए जैसे किसी का हाथ कट जाएं उसके लिए आप सिर्फ 6 हजार रुपए देते हैं इसको जितने रुपए में अंग मिले उतने रुपए देने चाहिए क्योंकि अब ऐसे इक्यूपमेंट आने लगे हैं कि जैसे किसी का हाथ आधा कट गया है तो वह उसको इस तरह का हाथ लगाएंगे जिसका माइण्ड से कनेक्शन होगा जो आपने बताया कि नोट गिनते हैं मैंने देखा है कि कटा हुआ हाथ निकालकर लोग अलग रख देते हैं बाद में जब वह लगाते हैं तो आप उनसे कहिए कि नोट गिन लो दस्तखत कर दो वह यह सब कर देंगे। सब्जी काट लेंगे इसका मतलब जो आर्टीफीसिएल हाथ लगता है उससे लगभग अपना 80 प्रतिशत काम कर लेते हैं। मैं समझता हूं कि जब तक ऐसे लिम्ब बनाने की आपकी स्कीम लागू नहीं होती जो लोग बनवा सकते हैं उनके लिए कम से कम 6 हजार रुपए से कुछ रुपया बढ़वा दिया जाय ताकि वह लोग इससे फायदा उठा सकें इसके साथ ही साथ गोरखपुर के अन्दर मूक बधिर विद्यालय है जो रेलवे लाइन और रोड के बीच में है जो बच्चे रोड से आते हैं उन्हें लाइन पार करनी पड़ती है जिसकी वजह से बहुत से बच्चे जो मूक बधिर होते हैं उनको आवाज सुनाई नहीं पड़ती जब गाड़ी काफी पास आ जाती है तो सुनाई पड़ती है जब वह भागते हैं तो गिर जाते हैं उनके लिये कुछ इस तरह का हो जाय ताकि रेल के ऊपर ब्रिज बन जाय या कम से कम फुट ब्रिज बन जाय ताकि आदमी पैदल चढ़ के चला जाय उसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहूंगा कि आपको इसमें बहुत से काम अभी करना बाकी है। हाइपर एक्टिव चिन्ड्रेन के लिये भी एक नई योजना है, जिसकी मैं सराहना करता हूं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो हाइपर एक्टिव हैं उनके लिये शायद मेरे ख्याल से इससे पहले यह योजना नहीं थी और बहुतों ने नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन यह जरूरी है, इसमें बच्चे के बिहेवियर को चेंज किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार पुनः यह कहूंगा

कि आपने जो यह योजनाएं बनाई हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो। योजनाएं तो बहुत कुछ बनाते हैं लेकिन आम आदमी को जमीनी लेविल पर क्या मिलता है उसकी ओर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कटौती का प्रस्ताव रखने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष–

इधर से कोई बोलेगा क्या ?

'श्री उपेन्द्र तिवारी–

मान्यवर, रख लेने दीजिये, विकलांग पर मैं रख लूं तो पिछड़ा पर यह बोल लेंगें। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से.....

श्री अध्यक्ष–

इसमें विकलांगों का पिछड़ों का बहुत ज्यादा है। जितना सुझाव देना था डाक्टर साहब ने दे दिया है।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, हम सुझाव देना चाहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग के बजट पर कटौती के विरोध में बोलने का मौका दिया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कटौती के विरोध में।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री उपेन्द्र तिवारी–

कटौती के समर्थन में।

श्री अध्यक्ष–

आप तो विरोध बोल रहे हैं।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

मान्यवर, कटौती के समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है और जो वर्तमान में सरकार चल रही है वह माननीय लोहिया जी की विचारधारा को लेकर चल रही है, जनेश्वर जी की विचारधारा को लेकर चल रही है। लोहिया जी का नारा था कि– समाजवादियों ने बांधी–गांठ, पिछड़ों को मिले सौ में साठ।

श्री अध्यक्ष–

सुझाव दीजिये ना।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

अध्यक्ष जी, सुझाव ही तो दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, कुछ तो बोलने दीजिये। माननीय अध्यक्ष जी, विकलांग व पिछड़े वर्ग के लोग पूरे समाज में सबसे दबे कुचले लोग होते हैं, सबसे निरीह लोग होते हैं, सबसे कमजोर होते हैं और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री, विकलांग और पिछड़ा वर्ग जी ने जो यह कहा कि 673 करोड़ रुपये का बजट रखा है जिससे तमाम विभिन्न योजनाओं के बारे में उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला। उन तमाम योजनाओं पर मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर रिकार्ड उठाकर देखा जाय तो साढ़े इक्तालीस लाख लोग विकलांग, निशक्त जन की श्रेणी में आते हैं जिसमें से पौने नौ लाख लोग ऐसे हैं जिनको विकलांगता का पेंशन मिलता है। साढ़े इक्तालीस लाख में पौने नौ लाख की संख्या अगर परसेन्टेज निकाल कर देखा जाय तो हमारे समझ से लगभग 25 प्रतिशत से कम है। और हमारे माननीय मंत्री जी विद्वान मंत्रीगण हैं, अन्य विभागों में भी रूचि लेते हैं लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस किताब के माध्यम से, बुक के माध्यम से इस सदन में जो बजट का प्रस्ताव रखा गया है यह विकलांग और पिछड़ा कल्याण मंत्रालय में यह बिल्कुल फैल्योर हैं। टोटल 25 प्रतिशत लोग इसका लाभ ले रहे हैं और इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, यह पिछले साल का रिकार्ड है। यह अभी तीन–चार दिन पहले प्रश्न लगा हुआ था तो उस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2014–2015 में विकलांग पेंशन में एक साल के अन्दर जो वृद्धि हुई है वह 3704 नवीन विकलांगों को पेंशन स्वीकृत की गई है इसलिये माननीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर निशक्त जनों की चिन्ता की जाय तो हम लोग बलिया जनपद से आते हैं।

माननीय मंत्री जी भी बलिया जनपद से हैं और हमारे समझ से 6 माननीय मंत्रीगण बलिया जनपद से हैं जिसमें से 3 केबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री हैं और बलिया जनपद उत्तर प्रदेश का वह जनपद है जो किसी शायर ने कहा है माननीय अध्यक्ष जी कि कोई सेहरा कफन बना होगा फिर शहीदों का तन बना होगा और हजारों दम बेदम हुए होंगें तो अपना भारत चमन बना होगा। लेकिन आजादी के 68 साल के बाद भी अगर बलिया जनपद में कोई विकलांग अपना सार्टिफिकेट बनवाने के लिए जाता है मा0 अध्यक्ष जी, तो उसको पांच–पांच बार चक्कर लगाने के बाद बैरंग वापस आना पड़ता है। इसलिए मुझे अनुभव है।

(शोर)

संग्राम सिंह जी बोलने दीजिए पुराने मित्र हैं।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करिए। आपका समय हो गया। एक सुझाव दे दो बस।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

मैं सुझाव ही देने जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

देते तो हो नहीं, इधर–उधर की बात कर रहे हों।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

मान्यवर, उसमें विकलांग और पिछड़ा वर्ग का दोष नहीं है। दो स्वास्थ्य विभाग के डाक्टर हैं जो चक्कर कटवाते हैं और इसलिए मैं कह रहा हूं अभी भारत सरकार द्वारा मैंने वहां पर कैम्प लगवाया था..

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

अरे थोड़ा बोलने दीजिए, उस कैम्प में मैंने महसूस किया जो सार्टीफिकेट लेकर आने वाले लोग थे तो उसमें जितने लोग आ रहे थे उसमें सार्टीफिकेट लेकर आने वालों की संख्या कम थी और बिना सार्टीफिकेट वालों की संख्या ज्यादा थी।

श्री अध्यक्ष–

आप सी0एम0ओ0 से मिल लीजिएगा। अब बैठिए पांच मिनट हो गए हैं।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

मान्यवर, मा0 अध्यक्ष जी मोदी जी का नारा था सबका साथ, सबका विकास, मैंने जो कैम्प लगवाया उसमें सार्टीफिकेट वालों की संख्या कम थी..

डा0 संग्राम यादव–

कितनी बार इसको कहेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब बैठिए बात आ गई है।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

यह चिन्ता का विषय है मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मैंने इस क्षेत्र में काफी काम किया है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से जो सार्टीफिकेट बनाने

का जो इन्होंने निर्णय लिया है निश्चित रूप से यह धन्यवाद देने योग्य है लेकिन मा0 अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं कि यह निर्णय 3–9–2014 का है आपने नियम बनाया है हो सकता है कि इसके क्रियान्वयन में देर हो, अभी सिकन्दपुर के विधायक जी नहीं हैं इस सदन में, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था,..

श्री अध्यक्ष–

अब आपका समय खत्म हो गया है। राणा जी इनको समझाओ।

(श्री उपेन्द्र जी द्वारा अखबार दिखाने पर)

कुछ नहीं लिखा जाएंगा, कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। अखबार का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। अभी नये–नये आये हो, जानते हो नहीं नियम। कोई अखबार का प्रदर्शन किया जाता है ? बैठिए कुछ नहीं लिखा जाएंगा और न यह कार्यवाही का अंग बनेगा। आपका लिखा नहीं जाएंगा टाइम हो गया है।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

बैठिए आप लोग। कुछ नहीं लिखा जा रहा है।अब बजट पास कराने दें। ज्यादती न करो अब बैठो।

'डा0 संग्राम यादव–

मान्यवर, हम आपके आभारी है कि आपने हमें बोलने का अवसर दिया।अभी हमारे साथी ने बार–बार डा0 लोहिया जी का उद्धरण दिया और कहा कि लोहिया जी ने पिछड़े वर्ग की बात कहीं, संसोपा ने बांधी गाय, पिछड़े पावें सौ में सात, क्या हमारे साथ न्याय हुआ ? इस देश की भारतीय जनता पार्टी की पिछड़े वर्ग के बारे में उसकी राय क्या है ? भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेता मा0 मुलायम सिंह यादव जी सामाजिक न्याय आन्दोलन को लेकरके जो देश के अन्दर अलख जगाने का काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों के हकों के खिलाफ सड़कों के ऊपर उतरकर विरोध किया। (मेजें थपथपाई गईं) कहां तक पिछड़ा समझते हैं। कौन बात कहां रखी जानी चाहिए। यह पिछड़े वर्ग की बात है हमारी देश के अन्दर संख्या कितनी है। हम चाहते हैं देश के अन्दर जनगणना हो जाएं। जो पिछड़े वर्ग की संख्या है उसके तादाद में हमें हक और अधिकार मिल जाएं। यह देश अपने आप मजबूत हो जाएंगा। (शोर)

एक सदस्य–

यह कोई बात नहीं है इनको बैठाइए।

डा0 संग्राम यादव–

मान्यवर, बात अगर कही जायेगी तो बात आयेगी।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, इस सदन में जो बजट और कटौती प्रस्ताव आता है तो सबकी चिन्ता प्रदेश के लोगों की बेहतरी और उनके कल्याण की ही चिन्ता है। जो कटौती रखते हैं, सुझाव और आलोचना देते हैं उनकी भी चिन्ता है और सरकार की ओर से जो बंदोबस्त है उसकी भी चिन्ता है। इसलिये मैं इस माहौल को कहीं दूसरी ओर नहीं ले जाना चाहता हूं कि मैं कोई उत्तेजनात्मक बात करके इसको कहीं दूसरी जगह नहीं ले जाना चाहता हूं। कटौती प्रस्ताव रखते हुए डाक्टर साहब ने जो बात कही मैं उनका धन्यवाद करता हूं और जो सुझाव आपने दिये हैं मैं प्रयास करूंगा कि इसमें से जो भी सुझाव जिनका क्रियान्वयन आगे हम कर सकें उन पर पूरी गम्भीरता से विचार करके और उसको आगे शामिल करने की कोशिश करेंगे। आपने कुछ सुझाव बहुत अच्छे दिये। मैंने बताया नहीं, चूंकि सारी बातें बताना संभव नहीं होता। आपने ब्रेल लिपि की बात कही है। मैंने उल्लेख नहीं किया कि हम ब्रेल प्रेस की भी स्थापना उत्तर प्रदेश में करने का बंदोबस्त कर रहे हैं। ब्रेल प्रेस जब हम बना रहे हैं तो ब्रेल लिपि की बात भी अपने आप आ जायेगी। आपने स्पीच थेरेपिस्ट की जो बात कही है उसको तैयार करने के क्रम में ही हम यूनिवर्सिटीज में अपने यहां प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब तक स्पीच थेरेपिस्ट नहीं होंगे तब तक थेरेपी कैसे देंगे। इन सारी चीजों को हम कर रहे हैं। आपने प्रमाण–पत्र की जो बात कही वह बात आ गई, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं और एक और बात का उल्लेख मैं कर देना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि आज शिक्षा के चार विभागों का बेसिक शिक्षा का आ गया, माध्यमिक शिक्षा का आ गया, उच्च शिक्षा का आ गया, व्यावसायिक शिक्षा का आ गया, तो इसलिये आज उल्लेख करना चाहता हूं। मान्यवर, हमारी एक योजना है कि प्रत्येक विद्यालय में एक टीचर को हम इसके लिये नोडल टीचर बना दें, क्योंकि विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ रहने में जो सुविधा–असुविधा होती है और उनको विशेष केयर की जो जरूरत होती है तो इस वजह से हम चाहते हैं कि प्रत्येक विद्यालय एक टीचर को नोडल बना दे और उन्हीं के माध्यम से विकलांग बच्चों की यदि कोई कठिनाई हो तो वह अधिकारियों तक भी पहुंचे, विभाग तक भी पहुंचे और हम उसके निराकरण के लिये काम कर सकें। अब तक यह व्यवस्था नहीं थी इसलिये हम यह नयी व्यवस्था करने जा रहे हैं। हम समझते हैं कि इसका भी समर्थन होना चाहिये कि बहुत शानदार व्यवस्था है। मान्यवर, मैं श्री उपेन्द्र तिवारी जी का धन्यवाद देता हूं मैं इनका मतदाता हूं कि इन्होंने इसमें भाग लिया और बहुत सारी बातों की सराहना की। इन्होंने एक बात जो कही थी उस पर मैं जरूर कहना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि पिछड़े सबसे निरीह हैं। यह निरीह शब्द गलत है। उत्तर प्रदेश में और देश में पिछड़ा निरीह नहीं है। उसके हकों के साथ नाइंसाफी हुयी है। मा0 अध्यक्ष जी, उसके तमाम संघर्षों को आगे बढ़ाने में निजी तौर पर आपने कितना संघर्ष किया है और कितनी बार जेल गये हैं। इस सदन में तमाम लोग ऐसे बैठे हुये हैं जिन्होंने पिछड़ों के उन अधिकारों के लिये डा0 राम मनोहर लोहिया जी के रास्ते पर चलते हुए उस संघर्ष को आगे बढ़ाया है। डा0 लोहिया ने कभी निरीह नहीं कहा। डा0 संग्राम यादव

नाराज हो रहे थे। कोई पिछड़ा निरीह नहीं है और मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते इस प्रदेश में कोई पिछड़ा निरीह नहीं रहेगा। मान्यवर, निरीह शब्द गलत है। हम निरीह नहीं हैं। हमारे हकों के साथ, हमारे साथ नाइंसाफी हुयी हैं यह बात अलग है। जो बातें उन लोगों ने कहीं हैं उनमें जिन बातों का जितना समावेश हो सकेगा अगली योजना में हम करने का काम करेंगे। मैं यह चाहता हूं कि जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है वह वापस ले लें और सर्वसम्मति से इसको पारित करा दें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 16,73,27,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

ख7.50, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम–51 में कुल 42 सूचनायें आई थीं, जिसमें से 10 सूचनाओं को लिया गया है। मैं नेताओं से अनुरोध करूंगा कि अपने माननीय सदस्यों से कह दें कि वह नियम–51 तो देते हैं और लेने से पहले मुझ पर भी दबाव डालते हैं कि उनकी सूचना ले ली जाये, लेकिन वह यहां रहते नहीं हैं। अब जो यहां नहीं रहेगा, उसके नियम–51 की सूचना निरस्त कर दी जायेगी और उसके बाद जो सदस्य यहां होंगे उनकी सूचना को ले लिया जायेगा।

पहली सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की है। यह नहीं हैं, इसलिये इनकी सूचना निरस्त की जाती है।

दूसरी सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की है। यह भी नहीं है, इनकी भी सूचना निरस्त की जाती है। यह सरकार का जवाब के लिये नहीं जायेगा। (निरस्त)

तीसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जनपद रायबरेली स्थित समसपुर पक्षी विहार में व्याप्त जलभराव की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)

चौथी सूचना श्री हरविन्दर साहनी उर्फ रोमी साहनी की है। यह भी नहीं हैं। इनकी सूचना भी निरस्त की जाती है। (निरस्त)

पांचवीं सूचना श्री अमरपाल शर्मा की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद में 100 बेड का सरकारी अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में। (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)

छठवीं सूचना श्री लोकेन्द्र सिंह की है। यह भी नहीं हैं। इनकी सूचना भी निरस्त की जाती है। (निरस्त)

सातवीं सूचना श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा की जनपद फतेहपुर के बिन्दकी क्षेत्रान्तर्गत पांच सौ आबादी वाली ग्राम पंचायतों को पक्की सड़कों से जोड़े जाने के सम्बन्ध में। (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)

आठवीं सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की है। यह भी नहीं हैं, इनकी सूचना भी निरस्त। (निरस्त)

नौवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में किसानों को खराब आलू की दवा दिये जाने से किसानों की बर्बाद हुई फसल के नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में। (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)

दसवीं सूचना श्री आशीष कुमार यादव की है। यह भी नहीं हैं। इनकी सूचना भी निरस्त। (निरस्त)

जो मा0 सदस्य उपस्थित हैं, उनकी सूचनायें ले लेते हैं।

एक सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की ले लेते हैं।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

अध्यक्ष जी, हमारी सूचना ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना इसमें नहीं है।

श्री सुरेश राणा जी हैं ? ठीक है, इनकी सूचना ले लेते हैं।

श्री राजेश त्रिपाठी जी की सूचना ले लेते हैं।

श्री बब्बन सिंह चौहान–

मान्यवर, मेरी सूचना ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आपकी सूचना ले लेते हैं।

मैं अभी मा0 नेताओं की बैठक करूंगा और उसके बाद जो अपने वक्तव्य के टाइम पर नहीं रहेगा तो उसका एक दिन का टी0ए0 पूरा निरस्त कर दिया जायेगा, तब यह लोग रहेंगे।

जनपद मथुरा अन्तर्गत गोवर्धन दानधारी मन्दिर के सामने दिनांक 15 सितम्बर, 2014 को गाड़ी यू0पी0 32 एफ0ए0 2002 का शीशा तोड़कर की गई चोरी के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू हैं ? नहीं हैं। (निरस्त)

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा स्थित मझिगवां मौरंग, बालू घाट को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

श्रीमती कृष्णा पासवान जी हैं ? यह भी नहीं नहीं हैं। (निरस्त)

फिरोजाबाद नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र हिमायूंपुर में 800 मीटर कच्ची पटरी की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

श्री मनीष असीजा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत .....

बेसिक शिक्षा (राज्य मंत्री) (श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया'')–

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

खदिनांक 12–03–2015 को यह सूचना दी गई कि नगर फिरोजाबाद में नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र हिमायूंपुर, सब्जी मण्डी नाला के किनारे से सीवर पम्पिंग स्टेशन सेक्टर–4, सुहाग नगर तक की लगभग 800 मीटर लम्बी पटरी पूर्णतया कच्ची है इस पटरी के सहारे लगभग 20 हजार की गरीब एवं मेहनतकश नागरिकों की आबादी है, जिनको आवागमन में विशेष कर वर्षा ऋतु में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जल भराव के कारण आये दिन कोई न कोई दुर्घटनाग्रस्त होता रहता है। जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कराने की आवश्यकता है। अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।

मा0 सदस्य द्वारा दी गई उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर फिरोजाबाद में हिमायूंपुर सब्जी मण्डी नाले के किनारे के सीवर पम्पिंग स्टेशन से0नं0–4 सुहाग नगर तक की पटरी पूर्णतया कच्ची है। इस कार्य को कराये जाने हेतु फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र मांगा गया था, जिसकी अनापत्ति निकाय द्वारा पूर्व में ही विकास प्राधिकरण को दे दिया गया है। उक्त

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पटरी की मरम्मत तथा निर्माण कार्य फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाता है।,

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में बी0पी0एल0 कार्ड/अन्त्योदय योजना में कार्ड के लाभार्थियों के चयन में की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

श्री बब्बन सिंह मा0 सदस्य द्वारा यह अवगत कराया गया है कि.....

बेसिक शिक्षा (राज्य मंत्री) (श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया'')–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

खवित्तीय वर्ष 2014–15 में जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र, विकास खण्ड–नियमताबाद के ग्राम सभा जफरपुर, कठौरी, मन्नापुर, परोरवां को समग्र ग्राम डा0 राम मनोहर लोहिया ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया था, जिसमें कि लोहिया आवास, समाजवादी पेंशन, जमीन पट्टा आवंटन, बी0पी0एल0 कार्ड/अन्त्योदय कार्ड पात्रों को न देकर अपात्रों को आवंटित किया गया है, जिसमें कि भारी मात्रा में धन उगाही की गई है उक्त ग्रामसभाओं में जो कुछ निर्माण कार्य करवाया गया है वह मानक के अनुरूप नहीं है, मेरे द्वारा पूर्व में भी इसकी शिकायत की गई लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में यथाशीघ्र कार्यवाही की मांग की गई है।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय अन्तर्गत विकास खण्ड–नियमताबाद के चयनित ग्राम जफरपुर, कठौरी, मन्नापुर, परोरवां में लोहिया आवास, समाजवादी पेंशन, जमीन पट्टा आवंटन, बी0पी0एल0 कार्ड/अन्त्योदय कार्डों का चयन शासन द्वारा निर्गत गाइड लाइन के अनुसार किया गया है। चयनित पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। अभी तक धन उगाही का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है और न ही मानक के विपरीत कार्य कराये जाने की कोई सूचना प्राप्त हुई है। मा0 विधायक जी द्वारा किसी विशिष्ट शिकायत का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसका परीक्षण कराया जा सके। यदि कोई विशिष्ट बिन्दु संज्ञान में लाया जाता है तो उस पर नियमानुसार जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।,

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग सी0डी0–1 तथा प्रान्तीय खण्ड के अन्तर्गत मुख्य सड़कों की मरम्मत/नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

श्री पूरन प्रकाश जी हैं ? नहीं हैं। (निरस्त)

जनपद बस्ती के तहसील भानपुर व रुधौली में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय प्रताप जयसवाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

श्री संजय प्रताप जयसवाल जी हैं ? यह भी नहीं हैं। (निरस्त)

जनपद बहराइच के विकास खण्ड नवाबगंज के किसानों के धान व गेहूं के मूल्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी हैं ? नहीं हैं। (निरस्त) । अगली बार हम नेताओं की राय करके इन लोगों का एक दिन का टी0ए0 काट देंगे।

जनपद बरेली में जिला विद्यालय निरीक्षक बरेली द्वारा शिक्षकों के जी0पी0एफ0 के भुगतान में की जा रही धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

प्रकरण में शिक्षा निदेशक माध्यमिक के पत्रांक–सामान्य (1) शिविर.....

बेसिक शिक्षा (राज्य मंत्री) (श्री योगेश प्रताप सिंह)–

मान्यवर इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाएं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख9956/नि–51–5/2014, दिनांक 13–03–2015 एवं पत्रांक पेंशन (2)/2058/2014–15, दिनांक 13–03–2015 के माध्यम से प्राप्त आख्या व सुसंगत अभिलेखों के अनुसार जनपद बरेली स्थित चाचा नेहरू बाल मन्दिर इण्टर कालेज,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आंवला में जी0पी0एफ0 के अन्तिम भुगतान हेतु श्रीमती हसीबा परवीन पुत्री स्वर्गीय श्री मुमताज अली प्रवक्ता के नाम से चेक जारी हुआ था। उक्त चेक बैंक द्वारा वापस लौटाये जाने के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, बरेली द्वारा वित्त एवं लेखाधिकारी (मा0) शिक्षा, बरेली से जांच कराई गई। वित्त एवं लेखाधिकारी (मा0) शिक्षा, बरेली की आख्या के अनुसार उक्त चेक की स्वीकृति विषयक आदेश 3928–31/2014–15, दिनांक 08–09–2014 के सम्बन्ध में पुष्टि नहीं हो पाई। कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक बरेली के पटल प्रभारी श्री मो0 कलीम खां को प्रश्नगत स्वीकृति कहां से प्राप्त हुई, यह स्पष्ट नहीं हो सका। पटल प्रभारी मो0 कलीम खां द्वारा स्वीकृति आदेश की मूल प्रति, कैशबुक तथा अभिलेख भी वित्त एवं लेखाधिकारी को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

2–वित्त एवं लेखाधिकारी (मा0) शिक्षा, बरेली (जांच अधिकारी) की आख्या के आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली मण्डल को प्रस्तुत की गई आख्या में उल्लिखित है कि श्री मो0 कलीम खां पटल प्रभारी द्वारा जानबूझकर बिना मूल अभिलेख प्रस्तुत किये उक्त अनियमित चेक जारी कराने के कार्यवाही की गई है, जबकि लाभार्थी श्रीमती हसीबा परवीन के पिता मुमताज अली के नाम का कोई प्रवक्ता उक्त विद्यालय में नहीं रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि श्री कलीम द्वारा अभी तक लेखा के किसी भी मद की कोई भी कैशबुक व वितरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3–वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, बरेली की संस्तुति व रिपोर्ट के आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली द्वारा मो0 कलीम खां, पटल प्रभारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली के निलम्बन की संस्तुति की गई जिसके आधार पर संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली के आदेश दिनांक 31–01–2015 द्वारा श्री कलीम खां के विरुद्ध अनुशासनिक जांच संस्थित कर निलम्बित करते हुए मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र, बरेली से सम्बद्ध किया गया है तथा आरोप–पत्र निर्गत करते हुए उप शिक्षा निदेशक (मा0) बरेली मण्डल बरेली को उक्त जांच हेतु जांच अधिकारी नामित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली द्वारा विशेष आडिट कराये जाने के अनुरोध–पत्र दिनांक 06–01–2015 के क्रम में अपर शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा को विशेष आडिट कराये जाने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।,

जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र कस्ता के ग्राम बेहजम से नीमगांव तक की सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार लाला द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

श्री सुनील कुमार लाला जी हैं? नहीं हैं। (निरस्त)

जनपद शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम–हजरतपुर के निवासी श्री महेश की दिनांक 08 मार्च, 2015 को ट्रैक्टर–ट्राली पलटने से हुई मृत्यु में कृषक दुर्घटना बीमा का

लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)

श्री अध्यक्ष–

श्री रोशन लाल वर्मा जी हैं ? नहीं है। इसमें मंत्री जी का लिखित अनुरोध स्थगन के लिये प्राप्त हुआ है।

जनपद झांसी में कुख्यात भू–माफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों का बिना लैण्ड यूज बदले अवैध प्लाटिंग कर विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि शर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

श्री रवि शर्मा जी हैं ? नहीं हैं। (निरस्त)

जनपद हाथरस के कस्बा सिकन्दराराऊ में रोडवेज बस स्टैण्ड स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

श्री रामवीर उपाध्याय जी हैं ? नहीं हैं। (निरस्त)

जनपद वाराणसी के रामनगर स्थित सुल्तानपुर गांव में स्थापित मिनी ट्यूबवेल को बिजली कनेक्शन दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव जी हैं ? नहीं हैं। (निरस्त)

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 08 बजे दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 16 मार्च, 2015

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 66 विधान सभा (121)–31–7–2015–813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।